



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं० 31] नई दिल्ली, जुलाई 27—अगस्त 2, 2003 शनिवार/श्रावण 5—श्रावण 11, 1925
No. 31] NEW DELHI, JULY 27—AUGUST 2, 2003 SATURDAY/SRAVANA 5—SRAVANA 11, 1925

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालयों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए
सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

मंत्रिमंडल सचिवालय

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 2003

का. आ. 2128.—केन्द्रीय सरकार एतद्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (1946 का अधिनियम सं. 25) की धारा 6 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्नाटक राज्य सरकार की अधिसूचना सं. एच. डी. 89 पीसीआर 2003 दिनांक 24-06-2003 द्वारा प्राप्त कर्नाटक राज्य सरकार की सहमति से मैसर्स फोनिक्स प्लास्टिक्स कम्पनी के मालिक श्री के. प्रभाकर राव, मैसर्स यूनाइटेड मशीनरी वर्क्स, होसूर और मैसर्स ए. एल. पोलिमर्स, होसूर के मालिक श्री के. अशोकन और केनरा बैंक के अज्ञात कर्मचारियों और किन्हीं अन्य लोकसेवकों अथवा व्यक्तियों के विरुद्ध उनके कपटपूर्ण कार्यों के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी संपठित धारा 420 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 2022 GI/2003 - 1

1988 की धारा 13 (2) संपठित धारा 13(1) (डी) के अधीन दंडनीय अपराधों और उक्त अपराधों से संबंधित अथवा संसक्त तथा उसी संव्यवहार के अनुक्रम में किए गए अथवा उन्हीं तथ्यों से उद्भूत किन्हीं अन्य अपराधों के अन्वेषण के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता का विस्तार सम्पूर्ण कर्नाटक राज्य पर करती है।

[सं. 228/63/2003-डी. एस. पी. ई.]

शुभा ठाकुर, अवर सचिव

CABINET SECRETARIAT

New Delhi, the 22nd July, 2003

S.O. 2128.—In exercise of the powers conferred by sub-section (I) of Section 5 read with Section 6 of the

(5375)

Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (Act No. 25 of 1946), the Central Government with the consent of the State Government of Karnataka vide Notification No. HD 89 PCR 2003 dated 24-06-2003, hereby extends the powers and jurisdiction of the members of Delhi Special Police Establishment to the whole of the State of Karnataka for investigation of offences punishable under section 120-B read with 420 IPC and under section 13(2) read with 13(1)(d) of Prevention of Corruption Act, 1988, against Shri K. Prabhakar Rao, Proprietor of M/s Phoenix Plasts Company, Shri K. Asokan, Proprietor of both M/s United Machinery Works, Hosur, and M/s A. L. Polymers, Hosur, and unknown officials of Canara Bank, for their fraudulent acts, and any other public servants or persons in relation to, or in connection with the said offences, and any other offences committed in the course of the same transaction or arising out of the same facts.

[No. 228/63/2003-DSPE]

SHUBHA THAKUR, Under Secy.

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 2003

का.आ. 2129.—केन्द्रीय सरकार एतद्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (1946 का अधिनियम सं. 25) की धारा 6 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड राज्य सरकार के गृह विभाग की दिनांक 17-5-2001 की अधिसूचना सं. 819/रांची द्वारा प्राप्त झारखंड राज्य सरकार की सहमति से 9-5-99 को बोकारो स्टील प्लांट (बी एस एल), बोकारो, झारखंड से 8.10 लाख रु. मूल्य के स्टेनलैस स्टील की चोरी के अपराध तथा उपर्युक्त अपराध से संबंधित अथवा संसक्त प्रयत्न, दुष्प्रेरण और षडयंत्र तथा उसी संव्यवहार के अनुक्रम में किए गए अथवा उन्हीं तथ्यों से उद्भूत किसी अन्य अपराध अथवा अपराधों के अन्वेषण के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता का विस्तार सम्पूर्ण झारखंड राज्य पर करती है।

[सं. 228/16/2003-डी. एस. पी. ई.]

शुभा ठाकुर, अवर सचिव

New Delhi, the 22nd July, 2003

S.O. 2129.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 read with Section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (Act No. 25 of 1946), the Central Government with the consent of

the State Government of Jharkhand, Home Department accorded vide Notification No. 11/C-101/2001/H.D./819/ dated 17th May 2001, hereby extends the powers and jurisdiction of the members of Delhi Special Police Establishment to the whole of the State of Jharkhand for investigation of offence of theft of stainless steel worth Rs. 8.10 lakh on 9-5-1999 from Bokaro Steel Plant (BSL) Bokaro, Jharkhand and attempts, abetments and conspiracy in relation to or in connection with the offence mentioned above and any other offence or offences committed in the course of the same transaction or arising out of the same facts.

[No. 228/16/2003-DSPE]

SHUBHA THAKUR, Under Secy.

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 2003

का.आ. 2130.—केन्द्रीय सरकार एतद्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (1946 का अधिनियम सं. 25) की धारा 6 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तरांचल राज्य सरकार के गृह विभाग की अधिसूचना सं. 57/गृह-03, देहरादून दिनांक 11-7-2003 द्वारा प्राप्त उत्तरांचल राज्य सरकार की सहमति से श्री हरक सिंह रावत, तत्कालीन राज्य मंत्री, उत्तरांचल सरकार द्वारा सुश्री जेनी, पुत्री श्री जवाहर ज्योति देवरी, निवासी गांव, साफिया सफा कुआं, जिला तिनसुकिया, असम को रोजगार का प्रलोभन देकर उसके साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाने और बाद में उसे एक महीने के भीतर रोजगार मिलने का आश्वासन देकर सरकारी संरक्षण केंद्र में भर्ती कराने परन्तु उक्त आश्वासन को पूरा करने में असफल रहने के संबंध में भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अधीन मामले के पंजीकरण और उपर्युक्त अपराधों में से एक अथवा अधिक से संबंधित अथवा संसक्त प्रयत्नों, दुष्प्रेरणों और षडयंत्रों तथा उसी संव्यवहार के अनुक्रम में किए गए अथवा उन्हीं तथ्यों से उद्भूत किन्हीं अन्य अपराधों के अन्वेषण के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता का विस्तार सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य पर करती है।

[सं. 228/56/2003-डी. एस. पी. ई.]

शुभा ठाकुर, अवर सचिव

New Delhi, the 25th July, 2003

S.O. 2130.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 read with section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (Act No. 25 of

1946), the Central Government, with the consent of the State Government of Uttaranchal, Home Department vide Home Deptt. Notification No. 57/Grih-03, Dehradun dated 11-7-2003, hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment to the whole of State of Uttaranchal for registration of case and for investigation of offence u/s. 376 IPC in connection with establishment of physical relations with Ms. Jenny d/o Sh. Jawahar Jyoti Devri r/o village Safiya Safa Kuan, Distt. Tinsukia, Assam, against her will by Sh. Harak Singh Rawat, the then Minister of State Govt. of Uttaranchal, by giving allurement of employment and subsequently getting her admitted to Govt. Protective Home with the assurance that she would be given a job within a month but failed to fulfil the assurance and attempts, abetments and conspiracies in relation or in connection with one or more of this offence and any other offences committed in the course of the same transaction arising out of the same facts.

[No. 228/56/2003-DSPE]

SHUBHA THAKUR, Under Secy.

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 2003

का.आ. 2131.—केन्द्रीय सरकार एतद्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (1946 का अधिनियम सं. 25) की धारा 6 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्नाटक राज्य सरकार की अधिसूचना सं. एच डी 90 पी सी आर 2003 दिनांक 24-06-2003 द्वारा प्राप्त कर्नाटक राज्य सरकार की सहमति से मैसर्स दिनेश एग्रो प्रोडक्ट्स लि. (डी ए पी एल), श्री डी. बी. मोरे, अध्यक्ष, मैसर्स दिनेश एग्रो प्रोडक्ट्स लि., श्री आर. बी. मोरे, प्रबंध निदेशक, मैसर्स दिनेश एग्रो प्रोडक्ट्स लि. और श्री एच. के. देशपांडे, पूर्व सहायक महाप्रबंधक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पुणे कैम्प शाखा, पुणे, श्री के. के. श्रीनिवासन, पूर्व वरिष्ठ प्रबंधक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पुणे कैम्प शाखा, पुणे और श्री पी. वी. शास्त्री, पूर्व प्रबंधक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पुणे कैम्प शाखा, पुणे और किन्हीं अन्य लोकसेवकों अथवा व्यक्तियों के विरुद्ध उनके कपटपूर्ण कार्यों के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी सपठित धारा 420, 409 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) सपठित धारा 13 (1)(डी) के अधीन दंडनीय अपराधों और उक्त अपराधों से संबंधित अथवा संसक्त तथा उसी संव्यवहार के अनुक्रम में किए गए अथवा उन्हीं तथ्यों से उद्भूत किन्हीं अन्य अपराधों के अन्वेषण के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों

की शक्तियों और अधिकारिता का विस्तार सम्पूर्ण कर्नाटक राज्य पर करती है।

[सं. 228/64/2003-डी. एस. पी. ई.]

शुभा ठाकुर, अवर सचिव

New Delhi, the 25th July, 2003

S.O. 2131.—In exercise of the powers conferred by sub-section (I) of section 5 read with section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (Act No. 25 of 1946), the Central Government with the consent of the State Government of Karnataka vide Notification No. HD 90 PCR 2003 dated 24-06-2003, hereby extends the powers and jurisdiction of the members of Delhi Special Police Establishment to the whole of the State of Karnataka for investigation of offences punishable under section 120-B read with Section 420, 409 IPC and under section 13(2) read with 13(1)(d) of Prevention of Corruption Act, 1988, against M/s. Dinesh Agro Products Ltd. (DAPL), Shri D.B. More, Chairman, M/s. Dinesh Agro Products Ltd., Shri R.B. More, Managing Director, M/s. Dinesh Agro Products Ltd., and Shri H.K. Deshpande, formerly Assistant General Manager, Central Bank of India, Pune Camp Branch, Pune, Shri K.K. Srinivasan, formerly Sr. Manager, Central Bank of India, Pune Camp Branch, Pune, and Shri P.V. Shastri, formerly Manager, Central Bank of India, Pune Camp Branch, Pune, for their fraudulent acts, and any other public servants or persons in relation to, or in connection with the said offences, and any other offences committed in the course of the same transaction or arising out of the same facts.

[No. 228/64/2003-DSPE]

SHUBHA THAKUR, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 2002

(आयकर)

का. आ. 2132.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा “स्वामी रामानंद तीर्थ

मेमोरियल समिति, हैदराबाद को वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 तक के कर निर्धारण वर्षों के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त उप-खंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

- (i) कर-निर्धारिती उसकी आय का इस्तेमाल अथवा उसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए उसका संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है;
- (ii) कर-निर्धारिती उपर्युक्त कर-निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से उसकी निधि (जेवर-जवाहिरात, फर्नीचर अथवा किसी अन्य वस्तु आदि के रूप में प्राप्त तथा अनुरक्षित स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा;
- (iii) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों;
- (iv) कर-निर्धारिती आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार अपनी आय विवरणी नियमित रूप से आयकर प्राधिकारी के समक्ष फाइल करेगा;
- (v) विघटन की स्थिति में अतिरिक्त राशियां और परिसम्पत्तियां समान उद्देश्यों वाले धर्मार्थ संगठन को दे दी जाएंगी।

[अधिसूचना सं. 356/2002/फ. सं. 197/240/2002-आ.क.नि.-I]

आई. पी. एस. बिन्द्रा, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

New Delhi, the 29th November, 2002

(INCOME-TAX)

S.O. 2132.—In exercise of the powers conferred by the sub-clause (iv) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies the "Swami Ramananda Tirtha Memorial Committee, Hyderabad" for the purpose of the said sub-clause for the assessment years 1999-2000 to 2001-2002 subject to the following conditions, namely :—

- (i) the assessee will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established;
- (ii) the assessee will not invest or deposit its funds (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture

etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of Section 11;

- (iii) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of account are maintained in respect of such business;
- (iv) the assessee will regularly file its return of income before the Income-tax authority in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961;
- (v) that in the event of dissolution, its surplus and the assets will be given to a charitable organisation with similar objectives.

[Notification No. 356/2002/F. No. 197/240/2002 ITA-I]

I. P. S. BINDRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 2003

(आयकर)

का. आ. 2133.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा "इंडिया ब्राण्ड इक्विटी फंड ट्रस्ट, नई दिल्ली" को वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 तक के कर निर्धारण वर्षों के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त उप-खंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

- (i) कर-निर्धारिती उसकी आय का इस्तेमाल अथवा उसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए उसका संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है;
- (ii) कर-निर्धारिती उपर्युक्त कर-निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से उसकी निधि (जेवर-जवाहिरात, फर्नीचर अथवा किसी अन्य वस्तु आदि के रूप में प्राप्त तथा अनुरक्षित स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा;
- (iii) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों;
- (iv) कर-निर्धारिती आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार अपनी आय विवरणी नियमित रूप से आयकर प्राधिकारी के समक्ष फाइल करेगा;

- (v) विघटन की स्थिति में अतिरिक्त राशियां और परिसम्पत्तियां समान उद्देश्यों वाले धर्मार्थ संगठन को दे दी जाएंगी।

[अधिसूचना सं. 28/2003/फ. सं. 197/84/99-आयकर नि.-I]

आई. पी. एस. बिन्द्रा, अवर सचिव

New Delhi, the 30th January, 2003

(INCOME-TAX)

S.O. 2133.—In exercise of the powers conferred by the sub-clause (iv) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies the “India Brand Equity Fund (IBEF) Trust, New Delhi” for the purpose of the said sub-clause for the assessment years 1999-2000 to 2001-2002 subject to the following conditions, namely :—

- (i) the assessee will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established;
- (ii) the assessee will not invest or deposit its funds (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of Section 11;
- (iii) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of account are maintained in respect of such business;
- (iv) the assessee will regularly file its return of income before the Income-tax authority in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961;
- (v) that in the event of dissolution, its surplus and the assets will be given to a charitable organisation with similar objectives.

[Notification No. 28/2003/F. No. 197/84/99-ITA-I]

I. P. S. BINDRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 2003

(आयकर)

का. आ. 2134.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा “युसुफ मेहराली सेंटर, मुंबई” को वर्ष 2001-02 से 2003-04 तक के कर निर्धारण वर्षों के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त उप-खंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

- (i) कर-निर्धारिणी उसकी आय का इस्तेमाल अथवा उसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए उसका संचयन पूर्णतया

तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है;

- (ii) कर-निर्धारिणी उपर्युक्त कर-निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से उसकी निधि (जेवर-जवाहिरात, फर्नीचर अथवा किसी अन्य वस्तु आदि के रूप में प्राप्त तथा अनुरक्षित स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा;
- (iii) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारिणी के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों;
- (iv) कर-निर्धारिणी आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार अपनी आय विवरणी नियमित रूप से आयकर प्राधिकारी के समक्ष फाइल करेगा;
- (v) विघटन की स्थिति में अतिरिक्त राशियों और परिसम्पत्तियां समान उद्देश्यों वाले धर्मार्थ संगठन को दे दी जाएंगी।

[अधिसूचना सं. 32/2003/फ. सं. 197/270/2002-आयकर नि.-I]

आई. पी. एस. बिन्द्रा, अवर सचिव

New Delhi, the 7th February, 2003

(INCOME-TAX)

S.O. 2134.—In exercise of the powers conferred by the sub-clause (iv) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies the “Yusuf Meherally Centre, Mumbai” for the purpose of the said sub-clause for the assessment years 2001-02 to 2003-04 subject to the following conditions, namely :—

- (i) the assessee will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established;
- (ii) the assessee will not invest or deposit its fund (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of Section 11;
- (iii) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of account are maintained in respect of such business;

- (iv) the assessee will regularly file its return of income before the Income-tax authority in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961;
- (v) that in the event of dissolution, its surplus and the assets will be given to a charitable organisation with similar objectives.

[Notification No. 32/2003/F. No. 197/270/2002-ITA-I]

I. P. S. BINDRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 14 फरवरी, 2003

(आयकर)

का. आ. 2135.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा “भारतीय विद्या भवन, मुम्बई” को वर्ष 2002-2003 से 2004-2005 तक के कर निर्धारण वर्षों के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त उप-खंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

- (i) कर-निर्धारिती उसकी आय का इस्तेमाल अथवा उसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए उसका संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है;
- (ii) कर-निर्धारिती उपर्युक्त कर-निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से उसकी निधि (जेवर-जवाहिरात, फर्नीचर अथवा किसी अन्य वस्तु आदि के रूप में प्राप्त तथा अनुरक्षित स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा;
- (iii) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों;
- (iv) कर-निर्धारिती आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार अपनी आय विवरणी नियमित रूप से आयकर प्राधिकारी के समक्ष फाइल करेगा;
- (v) विघटन की स्थिति में अतिरिक्त राशियों और परिसम्पत्तियां समान उद्देश्यों वाले धर्मार्थ संगठन को दे दी जाएंगी।

[अधिसूचना सं. 33/2003/फ. सं. 197/05/2003-आई. टी. ए.-I]

आई. पी. एस. बिन्द्रा, अवर सचिव

New Delhi, the 14th February, 2003

(INCOME-TAX)

S.O. 2135.—In exercise of powers conferred by the sub-clause (iv) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby

notifies the “Bharatiya Vidya Bhawan, Mumbai” for the purpose of the said sub-clause for the assessment years 2002-2003 to 2004-2005 subject to the following conditions, namely :—

- (i) the assessee will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established;
- (ii) the assessee will not invest or deposit its fund (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of Section 11;
- (iii) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of accounts are maintained in respect of such business;
- (iv) the assessee will regularly file its return of income before the Income-tax authority in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961;
- (v) that in the event of dissolution, its surplus and the assets will be given to a charitable organisation with similar objectives.

[Notification No. 33/2003/F. No. 197/05/2003-ITA-I]

I. P. S. BINDRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 14 फरवरी, 2003

(आयकर)

का. आ. 2136.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा “विवेकानन्द रॉक मैमोरियल एण्ड विवेकानन्द केन्द्र, चैन्नई” को वर्ष 2002-2003 से 2004-2005 तक के कर निर्धारण वर्षों के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त उप-खंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

- (i) कर-निर्धारिती उसकी आय का इस्तेमाल अथवा उसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए उसका संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है;
- (ii) कर-निर्धारिती उपर्युक्त कर-निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से उसकी निधि (जेवर-जवाहिरात, फर्नीचर अथवा किसी अन्य वस्तु आदि के रूप में प्राप्त तथा अनुरक्षित स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा;

(iii) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों;

(iv) कर-निर्धारिती आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार अपनी आय विवरणी नियमित रूप से आयकर प्राधिकारी के समक्ष फाइल करेगा;

(v) विघटन की स्थिति में अतिरिक्त राशियाँ और परिसम्पत्तियाँ समान उद्देश्यों वाले धर्मार्थ संगठन को दे दी जाएंगी।

[अधिसूचना सं. 34/2003/फ. सं. 197/03/2003-आई. टी. ए.-I]
आई. पी. एस. बिन्द्रा, अवर सचिव

New Delhi, the 14th February, 2003

(INCOME-TAX)

S.O. 2136.—In exercise of powers conferred by the sub-clause (iv) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies the "Vivekananda Rock Memorial and Vivekananda Kendra, Chennai" for the purpose of the said sub-clause for the assessment years 2002-2003 to 2004-2005 subject to the following conditions, namely:—

- (i) the assessee will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established;
- (ii) the assessee will not invest or deposit its funds (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of Section 11;
- (iii) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of accounts are maintained in respect of such business;
- (iv) the assessee will regularly file its return of income before the Income-tax authority in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961;
- (v) that in the event of dissolution, its surplus and the assets will be given to a charitable organisation with similar objectives.

[Notification No. 34/2003/F. No. 197/03/2003-ITA-I]
I. P. S. BINDRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2003

(आयकर)

का. आ. 2137.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा "मध्य प्रदेश महिला कल्याण समिति, भोपाल" को वर्ष 2002-2003 से 2004-2005 तक के कर निर्धारण वर्षों के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त उप-खंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

- (i) कर-निर्धारिती उसकी आय का इस्तेमाल अथवा उसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए उसका संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है;
- (ii) कर-निर्धारिती उपर्युक्त कर-निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से उसकी निधि (जेवर-जवाहिरात, फर्नीचर अथवा किसी अन्य वस्तु आदि के रूप में प्राप्त तथा अनुरक्षित स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा;
- (iii) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों;
- (iv) कर-निर्धारिती आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार अपनी आय विवरणी नियमित रूप से आयकर प्राधिकारी के समक्ष फाइल करेगा;
- (v) विघटन की स्थिति में अतिरिक्त राशियाँ और परिसम्पत्तियाँ समान उद्देश्यों वाले धर्मार्थ संगठन को दे दी जाएंगी।

[अधिसूचना सं. 43/2003/फ. सं. 197/18/2003-आई. टी. ए.-I]

आई. पी. एस. बिन्द्रा, अवर सचिव

New Delhi, the 28th February, 2003

(INCOME-TAX)

S.O. 2137.—In exercise of powers conferred by the sub-clause (iv) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies the "Madhya Pradesh Mahila Kalyan Samiti, Bhopal" for the purpose of the said sub-clause for the assessment years 2002-2003 to 2004-2005 subject to the following conditions, namely:—

- (i) the assessee will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established;

- (ii) the assessee will not invest or deposit its funds (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in Sub-section (5) of Section 11;
- (iii) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of accounts are maintained in respect of such business;
- (iv) the assessee will regularly file its return of income before the Income-tax authority in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961;
- (v) that in the event of dissolution, its surplus and the assets will be given to a charitable organisation with similar objectives.

[Notification No. 43/2003/F. No. 197/18/2003-ITA-I]
I. P. S. BINDRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2003

(आयकर)

का. आ. 2138.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा "संत श्री आसाराम आश्रम, अहमदाबाद, गुजरात" को वर्ष 2002-2003 से 2004-2005 तक के कर निर्धारण वर्षों के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त उप-खंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

- (i) कर-निर्धारिती उसकी आय का इस्तेमाल अथवा उसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए उसका संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है;
- (ii) कर-निर्धारिती उपर्युक्त कर निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से उसकी निधि (जेवर-जवाहिरात, फर्नीचर अथवा किसी अन्य वस्तु आदि के रूप में प्राप्त तथा अनुरक्षित स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा;
- (iii) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा पुस्तिकाएँ नहीं रखी जाती हों;

- (iv) कर-निर्धारिती आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार अपनी आय विवरणी नियमित रूप से आयकर प्राधिकारी के समक्ष फाइल करेगा;
- (v) विघटन की स्थिति में अतिरिक्त राशियाँ और परिसम्पत्तियाँ समान उद्देश्यों वाले धर्मार्थ संगठन को दे दी जाएंगी।

[अधिसूचना सं. 45/2003/फा. सं. 197/13/2003-
आयकर नि.-1]

आई. पी. एस. बिन्द्रा, अवर सचिव

New Delhi, the 28th February, 2003

(INCOME-TAX)

S.O. 2138.—In exercise of powers conferred by the Sub-clause (iv) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies the "Sant Shri Asharam Ashram, Ahmedabad, Gujarat" for the purpose of the said sub-clause for the assessment years 2002-2003 to 2004-2005 subject to the following conditions, namely :—

- (i) the assessee will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established;
- (ii) the assessee will not invest or deposit its fund (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in Sub-section (5) of Section 11;
- (iii) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of accounts are maintained in respect of such business;
- (iv) the assessee will regularly file its return of income before the Income-tax authority in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961;
- (v) that in the event of dissolution, its surplus and the assets will be given to a charitable organisation with similar objectives.

[Notification No. 45/2003/F. No. 197/13/2003-ITA-I]
I. P. S. BINDRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2003

(आयकर)

का. आ. 2139.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा "गुरुदेव सिद्ध पीठ, गणेशपुरी, जिला धारण महाराष्ट्र" को वर्ष 1999-2000 से

2001-2002 तक के कर निर्धारण वर्षों के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त उप-खंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

- (i) कर-निर्धारिती उसकी आय का इस्तेमाल अथवा उसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए उसका संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है;
- (ii) कर-निर्धारिती उपर्युक्त कर-निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से उसकी निधि (जेवर-जवाहिरात, फर्नीचर अथवा किसी अन्य वस्तु आदि के रूप में प्राप्त तथा अनुरक्षित स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा;
- (iii) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों;
- (iv) कर-निर्धारिती आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार अपनी आय विवरणी नियमित रूप से आयकर प्राधिकारी के समक्ष फाइल करेगा;
- (v) विघटन की स्थिति में अतिरिक्त राशियां और परिसम्पत्तियां समान उद्देश्यों वाले धर्मार्थ संगठन को दे दी जाएंगी।

[अधिसूचना सं. 56/2003/फा. सं. 197/22/2001-आई. टी. ए.-I]
आई. पी. एस. बिन्द्रा, अवर सचिव

New Delhi, the 27th March, 2003

(INCOME-TAX)

S.O. 2139.—In exercise of the powers conferred by the Sub-clause (iv) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies the “Gurudev Siddha Peeth, Ganeshpuri, Distt. Thane, Maharashtra” for the purpose of the said Sub-clause for the assessment years 1999-2000 to 2001-2002 subject to the following conditions, namely :—

- (i) the assessee will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established;
- (ii) the assessee will not invest or deposit its funds (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above

otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in Sub-section (5) of Section 11;

- (iii) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of accounts are maintained in respect of such business;
- (iv) the assessee will regularly file its return of income before the Income-tax authority in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961;
- (v) that in the event of dissolution, its surplus and the assets will be given to a charitable organisation with similar objectives.

[Notification No. 56/2003/F. No. 197/22/2001-ITA-I]
I. P. S. BINDRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2003

(आयकर)

का. आ. 2140.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा “संत निरंकारी मंडल, दिल्ली” को वर्ष 2004-2005 से 2006-2007 तक के कर निर्धारण वर्षों के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त उप-खंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

- (i) कर-निर्धारिती उसकी आय का इस्तेमाल अथवा उसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए उसका संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है;
- (ii) कर-निर्धारिती उपर्युक्त कर-निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से उसकी निधि (जेवर-जवाहिरात, फर्नीचर अथवा किसी अन्य वस्तु आदि के रूप में प्राप्त तथा अनुरक्षित स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा;
- (iii) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों;
- (iv) कर-निर्धारिती आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार अपनी आय विवरणी नियमित रूप से आयकर प्राधिकारी के समक्ष फाइल करेगा;

- (v) विघटन की स्थिति में अतिरिक्त राशियां और परिसम्पत्तियां समान उद्देश्यों वाले धर्मार्थ संगठन को दे दी जाएंगी।

[अधिसूचना सं. 57/2003/फा. सं. 197/55/2003-
आयकर नि.-1]

आई. पी. एस. बिन्द्रा, अवर सचिव

New Delhi, the 27th March, 2003

(INCOME-TAX)

S.O. 2140.—In exercise of the powers conferred by the sub-clause (iv) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies the "Sant Nirankari Mandal, Delhi" for the purpose of the said sub-clause for the assessment years 2004-2005 to 2006-2007 subject to the following conditions, namely :—

- (i) the assessee will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established;
- (ii) the assessee will **not** invest or deposit its funds (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of Section 11;
- (iii) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of account are maintained in respect of such business;
- (iv) the assessee will regularly file its return of income before the Income-tax authority in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961;
- (v) that in the event of dissolution, its surplus and the assets will be given to a charitable organisation with similar objectives.

[Notification No. 57/2003/F. No. 197/55/2003-ITA-I]

I. P. S. BINDRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2003

(आयकर)

का. आ. 2141.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा "इन्टिग्रेटेड रुरल डेवलपमेंट सर्विसिज, सिकन्दराबाद" को वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 तक के कर निर्धारण वर्षों के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त उप-खंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

- (i) कर-निर्धारिती उसकी आय का इस्तेमाल अथवा उसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए उसका संचयन पूर्णतया

तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है;

- (ii) कर-निर्धारिती उपर्युक्त कर-निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से उसकी निधि (जेवर-जवाहिरात, फर्नीचर अथवा किसी अन्य वस्तु आदि के रूप में प्राप्त तथा अनुरक्षित स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा;

- (iii) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों;

- (iv) कर-निर्धारिती आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार अपनी आय विवरणी नियमित रूप से आयकर प्राधिकारी के समक्ष फाइल करेगा;

- (v) विघटन की स्थिति में अतिरिक्त राशियां और परिसम्पत्तियां समान उद्देश्यों वाले धर्मार्थ संगठन को दे दी जाएंगी।

[अधिसूचना सं. 60/2003/फा. सं. 197/99/2002-आयकर नि.-I]

आई. पी. एस. बिन्द्रा, अवर सचिव

New Delhi, the 31st March, 2003

(INCOME-TAX)

S.O. 2141.—In exercise of powers conferred by the sub-clause (iv) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies the "Integrated Rural Development Services, Secunderabad" for the purpose of the said sub-clause for the assessment years 1999-2000 to 2001-2002 subject to the following conditions, namely :—

- (i) the assessee will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established;
- (ii) the assessee will **not** invest or deposit its funds (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of Section 11;
- (iii) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of account are maintained in respect of such business;

- (iv) the assessee will regularly file its return of income before the Income-tax authority in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961;
- (v) that in the event of dissolution, its surplus and the assets will be given to a charitable organisation with similar objectives.

[Notification No. 60/2003/F. No. 197/99/2002-ITA-I]
I. P. S. BINDRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 2003

(आयकर)

का. आ. 2142.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा नेताजी रिसर्च ब्यूरो, कोलकाता को वर्ष 2000-2001 से 2003-2004 तक के कर निर्धारण वर्षों के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त उप-खंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

- (i) कर-निर्धारिती उसकी आय का इस्तेमाल अथवा उसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए उसका संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है;
- (ii) कर-निर्धारिती उपर्युक्त कर-निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से उसकी निधि (जेवर-जवाहिरात, फर्नीचर अथवा किसी अन्य वस्तु आदि के रूप में प्राप्त तथा अनुरक्षित स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा;
- (iii) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों;
- (iv) कर-निर्धारिती आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार अपनी आय विवरणी नियमित रूप से आयकर प्राधिकारी के समक्ष फाइल करेगा;
- (v) विघटन की स्थिति में अतिरिक्त राशियां और परिसम्पत्तियां समान उद्देश्यों वाले धर्मार्थ संगठन को दे दी जाएंगी।

[अधिसूचना सं. 94/2003/फा. सं. 197/40/2003-
आयकर नि.-1]

आई. पी. एस. बिन्द्रा, अवर सचिव

New Delhi, the 25th April, 2003

(INCOME TAX)

S.O. 2142.—In exercise of powers conferred by the sub-clause (iv) of clause (23C) of Section 10 of the

Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies the "Netaji Research Bureau, Kolkata" for the purpose of the said sub-clause for the assessment years 2001-2002 to 2003-2004 subject to the following conditions, namely :—

- (i) the assessee will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established;
- (ii) the assessee will not invest or deposit its fund (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of Section II;
- (iii) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of account are maintained in respect of such business;
- (iv) the assessee will regularly file its return of income before the Income-tax authority in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961;
- (v) that in the event of dissolution, its surplus and the assets will be given to a charitable organisation with similar objectives.

[Notification No. 94/2003/F. No. 197/40/2003-
ITA-I]

I. P. S. BINDRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 2003

(आयकर)

का. आ. 2143.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा "बाम्बे आयरन एण्ड स्टील लेबर बोर्ड, काकाम्बली, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र" को वर्ष 1990-91 से 1992-93 तक के कर निर्धारण वर्षों के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त उप खंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

- (i) कर-निर्धारिती उसकी आय का इस्तेमाल अथवा उसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए उसका संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है;
- (ii) कर-निर्धारिती उपर्युक्त कर-निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उपधारा

(5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से उसकी निधि (जेवर-जवाहिरात, फर्नीचर अथवा किसी अन्य वस्तु आदि के रूप में प्राप्त तथा अनुरक्षित स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा;

(iii) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों;

(iv) कर-निर्धारिती आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार अपनी आय विवरणी नियमित रूप से आयकर प्राधिकारी के समक्ष फाइल करेगा;

(v) विघटन की स्थिति में अतिरिक्त राशियां और परिसम्पत्तियां समान उद्देश्यों वाले धर्मार्थ संगठन को दे दी जाएंगी।

[अधिसूचना सं. 98/2003/फा. सं. 197/65/2003-
आयकर नि.-1]

आई. पी. एस. बिन्द्रा, अवर सचिव

New Delhi, the 30th April, 2003

(INCOME TAX)

S.O. 2143.—In exercise of powers conferred by the sub-clause (iv) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies the "Bombay Iron & Steel Labour Board, Kakambali, Distt. Raigad, Maharashtra" for the purpose of the said sub-clause for the assessment years 1990-91 to 1992-93 subject to the following conditions, namely:—

- (i) the assessee will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established;
- (ii) the assessee will not invest or deposit its fund (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of Section 11;
- (iii) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of account are maintained in respect of such business;
- (iv) the assessee will regularly file its return of income before the Income-tax authority in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961;

(v) that in the event of dissolution, its surplus and the assets will be given to a charitable organisation with similar objectives.

[Notification No. 98/2003/F. No. 197/65/2003-
ITA-I]

I. P. S. BINDRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 2003

(आयकर)

का. आ. 2144.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा "कृष्णगोपाल आयुर्वेदिक धर्मार्थ औषधालय ट्रस्ट, अजमेर" को वर्ष 2001-2002 से 2003-2004 तक के कर निर्धारण वर्षों के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त उप-खंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

- (i) कर-निर्धारिती उसकी आय का इस्तेमाल अथवा उसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए उसका संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है;
- (ii) कर-निर्धारिती उपर्युक्त कर-निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से उसकी निधि (जेवर-जवाहिरात, फर्नीचर अथवा किसी अन्य वस्तु आदि के रूप में प्राप्त तथा अनुरक्षित स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा;
- (iii) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों;
- (iv) कर-निर्धारिती आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार अपनी आय विवरणी नियमित रूप से आयकर प्राधिकारी के समक्ष फाइल करेगा;
- (v) विघटन की स्थिति में अतिरिक्त राशियां और परिसम्पत्तियां समान उद्देश्यों वाले धर्मार्थ संगठन को दे दी जाएंगी।

[अधिसूचना सं. 99/2003/फा. सं. 197/35/2001-
आयकर नि.-1]

आई. पी. एस. बिन्द्रा, अवर सचिव

New Delhi, the 30th April, 2003

(INCOME TAX)

S.O. 2144.—In exercise of powers conferred by the sub-clause (iv) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies the "Krishnagopal Ayurvedic

Dharmarth Aushdhayala Trust, Ajmer" for the purpose of the said sub-clause for the assessment years 2001-2002 to 2003-2004 subject to the following conditions, namely :—

- (i) the assessee will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established;
- (ii) the assessee will not invest or deposit its fund (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of Section II;
- (iii) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of account are maintained in respect of such business;
- (iv) the assessee will regularly file its return of income before the Income-tax authority in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961;
- (v) that in the event of dissolution, its surplus and the assets will be given to a charitable organisation with similar objectives.

[Notification No. 99/2003/F. No. 197/35/2001-ITA-I]
I. P. S. BINDRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 2003

(आयकर)

का. आ. 2145.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा "श्री आनन्दपुर ट्रस्ट, नई दिल्ली" को वर्ष 2002-2003 से 2004-2005 तक के कर निर्धारण वर्षों के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त उप-खंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

- (i) कर-निर्धारिती उसकी आय का इस्तेमाल अथवा उसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए उसका संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है;
- (ii) कर-निर्धारिती उपर्युक्त कर-निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से उसकी निधि (जेवर-जवाहिरात, फर्नीचर अथवा किसी अन्य वस्तु आदि के रूप में प्राप्त तथा अनुरक्षित स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा;

- (iii) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अधिलाभ हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों;
- (iv) कर-निर्धारिती आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार अपनी आय विवरणी नियमित रूप से आयकर प्राधिकारी के समक्ष फाइल करेगा;
- (v) विघटन की स्थिति में अतिरिक्त राशियां और परिसम्पत्तियां समान उद्देश्यों वाले धर्मार्थ संगठन को दे दी जाएंगी।

[अधिसूचना सं. 100/2003/फा. सं. 197/43/2003-
आयकर नि.-1]

आई. पी. एस. बिन्द्रा, अवर सचिव

New Delhi, the 30th April, 2003

(INCOME-TAX)

S.O. 2145.—In exercise of powers conferred by the sub-clause (iv) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies the "Shri Anandpur Trust, New Delhi" for the purpose of the said sub-clause for the assessment years 2002-2003 to 2004-2005 subject to the following conditions, namely :—

- (i) the assessee will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established;
- (ii) the assessee will not invest or deposit its fund (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of Section 11;
- (iii) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of account are maintained in respect of such business;
- (iv) the assessee will regularly file its return of income before the Income-tax authority in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961;
- (v) that in the event of dissolution, its surplus and the assets will be given to a charitable organisation with similar objectives.

[Notification No. 100/2003/F. No. 197/43/2003-
ITA-I]

I. P. S. BINDRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 6 मई, 2003

(आयकर)

का.आ. 2146.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा "दि मुस्लिम एजुकेशनल सोसायटी, बैंक रोड, कालीकट" को वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 तक के कर निर्धारण वर्षों के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त उप-खंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

- (i) कर-निर्धारिती उसकी आय का इस्तेमाल अथवा उसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए उसका संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है;
- (ii) कर-निर्धारिती उपर्युक्त कर-निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से उसकी निधि (जेवर-जवाहिरात, फर्नीचर अथवा किसी अन्य वस्तु आदि के रूप में प्राप्त तथा अनुरक्षित स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा;
- (iii) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों;
- (iv) कर-निर्धारिती आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार अपनी आय विवरणी नियमित रूप से आयकर प्राधिकारी के समक्ष फाइल करेगा;
- (v) विघटन की स्थिति में अतिरिक्त राशियां और परिसम्पत्तियां समान उद्देश्यों वाले धर्मार्थ संगठन को दे दी जाएंगी।

[अधिसूचना सं. 102/2003/फा. सं. 197/22/2003-
आयकर नि.-1]

आई. पी. एस. बिन्द्रा, अवर सचिव

New Delhi, the 6th May, 2003

(INCOME-TAX)

S.O. 2146.—In exercise of powers conferred by the sub-clause (iv) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies the "The Muslim Educational Society, Bank Road, Calicut" for the purpose of the said sub-clause for the assessment years 1999-2000 to 2001-2002 subject to the following conditions, namely :—

- (i) the assessee will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established;

(ii) the assessee will not invest or deposit its fund (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of Section 11;

(iii) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of account are maintained in respect of such business;

(iv) the assessee will regularly file its return of income before the Income-tax authority in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961;

(v) that in the event of dissolution, its surplus and the assets will be given to a charitable organisation with similar objectives.

[Notification No. 102/2003/F. No. 197/22/2003-
ITA-I]

I. P. S. BINDRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 6 मई, 2003

(आयकर)

का.आ. 2147.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा "तिबतन होम्स फाउंडेशन, नई दिल्ली" को वर्ष 2001-2002 से 2003-2004 तक के कर निर्धारण वर्षों के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त उप-खंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

(i) कर-निर्धारिती उसकी आय का इस्तेमाल अथवा उसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए उसका संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है;

(ii) कर-निर्धारिती उपर्युक्त कर-निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से उसकी निधि (जेवर-जवाहिरात, फर्नीचर अथवा किसी अन्य वस्तु आदि के रूप में प्राप्त तथा अनुरक्षित स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा;

(iii) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों;

- (iv) कर-निर्धारिती आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार अपनी आय विवरणी नियमित रूप से आयकर प्राधिकारी के समक्ष फाइल करेगा;
- (v) विघटन की स्थिति में अतिरिक्त राशियां और परिसम्पत्तियां समान उद्देश्यों वाले धर्मार्थ संगठन को दे दी जाएंगी।

[अधिसूचना सं. 103/2003/फा. सं. 197/39/2003-
आयकर नि.-I]

आई. पी. एस. बिन्द्रा, अवर सचिव

New Delhi, the 6th May, 2003

(INCOME-TAX)

S.O. 2147.—In exercise of powers conferred by the sub-clause (iv) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies the "Tibetan Homes Foundation, New Delhi" for the purpose of the said sub-clause for the assessment years 2001-2002 to 2003-2004 subject to the following conditions, namely :—

- (i) the assessee will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established;
- (ii) the assessee will not invest or deposit its fund (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of Section 11;
- (iii) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of account are maintained in respect of such business;
- (iv) the assessee will regularly file its return of income before the Income-tax authority in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961;
- (v) that in the event of dissolution, its surplus and the assets will be given to a charitable organisation with similar objectives.

[Notification No. 103/2003/F. No. 197/39/2003-
ITA-I]

I. P. S. BINDRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 6 मई, 2003

(आयकर)

का.आ. 2148.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23ग) के उप-खंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का

प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा "सेंटर फार एडवांस्ड स्ट्रैटिजिक स्टडीज, पुणे" को वर्ष 2001-2002 से 2003-2004 तक के कर निर्धारण वर्षों के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त उप-खंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

- (i) कर-निर्धारिती उसकी आय का इस्तेमाल अथवा उसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए उसका संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है;
- (ii) कर-निर्धारिती उपर्युक्त कर-निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से उसकी निधि (जेवर-जवाहिरात, फर्नीचर अथवा किसी अन्य वस्तु आदि के रूप में प्राप्त तथा अनुरक्षित स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा;
- (iii) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों;
- (iv) कर-निर्धारिती आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार अपनी आय विवरणी नियमित रूप से आयकर प्राधिकारी के समक्ष फाइल करेगा;
- (v) विघटन की स्थिति में अतिरिक्त राशियां और परिसम्पत्तियां समान उद्देश्यों वाले धर्मार्थ संगठन को दे दी जाएंगी।

[अधिसूचना सं. 104/2003/फा. सं. 197/19/2003-
आयकर नि.-I]

आई. पी. एस. बिन्द्रा, अवर सचिव

New Delhi, the 6th May, 2003

(INCOME-TAX)

S.O. 2148.—In exercise of powers conferred by the sub-clause (iv) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies the "Centre for Advanced Strategic Studies, Pune" for the purpose of the said sub-clause for the assessment years 2001-2002 to 2003-2004 subject to the following conditions, namely :—

- (i) the assessee will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established;
- (ii) the assessee will not invest or deposit its fund (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the

forms or modes specified in sub-section (5) of Section 11;

- (iii) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of accounts are maintained in respect of such business;
- (iv) the assessee will regularly file its return of income before the Income-tax authority in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961;
- (v) that in the event of dissolution, its surplus and the assets will be given to a charitable organisation with similar objectives.

[Notification No. 104/2003/F. No. 197/19/2003-ITA-I]

I. P. S. BINDRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 6 मई, 2003

(आयकर)

का.आ. 2149.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा “नेशनल काउंसिल फॉर एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, नई दिल्ली” को वर्ष 2002-2003 से 2004-2005 तक के कर निर्धारण वर्षों के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त उप-खंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

- (i) कर-निर्धारिती उसकी आय का इस्तेमाल अथवा उसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए उसका संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है;
- (ii) कर-निर्धारिती उपर्युक्त कर-निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से उसकी निधि (जेवर-जवाहिरात, फर्नीचर अथवा किसी अन्य वस्तु आदि के रूप में प्राप्त तथा अनुरक्षित स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा;
- (iii) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों;
- (iv) कर-निर्धारिती आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार अपनी आय विवरणी नियमित रूप से आयकर प्राधिकारी के समक्ष फाइल करेगा;

- (v) विघटन की स्थिति में अतिरिक्त राशियां और परिसम्पत्तियां समान उद्देश्यों वाले धर्मार्थ संगठन को दे दी जाएंगी।

[अधिसूचना सं. 105/2003/फा. सं. 197/36/2003-आयकर नि.-I]

आई. पी. एस. बिन्द्रा, अवर सचिव

New Delhi, the 6th May, 2003

(INCOME-TAX)

S.O. 2149.—In exercise of powers conferred by the sub-clause (iv) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies the “National Council for Applied Economic Research, New Delhi” for the purpose of the said sub-clause for the assessment years 2002-2003 to 2004-2005 subject to the following conditions, namely :—

- (i) the assessee will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established;
- (ii) the assessee will not invest or deposit its fund (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of Section 11;
- (iii) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of accounts are maintained in respect of such business;
- (iv) the assessee will regularly file its return of income before the Income-tax authority in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961;
- (v) that in the event of dissolution, its surplus and the assets will be given to a charitable organisation with similar objectives.

[Notification No. 105/2003/F. No. 197/36/2003-ITA-I]

I. P. S. BINDRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 6 मई, 2003

(आयकर)

का.आ. 2150.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा “कृष्ण चन्द्र मेमोरियल ट्रस्ट, गनजाम, उड़ीसा” को वर्ष 2001-2002 से 2003-2004 तक

के कर निर्धारण वर्षों के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त उप-खंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

- (i) कर-निर्धारिती उसकी आय का इस्तेमाल अथवा उसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए उसका संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है;
- (ii) कर-निर्धारिती उपर्युक्त कर-निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से उसकी निधि (जेवर-जवाहिरात, फर्नीचर अथवा किसी अन्य वस्तु आदि के रूप में प्राप्त तथा अनुरक्षित स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा;
- (iii) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों;
- (iv) कर-निर्धारिती आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार अपनी आय विवरणी नियमित रूप से आयकर प्राधिकारी के समक्ष फाइल करेगा;
- (v) विघटन की स्थिति में अतिरिक्त राशियां और परिसम्पत्तियां समान उद्देश्यों वाले धर्मार्थ संगठन को दे दी जाएंगी।

[अधिसूचना सं. 106/2003/फा. सं. 197/49/2003—

आयकर नि.-1]

आई. पी. एस. बिन्द्रा, अवर सचिव

New Delhi, the 6th May, 2003

(INCOME TAX)

S.O. 2150.—In exercise of powers conferred by the sub-clause (iv) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies the “Krishna Chandra Memorial Trust, Ganjam, Orissa” for the purpose of the said sub-clause for the assessment years 2001-2002 to 2003-2004 subject to the following conditions, namely :—

- (i) the assessee will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established;
- (ii) the assessee will not invest or deposit its fund (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of Section 11;

- (iii) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of accounts are maintained in respect of such business;
- (iv) the assessee will regularly file its return of income before the Income-tax authority in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961;
- (v) that in the event of dissolution, its surplus and the assets will be given to a charitable organisation with similar objectives.

[Notification No. 106/2003/F. No. 197/49/2003-ITA-I]

I. P. S. BINDRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 6 मई, 2003

(आयकर)

का. आ. 2151.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा “पीपल्स एक्शन फॉर डेवलपमेंट (महाराष्ट्र), मुम्बई” को वर्ष 1996-1997 तक के कर निर्धारण वर्षों के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त उप-खंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

- (i) कर-निर्धारिती उसकी आय का इस्तेमाल अथवा उसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए उसका संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है;
- (ii) कर-निर्धारिती उपर्युक्त कर-निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से उसकी निधि (जेवर-जवाहिरात, फर्नीचर अथवा किसी अन्य वस्तु आदि के रूप में प्राप्त तथा अनुरक्षित स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा;
- (iii) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों;
- (iv) कर-निर्धारिती आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार अपनी आय विवरणी नियमित रूप से आयकर प्राधिकारी के समक्ष फाइल करेगा;
- (v) विघटन की स्थिति में अतिरिक्त राशियां और परिसम्पत्तियां समान उद्देश्यों वाले धर्मार्थ संगठन को दे दी जाएंगी।

[अधिसूचना सं. 107/2003/फा. सं. 197/37/2003—

आयकर नि.-1]

आई. पी. एस. बिन्द्रा, अवर सचिव

New Delhi, the 6th May, 2003

(INCOME TAX)

S.O. 2151.—In exercise of powers conferred by the sub-clause (iv) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies the "People's Action for Development (Maharashtra), Mumbai" for the purpose of the said Sub-clause for the assessment year 1996-1997 subject to the following conditions, namely :—

- (i) the assessee will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established;
- (ii) the assessee will not invest or deposit its fund (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in Sub-section (5) of Section 11;
- (iii) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of accounts are maintained in respect of such business;
- (iv) the assessee will regularly file its return of income before the Income-tax authority in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961;
- (v) that in the event of dissolution, its surplus and the assets will be given to a charitable organisation with similar objectives.

[Notification No. 107/2003/F. No. 197/37/2003-ITA-I]

I.-P. S. BINDRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 6 मई, 2003

(आयकर)

का. आ. 2152.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा "दि नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड कर्नाटक ब्रांच, बंगलौर" को वर्ष 2001-2002 से 2003-2004 तक के कर निर्धारण वर्षों के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त उप-खंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

- (i) कर-निर्धारिती उसकी आय का इस्तेमाल अथवा उसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए उसका संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है;

(ii) कर-निर्धारिती उपर्युक्त कर-निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से उसकी निधि (जेवर-जवाहिरात, फर्नीचर अथवा किसी अन्य वस्तु आदि के रूप में प्राप्त तथा अनुरक्षित स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा;

(iii) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों;

(iv) कर-निर्धारिती आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार अपनी आय विवरणी नियमित रूप से आयकर प्राधिकारी के समक्ष फाइल करेगा;

(v) विघटन की स्थिति में अतिरिक्त राशियां परिसम्पत्तियां समान उद्देश्यों वाले धर्मार्थ संगठन को दे दी जाएंगी।

[अधिसूचना सं. 108/2003/फा. सं. 197/51/2003-आयकर नि.-1]

आई. पी. एस. बिन्द्रा, अवर सचिव

New Delhi, the 6th May, 2003

(INCOME TAX)

S.O. 2152.—In exercise of powers conferred by the sub-clause (iv) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies the "The National Association for the Blind, Karnataka Branch, Bangalore" for the purpose of the said sub-clause for the assessment years 2001-2002 to 2003-2004 subject to the following conditions, namely :—

(i) the assessee will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established;

(ii) the assessee will not invest or deposit its fund (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in Sub-section (5) of Section 11;

(iii) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of accounts are maintained in respect of such business;

- (iv) the assessee will regularly file its return of income before the Income-tax authority in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961;
- (v) that in the event of dissolution, its surplus and the assets will be given to a charitable organisation with similar objectives.

[Notification No. 108/2003/F. No. 197/51/2003-ITA-I]

I. P. S. BINDRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 6 मई, 2003

(आयकर)

का.आ. 2153.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा “विवेकानन्द निधि, कोलकाता” को वर्ष 1998-1999 से 2000-2001 तक के कर निर्धारण वर्षों के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त उप-खंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

- (i) कर-निर्धारिती उसकी आय का इस्तेमाल अथवा उसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए उसका संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है;
- (ii) कर-निर्धारिती उपर्युक्त कर-निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से उसकी निधि (जेवर-जवाहिरात, फर्नीचर अथवा किसी अन्य वस्तु आदि के रूप में प्राप्त तथा अनुरक्षित स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा;
- (iii) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों;
- (iv) कर-निर्धारिती आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार अपनी आय विवरणी नियमित रूप से आयकर प्राधिकारी के समक्ष फाइल करेगा;
- (v) विघटन की स्थिति में अतिरिक्त राशियां और परिसम्पत्तियां समान उद्देश्यों वाले धर्मार्थ संगठन को दे दी जाएंगी।

[अधिसूचना सं. 109/2003/फा. सं. 197/4/2002-आयकर नि.-1]

आई. पी. एस. बिन्द्रा, अवर सचिव

New Delhi, the 6th May, 2003

(INCOME TAX)

S.O. 2153.—In exercise of powers conferred by the Sub-clause (iv) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies the “Vivekananda Nidhi, Kolkata” for the purpose of the said Sub-clause for the assessment years 1998-1999 to 2000-2001 subject to the following conditions, namely :—

- (i) the assessee will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established;
- (ii) the assessee will not invest or deposit its fund (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in Sub-section (5) of Section 11;
- (iii) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of accounts are maintained in respect of such business;
- (iv) the assessee will regularly file its return of income before the Income-tax authority in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961;
- (v) that in the event of dissolution, its surplus and the assets will be given to a charitable organisation with similar objectives.

[Notification No. 109/2003/F. No. 197/4/2002-ITA-I]

I. P. S. BINDRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 6 मई, 2003

(आयकर)

का. आ. 2154.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा “वाईल्डलाइफ एसोसिएशन ऑफ साऊथ इंडिया, विक्टोरिया रोड, बंगलौर” को वर्ष 1998-1999 से 2000-2001 तक के कर निर्धारण वर्षों के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त उप-खंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

- (i) कर-निर्धारिती उसकी आय का इस्तेमाल अथवा उसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए उसका संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है;

- (ii) कर-निर्धारिती उपर्युक्त कर-निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से उसकी निधि (जेवर-जवाहिरात, फर्नीचर अथवा किसी अन्य वस्तु आदि के रूप में प्राप्त तथा अनुरक्षित स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा;
- (iii) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों;
- (iv) कर-निर्धारिती आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार अपनी आय विवरणी नियमित रूप से आयकर प्राधिकारी के समक्ष फाइल करेगा;
- (v) विघटन की स्थिति में अतिरिक्त राशियां और परिसम्पत्तियां समान उद्देश्यों वाले धर्मार्थ संगठन को दे दी जाएंगी।

[अधिसूचना सं. 110/2003/फा. सं. 197/20/2003-
आयकर नि.-1]

आई. पी. एस. बिन्द्रा, अवर सचिव

New Delhi, the 6th May, 2003

(INCOME-TAX)

S.O. 2154.—In exercise of powers conferred by the sub-clause (iv) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies the "Wildlife Association of South India, Victoria Road, Bangalore" for the purpose of the said sub-clause for the assessment years 1998-1999 to 2000-2001 subject to the following conditions, namely :—

- (i) the assessee will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established;
- (ii) the assessee will not invest or deposit its fund (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of Section 11;
- (iii) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of accounts are maintained in respect of such business;

(iv) the assessee will regularly file its return of income before the Income-tax authority in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961;

(v) that in the event of dissolution, its surplus and the assets will be given to a charitable organisation with similar objectives.

[Notification No. 110/2003/F. No. 197/20/2003-ITA-I]

I. P. S. BINDRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 6 मई, 2003

(आयकर)

का.आ. 2155.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा "पीपल्स एक्शन फॉर डवलपमेंट (महाराष्ट्र), मुम्बई" को वर्ष 2000-2001 से 2002-2003 तक के कर निर्धारण वर्षों के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त उप-खंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

- (i) कर-निर्धारिती उसकी आय का इस्तेमाल अथवा उसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए उसका संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है;
- (ii) कर-निर्धारिती उपर्युक्त कर-निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से उसकी निधि (जेवर-जवाहिरात, फर्नीचर अथवा किसी अन्य वस्तु आदि के रूप में प्राप्त तथा अनुरक्षित स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा;
- (iii) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों;
- (iv) कर-निर्धारिती आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार अपनी आय विवरणी नियमित रूप से आयकर प्राधिकारी के समक्ष फाइल करेगा;
- (v) विघटन की स्थिति में अतिरिक्त राशियां और परिसम्पत्तियां समान उद्देश्यों वाले धर्मार्थ संगठन को दे दी जाएंगी।

[अधिसूचना सं. 111/2003/फा. सं. 197/38/2003-
आयकर नि.-1]

आई. पी. एस. बिन्द्रा, अवर सचिव

New Delhi, the 6th May, 2003

(INCOME TAX)

S.O. 2155.—In exercise of powers conferred by the sub-clause (iv) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies the "People's Action for Development (Maharashtra), Mumbai" for the purpose of the said sub-clause for the assessment years 2000-2001 to 2002-2003 subject to the following conditions, namely :—

- (i) the assessee will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established;
- (ii) the assessee will not invest or deposit its fund (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of Section 11;
- (iii) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of accounts are maintained in respect of such business;
- (iv) the assessee will regularly file its return of income before the Income-tax authority in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961;
- (v) that in the event of dissolution, its surplus and the assets will be given to a charitable organisation with similar objectives.

[Notification No. 111/2003/F. No. 197/38/2003-ITA-I]

I. P. S. BINDRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 6 मई, 2003

(आयकर)

का.आ. 2156.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा "डिवाइन लाइट ट्रस्ट फॉर द ब्लाइंड, बंगलौर" को वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 तक के कर-निर्धारण वर्षों के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त उप-खंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

- (i) कर-निर्धारिती उसकी आय का इस्तेमाल अथवा उसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए उसका संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है;

- (ii) कर-निर्धारिती उपर्युक्त कर-निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से उसकी निधि (जेवर-जवाहिरात, फर्नीचर अथवा किसी अन्य वस्तु आदि के रूप में प्राप्त तथा अनुरक्षित स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा;
- (iii) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों;
- (iv) कर-निर्धारिती आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार अपनी आय विवरणी नियमित रूप से आयकर प्राधिकारी के समक्ष फाइल करेगा;
- (v) विघटन की स्थिति में अतिरिक्त राशियां और परिसम्पत्तियां समान उद्देश्यों वाले धर्मार्थ संगठन को दे दी जाएंगी।

[अधिसूचना सं. 112/2003/फा. सं. 197/57/2003-आयकर नि.-1]

आई. पी. एस. बिन्द्रा, अवर सचिव

New Delhi, the 6th May, 2003

(INCOME TAX)

S.O. 2156.—In exercise of powers conferred by the sub-clause (iv) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies the "Divine Light Trust for the Blind, Bangalore" for the purpose of the said sub-clause for the assessment years 1999-2000 to 2001-2002 subject to the following conditions, namely :—

- (i) the assessee will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established;
- (ii) the assessee will not invest or deposit its fund (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of Section 11;
- (iii) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of accounts are maintained in respect of such business;
- (iv) the assessee will regularly file its return of income before the Income-tax authority in

accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961;

- (v) that in the event of dissolution, its surplus and the assets will be given to a charitable organisation with similar objectives.

[Notification No. 112/2003/F. No. 197/57/2003-ITA-I]

I. P. S. BINDRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 21 मई, 2003

(आयकर)

का. आ. 2157.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 'पंजाब स्त्री सभा रिलीफ ट्रस्ट, अमृतसर' को वर्ष 1997-1998 से 1999-2000 तक के कर-निर्धारण वर्षों के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त उप-खंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

- (i) कर-निर्धारिती उसकी आय का इस्तेमाल अथवा उसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए उसका संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है;
- (ii) कर-निर्धारिती उपर्युक्त कर-निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से उसकी निधि (जेवर-जवाहिरात, फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा अनुरक्षित स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा;
- (iii) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों;
- (iv) कर-निर्धारिती आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार अपनी आय विवरणी नियमित रूप से आयकर प्राधिकारी के समक्ष फाइल करेगा;
- (v) विघटन की स्थिति में अतिरिक्त राशियां और परिसम्पत्तियां समान उद्देश्यों वाले धर्मार्थ संगठन को दे दी जाएंगी।

[अधिसूचना सं. 132/2003/फा. सं. 197/45/2003-आयकर वि.-I]

आई. पी. एस. बिन्द्रा, अवर सचिव

New Delhi, the 21st May, 2003

(INCOME-TAX)

S.O. 2157.—In exercise of powers conferred by the sub-clause (iv) of clause (23C) of Section 10 of the

Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies the "Punjab Istri Sabha Relief Trust, Amritsar" for the purpose of the said sub-clause for the assessment years 1997-1998 to 1999-2000 subject to the following conditions, namely :—

- (i) the assessee will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established;
- (ii) the assessee will not invest or deposit its fund (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of Section 11;
- (iii) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of accounts are maintained in respect of such business;
- (iv) the assessee will regularly file its return of income before the Income-tax authority in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961;
- (v) that in the event of dissolution, its surplus and the assets will be given to a charitable organisation with similar objectives.

[Notification No. 132/2003/F. No. 197/45/2003-ITA-I]

I. P. S. BINDRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 21 मई, 2003

(आयकर)

का.आ. 2158.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 'दि दिल्ली सोसायटी फार दि वेलफयर आफ मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रेन, नई दिल्ली' को वर्ष 2000-2001 से 2002-2003 तक के कर-निर्धारण वर्षों के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त उप-खंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

- (i) कर-निर्धारिती उसकी आय का इस्तेमाल अथवा उसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए उसका संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है;
- (ii) कर-निर्धारिती उपर्युक्त कर-निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से उसकी निधि (जेवर-

जवाहिरात, फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा अनुरक्षित स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा;

- (iii) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों;
- (iv) कर-निर्धारिती आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार अपनी आय विवरणी नियमित रूप से आयकर प्राधिकारी के समक्ष फाइल करेगा;
- (v) विघटन की स्थिति में अतिरिक्त राशियां और परिसम्पत्तियां समान उद्देश्यों वाले धर्मार्थ संगठन को दे दी जाएंगी।

[अधिसूचना सं. 133/2003/फा. सं. 197/53/2003-

आयकर नि.-I]

आई. पी. एस. बिन्द्रा, अवर सचिव

New Delhi, the 21st May, 2003

(INCOME-TAX)

S.O. 2158.—In exercise of powers conferred by the sub-clause (iv) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies the “The Delhi Society for the Welfare of Mentally Retarded Children, New Delhi” for the purpose of the said sub-clause for the assessment years 2000-2001 to 2002-2003 subject to the following conditions, namely :—

- (i) the assessee will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established;
- (ii) the assessee will not invest or deposit its fund (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of Section 11;
- (iii) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of accounts are maintained in respect of such business;
- (iv) the assessee will regularly file its return of income before the Income-tax authority in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961;

- (v) that in the event of dissolution, its surplus and the assets will be given to a charitable organisation with similar objectives.

[Notification No. 133/2003/F. No. 197/53/2003-ITA-I]

I. P. S. BINDRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 21 मई, 2003

(आयकर)

का. आ. 2159.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा “ श्री बमलेश्वरी मंदिर ट्रस्ट समिति, डोंगरगढ़ (मध्य प्रदेश) ” को वर्ष 2000-2001 से 2002-2003 तक के कर-निर्धारण वर्षों के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त उप-खंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

- (i) कर-निर्धारिती उसकी आय का इस्तेमाल अथवा उसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए उसका संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है;
- (ii) कर-निर्धारिती उपयुक्त कर-निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से उसकी निधि (जेवर-जवाहिरात, फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा अनुरक्षित स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा;
- (iii) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों;
- (iv) कर-निर्धारिती आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार अपनी आय विवरणी नियमित रूप से आयकर प्राधिकारी के समक्ष फाइल करेगा;
- (v) विघटन की स्थिति में अतिरिक्त राशियां और परिसम्पत्तियां समान उद्देश्यों वाले धर्मार्थ संगठन को दे दी जाएंगी।

[अधिसूचना सं. 134/2003/फा. सं. 197/47/2003-

आयकर नि.-I]

आई. पी. एस. बिन्द्रा, अवर सचिव

New Delhi, the 21st May, 2003

(INCOME-TAX)

S.O. 2159.—In exercise of powers conferred by the sub-clause (iv) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central

Government hereby notifies the "Shri Bamleshwari Mandir Trust Samity, Dongargarh (M.P.)" for the purpose of the said sub-clause for the assessment years 2000-2001 to 2002-2003 subject to the following conditions, namely :—

- (i) the assessee will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established;
- (ii) the assessee will not invest or deposit its fund (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of Section 11;
- (iii) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of accounts are maintained in respect of such business;
- (iv) the assessee will regularly file its return of income before the Income-tax authority in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961;
- (v) that in the event of dissolution, its surplus and the assets will be given to a charitable organisation with similar objectives.

[Notification No. 134/2003/F. No. 197/47/2003-ITA-I]

I. P. S. BINDRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 30 मई, 2003

(आयकर)

का.आ. 2160.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा "श्री रामकृष्ण आश्रम 24 परगना (दक्षिण) पश्चिम बंगाल" को वर्ष 2001-2002 से 2003-2004 तक के कर निर्धारण वर्षों के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त उप-खंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

- (i) कर-निर्धारिती उसकी आय का इस्तेमाल अथवा उसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए उसका संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है;
- (ii) कर-निर्धारिती उपर्युक्त कर-निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से उसकी निधि (जेवर-

जवाहिरात, फर्नीचर अथवा किसी अन्य वस्तु आदि के रूप में प्राप्त तथा अनुरक्षित स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा;

- (iii) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों;
- (iv) कर-निर्धारिती आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार अपनी आय विवरणी नियमित रूप से आयकर प्राधिकारी के समक्ष फाइल करेगा;
- (v) विघटन की स्थिति में अतिरिक्त राशियां और परिसम्पत्तियां समान उद्देश्यों वाले धर्मार्थ संगठन को दे दी जाएंगी।

[अधिसूचना सं. 139/2003/फा. सं. 197/68/2003-आयकर नि.-1]

आई. पी. एस. बिन्द्रा, अवर सचिव

New Delhi, the 30th May, 2003

(INCOME TAX)

S.O. 2160.—In exercise of powers conferred by the sub-clause (iv) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies the "Sri Ramkrishna Ashram, 24 Parganas (South), West Bengal" for the purpose of the said sub-clause for the assessment years 2001-2002 to 2003-2004 subject to the following conditions, namely :—

- (i) the assessee will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established;
- (ii) the assessee will not invest or deposit its fund (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of Section 11;
- (iii) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of accounts are maintained in respect of such business;
- (iv) the assessee will regularly file its return of income before the Income-tax authority in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961;

- (v) that in the event of dissolution, its surplus and the assets will be given to a charitable organisation with similar objectives.

[Notification No. 139/2003/F. No. 197/68/2003-ITA-I]

I. P. S. BINDRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 6 जून, 2003

(आयकर)

का.आ. 2161.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा “रामकृष्ण शारदा मिशन, दक्षिणेश्वर, कोलकाता” को वर्ष 2002-2003 से 2004-2005 तक के कर निर्धारण वर्षों के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त उप-खंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

- (i) कर-निर्धारिती उसकी आय का इस्तेमाल अथवा उसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए उसका संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है;
- (ii) कर-निर्धारिती उपर्युक्त कर-निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से उसकी निधि (जैवर-जवाहिरात, फर्नीचर अथवा किसी अन्य वस्तु आदि के रूप में प्राप्त तथा अनुरक्षित स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा;
- (iii) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों;
- (iv) कर-निर्धारिती आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार अपनी आय विवरणी नियमित रूप से आयकर प्राधिकारी के समक्ष फाइल करेगा;
- (v) विघटन की स्थिति में अतिरिक्त राशियां और परिसम्पत्तियां समान उद्देश्यों वाले धर्मार्थ संगठन को दे दी जाएंगी।

[अधिसूचना सं. 142/2003/फा. सं. 197/67/2003-आयकर नि.-1]

आई. पी. एस. बिन्द्रा, अवर सचिव

New Delhi, the 6th June, 2003

(INCOME TAX)

S.O. 2161.—In exercise of powers conferred by the sub-clause (iv) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central

Government hereby notifies the “Ramakrishna Sarada Mission, Dakshineswar, Kolkata” for the purpose of the said sub-clause for the assessment years 2002-2003 to 2004-2005 subject to the following conditions, namely :—

- (i) the assessee will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established;
- (ii) the assessee will not invest or deposit its fund (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of Section 11;
- (iii) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of accounts are maintained in respect of such business;
- (iv) the assessee will regularly file its return of income before the Income-tax authority in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961;
- (v) that in the event of dissolution, its surplus and the assets will be given to a charitable organisation with similar objectives.

[Notification No. 142/2003/F. No. 197/67/2003-ITA-I]

I. P. S. BINDRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 3 जुलाई, 2003

(आयकर)

का.आ. 2162.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा “अधिपेराशक्ति चेरिटेबल, मेडिकल, एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट, मेलमारुवाथुर, तमिलनाडु” को वर्ष 2003-2004 से 2005-2006 तक के कर निर्धारण वर्षों के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त उप-खंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

- (i) कर-निर्धारिती उसकी आय का इस्तेमाल अथवा उसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए उसका संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है;
- (ii) कर-निर्धारिती उपर्युक्त कर-निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग

अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से उसकी निधि (जेवर-जवाहिरात, फर्नीचर अथवा किसी अन्य वस्तु आदि के रूप में प्राप्त तथा अनुरक्षित स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा;

- (iii) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों;
- (iv) कर-निर्धारिती आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार अपनी आय विवरणी नियमित रूप से आयकर प्राधिकारी के समक्ष फाइल करेगा;
- (v) विघटन की स्थिति में अतिरिक्त राशियां और परिसम्पत्तियां समान उद्देश्यों वाले धर्मार्थ संगठन को दे दी जाएंगी।

[अधिसूचना सं. 161/2003/फा. सं. 197/78/2003-
आयकर नि.-I]

आई. पी. एस. बिन्द्रा, अवर सचिव

New Delhi, the 3rd July, 2003

(INCOME-TAX)

S.O. 2162.—In exercise of powers conferred by the sub-clause (iv) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies the "Adhiparasakthi Charitable, Medical, Educational and Cultural Trust, Melmaruvathur, Tamil Nadu" for the purpose of the said sub-clause for the assessment years 2003-2004 to 2005-2006 subject to the following conditions, namely :—

- (i) the assessee will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established;
- (ii) the assessee will not invest or deposit its fund (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of Section 11;
- (iii) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of accounts are maintained in respect of such business;
- (iv) the assessee will regularly file its return of income before the Income-tax authority in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961;

- (v) that in the event of dissolution, its surplus and the assets will be given to a charitable organisation with similar objectives.

[Notification No. 161/2003/F. No. 197/78/2003-
ITA-I]

I. P. S. BINDRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 3 जुलाई, 2003

(आयकर)

का.आ. 2163.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 'ग्रोसरी मार्केट्स एण्ड शॉप्स बोर्ड, मुम्बई' को वर्ष 1990-1991 से 1992-1993 तक के कर निर्धारण वर्षों के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त उप-खंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

- (i) कर-निर्धारिती उसकी आय का इस्तेमाल अथवा उसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए उसका संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है;
- (ii) कर-निर्धारिती उपर्युक्त कर-निर्धारण वर्षों से संगत पूर्वतर्फी वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से उसकी निधि (जेवर-जवाहिरात, फर्नीचर अथवा किसी अन्य वस्तु आदि के रूप में प्राप्त तथा अनुरक्षित स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा;
- (iii) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों;
- (iv) कर-निर्धारिती आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार अपनी आय विवरणी नियमित रूप से आयकर प्राधिकारी के समक्ष फाइल करेगा;
- (v) विघटन की स्थिति में अतिरिक्त राशियां और परिसम्पत्तियां समान उद्देश्यों वाले धर्मार्थ संगठन को दे दी जाएंगी।

[अधिसूचना सं. 163/2003/फा. सं. 197/77/2003-
आयकर नि.-I]

आई. पी. एस. बिन्द्रा, अवर सचिव

New Delhi, the 3rd July, 2003

(INCOME-TAX)

S.O. 2163.—In exercise of powers conferred by the sub-clause (iv) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies the "Grocery Markets and Shops Board, Mumbai" for the purpose of the said sub-

clause for the assessment years 1990-1991 to 1992-1993 subject to the following conditions, namely :—

- (i) the assessee will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established;
- (ii) the assessee will not invest or deposit its fund (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of Section 11;
- (iii) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of accounts are maintained in respect of such business;
- (iv) the assessee will regularly file its return of income before the Income-tax authority in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961;
- (v) that in the event of dissolution, its surplus and the assets will be given to a charitable organisation with similar objectives.

[Notification No. 163/2003/F. No. 197/77A/2003-ITA-I]

I. P. S. BINDRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 8 जुलाई, 2003

का.आ. 2164.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि केन्द्र सरकार आयकर नियमावली, 1962 के नियम 2ड के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23-छ) के प्रयोजनार्थ कर निर्धारण वर्ष 2002-2003, 2003-2004 और 2004-2005 के लिए नीचे पैरा (3) में उल्लिखित उद्यम को अनुमोदित करती है।

2. यह अनुमोदन इस शर्त के अधीन है कि :—

- (i) उद्यम/औद्योगिक उपक्रम आयकर नियमावली, 1962 के नियम 2ड के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23छ) के उपबंधों के अनुरूप होगा और उनका अनुपालन करेगा,
- (ii) केन्द्र सरकार यह अनुमोदन वापिस ले लेगी यदि उद्यम/औद्योगिक उपक्रम :—

- (क) अवसंरचनात्मक सुविधा को जारी रखना बंद कर देता है, और

(ख) खाता बहियों का रख-रखाव नहीं करता है तथा आयकर नियमावली, 1962 के नियम 2ड के उपनियम (7) द्वारा यथा अपेक्षित किसी लेखाकार द्वारा ऐसे खातों की लेखापरीक्षा नहीं कराता है, अथवा

(ग) आयकर नियमावली, 1962 के नियम 2ड के उपनियम (7) द्वारा यथा अपेक्षित लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है।

3. अनुमोदित उद्यम/औद्योगिक उपक्रम है :

मैसर्स इस्ट कोस्ट कंसल्टेंट्स एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि०, संख्या 4, मूस रोड, चैनई-600006 निर्माण-रख-रखाव हस्तांतरण (बी ओ टी) आधार पर अमरावती नदी पर एक पुल के निर्माण हेतु उनकी परियोजना के लिए। (फा. सं. 205/121/99-आयकर नि०-II)

[अधिसूचना सं. 168/2003/फा. सं. 205/121/99-आयकर नि. -II]

ए. के. पाण्डेय, उप सचिव (आयकर नि.-II)

New Delhi, the 8th July, 2003

S.O. 2164.—It is notified for general information that enterprise/industrial undertaking, listed at para (3) below has been approved by the Central Government for the purpose of Section 10(23G) of the Income-tax Act, 1961, read with rule 2E of the Income-tax Rules, 1962, for the assessment years 2002-2003, 2003-2004 and 2004-2005.

2. The approval is subject to the condition that—

- (i) the enterprise/industrial undertaking will conform to and comply with the provisions of Section 10(23G) of the Income-tax Act, 1961, read with rule 2E of the Income-tax Rules, 1962;
- (ii) the Central Government shall withdraw this approval if the enterprise/industrial undertaking :—
 - (a) ceases to carry on infrastructure facility; or
 - (b) fails to maintain books of account and get such accounts audited by an accountant as required by sub-rule (7) of rule 2E of the Income-tax Rules, 1962; or
 - (c) fails to furnish the audit report as required by sub-rule (7) of rule 2E of the Income-tax Rules, 1962.

3. The enterprise/industrial undertaking approved is—

M/s East Coast Consultants and Infrastructure Limited, No. 4, Moors Road, Chennai-60006 for their project to construct a bridge over river Anravathi on Build-Operate-Transfer (BOT) basis.

[Notification No. 168/2003/F. No. 205/121/99-ITA-II]
A. K. PANDEY, Dy. Secy. (ITA-II)

नई दिल्ली, 8 जुलाई, 2003

का.आ. 2165.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि केन्द्र सरकार आयकर नियमावली, 1962 के नियम 2ड के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23-छ) के प्रयोजनार्थ कर निर्धारण वर्ष 2002-2003, 2003-2004 और 2004-2005 के लिए नीचे पैरा (3) में उल्लिखित उद्यम को अनुमोदित करती है।

2. यह अनुमोदन इस शर्त के अधीन है कि :—

(i) उद्यम/औद्योगिक उपक्रम आयकर नियमावली, 1962 के नियम 2ड के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23छ) के उपबंधों के अनुरूप होगा और उनका अनुपालन करेगा,

(ii) केन्द्र सरकार यह अनुमोदन वापिस ले लेगी यदि उद्यम/औद्योगिक उपक्रम :—

(क) अवसंरचनात्मक सुविधा को जारी रखना बंद कर देता है, और

(ख) खाता बहियों का रख-रखाव नहीं करता है तथा आयकर नियमावली, 1962 के नियम 2ड के उपनियम (7) द्वारा यथा अपेक्षित किसी लेखाकार द्वारा ऐसे खातों की लेखा परीक्षा नहीं कराता है, अथवा

(ग) आयकर नियमावली, 1962 के नियम 2ड के उपनियम (7) द्वारा यथा अपेक्षित लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है।

3. अनुमोदित उद्यम/औद्योगिक उपक्रम है :

मेसर्स बड़ोदरा हलोल टॉल रोड कम्पनी लि०, सचिव, सड़क एवं भवन विभाग, गुजरात सरकार, ब्लॉक सं. 14, दूसरी मंजिल, सचिवालय, गांधी नगर-380010 को बड़ोदरा और हलोल के औद्योगिक शहर के मध्य राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 87 को चौड़ा और सुदृढ़ करने की उनकी परियोजना के लिए।

[अधिसूचना सं. 169/2003/फा. सं. 205/59/98-आयकर नि.-II,
खंड-I]

ए. के. पाण्डेय, उप सचिव (आयकर नि.-II)

New Delhi, the 8th July, 2003

S.O. 2165.—It is notified for general information that enterprise/industrial undertaking, listed at para (3) below has been approved by the Central Government for the purpose of Section 10(23G) of the Income-tax Act, 1961, read with rule 2E of the Income-tax Rules, 1962, for the assessment years 2002-2003, 2003-2004 and 2004-2005.

2. The approval is subject to the condition that—

(i) the enterprise/industrial undertaking will conform to and comply with the provisions of Section 10(23G) of the Income-tax Act, 1961, read with rule 2E of the Income-tax Rules, 1962;

(ii) the Central Government shall withdraw this approval if the enterprise/industrial undertaking :—

(a) ceases to carry on infrastructure facility; or

(b) fails to maintain books of account and get such accounts audited by an accountant as required by sub-rule (7) of rule 2E of the Income-tax Rules, 1962; or

(c) fails to furnish the audit report as required by sub-rule (7) of rule 2E of the Income-tax Rules, 1962.

3. The enterprise/industrial undertaking approved is—

M/s Vadodara Halol Toll Road Company Limited, Secretary, Roads and Building Department, Government of Gujarat, Block No. 14, Second Floor, Sachivalaya, Gandhi Nagar-380010 for their project of widening and strengthening of National Highway No. 87 between Vadodara and Industrial Town of Halol.

[Notification No. 169/2003/F. No. 205/59/98-ITA-II,
Vol. I]

A. K. PANDEY, Dy. Secy. (ITA-II)

नई दिल्ली, 8 जुलाई, 2003

का.आ. 2166.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि केन्द्र सरकार आयकर नियमावली, 1962 के नियम 2ड के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23-छ) के प्रयोजनार्थ कर निर्धारण वर्ष 2003-2004 और 2004-2005 के लिए नीचे पैरा (3) में उल्लिखित उद्यम को अनुमोदित करती है।

2. यह अनुमोदन इस शर्त के अधीन है कि :—

(i) उद्यम/औद्योगिक उपक्रम आयकर नियमावली, 1962 के नियम 2ड के साथ पठित आयकर अधिनियम,

1961 की धारा 10(23छ) के उपबंधों के अनुरूप होगा और उनका अनुपालन करेगा,

(ii) केन्द्र सरकार यह अनुमोदन वापिस ले लेगी यदि उद्यम/औद्योगिक उपक्रम :—

(क) अवसंरचनात्मक सुविधा को जारी रखना बंद कर देता है, और

(ख) खाता बहियों का रख-रखाव नहीं करता है तथा आयकर नियमावली, 1962 के नियम 2ड के उपनियम (7) द्वारा यथा अपेक्षित किसी लेखाकार द्वारा ऐसे खातों की लेखा परीक्षा नहीं कराता है, अथवा

(ग) आयकर नियमावली, 1962 के नियम 2ड के उपनियम (7) द्वारा यथा अपेक्षित लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है।

3. अनुमोदित उद्यम/औद्योगिक उपक्रम है :—

मैसर्स अहमदाबाद महसाना टॉल रोड कम्पनी लि०, गांधी नगर, जिनका पंजीकृत कार्यालय सचिब, सड़क एवं भवन विभाग, गुजरात सरकार, ब्लॉक सं. 14, दूसरी मंजिल, सचिवालय, गांधी नगर- 380010 का अहमदाबाद और महसाना शहरों के मध्य बी ओ ओ टी आधार पर राज्य राजमार्ग सं. 41 को चौड़ा और सुदृढ़ करने की उनकी परियोजना के लिए।

[अधिसूचना सं. 167/2003/फा. सं. 205/8/2000-आयकर नि.-II, खंड-1]

ए. के. पाण्डेय, उप सचिब (आयकर नि.-II)

New Delhi, the 8th July, 2003

S.O. 2166.—It is notified for general information that enterprise/industrial undertaking, listed at para (3) below has been approved by the Central Government for the purpose of Section 10(23G) of the Income-tax Act, 1961, read with rule 2E of the Income-tax Rules, 1962, for the assessment years 2003-2004 and 2004-2005.

2. The approval is subject to the condition that—

(i) the enterprise/industrial undertaking will conform to and comply with the provisions of Section 10(23G) of the Income-tax Act, 1961, read with rule 2E of the Income-tax Rules, 1962;

(ii) the Central Government shall withdraw this approval if the enterprise/industrial undertaking :—

(a) ceases to carry on infrastructure facility; or

(b) fails to maintain books of account and get such accounts audited by an accountant

as required by sub-rule (7) of rule 2E of the Income-tax Rules, 1962; or

(c) fails to furnish the audit report as required by sub-rule (7) of rule 2E of the Income-tax Rules, 1962.

3. The enterprise/industrial undertaking approved is—

M/s. Ahmedabad Mehsana Toll Road Company Limited, Gandhinagar, having its registered office at Secretary, Roads and Building Department, Government of Gujarat, Block No. 14, Second Floor, Sachivalaya, Gandhi Nagar-380010 for their project to widening and strengthening of State Highway No. 41 between the cities of Ahmedabad and Mehsana on BOOT basis.

[Notification No. 167/2003/F. No. 205/8/2000-ITA-II, Vol. I]

A. K. PANDEY, Dy. Secy. (ITA-II)

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 2003

का. आ. 2167.— भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 (1964 का 18) की धारा 6 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री एन. एस. सिसोदिया, आई. ए. एस. (राज : 68), जो वर्तमान में वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली में सचिब (वित्तीय क्षेत्र) हैं, को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश होने तक सुश्री विनीता राय के स्थान पर भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के निदेशक मंडल में निदेशक के पद पर नियुक्त करती है।

[फा. सं. 24(4)/2002-आई. एफ-1]

बी. डी. बेरवाल, अवर सचिब

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

New Delhi, the 10th July, 2003

S.O. 2167.—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (1) of Section 6 of the Industrial Development Bank of India Act, 1964 (18 of 1964), the Central Government, hereby appoint Shri N. S. Sisodia, IAS (RJ : 1968), Secretary (Financial Sector), Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, New Delhi as a Director on the Board of Director of Industrial Development Bank of India with immediate effect and until further orders *vice* Ms. Vineeta Rai.

[F. No. 24(4)/2002-IF. I]

B. D. BERWAL, Under Secy.

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 2003

का.आ. 2168.— भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 (1989 का 39) की धारा 6 की उप-धारा 2 के साथ पठित धारा 6 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, ओरियंटल बैंक आफ कामर्स में कार्यपालक निदेशक श्री विजय कुमार चोपड़ा को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से उनकी अधिवर्षिता की आयु पूरी होने तक अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्त करती है।

[फा. सं. 24(1)/2001-आई. एफ-1]

अतुल कुमार राय, निदेशक

New Delhi, the 16th July, 2003

S.O. 2168.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 6 read with sub-section 2 of Section 6 of the Small Industries Development Bank of India Act, 1989 (39 of 1989), the Central Government hereby appoints Shri Vijay Kumar Chopra, Executive Director, Oriental Bank of Commerce, as Chairman and Managing Director, Small Industries Development Bank of India with effect from the date of his assuming charge and upto the date of his superannuation or until further orders whichever is earlier.

[F. No. 24(1)/2001-IF. 1]

ATUL KUMAR RAI, Director

(बीमा प्रभाग)

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 2003

का.आ. 2169.—केन्द्रीय सरकार भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री एन. एस. सिसोदिया, सचिव (वित्तीय क्षेत्र) आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय को श्रीमती विनीता राय, के स्थान पर उक्त निगम के सदस्य के रूप में तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेश तक के लिए नियुक्त करती है।

[फा. सं. 14(3)/2003-बीमा-IV]

आर. रंगनाथ, निदेशक

(Insurance Division)

New Delhi, the 17th July, 2003

S.O. 2169.—In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956), the Central Government hereby appoints Sh. N. S. Sisodia, Secretary (Financial Sector), Department of Economic Affairs, Ministry of Finance as Member of the said Corporation vice Smt. Vineeta Rai with immediate effect till further orders.

[F. No. 14/3/2003-Ins. IV]

R. RENGANATH, Director

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2003

(आयकर)

का.आ. 2170.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23-ग) के उपखंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार द्वारा "सेन्टर फार हाई टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली" को वर्ष 1995-1996 से 1997-1998 तक के कर निर्धारण वर्षों के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त उप-खंड के प्रयोजनार्थ अनुमोदित करती है, अर्थात् :—

- (i) कर-निर्धारिती उसकी आय का इस्तेमाल अथवा उसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए उसका संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है;
- (ii) कर-निर्धारिती उपर्युक्त कर-निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से उसकी निधि (जेवर-जवाहिरात, फर्नीचर अथवा किसी अन्य वस्तु आदि के रूप में प्राप्त तथा अनुरक्षित स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा;
- (iii) यह आदेश किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगा, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों;
- (iv) कर-निर्धारिती आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार अपनी आय विवरणी नियमित रूप से आयकर प्राधिकारी के समक्ष फाइल करेगा;
- (v) विघटन की स्थिति में इसकी अतिरिक्त राशियाँ और परिसम्पत्तियाँ समान उद्देश्यों वाले धर्मार्थ संगठन को दे दी जाएंगी।

[अधिसूचना सं. 173/2003/फा. सं. 197/19/2002-आयकर नि.-1]

आई. पी. एस. बिन्द्रा, अवर सचिव

(Department of Revenue)

New Delhi, the 18th July, 2003

(INCOME TAX)

S.O. 2170.—In exercise of powers conferred by the sub-clause (iv) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies the "Centre for High Technology, New Delhi" for the purpose of the said sub-clause for the assessment years 1995-1996 to 1997-1998 subject to the following conditions, namely :—

- (i) the assessee will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established;

- (ii) the assessee will not invest or deposit its fund (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of Section 11;
- (iii) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of accounts are maintained in respect of such business;
- (iv) the assessee will regularly file its return of income before the Income-tax authority in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961;
- (v) that in the event of dissolution, its surplus and the assets will be given to a charitable organisation with similar objectives.

[Notification No. 173/2003/F. No. 197/19/2002-ITA-I]

I. P. S. BINDRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2003

(आयकर)

का.आ. 2171.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23-ग) के उपखंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा “द क्लीयरिंग एण्ड फॉरवर्डिंग अनप्रोटेक्टेड डॉक लेबर बोर्ड, मुम्बई” को वर्ष 1993-94 से 1995-96 तक के कर निर्धारण वर्षों के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त उप-खंड के प्रयोजनार्थ अनुमोदित करती है, अर्थात्:—

- (i) कर-निर्धारिता उसकी आय का इस्तेमाल अथवा उसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए उसका संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है;
- (ii) कर-निर्धारिता उपर्युक्त कर-निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से उसकी निधि (जेवर-जवाहिरात, फर्नीचर अथवा किसी अन्य वस्तु आदि के रूप में प्राप्त तथा अनुरक्षित स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा;
- (iii) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारिता के उद्देश्यों की

प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा पुस्तिकाएँ नहीं रखी जाती हों;

- (iv) कर-निर्धारिता आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार अपनी आय विवरणी नियमित रूप से आयकर प्राधिकारी के समक्ष फाइल करेगा;
- (v) विघटन की स्थिति में इसकी अतिरिक्त राशियाँ और परिसम्पत्तियाँ समान उद्देश्यों वाले धर्मार्थ संगठन को दे दी जाएंगी।

[अधिसूचना सं. 174/2003/फ. सं. 197/83/2003-आयकर नि.-1]

आई. पी. एस. बिन्द्रा, अवर सचिव

New Delhi, the 18th July, 2003

(INCOME TAX)

S.O. 2171.—In exercise of powers conferred by the sub-clause (iv) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies the “The Clearing & Forwarding Unprotected Dock Labour Board, Mumbai” for the purpose of the said sub-clause for the assessment years 1993-1994 to 1995-1996 subject to the following conditions, namely:—

- (i) the assessee will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established;
- (ii) the assessee will not invest or deposit its fund (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of Section 11;
- (iii) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of accounts are maintained in respect of such business;
- (iv) the assessee will regularly file its return of income before the Income-tax authority in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961;
- (v) that in the event of dissolution, its surplus and the assets will be given to a charitable organisation with similar objectives.

[Notification No. 174/2003/F. No. 197/83/2003-ITA-I]

I. P. S. BINDRA, Under Secy.

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2003

का.आ. 2172.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध एवं प्रकीर्ण) उपबंध स्कीम, 1980 के खंड 3 के उपखंड (1) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9 की उपधारा (3) (छ) एवं (3क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, 113/233, स्वरूप नगर, कानपुर में चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, श्री एस. के. जैन को जुलाई, 2003 से तीन वर्ष की अवधि के लिए पंजाब एंड सिंध बैंक में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के पद पर नामित करती है।

[सं. एफ 9/17/2000-बी ओ-1]

रमेश चन्द्र, अवर सचिव

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

New Delhi, the 21st July, 2003

S.O. 2172.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (3)(g) and (3-A) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 read with sub-clause (1) of Clause 3 of the Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980, the Central Government, hereby nominates Shri S. K. Jain, Chartered Accountant, 113/233, Swaroop Nagar, Kanpur as part-time non-official director of Punjab & Sind Bank for a period of three years commencing on 21st July, 2003.

[F. No. 9/17/2000-B. O. I.]

RAMESH CHAND, Under Secy.

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 2003

का.आ. 2173.—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 8 की उपधारा (4) के साथ पठित उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, डॉ. वाई. वेणुगोपाल रेड्डी, जो वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कार्यपालक निदेशक हैं, को पांच वर्ष की अवधि के लिये डॉ. बिमल जालान के स्थान पर भारतीय रिजर्व बैंक में गवर्नर के रूप में नियुक्त करती है।

डॉ. वाई. वेणुगोपाल रेड्डी की भारतीय रिजर्व बैंक में गवर्नर के पद पर नियुक्ति डॉ. बिमल जालान के उक्त पद पर कार्यभार त्याग देने के बाद ही प्रभावी होगी।

[फा. सं. 7/3/2003-बी ओ-1]

शेखर अग्रवाल, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 23rd July, 2003

S.O. 2173.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) read with sub-section (4) of Section 8 of the Reserve Bank of India Act, 1934, the Central Government, hereby appoints Dr. Y. Venugopal

Reddy, currently Executive Director, International Monetary Fund, as Governor, Reserve Bank of India, for a term of five years vice Dr. Bimal Jalan.

The appointment of Dr. Y. Venugopal Reddy as Governor, Reserve Bank of India, will take effect after Dr. Bimal Jalan demits charge of the post.

[F. No. 7/3/2003-B. O. I.]

SHEKHAR AGARWAL, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 2003

का.आ. 2174.—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 56 के साथ पठित धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंध सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 31 मार्च, 2004 तक दि नागालैंड स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लि., दीमापुर, नागालैंड पर लागू नहीं होंगे।

[फा. सं. 1(39)/99-ए. सी.]

मंगल मरांडी, अवर सचिव

New Delhi, the 23rd July, 2003

S.O. 2174.—In exercise of the powers conferred by Section 53 read with Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) the Central Government on recommendation of the Reserve Bank of India declares that the provisions of sub-section (1) of Section 11 of the said Act shall not apply to The Nagaland State Co-operative Bank Ltd., Dimapur, Nagaland, from the date of publication of this notification in the Official Gazette till 31 March, 2004.

[F. No. 1(39)/99-AC]

MANGAL MARNDI, Under Secy.

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2003

का.आ. 2175.—केन्द्रीय सरकार राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उप-नियम (4) के अनुसरण में कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम नेशनल सीड्स कार्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के निम्नलिखित क्षेत्रीय तथा प्रक्षेत्र कार्यालयों को, जिसके 80% कर्मचारीवृन्द ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है :—

1. क्षेत्रीय कार्यालय,
नेशनल सीड्स कार्पोरेशन लिमिटेड,
65, पान दरीबा,
लखनऊ-226004

2. प्रक्षेत्र कार्यालय,
नेशनल सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड,
दुर्गापुर रोड, अमेठी-227405
3. प्रक्षेत्र कार्यालय,
नेशनल सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड,
प्लॉट नं. डी-25, साइट नं. 1,
पनकी इंडस्ट्रियल एरिया,
कानपुर-208022
4. प्रक्षेत्र कार्यालय,
नेशनल सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड,
बाई पास रोड,
इटावा-206003
5. प्रक्षेत्र कार्यालय,
नेशनल सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड,
165, सिविल लाइन्स,
बरेली-243001
6. प्रक्षेत्र कार्यालय,
नेशनल सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड,
भारतीय स्टेट बैंक के सामने,
रुद्रपुर-263153 (जिला ऊधम सिंह नगर)
7. प्रक्षेत्र कार्यालय,
नेशनल सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड,
डाकघर आर. टी. सी.,
हेमपुर-244716 (जिला ऊधम सिंह नगर)
8. प्रक्षेत्र कार्यालय,
नेशनल सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड,
मोहल्ला-जियाखेल,
शाहजहांपुर-241001
9. प्रक्षेत्र कार्यालय,
नेशनल सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड,
प्लॉट नं. बी-17,
यू. पी. एस. आई. डी. सी.,
इंडस्ट्रियल एरिया, मथुरा रोड,
सिकन्दरा, आगरा-282007
10. प्रक्षेत्र कार्यालय,
नेशनल सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड,
राजा दाल मिल,
इग्लास रोड,
हाथरस-204101
11. प्रक्षेत्र कार्यालय,
नेशनल सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड,
पी. सी. एफ. गोदाम, अशोक नगर,
डाकघर-बरसातपुर,
गोरखपुर-273007
12. प्रक्षेत्र कार्यालय,
नेशनल सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड,
80, गांधीनगर,
वाराणसी-201001
13. क्षेत्रीय कार्यालय,
नेशनल सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड,
48-49, इंडस्ट्रियल एरिया,
गोविन्दपुरा,
भोपाल-462023
14. प्रक्षेत्र कार्यालय,
नेशनल सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड,
48-49, इंडस्ट्रियल एरिया,
गोविन्दपुरा,
भोपाल-462023
15. प्रक्षेत्र कार्यालय,
नेशनल सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड,
ई-112/113, इंडस्ट्रियल एरिया,
सांवेर रोड,
इंदौर-462003
16. प्रक्षेत्र कार्यालय,
नेशनल सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड,
कृषि उपल मंडी,
लक्ष्मीगंज, लश्कर,
ग्वालियर-474001
17. प्रक्षेत्र कार्यालय,
नेशनल सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड,
देवेन्द्रपुर, मऊरानी पुर रोड,
निवाड़ी-472442,
जिला टीकमगढ़
18. क्षेत्रीय कार्यालय,
नेशनल सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड,
एस. सी. ओ., 1024-25,
सेक्टर-22 बी,
चंडीगढ़-160022
19. प्रक्षेत्र कार्यालय,
नेशनल सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड,
मार्फत मैसर्स नरुला राईस एंड जनरल मिल्स,
हाँसी रोड,
करनाल-132001
20. प्रक्षेत्र कार्यालय,
नेशनल सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड,
15, आई. डी. सी.,
दैनिक जागरण प्रेस के सामने,
हिसार-125001

21. प्रक्षेत्र कार्यालय,
नेशनल सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड,
सी. 25, फोकल प्वाइंट,
बाईपास,
जालंधर-144004
22. प्रक्षेत्र कार्यालय,
नेशनल सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड,
प्लॉट नं. ए-2,
फोकल प्वाइंट, डबवाली रोड,
भटिण्डा-151006
23. प्रक्षेत्र कार्यालय,
नेशनल सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड,
मकान नं. 388,
नजदीक लेन नं. 14,
तालाब तिल्लो,
जम्मू-180002
24. प्रक्षेत्र कार्यालय,
नेशनल सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड,
मिन्तल कॉम्प्लेक्स, बाईपास रोड,
पी. ओ. सपरून,
सोलन-173212
25. प्रक्षेत्र कार्यालय,
नेशनल सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड,
गायत्री सोसाइटी,
एस. टी. नगर के पास,
गोधरा-389001
26. प्रक्षेत्र कार्यालय,
नेशनल सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड,
सहकारी जिन,
शामलाजी रोड,
पोस्ट बॉक्स नं. 45,
हिम्मतनगर-383001
27. प्रक्षेत्र कार्यालय,
नेशनल सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड,
शकर टेकरी,
कला भवन के सामने
डांडिया बाजार,
बदोदरा-390001
28. प्रक्षेत्र कार्यालय,
नेशनल सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड,
अबोहर रोड,
इंडस्ट्रियल एरिया,
श्रीगंगानगर-335001
29. प्रक्षेत्र कार्यालय,
नेशनल सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड,
दुकान नं. 2, कृषि उपज मण्डी, अलवर
30. प्रक्षेत्र कार्यालय,
नेशनल सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड,
दुकान नं. 47, ब्लाक-ए,
कृषि उपज मण्डी (मण्डी यार्ड),
उदयपुर-313001
31. प्रक्षेत्र कार्यालय,
नेशनल सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड,
ई-12-13, इंडस्ट्रियल एरिया, भरतपुर
32. प्रक्षेत्र कार्यालय,
नेशनल सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड,
कॉटन जनिंग फैक्टरी,
चित्तौड़गढ़-312001
33. प्रक्षेत्र कार्यालय,
नेशनल सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड,
डी-14, सब्जी मण्डी (पावटा),
जोधपुर-342006
34. प्रक्षेत्र कार्यालय,
नेशनल सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड,
कृषि उपज मण्डी समिति, सीकर
35. प्रक्षेत्र कार्यालय,
नेशनल सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड,
ई-134, इन्द्रप्रस्थ इंडस्ट्रियल एरिया,
कोटा-324005
36. प्रक्षेत्र कार्यालय,
नेशनल सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड,
शेखपुरा, राजा बाजार,
पटना-800014
37. प्रक्षेत्र कार्यालय,
नेशनल सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड,
मिर्जा नहट,
भागलपुर-854326
38. प्रक्षेत्र कार्यालय,
नेशनल सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड,
प्रभात सिनेमा के पास,
मुजफ्फरनगर-842001
39. प्रक्षेत्र कार्यालय,
नेशनल सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड,
मार्किट यार्ड, गुलाब बाग,
पूर्णिया-854326

40. प्रक्षेत्र कार्यालय,
नेशनल सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड,
सुखदेव नगर, रातु रोड,
रांची-834005
41. प्रक्षेत्र कार्यालय,
नेशनल सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड,
रामराज मोड़,
सिवान-841226
42. प्रक्षेत्र कार्यालय,
नेशनल सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड,
कोर्ट कम्पाउंड,
समस्तीपुर-848101
43. प्रक्षेत्र कार्यालय,
नेशनल सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड,
पी. ओ. एवं जिला मधुबनी,
पिन-847211
44. प्रक्षेत्र कार्यालय,
नेशनल सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड,
दुकान नं. 8, हाउसिंग बोर्ड, कॉलोनी,
झारसा रोड,
गुड़गांव-122001

[सं. 3-2/2002-हिंदी नीति]

सतीश चन्द्र, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE**(Department of Agriculture & Cooperation)**

New Delhi, the 2nd July, 2003

S.O. 2175.—In pursuance of Sub-Rule (4) 10 of the Official Language (Use for Official Purposes of the Union) Rules, 1976 the Central Government hereby notifies the following regional and area offices of the National Seeds Corporation Limited, New Delhi, a Public Sector Undertaking under the control of the Department of Agriculture & Cooperation, Ministry of Agriculture, 80% staff whereof have acquired the working knowledge of Hindi :—

1. Regional Office,
National Seeds Corporation Ltd.,
65, Pan Dariba,
Lucknow-226004
2. Area Office,
National Seeds Corporation Ltd.,
Durgapur Road,
Amethi-227405

3. Area Office,
National Seeds Corporation Ltd.,
Plot No. D-25, Site No. 1,
Panki Industrial Area,
Kanpur-208022
4. Area Office,
National Seeds Corporation Ltd.,
By Pass Road,
Etawah-206003
5. Area Office,
National Seeds Corporation Ltd.,
165, Civil Lines,
Barcilly-243001
6. Area Office,
National Seeds Corporation Ltd.,
Opp. State Bank of India,
Rudrapur-263153
(District-Udham Singh Nagar)
7. Area Office,
National Seeds Corporation Ltd.,
P.O., R.T.C.,
Hempur-244716
(District-Udham Singh Nagar)
8. Area Office,
National Seeds Corporation Ltd.,
Mohalla-Ziakhel,
Shahjahanpur-241001
9. Area Office,
National Seeds Corporation Ltd.,
Plot No. B-17, U.P.S.I.D.C.,
Industrial Area, Mathura Road,
Sikandara, Agra-282007
10. Area Office,
National Seeds Corporation Ltd.,
Raja Daal Mill,
Iglass Road,
Hathras-204101
11. Area Office,
National Seeds Corporation Ltd.,
P.C.F. Godown, Ashok Nagar,
P.O. Basaratpur,
Gorakhpur-273007
12. Area Office,
National Seeds Corporation Ltd.,
80, Gandhi Nagar,
Varanasi-201001
13. Regional Office,
National Seeds Corporation Ltd.,
48-49, Industrial Area,
Govindpura,
Bhopal-462023

14. Area Office,
National Seeds Corporation Ltd.,
-48-49, Industrial Area,
Govindpura,
Bhopal-462023
15. Area Office,
National Seeds Corporation Ltd.,
E-112/113, Industrial Area,
Sanwar Road,
Indore-462003
16. Area Office,
National Seeds Corporation Ltd.,
Krishi Upaj Mandi,
Lakshmi Ganj, Lashkar,
Gwalior-474001
17. Area Office,
National Seeds Corporation Ltd.,
Davendrapura, Maurani Road,
Nivari-472442
District-Tikamgarh
18. Regional Office,
National Seeds Corporation Ltd.,
S.C.O. 1024-25,
Sector-22-B,
Chandigarh-160022
19. Area Office,
National Seeds Corporation Ltd.,
C/o M/s. Narula Rice and
General Mills, Hansi Road,
Karnal-132001
20. Area Office,
National Seeds Corporation Ltd.,
15, I.D.C., Opp., Dainik Jagran Press,
Delhi Road,
Hisaar-125001
21. Area Office,
National Seeds Corporation Ltd.,
C-25, Focal Point,
Bypass,
Jullundhur-144004
22. Area Office,
National Seeds Corporation Ltd.,
Plot No. A-2,
Focal Point, Dabwali Road,
Bhatinda-151006
23. Area Office,
National Seeds Corporation Ltd.,
House No. 388,
Near Lane No. 14,
Talab Tillo,
Jamnagar-380002
24. Area Office,
National Seeds Corporation Ltd.,
Mittal Complex, Bypass Road,
P.O. Saproun,
Solani-173212
25. Area Office,
National Seeds Corporation Ltd.,
Gayatri Society,
Near S. T. Nagar,
Godhra-389001
26. Area Office,
National Seeds Corporation Ltd.,
Sahkari Zin, Shamlaj Road,
Post Box No. 45,
Himmatnagar-383001
27. Area Office,
National Seeds Corporation Ltd.,
Shankar Tekari,
Opp. Kala Bhawan, Dandia Bazaar,
Vadodara-390001
28. Area Office,
National Seeds Corporation Ltd.,
Abohar Road, Industrial Area,
Sriganganagar-335001
29. Area Office,
National Seeds Corporation Ltd.,
Shop No. 2, Krishi Upaj Mandi,
Alwar
30. Area Office,
National Seeds Corporation Ltd.,
Shop No. 47, Block-A,
Krishi Upaj Mandi (Mandi Yard),
Udaipur-313001
31. Area Office,
National Seeds Corporation Ltd.,
E-12-13, Industrial Area,
Bharatpur
32. Area Office,
National Seeds Corporation Ltd.,
Cotton Ginning Factory,
Chittorgarh-312001
33. Area Office,
National Seeds Corporation Ltd.,
D-14, Sabji Mandi (Pawta),
Jodhpur-342006
34. Area Office,
National Seeds Corporation Ltd.,
Krishi Upaj Mandi Samiti,
Sikar

35. Area Office,
National Seeds Corporation Ltd.,
E-134, Indraprasth,
Industrial Area,
Kota-324005
36. Area Office,
National Seeds Corporation Ltd.,
Sheikhpura, Raja Bazaar,
Patna-800014
37. Area Office,
National Seeds Corporation Ltd.,
Mirzanahat,
Bhagalpur-812005
38. Area Office,
National Seeds Corporation Ltd.,
Near Prabhat Cinema,
Muzaffarpur-842001
39. Area Office,
National Seeds Corporation Ltd.,
Market Yard, Gulab Bagh,
Purnia-854326
40. Area Office,
National Seeds Corporation Ltd.,
Sukhdev Nagar, Raatu Road,
Ranchi-834005
41. Area Office,
National Seeds Corporation Ltd.,
Ramraj Modh,
Near Andar Dhala,
Siwan-841226
42. Area Office,
National Seeds Corporation Ltd.,
Court Compound,
Samstipur-848101
43. Area Office,
National Seeds Corporation Ltd.,
P.O. & District Madhubani,
Pin-847211
44. Area Office,
National Seeds Corporation Ltd.,
Shop No. 8, Housing Board Colony,
Jharsa Road,
Gurgaon-122001

[No. 3-2/2002-Hindi Neeti]

SATISH CHANDER, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 2003

का.आ. 2176. — केन्द्रीय सरकार राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उप नियम (4) के अनुसरण में कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय के

अंतर्गत निम्नलिखित कार्यालयों को, जिसके 80% कर्मचारिवृन्द ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है :

1. केन्द्रीय एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन केन्द्र,
खजानी रोड, गुरौली बजुर्ग,
पो.ऑ. छपिया,
गोरखपुर-273016 (उ.प्र.)
2. केन्द्रीय एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन केन्द्र,
मशीनरी स्टोर भवन,
एन.एच.-4,
फरीदाबाद-121001 (हरियाणा)
3. केन्द्रीय एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन केन्द्र,
सरकारी माध्यमिक स्कूल के सामने,
दिगनाबाद, पोर्ट ब्लेयर-744104
अंडमान एवं निकोबार
4. वनस्पति संगरोध केन्द्र,
जयप्रकाश नारायण अंतराष्ट्रीय हवाई अड्डा,
पो.ऑ. बी.बी.वी. कालेज,
पटना-800014 (बिहार)
5. टिड्डो चेतावनी संगठन,
भू-उपग्रह केन्द्र के पास,
जैसलमेर-345001 (राजस्थान)
6. क्षेत्रीय निदेशालय,
राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम,
34 एवं 35, गार्मेन्ट काम्प्लेक्स,
दूसरा तल, इंडस्ट्रीयल एस्टेट,
गुडंडी, चेन्नई-600032
7. क्षेत्रीय निदेशालय (पूर्व),
पी.-161/1, वी.आई.पी.रोड,
(चौथी मंजिल),
कोलकाता-700054
8. क्षेत्रीय निदेशालय,
राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम,
बोरा सर्विस स्टेशन बिल्डिंग,
जी.एस. रोड, उल्लुबारी,
गुवाहाटी-781007
9. क्षेत्रीय निदेशालय,
राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम,
5-10-193, हाका भवन,
दूसरी मंजिल, पब्लिक गार्डन के सामने,
हैदराबाद-500004
10. विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय,
केन्द्रीय सदन, छठवीं मंजिल,
सेक्टर-9 ए, उप-कार्यालय, चंडीगढ़।

11. विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय,
12/डी, लारेन्स रोड, उपकार्यालय
अमृतसर।
12. विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय,
क्षेत्रीय एगमार्क प्रयोगशाला,
डब्ल्यू-6, ओखला, औद्योगिक क्षेत्र,
फेज-2, नई दिल्ली-110020
13. विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय,
क्षेत्रीय एगमार्क प्रयोगशाला,
83, मालवीय नगर,
भोपाल-462003 (म.प्र.)
14. विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय,
कपास वर्गीकरण केन्द्र,
अटवा लाइन्स, सूरत-395007
(गुजरात)
15. विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय,
क्षेत्रीय एगमार्क प्रयोगशाला,
58, मानसिंह पुरा टोंक रोड,
जयपुर-18 (राजस्थान)
16. विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय,
58, मानसिंह पुरा टोंक रोड,
उप-कार्यालय, जयपुर-18 (राजस्थान)
17. क्षेत्रीय संस्थान,
सहकारी प्रबन्ध संस्थान,
ई-8/77, शाहपुरा, त्रिलंगा रोड,
भोपाल-482039
(मध्य प्रदेश)
18. क्षेत्रीय संस्थान,
दीप नारायण सिंह,
क्षेत्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान,
शास्त्रीनगर, पटना-90023 (बिहार)
19. सहकारी प्रबन्ध संस्थान,
राजपुर,
देहरादून-248009 (उत्तरांचल)
20. सहकारी प्रबन्ध संस्थान,
इंदिरागांधी सहकारी प्रबंध संस्थान,
ब्लॉक-बी, सैक्टर 18, राजाजीपुरम,
लखनऊ-226017 (उत्तर प्रदेश)
21. क्षेत्रीय कार्यालय,
क्षेत्रीय जैव उर्वरक विकास केन्द्र,
विदर्भ क्रिकेट एसोसियेशन काम्पलेक्स,
सिविल लाइन्स, नागपुर-440001
महाराष्ट्र
22. क्षेत्रीय जैव उर्वरक विकास केन्द्र,
ए-156/ शहीद नगर,
भुवनेश्वर-751007
उड़ीसा
23. नारियल विकास बोर्ड,
राज्य केन्द्र, पश्चिम बंगाल,
बी जे-108-सैक्टर-11,
साल्ट लेक, कोलकाता-700091
24. नारियल विकास बोर्ड,
राज्य केन्द्र, उड़ीसा,
एन-1/297, नयापल्ली,
आई.आर.सी. विलेज (डाक)
भुवनेश्वर-751015
25. तम्बाकू विकास निदेशालय,
शास्त्री भवन एनेक्सी,
तीसरा तल, 26, हैडोज रोड,
चेन्नै-600006

[सं. 3-2/2000-हिन्दी नीति]

सतीश चन्द्र, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 16th July, 2003

S.O. 2176.—In pursuance of Sub-Rule (4) of Rule 310 of the Official Language (Use for Official Purposes of the Union) Rule, 1976, the Central Government hereby notifies the following office under the control of the Department of Agriculture and Cooperation, Ministry of Agriculture, 80% staff whereof have acquired the working knowledge of Hindi :

1. Central Integrated Pest Management Centre
Khajni Road,
Guraulli Bajurg,
P.O. Chhapiya,
Gorakhpur-273016 (U.P.)
2. Central Integrated Pest Management Centre
Machinery Store Bhawan,
N.H.-4,
Faridabad-121001 (Haryana).
3. Central Integrated Pest Management Centre
Opp. Govt. Higher Secondary School,
Dignabad, Port Blair-744104
Andaman & Nicobar.
4. Plant Quarantine Centre,
Jai Prakash Narayan International Airport,
P.O.B.B.V. College,
Patna-800014 (Bihar)

5. Locust Warning Organisation,
Near Geo Satellite Centre,
Jaisalmer-345001, Rajasthan
6. Regional Directorate,
National Cooperative Development Corporation
34 & 35, Garment Complex,
2nd floor, Institutional Estate, Guindi,
Chennai-600032
7. Regional Directorate (East),
P-161/1, V.I.P. Road,
(Fourth floor),
Kolkata-700054
8. Regional Directorate,
Bora Service Station Building,
G.S. Road, Ullubari,
Guwahati-781007
9. Regional Directorate,
National Cooperative Development Corporation,
5-10-193, Haaka Bhawan,
2nd floor, Opp. Public Garden,
Hyderabad-500004
10. Directorate of Marketing & Inspection,
Kendriya Sadan, 6th floor,
Sector-9A, Sub Office,
Chandigarh
11. Directorate of Marketing & Inspection,
12/D Lowrance Road Sub office,
Amritsar
12. Directorate of Marketing & Inspection,
Regional Agmark Laboratory,
W-6, Okhla Industrial Area,
Phase-2, New Delhi-110020
13. Directorate of Marketing & Inspection,
Regional Agmark Laboratory,
83, Malviya Nagar,
Bhopal-462003 (M.P.)
14. Directorate of Marketing & Inspection,
Cotton Classification Centre,
Athwa Lines,
Surat-395007 (Gujarat)
15. Directorate of Marketing & Inspection,
Regional Agmark Laboratory,
58, Mansingh Pura, Tonk Road,
Jaipur-18 (Rajasthan)
16. Directorate of Marketing & Inspection,
58, Mansingh Pura, Tonk Road,
Sub Office,
Jaipur-18 (Rajasthan)
17. Regional Institute,
Institute of Cooperative Management,
E-8/77, Shahpura, Trilanga Road,
Bhopal-482039, (Madhya Pradesh)
18. Regional Institute,
Deep Narayan Singh,
Institute of Regional Cooperative
Management, Shastri Nagar,
Patna 90023 (Bihar)
19. Institute of Cooperative Management,
Rajpur,
Dehradun-248009 (Uttaranchal)
20. Institute of Indira Gandhi Cooperative
Management,
Block-B, Sector 18, Rajajipuram,
Lucknow-226017 (U.P.)
21. Regional Office,
Regional Bio Fertiliser Development Centre,
Vidarbha Cricket Association Complex,
Civil Lines,
Nagpur-440001 (Maharashtra)
22. Regional Bio Fertiliser Development Centre,
A-156, Shaheed Nagar,
Bhubaneswar-751007 (Orissa)
23. Coconut Development Board,
State Centre, West Bengal,
Salt Lake, Kolkata-700091
24. Coconut Development Board,
State Centre, Orissa,
N-1/297, Nayapally,
ICR Village P.O.,
Bhubaneswar-751015
25. Directorate of Tobacco Development,
Shastri Bhawan Annexe III floor
26. Haddows Road,
Chennai-600006

[No. 3-2/2000-Hindi Neeti]

SATISH CHANDER, Jt. Secy.

(कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2003

का.अ. 2177.—केन्द्रीय सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियमावली, 1976 के नियम 10 के उप-नियम (4) के अनुसरण में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, आई.सी.ए. आर. के निम्नलिखित क्षेत्रीय केंद्रों में हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले कर्मचारियों की संख्या 80 प्रतिशत से अधिक हो जाने के फलस्वरूप उन्हें एतद्वारा अधिसूचित करती है :

क्रम संख्या	क्षेत्रीय केन्द्र
1.	पूसा (बिहार)
2.	इन्दौर (मध्यप्रदेश)
3.	करनाल (हरियाणा)
4.	कलिंग (पश्चिम बंगाल)
5.	पुणे (महाराष्ट्र)
6.	कटराई कुल्लू घाटी (हिमाचल प्रदेश)
7.	धारवाड (कर्नाटक)
8.	टूटीकण्डी, शिमला (हिमाचल प्रदेश)
9.	अमरतारा काटेज, शिमला (हिमाचल प्रदेश)

[संख्या 13-2/2002-हिन्दी]

एम.सी. चांद, अवर सचिव

(Department of Agricultural Research & Education)
New Delhi, the 21st July, 2003

S.O. 2177.—In pursuance of Sub-Rule (4) of Rule 10 of the Official Language (Use for Official Purpose of the Union) Rules, 1976, the Central Government, Ministry of Agriculture, Department of Agricultural Research & Education hereby notifies the following regional centres of the Indian Agricultural Research Institute, ICAR where the percentage of Hindi knowing staff has gone above 80% :

S.No.	Regional Centre
1.	Pusa (Bihar)
2.	Indore (M.P.)
3.	Karnal (Haryana)
4.	Kalinpong (West Bengal)
5.	Pune (Maharashtra)
6.	Katrain, Kulu Ghati (H.P.)
7.	Dharwar (Karnataka)
8.	Tutikand, Shimla (H.P.)
9.	Amartara Cottage, Shimla (H.P.)

[No. 13-2/2002-Hindi]
M.C. CHAND, Under Secy.

विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 2003

का.आ. 2178.—सार्वजनिक परिसर (अनाधिकृत उपभोक्ताओं की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 16 नवंबर, 2000 को जारी अधिसूचना सं. एस. ओ. 128 में निम्नलिखित संशोधन करती है :—

निम्न तालिका के अनुसार उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या 2 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात् :—

क्रम अधिकारी का नाम और संख्या पदनाम	सार्वजनिक परिसर की श्रेणी तथा अधिकार-क्षेत्र की स्थानीय सीमा
“2. श्री अजय कुमार झा, वरिष्ठ प्रबंधक (मानवीय संबंध), रिहन्द सुपर ताप विद्युत परियोजना	डाक घर रिहन्द नगर, जिला सोनभद्र, उत्तर प्रदेश स्थित नेशनलथर्मल पावर कॉरपोरेशन की रिहन्द सुपर ताप विद्युत परियोजना के कब्जे में/द्वारा लीज या किराये पर ली गई सभी भूमि, क्वार्टर, संपदा, संपत्ति तथा अन्य आवास।”

[एफ. नं. 8/6/1992-थर्मल-1]

अजय शंकर, संयुक्त सचिव

फुटनोट : भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड-3 के उप-खंड (ii) में प्रकाशित मुख्य अधिसूचना, दिनांक 27 जनवरी, 2001

MINISTRY OF POWER

New Delhi, the 17th July, 2003

S.O. 2178.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorized Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Power No. S.O. 128, dated the 16th November, 2000, namely :—

In the said notification, below the Table, for serial number 2 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :

S.No.	Name and designation of officer	Categories of public premises and local limits of jurisdiction
“2.	Shri Ajay Kumar Jha, Senior Manager (Human Relations), Rihand Super Thermal Power Project.	All lands, quarters, estates, properties and other accommodations owned/leased and rented by Rihand Super Thermal Power Project of National Thermal Power Corporation Ltd., at Post Office Rihand Nagar, District Sonbhadra Uttar Pradesh.”

[F. No. 8/6/1992-Th. I]

AJAY SHANKAR, Jt. Secy.

Footnote : Principal notification published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 27th January, 2001.

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

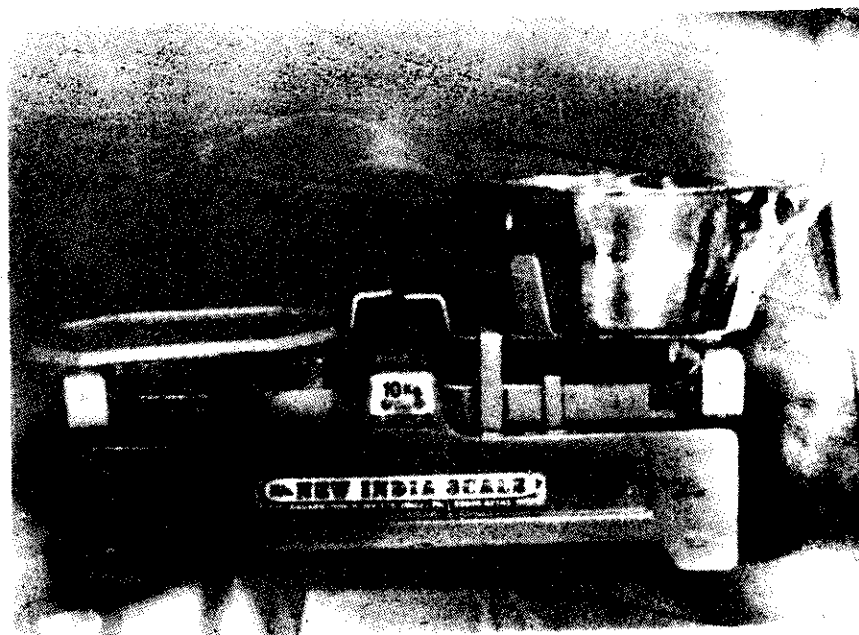
(उपभोक्ता मामले विभाग)

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 2003

का.आ. 2179.—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित माडल (नीचे दी गई आकृति देखें) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) तथा बाट तथा माप मानक (माडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त माडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा :

अतः अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स न्यू इन्डिया स्केल, शिवाजी नगर, 3, सावरकुण्डला-364515 (गुजरात) द्वारा विनिर्मित काउंटर मशीन के माडल का, जिसके ब्रांड का नाम “एन आई एस” है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त माडल कहा गया है) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/2003/67 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है।

उक्त माडल (आकृति देखें) काउंटर मशीन है जो बीम के सिद्धान्त पर कार्य करती है। इसकी अधिकतम क्षमता 10 कि.ग्रा. है।



और, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त माडल के इस अनुमोदन प्रमाणपत्र के अंतर्गत, उसी शृंखला के उसी मेक, यथार्थता और कार्यपालन वाले ऐसे तोलन उपकरण भी होंगे जिनकी अधिकतम क्षमता 500 ग्राम से 50 कि.ग्रा. के रेंज में है और जिनका विनिर्माण उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन और उसी सामग्री से किया जाता है जिससे अनुमोदित माडल का विनिर्माण किया गया है।

[फा. सं. डब्ल्यू एम-21(141)/2001]

पी.ए. कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION**(Department of Consumer Affairs)**

New Delhi, the 24th July, 2003

S.O. 2179.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over period of sustained use and to render accurate service under varied conditions:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 36 of the said Act, the Central Government hereby publishes the certificate of approval of the Model of counter machine (herein referred to as the said model) with brand name 'NIS', manufactured by M/s. New India Scale, Shivaji Nagar, 3, Savarkundla-364515 (Gujarat) and which is assigned the approval mark IND/09/2003/67;

The said Model (see the figure) is counter machine working on the principle of beam with maximum capacity of 10kg.



Further, in exercise of the powers conferred by sub-section (12) of the said section 36 of the said Act, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said Model shall also cover the weighing instruments of similar make, accuracy and performance of same series with maximum capacity in the range of 500g to 50kg, manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which, the approved Model has been manufactured.

[F.No. WM-21 (141)/2001]

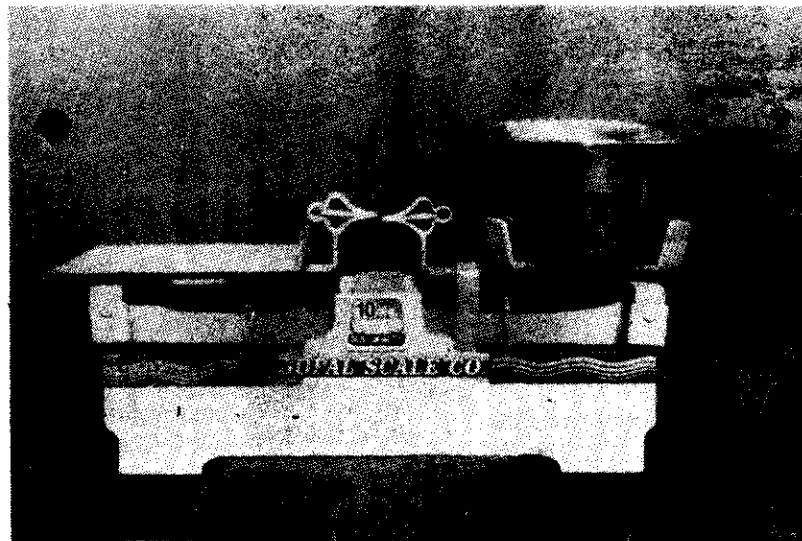
P.A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 2003

का.आ. 2180 .—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित माडल (नीचे दी गई आकृति देखें) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) तथा बाट तथा माप मानक (माडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त माडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा ;

अतः अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स गोपाल स्केल, शिवाजी नगर, सावरकुण्डला-364515 (गुजरात) द्वारा विनिर्मित काउंटर मशीन का माडल (जिसे इसमें उक्त माडल कहा गया है) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/2003/49 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है ;

उक्त माडल (आकृति देखें) एक "काउंटर मशीन" है। इसकी अधिकतम क्षमता 10 कि.ग्रा. है और ब्रांड का नाम "कावेरी" है।



और, केन्द्रीय सरकार उक्त धारा 3 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त माडल के इस अनुमोदन प्रमाणपत्र के अंतर्गत, उसी शृंखला के उसी मॉक, यथार्थता और कार्यक्षमता वाले ऐसे मॉलन उपकरण भी होंगे जिनकी अधिकतम क्षमता 500 ग्राम से 50 कि.ग्रा. की रेंज में है और जिनका विनिर्माण उक्त विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन और ठोसी सामग्री से किया जाता है जिससे अनुमोदित माडल का विनिर्माण किया गया है।

[फा. सं. डब्ल्यू.एम-21(192)/2001]

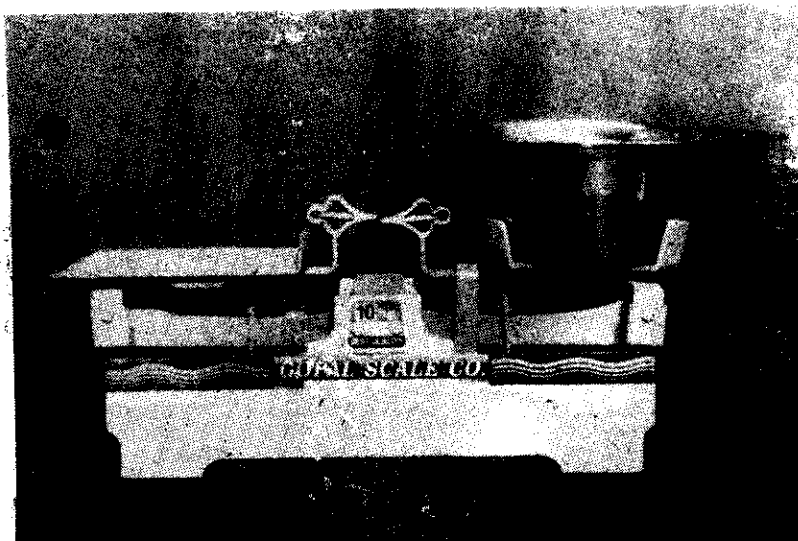
पी. ए. कृष्णमूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 24th July, 2003

S.O. 2180.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report (See the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 36 of the said Act, the Central Government hereby publishes the certificate of approval of the Model of counter machine (herein referred to as the model), manufactured by M/s Gopal Scale, Shivaji Nagar, Savarkundla-364515, (Gujarat) and which is assigned the approval mark IND/09/2003/49;

The said Model (see the figure) is "counter machine". The maximum capacity is 10kg with brand name 'Kaveri'.



Further, in exercise of the powers conferred by sub-section (12) of the said section, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said Model shall also cover the weighing instruments of similar make, accuracy and performance of same series with maximum capacity in the range of 500g to 50kg, manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which, the approved model has been manufactured.

[F. No. WM-21 (192)/2001]

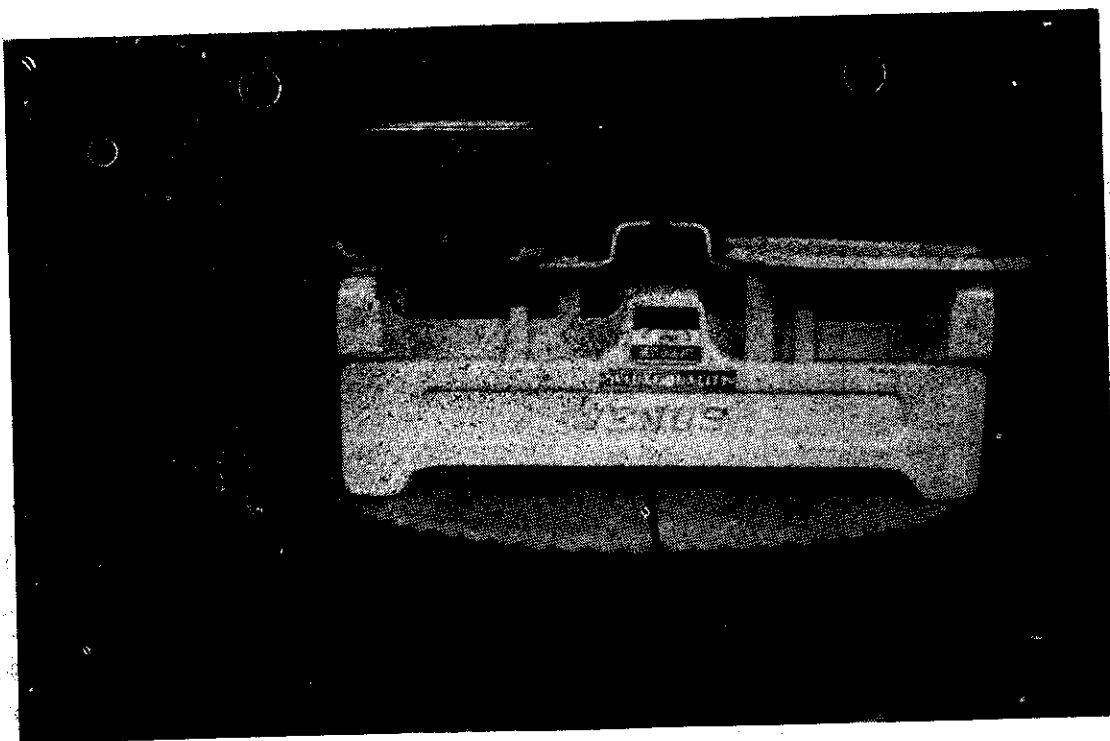
P.A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 2003

का.आ. 2181.—केन्द्रीय सरकार का, विदित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) तथा बाट तथा माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप हैं और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स वीनस इंडस्ट्रीज, 9, शिवाजी नगर, सावरकुण्डला-364515 (गुजरात) द्वारा विनिर्मित काउंटर मशीन के मॉडल का, जिसके ब्रांड का नाम 'वीनस इंड.' है (जिसे इसमें मॉडल कहा गया है) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी 09/2003/46 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र करती है;

उक्त मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें) एक काउंटर मशीन है। इसकी अधिकतम क्षमता 5 कि.ग्रा. है।



और, केन्द्रीय सरकार उक्त धारा की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि मॉडल के इस अनुमोदन प्रमाणपत्र के अंतर्गत, उसी शृंखला के उसी मेक, यथार्थता और कार्यपालन वाले ऐसे तोलन उपक्रम भी होंगे जिनकी क्षमता 500 ग्राम से 50 कि.ग्रा. के रेंज में हैं और जिनका विनिर्माण उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन और उसी सामग्री से किया जाता है जिससे अनुमोदित उक्त मॉडल का विनिर्माण किया गया है।

[फा.सं. डब्ल्यू एम-21(166)/2002]

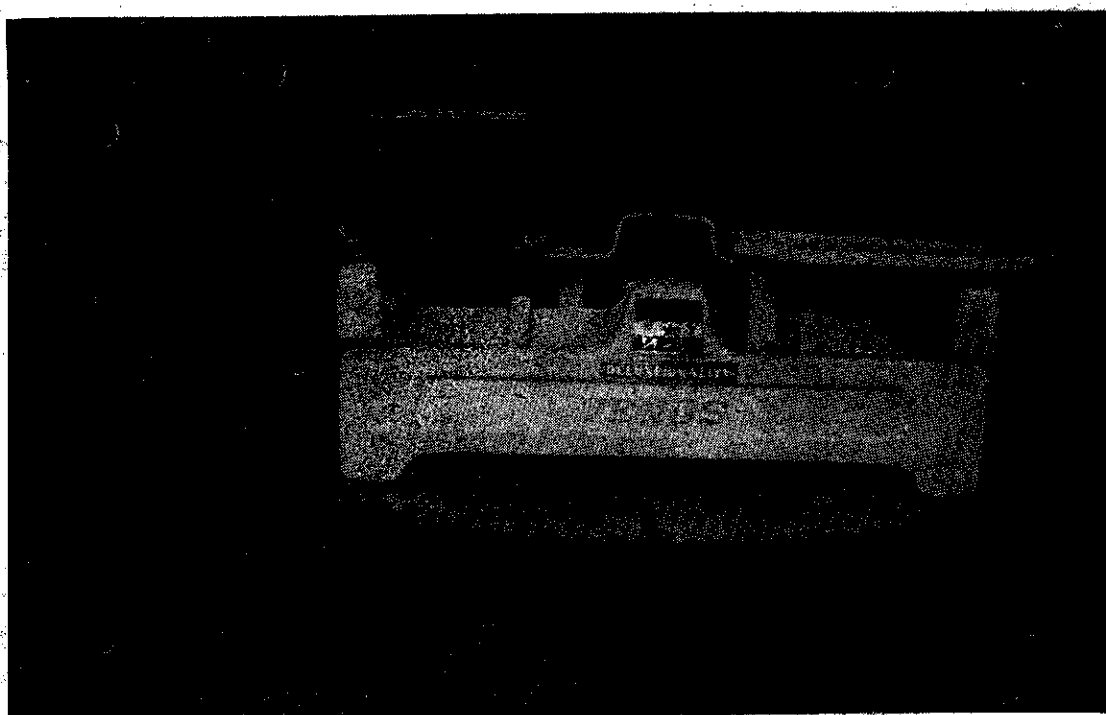
पी. ए. कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 24th July, 2003

S.O. 2181.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report (*see* the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976(60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (7) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby publishes the certificate of approval of the Model of Counter Machine with brand name "Venus Ind" (herein referred to as the model) Manufactured by M/s Venus Industries, 9, Shivaji Nagar, Savarkundla-364515 (Gujarat) and which is assigned the approval mark IND/09/03/46;

The said Model (*see* the figure) is Counter Machine. The Maximum capacity is 5 kg.



Further, in exercise of the powers conferred by Sub-section (12) of the said section the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the Model shall also cover the weighing instruments of similar make, accuracy and performance of same series with capacity ranging from 500g to 50kg, manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which, the approved Model has been manufactured.

[F.No. WM-21 (166)/2002]

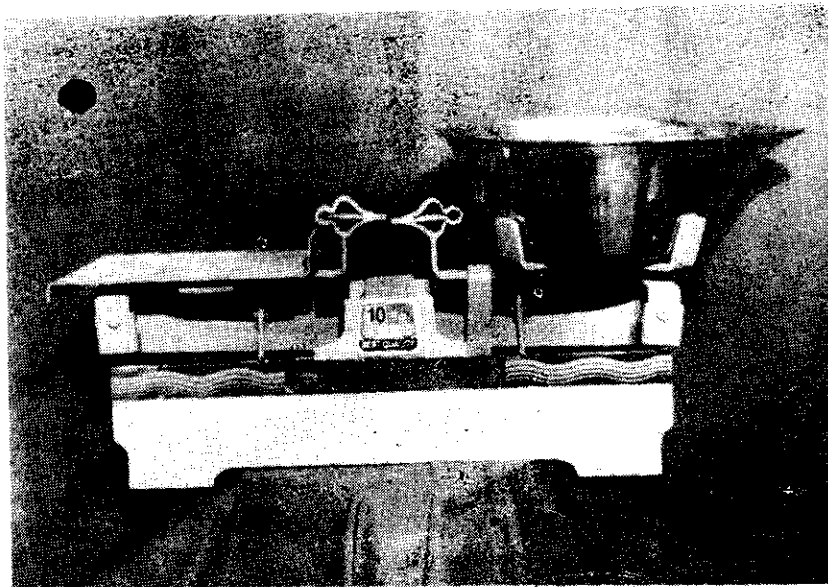
P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 2003

का.आ. 2182.—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) तथा बाट तथा माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप हैं और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) और उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स लुहार मोहन वीर स्केल मैन्युफेक्चरर, धोबी स्ट्रीट, सावरकुण्डला-364515 (गुजरात) द्वारा विनिर्मित काउंटर मशीन के मॉडल का, जिसके ब्रांड का नाम “श्रीफल” है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/2003/24 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है।

उक्त मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें) काउंटर मशीन है। इसकी अधिकतम क्षमता 10 कि.ग्रा. है।



और, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के इस अनुमोदन प्रमाणपत्र के अंतर्गत, उसी शृंखला के उसी मेक, यथार्थता और कार्यपालन वाले ऐसे तोलन उपकरण भी होंगे जिनकी अधिकतम क्षमता 500 ग्राम से 50 कि.ग्रा. के रेंज में हैं और जिनका विनिर्माण उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन और उसी सामग्री से किया जाता है जिससे अनुमोदित मॉडल का विनिर्माण किया गया है।

[फा.सं. डब्ल्यू एम-21(246)/2001]

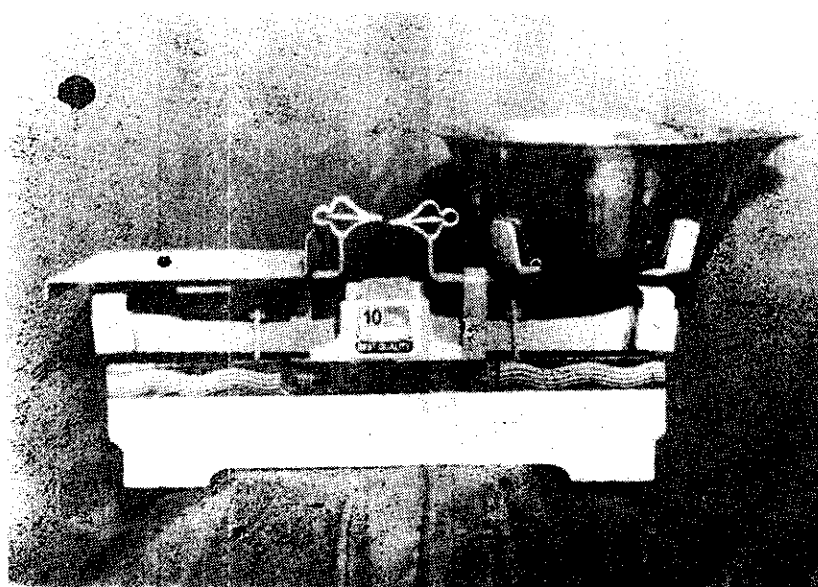
पी. ए. कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 24th July, 2003

S.O. 2182.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Models described in the said report (*see the figure given below*) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (7) and (8) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the Model of counter machine (herein referred to as the said model) with brand name 'SHREEFAL' manufactured by M/s Luhar Mohan Vir Scale Manufacturer, Dhobi Street Savarkundla-364515 (Gujarat) and also assigned the approval mark IND/09/2003/24;

The said Model (*see the figure given below*) is counter machine with maximum capacity of 10kg.



Further, in exercise of the powers conferred by Sub-section (12) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said Model shall also cover the weighing instruments of similar make, accuracy and performance of same series with maximum capacity in the range of 500g to 50kg, manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which, the said approved Model has been manufactured.

[F.No. WM-21 (246)/2001]

P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology

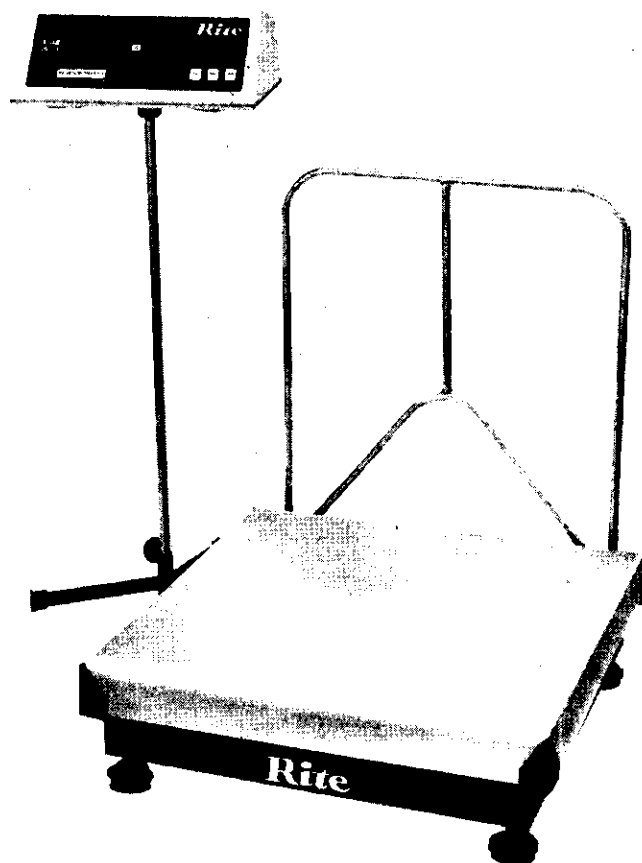
नई दिल्ली, 24 जुलाई, 2003

का.आ. 2183.—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) तथा बाट तथा माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप हैं और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त माडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा ;

अतः अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स एन्कार्डियोराइट इलैक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ए-5 इंडस्ट्रियल एस्टेट, तालकटोरा रोड, लखनऊ-226001 द्वारा विनिर्मित उच्च यथार्थता (यथार्थता वर्ग 2) वाले “स्मार्ट स्कैल 901” शृंखला के स्वतः सूचक, अस्वचालित, अंकक सूचन सहित तोलन उपकरण (प्लेटफार्म प्रकार) के माडल का, जिसमें ब्रांड का नाम “राइट” है (जिसे इसमें इसके पश्चात् मॉडल कहा गया है) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/2002/140 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है।

उक्त मॉडल (आकृति देखें) भार सेल आधारित तोलन उपकरण है इसकी अधिकतम क्षमता 240 कि.ग्रा. और न्यूनतम क्षमता 1 कि.ग्रा. है। सत्यापन मापमान अंतराल (ई) का मान 20 ग्राम है। इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत प्रतिशत व्यवकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है। प्रकाश उत्सर्क डायोड (एल ई डी) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है। उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्टज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है।

सीलिंग : स्टाम्पिंग प्लेट को सील करने के साथ, सीलिंग कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए मशीन खोलने से रोकने के लिए पेंच बिन्दु पर की जाती है।



और, केन्द्रीय सरकार उक्त धारा 36 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त माडल के इस अनुमोदन प्रमाणपत्र के अंतर्गत, उसी शृंखला के उसी मेक, यथार्थता और कार्यपालन वाले ऐसे तोलन उपकरण भी होंगे जिनकी अधिकतम क्षमता 50 कि. ग्राम से अधिक और 500 कि.ग्रा. तक है और जिनका विनिर्माण उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन और उसी सामग्री से किया जाता है जिससे अनुमोदित माडल का विनिर्माण किया गया है, और जिनके सत्यापन मापमान अन्तराल (एन) 2 ग्रा. या अधिक के “ई” मान के लिए 500 से 50,000 की रेंज में है तथा जिनका “ई” मान 1×10^3 , 2×10^3 या 5×10^3 हैं जिसमें ‘के’ धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक है या शून्य के समतुल्य है।

[फा.सं. डब्ल्यू एम-21(15)/99]

‘पी.ए. कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

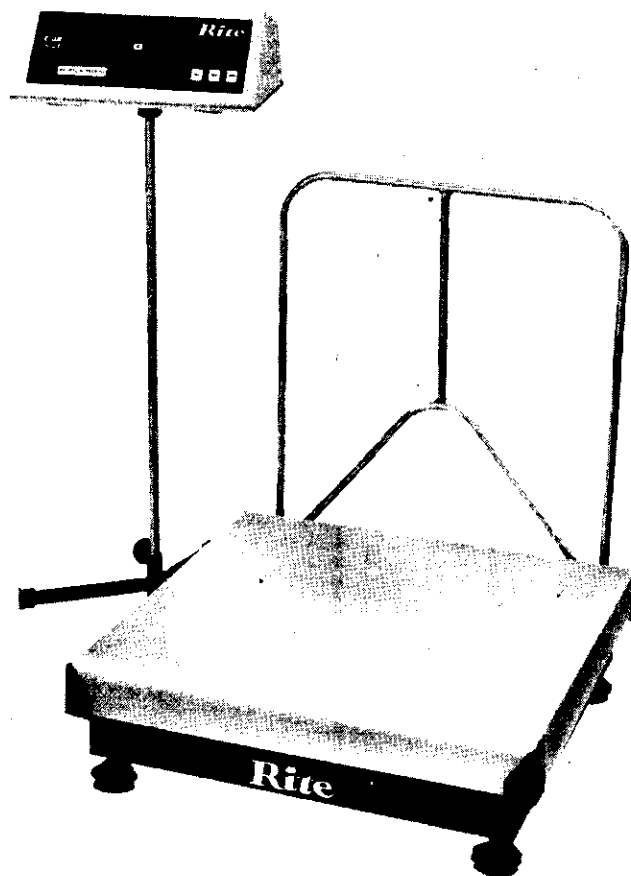
New Delhi, the 24th July, 2003

S.O. 2183.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report (See the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 36 of the said Act, the Central Government hereby publishes the certificate of approval of the Model of the self-indicating, non-automatic, (Platform type) weighing instrument with digital indication of "Smart Scale 901" series of High accuracy (Accuracy class II) and with brand name "Rite" (herein referred to as the Model), manufactured by M/s. Encardio-Rite Electronics Private Ltd, A-5, Industrial Estate, Talkatora Road, Lucknow-226001 and which is assigned the approval mark IND/09/2002/140;

The said Model (see the figure) is a load cell based weighing instrument with a maximum capacity of 240kg and minimum capacity of 1kg. The verification scale interval (e) is 20g. It has a tare device with a 100 percent subtractive retained tare effect. The Light Emitting Diode display indicates the weighing result. The instrument operates on 230 volts and 50-Hertz alternate current power supply.

Sealing : In addition to sealing the stamping plate, sealing shall be done to prevent opening of the machine for fraudulent practices.



Further, in exercise of the powers conferred by sub-section (12) of the said section, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the Model shall also cover the weighing instruments of similar make, accuracy and performance and of same series with maximum capacity in the range of 50kg and upto 500kg and with number of verification scale interval(n) in the range of 500 to 50,000 for 'e' value of 2g or more and with 'e' value 1×10^k , 2×10^k , or 5×10^k , k being the positive or negative whole number or equal to zero, manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which, the approved model has been manufactured.

[F.No. WM-21 (15)/99]

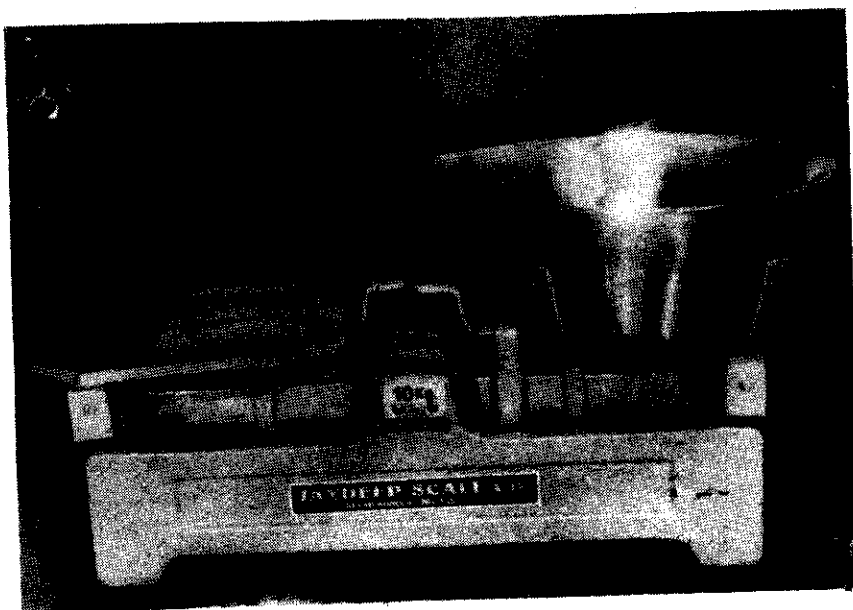
P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 2003

का.आ. 2184.—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित माडल (नीचे दी गई आकृति देखें) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) तथा बाट तथा माप मानक (माडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप हैं और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त माडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा ;

अतः अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स जयदीप स्केल कं. देवला गेट, कृष्णा पोल्टे नं. 5, सावरकुण्डला-364515 (गुजरात) द्वारा विनिर्मित काउंटर मशीन के माडल का, जिसके ब्रांड का नाम "केपशन" है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त माडल कहा गया है) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/2003/39 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है ;

उक्त माडल (आकृति देखें) "काउंटर मशीन" है। इसकी अधिकतम क्षमता 10 कि.ग्रा. है।



और, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त माडल के इस अनुमोदन प्रमाणपत्र के अंतर्गत, उसी शृंखला के उसी मेक, यथार्थता और कार्यपालन वाले ऐसे तोलन उपक्रम भी होंगे जिनकी अधिकतम क्षमता 500 ग्राम से 50 कि.ग्रा. के रेंज में है और जिनका विनिर्माण उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन और उसी सामग्री से किया जाता है जिससे अनुमोदित माडल का विनिर्माण किया गया है।

[फा.सं. डब्ल्यू एम-21(26)/2002]

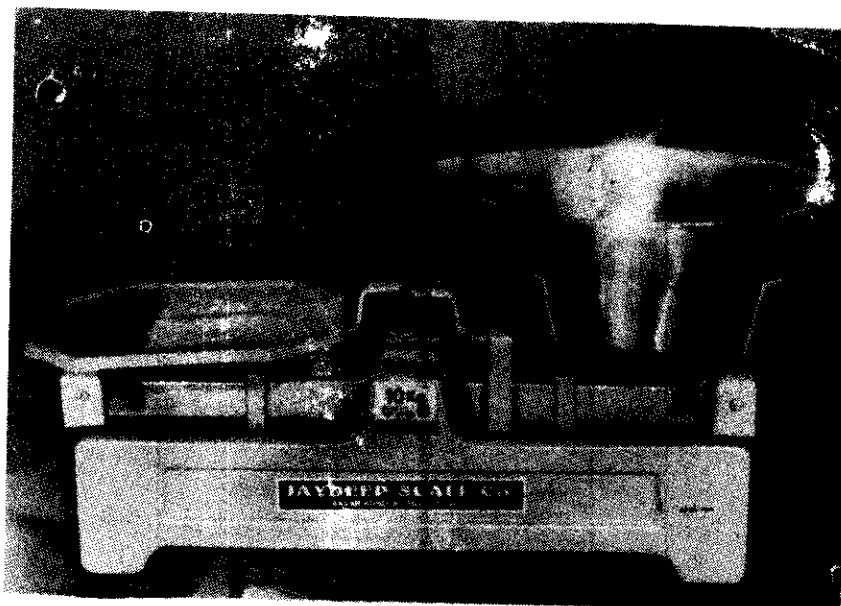
पी.ए. कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 24th July, 2003

S.O. 2184.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (7) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby publishes the certificate of approval of the Model of counter machine (herein referred to as the said Model) with brand name "CAPTION" manufactured by M/s Jaydeep Scale Co., Devla Gate, Krushna Polte, No.5, Savarkundla-364515 (Gujarat) and which is assigned the approval mark IND/09/2003/39:

The said Model (see the figure) is "counter machine". The maximum capacity is 10 kg.



Further, in exercise of the powers conferred by sub-section (12) of the said section, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the Model shall also cover the weighing instruments of similar make, accuracy and performance of same series with maximum capacity in the range of 500g to 50kg, manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which the said approved Model has been manufactured.

[F. No. WM-21 (26)/2002]

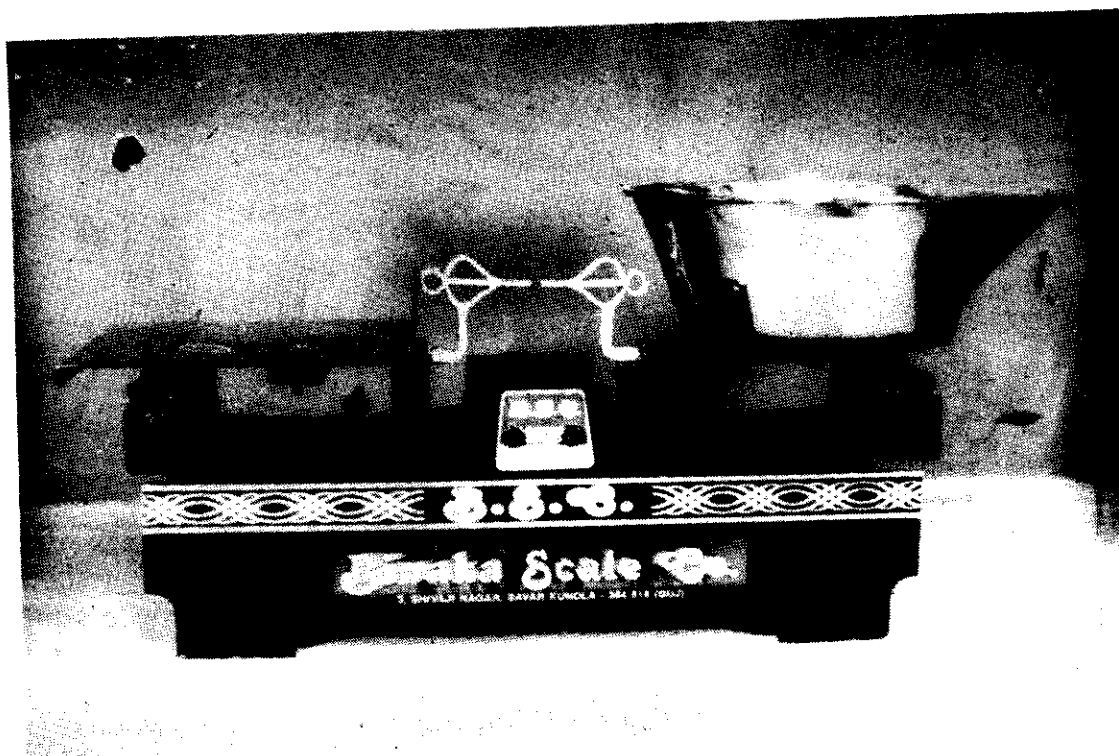
P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 2003

का.आ. 2185.—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित माडल (नीचे दी गई आकृति देखें) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) तथा बाट तथा माप मानक (माडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त माडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) और उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स बिनाका स्केल कंपनी, शिवाजी नगर, सावरकुण्डला-364515 (गुजरात) द्वारा विनिर्मित बी. एस. सी. ब्रांड काउंटर मशीन के माडल का, (जिसे इसमें उक्त माडल कहा गया है) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी 09/2003/85 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है;

उक्त माडल (नीचे दी गई आकृति देखें) दण्ड के सिद्धान्त पर कार्य करने वाली काउंटर मशीन है। इसकी अधिकतम क्षमता 5 कि.ग्रा. है।



और, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त माडल के इस अनुमोदन प्रमाणपत्र के अंतर्गत, उसी श्रृंखला के उसी मेक, यथार्थता और कार्यपालन वाले ऐसे तोलन उपकरण भी होंगे जिनकी अधिकतम क्षमता 500 ग्राम से 50 कि.ग्रा. तक है और जिनका विनिर्माण उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन और उसी सामग्री से किया जाता है जिससे उक्त अनुमोदित माडल का विनिर्माण किया गया है।

[फा.सं. डब्ल्यू एम-21(120)/2002]

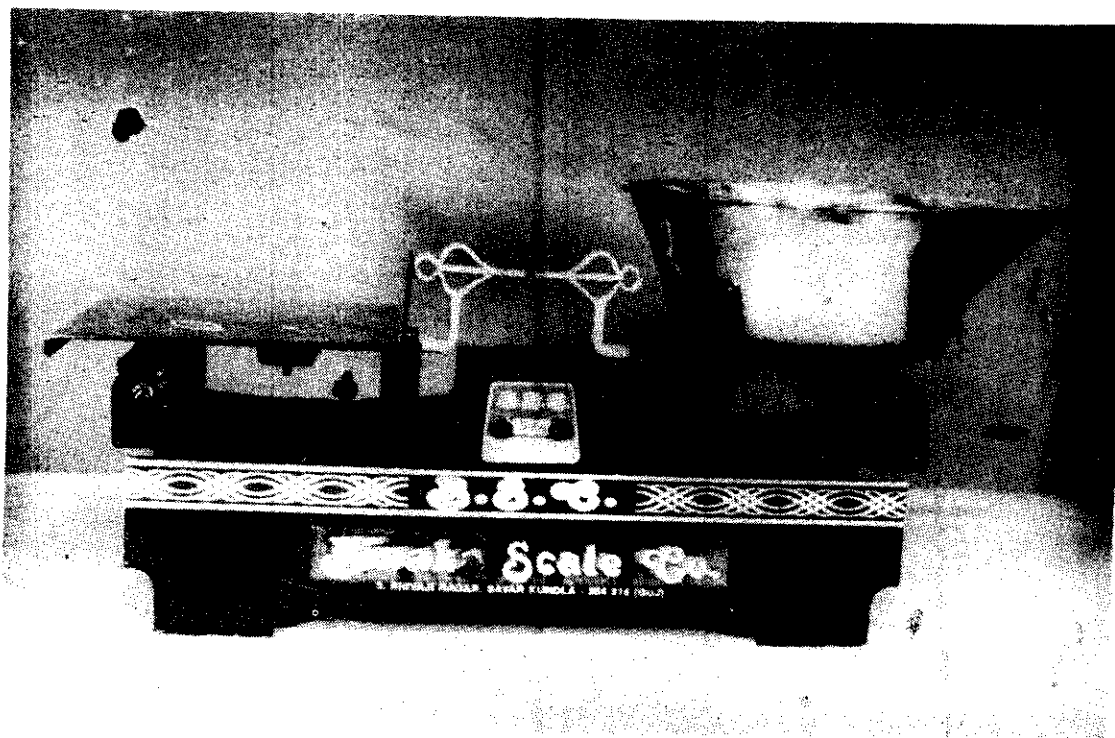
पी.ए. कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 24th July, 2003

S.O. 2185.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (7) and (8) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the Model of counter machine with brand name "BSC" (herein referred to as the said model) manufactured by M/s. Binaka Scale Company, Shivaji Nagar, Savarkundla-364515 (Gujarat) and which is assigned the approval mark IND/09/2003/85;

The said Model (see the figure given below) is counter machine working on the principle of beam with maximum capacity of 5 kg.



Further, in exercise of the powers conferred by sub-section (12) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instruments of similar make, accuracy and performance of same series with maximum capacity from 500 g to 50 kg, manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which, the said approved model has been manufactured.

[F. No. WM-21(120)/2002]

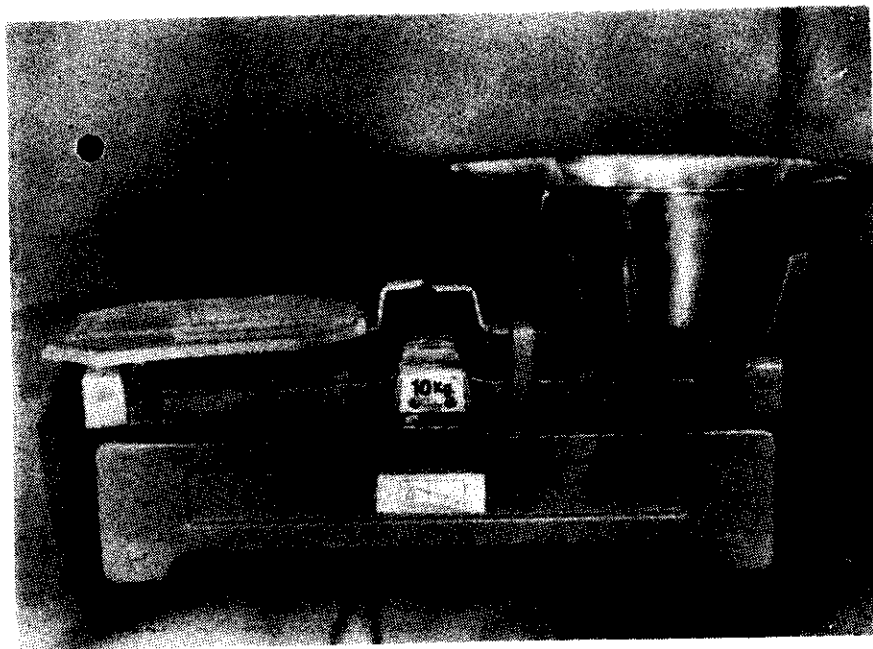
P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 2003

का.आ. 2186.—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित माडल (नीचे दी गई आकृति देखें) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) तथा बाट तथा माप मानक (माडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त माडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा ;

अतः अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) और उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स लुहार जीवा गोपाल एण्ड कं. पटेलवाडी के सामने, शिवाजी नगर, सावरकुण्डला-364515 (गुजरात) द्वारा विनिर्मित काउंटर मशीन के माडल का, जिसके ब्रांड का नाम "जीवा गोपाल एण्ड कं." है (जिसे इसमें उक्त माडल कहा गया है) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/2003/104 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है ;

उक्त माडल (नीचे दी गई आकृति देखें) एक काउंटर मशीन है। इसकी अधिकतम क्षमता 10 कि.ग्रा. है।



और, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त माडल के इस अनुमोदन प्रमाणपत्र के अंतर्गत, उसी श्रृंखला के उसी मेक, यथार्थता और कार्यपालन वाली ऐसी यांत्रिक काउंटर मशीनें भी होंगी जिनकी अधिकतम क्षमता 500 ग्राम से 50 कि.ग्रा. की रेंज में है और जिनका विनिर्माण उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन और उसी सामग्री से किया जाता है जिससे उक्त अनुमोदित माडल का विनिर्माण किया गया है।

[फा.सं. डब्ल्यू एम-21(301)/2002]

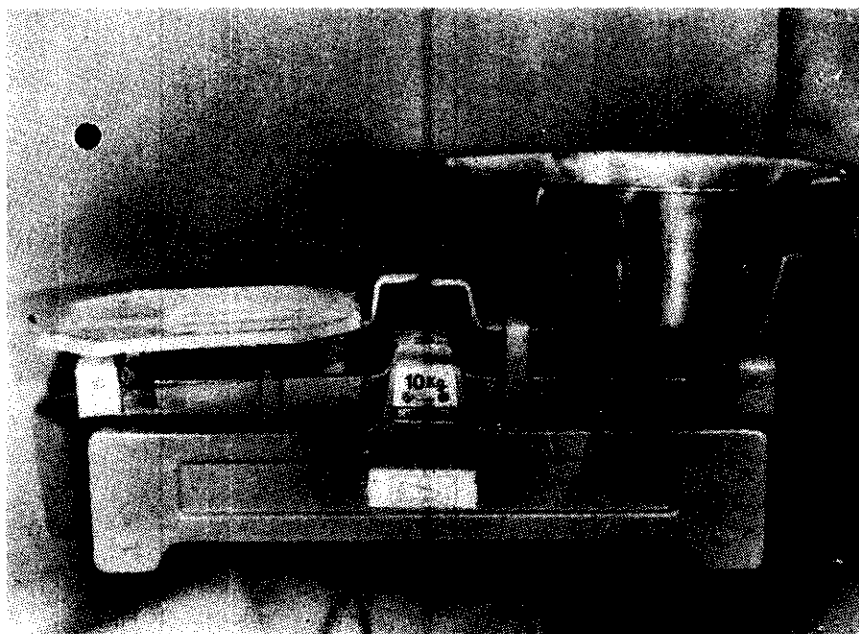
पी.ए. कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 24th July, 2003

S.O. 2186.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Models described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (7) and (8) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the Model of counter machine (herein referred to as the said model) manufactured by M/s. Luhar Jiva Gopal & Co., Opp. Patewadi, Shivaji Nagar, Savarkundla-364515 (Gujarat) with brand name "Jiva Gopal & Co." and which is assigned the approval mark IND/09/2003/104;

The said Model (see the figure given below) is a counter machine with maximum capacity of 10 kg.



Further, in exercise of the powers conferred by sub-section (12) of the Section 36 of the said Act, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the mechanical counter machines of similar make, accuracy and performance of the same series with capacity ranging from 500 g to 50 kg, manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which, the said approved Model has been manufactured.

[F. No. WM-21(301)/2002]

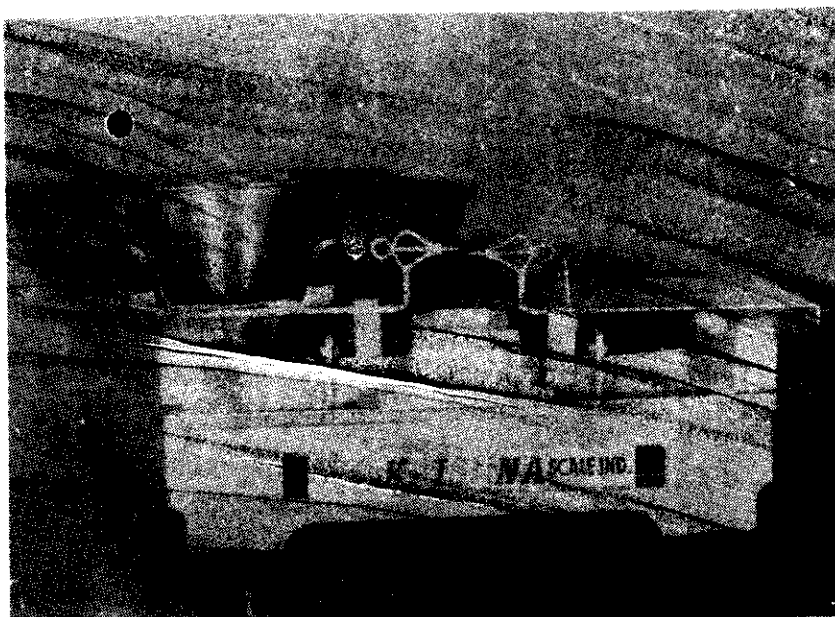
P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 2003

का.आ. 2187.—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित माडल (नीचे दी गई आकृति देखें) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) तथा बाट तथा माप मानक (माडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप हैं और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त माडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा ;

अतः अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स कृष्णा स्केल इंडस्ट्रीज, शिवाजी नगर, सावरकुण्डला (गुजरात) द्वारा विनिर्मित यांत्रिक काउंटर मशीन के माडल का, जिसके ब्रांड का नाम "कृष्णा स्केल इंड." है (जिसे इसमें माडल कहा गया है) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी 09/2003/78 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है;

यह माडल (आकृति देखें) एक काउंटर मशीन है। इसकी अधिकतम क्षमता 10 कि.ग्रा. है।



और, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि माडल के इस अनुमोदन प्रमाणपत्र के अंतर्गत, उसी शृंखला के उसी मेक, यथार्थता और कार्यपालन वाली ऐसी यांत्रिक काउंटर मशीन भी होगी जो 500 ग्राम से 50 कि.ग्रा. की रेंज में है और जिनका विनिर्माण उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन और उसी सामग्री से किया जाता है जिससे अनुमोदित माडल का विनिर्माण किया गया है।

[फा.सं. डब्ल्यू एम-21(310)/2002]

पी.ए. कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 24th July, 2003

S.O. 2187.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Models described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (7) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the Model of mechanical Counter Machine (herein referred to as the Model) with brand name “Krishna Scale Ind.” Manufactured by M/s Krishna Scale Industries, Shivaji Nagar, Savarkundla (Gujarat) and which is assigned the approval mark IND/09/2003/78;

The said Model (see the figure) is a counter machine with maximum capacity is 10 kg.



Further, in exercise of the powers conferred by Sub-section (12) of the said Section 36, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the Model shall also cover the mechanical counter machine of similar make, accuracy and performance with in the range of 500g to 50kg, manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which, the said approved Model has been manufactured.

[F. No. WM-21(310)/2002]

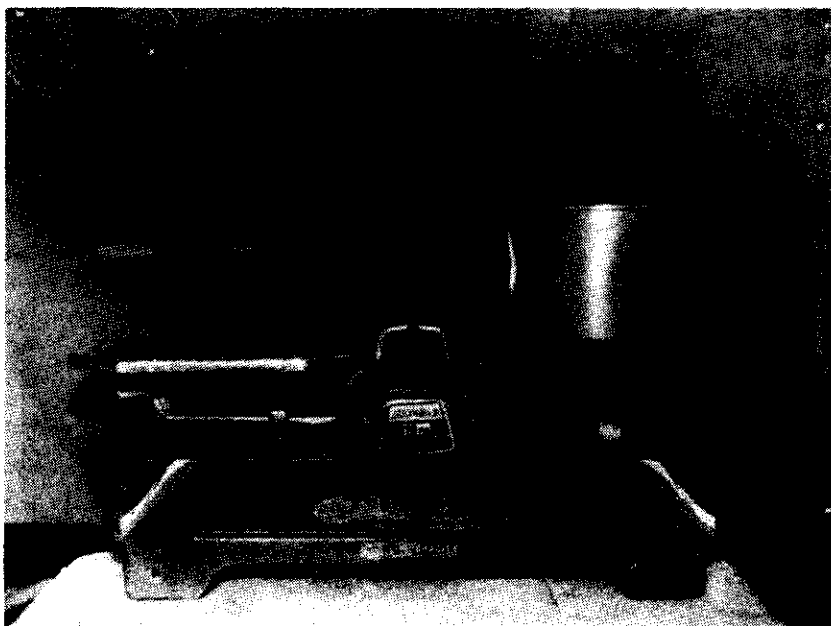
P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 2003

का.आ. 2188.—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित माडल (नीचे दी गई आकृति देखें) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) तथा बाट तथा माप मानक (माडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त माडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा ;

अतः अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) और उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स लुहार नानजी जादवजी एण्ड संस, शिवाजी नगर, सावरकुण्डला-364515 (गुजरात) द्वारा विनिर्मित यांत्रिक काउंटर मशीन के माडल का, जिसके ब्रांड का नाम “एल नानजी जादवजी” है (जिसे इसमें उक्त माडल कहा गया है) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/2003/80 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है;

उक्त माडल (नीचे दी गई आकृति देखें) एक यांत्रिक काउंटर मशीन है। इसकी अधिकतम क्षमता 10 कि.ग्रा. है।



और, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त माडल के इस अनुमोदन प्रमाणपत्र के अंतर्गत, उससे गैर, यथार्थता और कार्यप्रणाली वाली ऐसी तोलन उपकरण भी होंगी जिनकी अधिकतम क्षमता 500 ग्राम से 50 कि.ग्रा. की रेंज में है और जिनका विनिर्माण उसी विनिर्माण द्वारा उसी विद्युत्, डिजाइन और उसी सामग्री से किया जाता है जिससे उक्त अनुमोदित माडल का विनिर्माण किया गया है।

[फा.सं. डब्ल्यू एम-21(18)/2002]

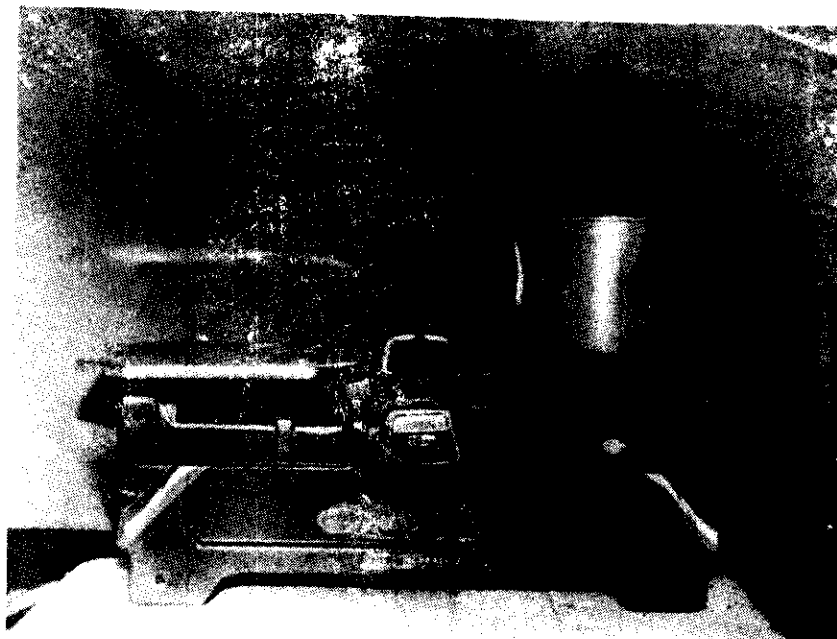
सी. ए. कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 24th July, 2003

S.O. 2188.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Models described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said model is likely to maintain its accuracy over period of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-sections (7) and (8) of section 36 of the said Act, the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the model of mechanical counter machine (herein referred to as the said Model) with brand name 'L. Nanji Jadavji' manufactured by M/s. Luhar Nanji Jadavji & Sons, Shivaji Nagar, Savarkundla-364515 (Gujarat) and which is assigned the approval mark IND/09/2003/80;

The said Model (see the figure given below) is a mechanical counter machine with maximum capacity of 10 kg.



Further, in exercise of the powers conferred by Sub-section (12) of the Section 36 of the said Act, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the mechanical of similar make, accuracy and performance with the maximum capacity in the range of 500 g to 50 kg, manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which, the said approved Model has been manufactured.

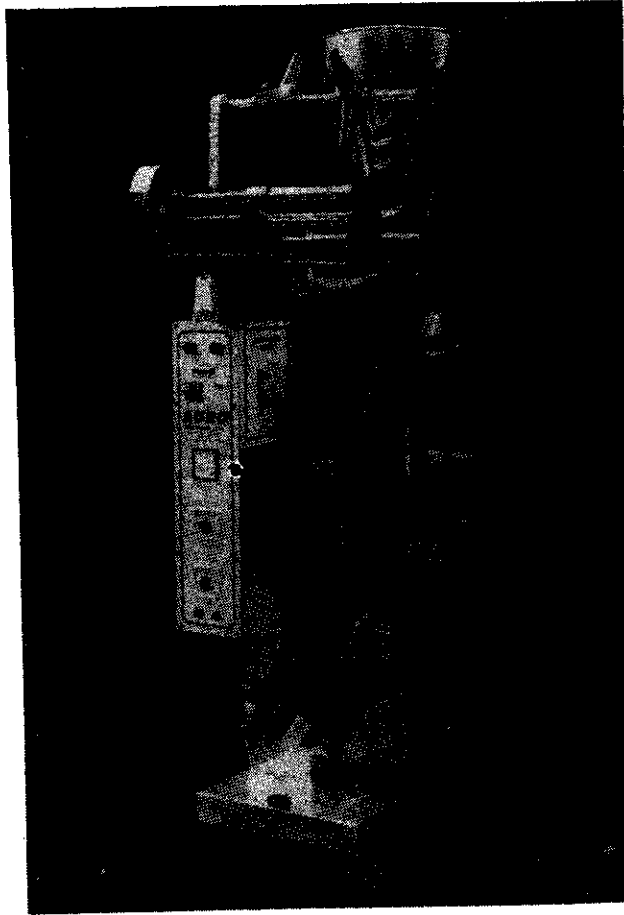
[F. No. WM-21(18)/2002]

P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 2003

का.आ. 2189.—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित माडल (नीचे दी गई आकृति देखें) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) तथा बाट तथा माप मानक (माडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त माडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा ;

अतः अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) और उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स ऑरो मशीन (प्रा.) लि., प्लॉट नं. 405, सैक्टर 23, फरीदाबाद-121005 द्वारा विनिर्मित 'ए एम पी/पी/401/2001' शृंखला की स्वतः भरण मशीन (कप पूरक) के माडल का, जिसके ब्रांड का नाम "ऑरो" है (जिसे इसमें उक्त माडल कहा गया है) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/03/90 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है।



उक्त माडल एक स्वतः भरण मशीन (कप पूरक) है। इसकी अधिकतम क्षमता 500 ग्रा. और न्यूनतम क्षमता 20 ग्रा. या समतुल्य परिमाण है। इस मशीन को मुक्त प्रवाह वाले श्यानता हीन द्रव उत्पादों जैसे दुग्ध चूर्ण, कॉफी, चाय चूर्ण और नमक को भरने के लिए डिजाइन किया गया है। यह 45 पूर्ण प्रति मिनट भर सकती है और यह 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करती है।

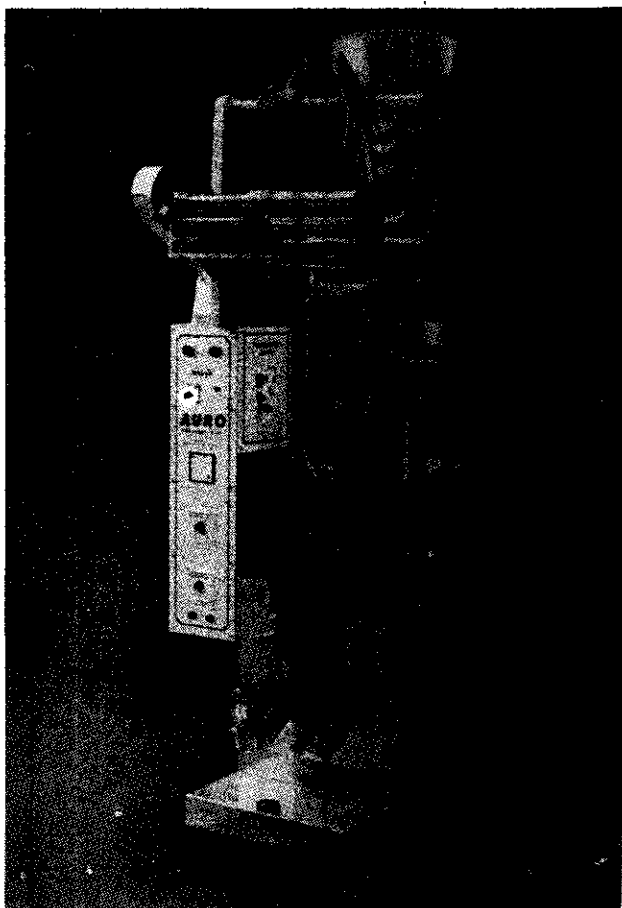
[फा.सं. डब्ल्यू एम-21(85)/2001]

पी.ए. कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 24th July, 2003

S.O. 2189.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Models described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over period of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (7) and (8) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the Model of automatic filling machine (Cup Filler) of 'AMP/P/401/2001' series with brand name "Auro" (herein referred to as the said model), manufactured by M/s. Auro Machine (P) Ltd., Plot No. 405, Sector 23, Faridabad-121005 and which is assigned the approval mark IND/09/03/90;



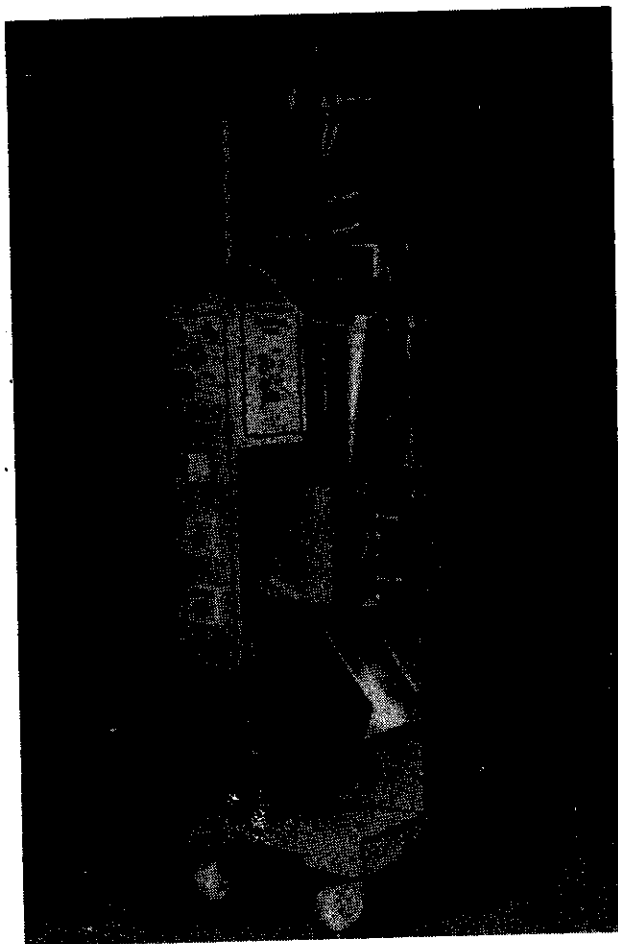
The said Model is an automatic filling machine (Cup Filler). Its maximum capacity is 500g and minimum capacity is 20g or equivalent volume. The machine is designed for filling non-free flowing products such as milk powder, coffee, tea powder and salt. It can fill 45 fills per minute and it operates on 230 Volts and 50 Hz alternate current powder supply.

[F. No. WM-21 (85)/2001]
P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 2003

का.आ. 2190.—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित माडल (नीचे दी गई आकृति देखें) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) तथा बाट तथा माप मानक (माडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त माडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा :

अतः अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) और उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स ऑरो मशीन (प्रा.) लि., प्लॉट नं. 405, सैक्टर 23, फरीदाबाद-121005 द्वारा विनिर्मित "ए एम पी/एल/201/2001" श्रृंखला की स्वतः भरण मशीन (पिस्टन पूरक) के माडल का, जिसके ब्रांड का नाम "ऑरो" है (जिसे इसमें उक्त माडल कहा गया है) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी 09/03/91 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है।



उक्त माडल एक स्वतः भरण मशीन (पिस्टन पूरक) है। इसकी अधिकतम क्षमता 200 ग्रा. और न्यूनतम क्षमता 5 ग्रा. या समतुल्य परिमाण है। इस मशीन को मुक्त प्रवाह वाले उत्पादों जैसे जल, कैचप, तेल 2 टी आइल आदि को भरने के लिए डिजाइन किया गया है। यह 45 पूरण प्रति मिनट भर सकती है और यह 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करती है।

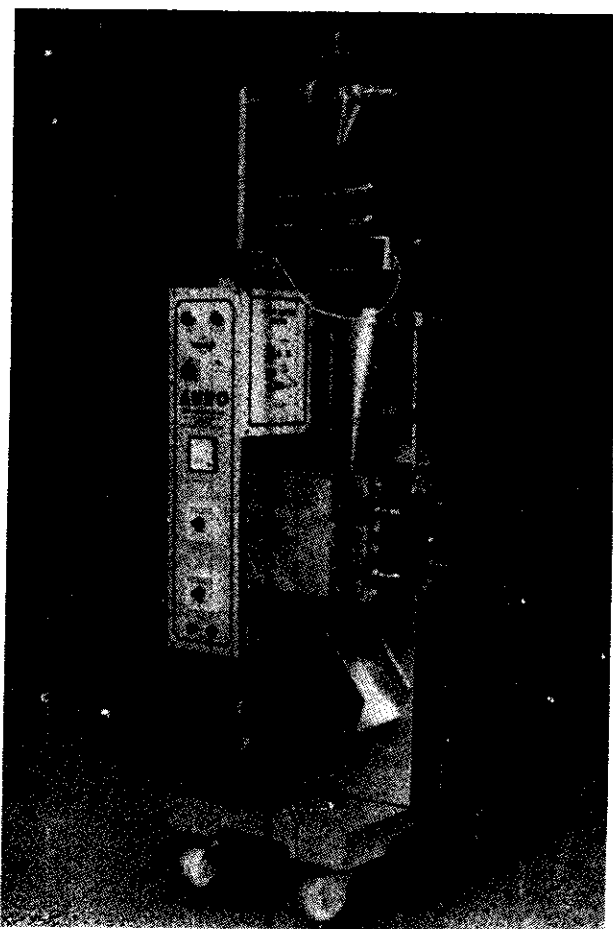
[फा.सं. डब्ल्यू एम-21(85)/2001]

पी. ए. कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 24th July, 2003

S.O. 2190.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Models described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over period of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (7) and (8) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the Model of automatic filling machine (Piston Filler) of 'AMP/L/201/2001' series with brand name "Auro" (herein referred to as the said model), manufactured by M/s. Auro Machine (P) Ltd., Plot No. 405, Sector 23, Faridabad-121005 and which is assigned the approval mark IND/09/03/91;



The said Model is an automatic filling machine (Piston Filler). Its maximum capacity is 200g and minimum capacity is 5 g or equivalent volume. The machine is designed for filling free flowing products such as water, ketchup, shampoo, oil, 2 T oil etc. It can fill 45 fills per minute and it operates on 230 Volts and 50 Hz alternate current power supply.

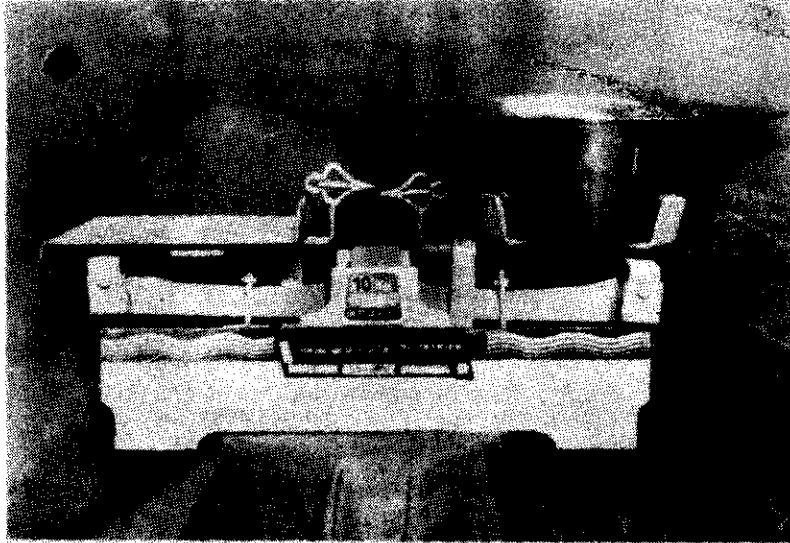
[F. No. WM-21(85)/2001]
P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 2003

का.आ. 2191.—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित माडल (नीचे दी गई आकृति देखें) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) तथा बाट तथा माप मानक (माडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त माडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा :

अतः अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) और उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स ग्रेविटी इंडस्ट्रीज, अमरेली रोड, सावरकुण्डला-364515 (गुजरात) द्वारा विनिर्मित काउंटर मशीन के माडल का, जिसके ब्रांड का नाम "ग्रेविटी इंडस्ट्रीज" है (जिसे इसमें उक्त माडल कहा गया है) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी 09/2003/34 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है।

उक्त माडल (नीचे दी गई आकृति देखें) एक काउंटर मशीन है। इसकी अधिकतम क्षमता 10 कि. ग्रा. है।



और, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त माडल के इस अनुमोदन प्रमाणपत्र के अंतर्गत, उसी श्रृंखला के उसी मेक, यथार्थता और कार्यपालन वाले ऐसे तोलन उपकरण भी होंगे जिनकी अधिकतम क्षमता 500 ग्रा. से 50 कि. ग्रा. की रेंज में है और जिनका विनिर्माण उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन और उसी सामग्री से किया जाता है जिससे अनुमोदित माडल का विनिर्माण किया गया है।

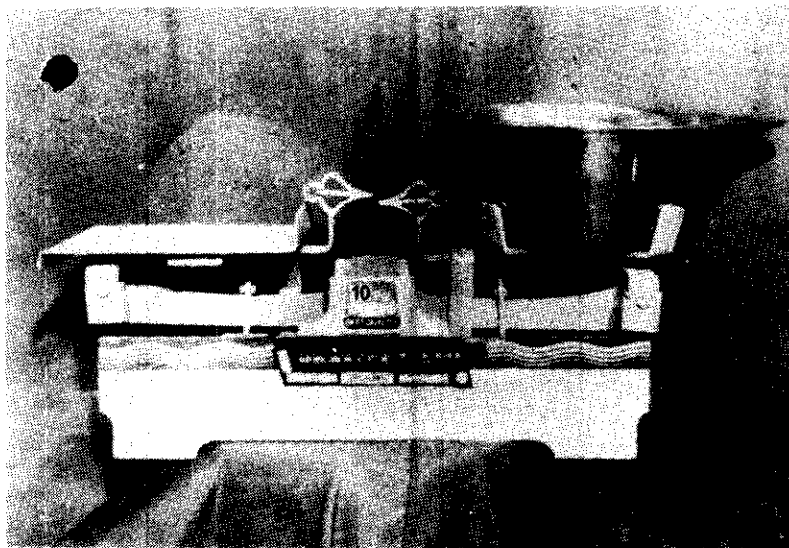
[फा. सं. डब्ल्यू एम-21(182)/2001]
पी. ए. कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 24th July, 2003

S.O. 2191.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Models described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over period of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (7) and (8) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the Model of counter machine (herein referred to as the said model) with brand name 'GRAVITY INDUSTRIES', manufactured by M/s. Gravity Industries, Anreli Road, Savarkundla-364515 (Gujarat) and which is assigned the approval mark IND/09/2003/34:

The said Model (See the figure given below) is a counter machine. The maximum capacity is 10 Kg.



Further, in exercise of the powers conferred by sub-section (12) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instruments of similar make, accuracy and performance of same series with maximum capacity in the range of 500 g to 50 kg, manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which, the approved model has been manufactured.

[F. No. WM-21(182)/2001]

P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 2003

का.आ. 2192.—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित माडल (नीचे दी गई आकृति देखें) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) तथा बाट तथा माप मानक (माडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त माडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा ;

अतः अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स सावरकुण्डला स्केल, शिवाजी नगर, सावरकुण्डला-364515 (गुजरात) द्वारा विनिर्मित काउंटर मशीन के माडल का, जिसके ब्रांड का नाम "सावरकुण्डला स्केल" है (जिसे इसमें उक्त माडल कहा गया है) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/2003/77 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है।

उक्त माडल (नीचे दी गई आकृति देखें) एक काउंटर मशीन है। इसकी अधिकतम क्षमता 10 कि. ग्रा. है।



और, केन्द्रीय सरकार उक्त धारा की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त माडल के इस अनुमोदन प्रमाणपत्र के अंतर्गत, उसी मेक, यथार्थता और कार्यपालन वाले ऐसे तोलन उपकरण भी होंगे जो 500 ग्रा. से 50 कि. ग्रा. की रेंज में हैं और जिनका विनिर्माण उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन और उसी सामग्री से किया जाता है जिससे अनुमोदित माडल का विनिर्माण किया गया है।

[का.सं. डब्ल्यू एम-21(14)/2002]

पी. ए. कुण्डामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 24th July, 2003

S.O. 2192.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Models described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976(60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions :

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 36 of the said Act, the Central Government hereby publishes the certificate of approval of the Model of counter machine (herein referred to as the said model), with brand name 'Savarkundla Scale', manufactured by M/s. Savarkundla Scale, Shivaji Nagar, Savarkundla-364515 (Gujarat) and which is assigned the approval mark IND/09/2003/77.

The said Model (See the figure) is a counter machine with maximum capacity of 10 Kg.



Further, in exercise of the powers conferred by sub-section (12) of the said section, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instruments of similar make, accuracy and performance in the range of 500 g to 50 kg, manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which, the said approved model has been manufactured.

[F.No. WM-21(14)/2002]

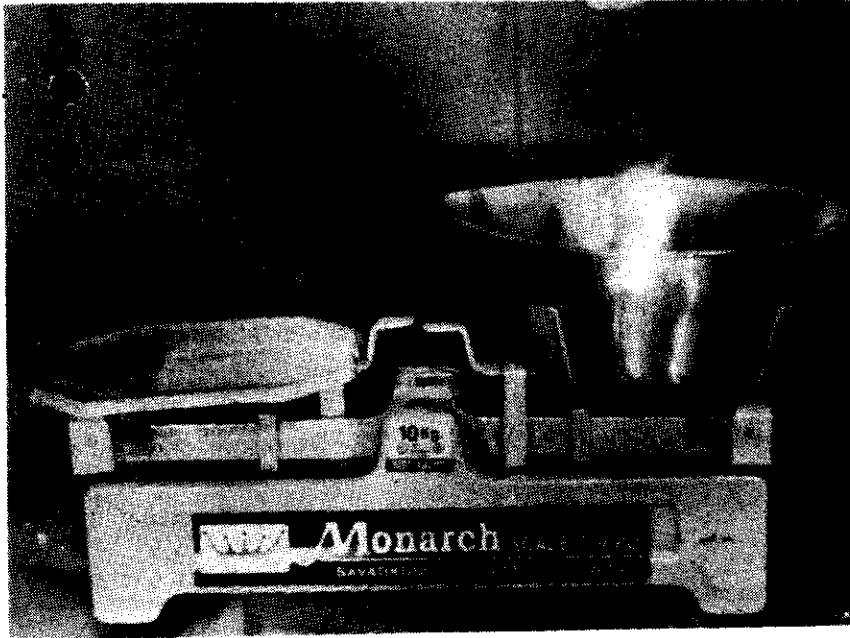
P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 2003

का.आ. 2193.—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित माडल (नीचे दी गई आकृति देखें) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) तथा बाट तथा माप मानक (माडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त माडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स मोनार्क स्केल कारपोरेशन, शिवाजी नगर, पटेल वाड़ी के सामने, सावरकुण्डला-364515 (गुजरात) द्वारा विनिर्मित काउंटर मशीन के माडल का, जिसके ब्रांड का नाम "मोनार्क" है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त माडल कहा गया है) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी 09/2003/23 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है;

उक्त माडल (आकृति देखें) काउंटर मशीन है। इसकी अधिकतम क्षमता 10 कि. ग्रा. है।



और, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त माडल के इस अनुमोदन प्रमाणपत्र के अंतर्गत, उसी शृंखला के उसी मेक, यथार्थता और कार्यपालन वाले ऐसे तोलन उपकरण भी होंगे जो जिनकी अधिकतम क्षमता 500 ग्रा. से 50 कि. ग्रा. की रेंज में है और जिनका विनिर्माण उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन और उसी सामग्री से किया जाता है जिससे अनुमोदित माडल का विनिर्माण किया गया है।

[फा.सं. डब्ल्यू एम-21(248)/2001]

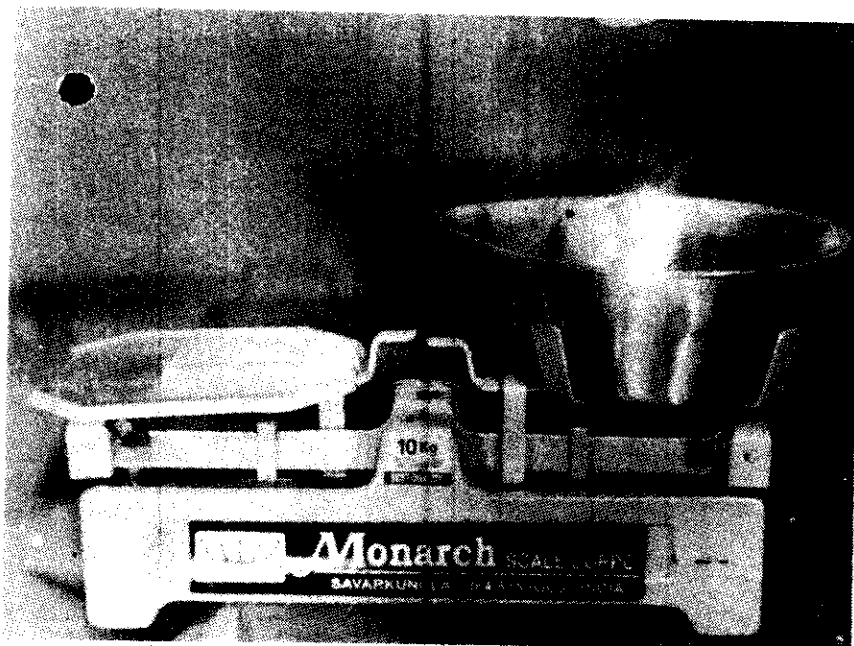
पी. ए. कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 24th July, 2003

S.O. 2193.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Models described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976(60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (7) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby publishes the certificate of approval of the Model of counter machine (herein referred to as the said Model), with brand name 'MONARCH', manufactured by M/s. Monarch Scale Corporation, Shivaji Nagar, Opp. Patel Wadi, Savarkundla-364515 (Gujarat) and which is assigned the approval mark IND/09/2003/23;

The said Model (See the figure) is "counter machine". The maximum capacity is 10 Kg.



Further, in exercise of the power conferred by sub-section (12) of the said Section, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said Model shall also cover the weighing instruments of similar make, accuracy and performance of same series within the range of 500 g to 50 kg, manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which, the approved Model has been manufactured.

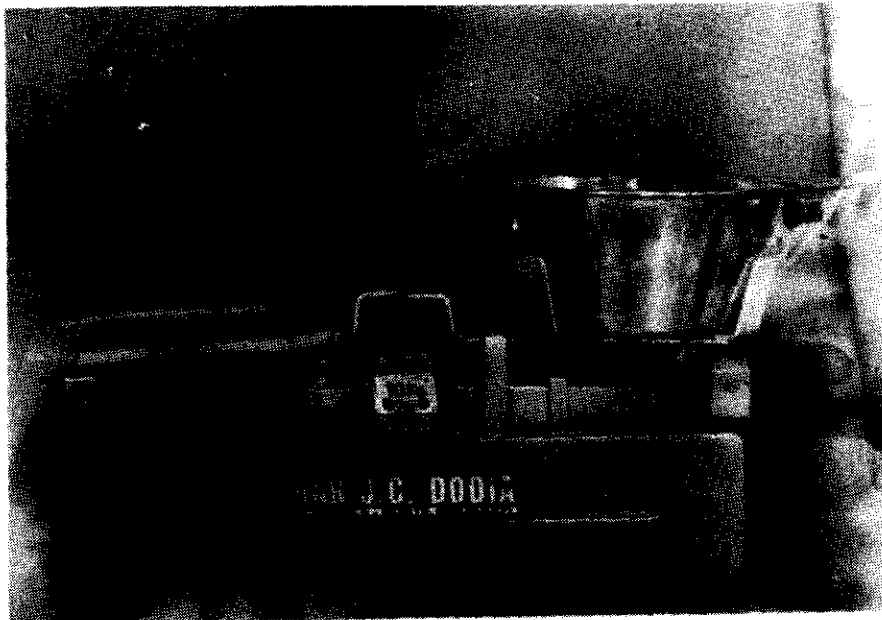
[F. No. WM-21(248)/2001]
P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 2003

का.आ. 2194.—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित माडल (नीचे दी गई आकृति देखें) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) तथा बाट तथा माप मानक (माडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त माडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा ;

अतः अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स लुहार जे. सी. डोडिया, आजाद चौक, सावरकुण्डला-364515 (गुजरात) द्वारा विनिर्मित एल. जे. सी. डोडिया ब्रान्ड काउंटर मशीन के माडल का (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त माडल कहा गया है) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी 09/2003/36 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है ;

उक्त माडल (आकृति देखें) काउंटर मशीन है जो बीम के सिद्धान्त पर कार्य करती है। इसकी अधिकतम क्षमता 10 कि. ग्रा. है।



और, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त माडल के इस अनुमोदन प्रमाणपत्र के अंतर्गत, उसी शृंखला के उसी मेक, यथार्थता और कार्यपालन वाले ऐसे तोलन उपकरण भी होंगे जिनकी अधिकतम क्षमता 500 ग्रा. से 50 कि. ग्रा. की रेंज में है और जिनका विनिर्माण उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन और उसी सामग्री से किया जाता है जिससे अनुमोदित माडल का विनिर्माण किया गया है।

[फा.सं. डब्ल्यू एम-21(236)/2001]
पी. ए. कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 24th July, 2003

S.O. 2194.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Models described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (8) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby publishes the certificate of approval of the Model of counter machine with the brand name L. J. C. DODIYA (herein referred to as the said model), manufactured by M/s. Luhar J. C. Dodia, Azad Chowk, Savarkundla-364515 (Gujarat) and which is assigned the approval mark IND/09/2003/66;

The said Model (see the figure) is a counter machine working on the principle of beam with maximum capacity of 10 kg.



Further, in exercise of the power conferred by sub-section (12) of the said Section, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said Model shall also cover the weighing instruments of similar make, accuracy and performance of same series with maximum capacity in the range of 500 g to 50 kg, manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which the approved Model has been manufactured.

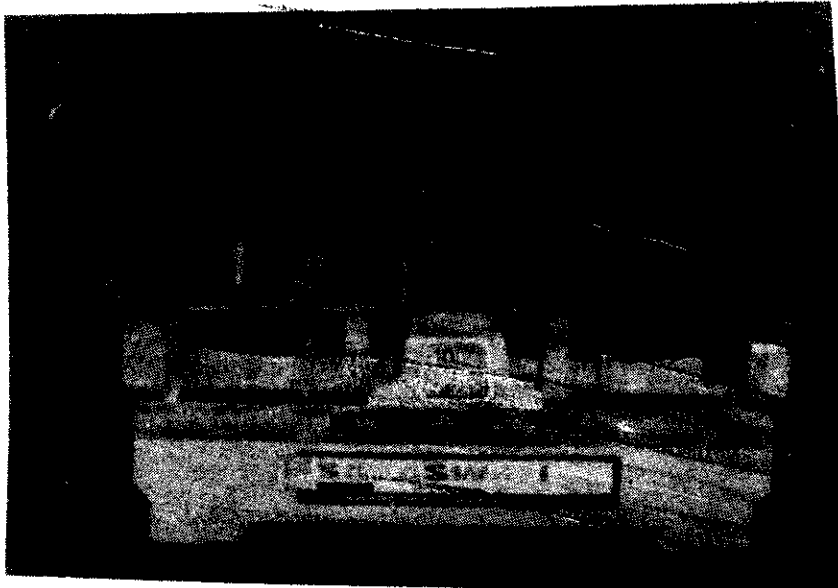
[F. No. WM-21(236)/2001]
P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 2003

का.आ. 2195.—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित माडल (नीचे दी गई आकृति देखें) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) तथा बाट तथा माप मानक (माडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त माडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा ;

अतः अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) और उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स सरस्वती स्केल, पनियल टंकी के पास, परेवा घर रोड, सावरकुण्डला-364515 (गुजरात) द्वारा विनिर्मित काउंटर मशीन के माडल का, जिसके ब्रांड का नाम "सरस्वती स्केल" है (जिसे इसमें उक्त माडल कहा गया है) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी 09/2003/50 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है ;

उक्त माडल (नीचे दी गई आकृति देखें) एक काउंटर मशीन है। इसकी अधिकतम क्षमता 10 कि. ग्रा. है।



और, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त माडल के इस अनुमोदन प्रमाणपत्र के अंतर्गत, उसी शृंखला के उसी मेक, यथार्थता और कार्यपालन वाले ऐसे तोलन उपकरण भी होंगे जिनकी अधिकतम क्षमता 500 ग्रा. से 50 कि. ग्रा. तक है और जिनका विनिर्माण उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन और उसी सामग्री से किया जाता है जिससे अनुमोदित माडल का विनिर्माण किया गया है।

[फा.सं. डब्ल्यू एम-21(244)/2001]

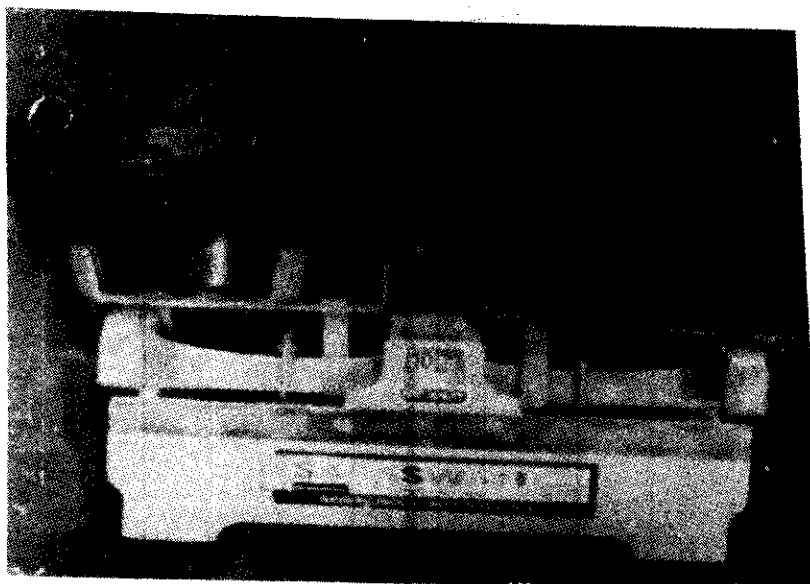
पी. ए. कृष्णामूर्ति, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 24th July, 2003

S.O. 2195.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Models described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (7) and (8) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the Model of counter machine with brand name "SARASWATI SCALE" (herein referred to as the said model), manufactured by M/s. Saraswati Scale, Near Panjal Tanki, Parewa Ghar Road, Savarkundla-364515 (Gujarat) and which is assigned the approval mark IND/09/2003/50.

The said Model (see the figure given below) is a counter machine with maximum capacity of 10 kg.



Further, in exercise of the power conferred by sub-section (12) of Section 36 of said Act, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the model shall also cover the weighing instruments of similar make, accuracy and performance of same series with maximum capacity from 500 g to 50 kg, manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which the said approved model has been manufactured.

[F.No. WM-21(244)/2001]
P. A. KRISHNAMOORTHY, Director of Legal Metrology

कोयला मंत्रालय

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2003

का. आ. 2196 .— केन्द्रीय सरकार ने कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 11 जनवरी, 2003 में पृष्ठ 157 से 159 पर प्रकाशित भारत सरकार के कोयला और खान मंत्रालय (कोयला विभाग) की अधिसूचना सं. का. आ. 79, तारीख 3 जनवरी, 2003 द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र की भूमि में, जिसका माप 210.00 हेक्टर (लगभग) या 518.91 एकड़ (लगभग) है, कोयले का पूर्वक्षण करने के अपने आशय की सूचना दी थी ;

और केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है, कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूचियों में वर्णित उक्त भूमि के भाग में कोयला अभिप्राप्य है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित का अर्जन करने के अपने आशय की सूचना देती है -

- (क) इससे संलग्न अनुसूची "क" में वर्णित 186.00 हेक्टर (लगभग) या 459.61 एकड़ (लगभग) माप वाली भूमि में या उस पर के सभी अधिकार ;
- (ख) इससे संलग्न अनुसूची 'ख' में वर्णित 15.25 हेक्टर (लगभग) या 37.68 एकड़ (लगभग) माप वाली भूमि में खनिजों के खनन, खदान करने, बोर करने, खुदाई करने और तलाश करने, प्राप्त करने, उन पर कार्य करने और खनिजों को ले जाने के अधिकार ;

टिप्पणी 1 :- इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के रेखांक सं. सी-1 (ई) /III/जेजेएमआर/706-0403, तारीख 4 अप्रैल, 2003 का निरीक्षण, कलेक्टर, चन्द्रपुर (महाराष्ट्र) के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कोलकाता - 700 001 के कार्यालय में या वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, (राजस्व विभाग) कोल इस्टेट, सिविल लाईन्स, नागपुर - 440 001 (महाराष्ट्र) के कार्यालय में किया जा सकता है ।

टिप्पणी 2 :- पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 8 के उपबंधों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसमें निम्नलिखित उपबंध है :-

“अर्जन की बाबत आपत्तियां :-

- 8(1) कोई व्यक्ति जो किसी भूमि में जिसकी बाबत धारा 7 के अधीन अधिसूचना निकाली गई है, हितबद्ध है, अधिसूचना के निकाले जाने से तीस दिन के भीतर सम्पूर्ण भूमि या उसके किसी भाग या ऐसी भूमि में या उस पर के किन्हीं अधिकारों का अर्जन किए जाने के बारे में आपत्ति कर सकेगा ।

स्पष्टीकरण - इस धारा के अर्थान्तर्गत यह आपत्ति नहीं मानी जाएगी कि कोई व्यक्ति किसी भूमि में कोयला उत्पादन के लिए स्वयं खनन संक्रियाएं करना चाहता है और ऐसी संक्रियाएं केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए ।

- (2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी को लिखित रूप में दी जाएगी और सक्षम प्राधिकारी आपत्तिकर्ता को स्वयं सुने जाने का या विधि व्यवसायी द्वारा सुनवाई का अवसर देगा और ऐसी सभी आपत्तियों को सुनने के पश्चात् और ऐसी अतिरिक्त जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझता है, वह या तो धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित भूमि के या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के संबंध में एक रिपोर्ट या ऐसी भूमि के विभिन्न टुकड़ों या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के संबंध में आपत्तियों पर अपनी सिफारिशों और उसके द्वारा की गई कार्यवाही के अभिलेख सहित विभिन्न रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को उसके विनिश्चय के लिए देगा ।

- (3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए वह व्यक्ति किसी भूमि में हितबद्ध समझा जाएगा जो प्रतिकर में हित का दावा करने का हकदार होता यदि भूमि या किसी ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकार इस अधिनियम के अधीन अर्जित कर लिए जाते हैं । ”

टिप्पणी 3 :- केन्द्रीय सरकार ने कोयला नियंत्रक, 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कोलकाता को भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड स(ii) तारीख 11 जून, 1983 में प्रकाशित अधिसूचना सं. का.आ. 2519, तारीख 27 मई, 1983 द्वारा उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया है ।

अनुसूची "क"
जूना कुनाडा ओ/सी खंड
माजरी क्षेत्र
जिला चंद्रपुर (महाराष्ट्र)

(रेखांक सं.सी - 1 (ई) / III / जेजेएमआर/706-0403 तारीख 4 अप्रैल, 2003)

सभी अधिकार:

क्रम सं.	ग्राम का नाम	पटवारी सर्किल संख्या	तहसील	जिला	क्षेत्र हेक्टर में	टिप्पणी
1	कुनाडा	28	भद्रावती	चंद्रपुर	186.00	भाग

कुल क्षेत्र:- 186.00 हेक्टर (लगभग)

या

459.61 एकड (लगभग)

ग्राम कुनाडा में अर्जित किए जाने वाले प्लॉट संख्यांक:

1/1- 1/2- 1/3- 1/4, 2 से 11, 12/1- 12/2- 12/3- 12/4, 13/1क, 13/1ख, 13/2, 13/3, 14/1- 14/2- 14/3, 15, 16, 17/1, 17/2, 18, 19, 20/1, 20/2, 20/3, 21 से 28, 29/1, 29/2, 29/3, 30/1, 30/2, 30/3, 31 से 48, 49/1, 49/2, 50/1- 50/2, 51/1, 51/2, 51/3, 52 से 55, 66/4, 71, 72/1क, 72/1ख, 72/2क, 72/2ख, 72/3- 72/4, 73, 74 भाग, 75/1- 75/2, 76/1- 76/2 भाग, 78 से 82, 83/1, 83/2, 84, 85, 86/1- 86/2- 86/3, 87/1- 87/2, 88 से 91, 92/1, 92/2, 92/3, 93/1, 93/2, 94/1- 94/2, 95, 96, 97/1, 97/2, 98 से 102, 103/1- 103/2, 104 से 107, 108/1, 108/2, 109/1 भाग, 109/2, 114, 115, 132/1- 132/2- 132/3 भाग, 232/1, 232/2, 234/1- 234/2, 236, 237, 238/1- 238/2, 239 से 248, 249 भाग, 250 भाग, 251 से 254, 259, 260, 273, 276 से 281, सड़क, पुरानी आबादी, नाला भाग ।

सीमा वर्णन:

क - ख: रेखा बिन्दु "क" से आरम्भ होती है और ग्राम कुनाडा से होकर जाती है और प्लॉट संख्यांक 55, 54, 53, 52, 51/3, 51/2, 51/1, 50/1- 50/2, 49/2, 49/1, 48, 47, 46, सड़क, प्लॉट संख्या 45, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 29/1, 29/2, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20/2, 20/1, 13/1ख, 279, 13/1क, 10, 9, 1/1- 1/2- 1/3- 1/4, 240, 239, 238/1- 238/2, 259, 260, 236 की बाहरी सीमा के साथ तथा वर्धा नदी के उत्तरी और पूर्वी किनारों के साथ-साथ होती हुई जाती है और बिन्दु "ख" पर मिलती है ।

- ख - ग: रेखा ग्राम कुनाडा से होकर जाती है और प्लॉट संख्यांक 236, 237, 234/1-234/2, 232/2, नाला की बाहरी सीमा के साथ जाती है और बिन्दु "ग" पर मिलती है।
- ग - क: रेखा ग्राम कुनाडा से होकर जाती है, नाला पार करती है, फिर प्लॉट संख्यांक 249, 250, 132/1- 132/2- 132/3 में से होकर जाती है और प्लॉट संख्यांक 109/1 की बाहरी सीमा के साथ फिर प्लॉट संख्यांक 109/1 में से होती हुई जाती है और प्लॉट संख्यांक 102, 273, 98, 114, 115, 71 की बाहरी सीमा के साथ जाती है, फिर प्लॉट संख्यांक 74, 76/1- 76/2 में से होकर जाती है और प्लॉट संख्यांक 76/1- 76/2, सड़क, प्लॉट संख्यांक 66/4, 54, 55 की बाहरी सीमा के साथ जाती है और आरंभिक बिन्दु "क" पर मिलती है।

अनुसूची "ख"

जूना कुनाडा ओ/सी खंड
माजरी क्षेत्र
जिला चंद्रपुर (महाराष्ट्र)

(रेखांक सं.सी - I (ई) / III / जेजेएमआर/706-0403 तारीख 4 अप्रैल, 2003)

खनन अधिकार:

क्रम सं.	ग्राम का नाम	पटवारी सर्किल संख्या	तहसील	जिला	क्षेत्र हेक्टर में	टिप्पणी
1	कुनाडा	28	भद्रावती	चंद्रपुर	15.25	भाग

कुल क्षेत्र:- 15.25 हेक्टर (लगभग)

या

37.68 एकड़ (लगभग)

ग्राम कुनाडा में अर्जित किए जाने वाले प्लॉट संख्यांक:

186 से 188, 193/1 भाग, 193/2, 228 से 231, 233, 235, 283, 284, सड़क भाग।

सीमा वर्णन:

- ख - ग: रेखा बिन्दु 'ख' से आरम्भ होती है और ग्राम कुनाडा से होकर जाती है और प्लॉट संख्यांक 235, 233, 284, 283 की बाहरी सीमा के साथ जाती है, सड़क पार करती है और प्लॉट संख्यांक 187, 186 की बाहरी सीमा के साथ जाती है और बिन्दु "ग" पर मिलती है।

- ग - घ: रेखा ग्राम कुनाड़ा से होकर जाती है और प्लॉट संख्यांक 186, 188, 193/2, 193/1 की बाहरी सीमा के साथ जाती है, प्लॉट संख्यांक 193/1 में से होकर और सड़क की बाहरी सीमा के साथ जाती है और बिन्दु "घ" पर मिलती है।
- घ - ड: रेखा ग्राम कुनाड़ा से होकर जाती है, सड़क पार करती है और सड़क की बाहरी सीमा, प्लॉट संख्यांक 283, 284, 228 की बाहरी सीमा के साथ जाती है और बिन्दु "ड" पर मिलती है।
- ड - ख: रेखा ग्राम कुनाड़ा से होकर जाती है और प्लॉट संख्यांक 228, 231, 233, 235 की बाहरी सीमा के साथ जाती है और आरंभिक बिन्दु 'ख' पर मिलती है।

[फा. सं. -43015/8/2002-पी.आर.आई. डब्ल्यू.]

संजय बहादुर, उप सचिव

MINISTRY OF COAL

New Delhi, the 29th July, 2003

S. O. 2196.— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Coal and Mines (Department of Coal) number S.O. 79 dated the 3rd January, 2003, issued under sub-section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) (hereinafter referred to as the said Act) and published in Part II, Section 3, Sub-section (ii) of the Gazette of India, dated the 11th January, 2003 at pages 157 to 159, the Central Government gave notice of its intention to prospect for coal in 210.00 hectares (approximately) or 518.91 acres (approximately) of the lands in the locality specified in the Schedule annexed to that notification;

And whereas the Central Government is satisfied that coal is obtainable in a part of the said lands described in the Schedules appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby gives notice of its intention to acquire –

- a) all rights in or over the lands measuring 186.00 hectares (approximately) or 459.61 acres (approximately) described in Schedule 'A' appended hereto;
- b) the rights to mine, quarry, bore, dig and search for, win, work and carry away minerals in the lands measuring 15.25 hectares (approximately) or 37.68 acres (approximately) described in Schedule 'B' appended hereto;

Note 1 :- The plan bearing No. C-I(E)/III/JJMR/706-0403 dated the 4th April, 2003 of the area covered by this notification may be inspected at the office of the Collector, Chandrapur (Maharashtra) or in the office of the Coal Controller, 1 Council House Street, Kolkata (PIN 700 001) or in the office of the Western Coalfields Limited (Revenue Department), Coal Estate, Civil Lines, Nagpur - 440 001 (Maharashtra).

Note 2 :- Attention is hereby invited to the provisions of section 8 of the aforesaid Act which provides as follows :-

Objections to Acquisition :

- “8. (1) Any person interested in any land in respect of which a notification under section 7 has been issued may, within thirty days of the issue of the notification, object to the acquisition of the whole or any part of the land or of any rights in or over such land.

Explanation - It shall not be an objection within the meaning of this section for any person to say that he himself desires to undertake mining operations in the land for the production of coal and that such operations should not be undertaken by the Central Government or by any other person.

- (2) Every objection under sub-section (1) shall be made to the competent authority in writing and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard either in person or by a legal practitioner and shall, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as he thinks necessary, either make a report in respect of the land which has been notified under sub-section (1) of Section 7 or of rights in or over such land, or make different reports in respect of different parcels of such land or of rights in or over such land, to the Central Government, containing his recommendations on the objections, together with the record of the proceedings held by him, for the decision of that Government.

- (3) For the purpose of this section, a person shall be deemed to be interested in land who would be entitled to claim an interest in compensation if the land or any rights in or over such land were acquired under this Act.”

Note 3 :- The Coal Controller, 1, Council House Street, Kolkata- 700 001, has been appointed by the Central Government as the competent authority under the Act vide notification number S.O. 2519, dated the 27th May, 1983, published in Part II, Section 3, Sub-Section (ii) of the Gazette of India, dated the 11th June, 1983.

SCHEDULE –‘A’
JUNA KUNADA O/C BLOCK
MAJRI AREA
DISTRICT- CHANDRAPUR (MAHARASHTRA)

(Plan No. C-I(E)/III/JJMR/706-0403 dated the 4th April, 2003).

All Rights

Serial number	Name of village	Patwari circle number	Tahsil	District	Area in Hectares	Remarks
1	Kunada	28	Bhadrawati	Chandrapur	186.00	Part

Total area : 186.00 hectares
 (approximately)
 or
 459.61 acres
 (approximately)

Plot numbers to be acquired in village Kunada :-

1/1- 1/2- 1/3- 1/4, 2 to 11, 12/1- 12/2- 12/3-12/4, 13/1A, 13/1B, 13/2, 13/3, 14/1- 14/2- 14/3, 15, 16, 17/1, 17/2, 18, 19, 20/1, 20/2, 20/3, 21 to 28, 29/1, 29/2, 29/3, 30/1, 30/2, 30/3, 31 to 48, 49/1, 49/2, 50/1- 50/2, 51/1, 51/2, 51/3, 52 to 55, 66/4, 71, 72/1A, 72/1B, 72/2A, 72/2B, 72/3- 72/4, 73, 74 part, 75/1- 75/2, 76/1- 76/2 part, 78 to 82, 83/1, 83/2, 84, 85, 86/1- 86/2- 86/3, 87/1- 87/2, 88 to 91, 92/1, 92/2, 92/3, 93/1, 93/2, 94/1- 94/2, 95, 96, 97/1, 97/2, 98 to 102, 103/1- 103/2, 104 to 107, 108/1, 108/2, 109/1 part, 109/2, 114, 115, 132/1- 132/2- 132/3 part, 232/1, 232/2, 234/1- 234/2, 236, 237, 238/1- 238/2, 239 to 248, 249 part, 250 part, 251 to 254, 259, 260, 273, 276 to 281, Road, Old Abadi, Nallah Part.

Boundary description :-

- A – B : Line starts from point 'A' and passes through village Kunada and passes along the outer boundary of plot numbers 55, 54, 53, 52, 51/3, 51/2, 51/1, 50/1- 50/2, 49/2, 49/1, 48, 47, 46, Road, plot numbers 45, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 29/1, 29/2, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20/2, 20/1, 13/1B, 279, 13/1A, 10, 9, 1/1- 1/2- 1/3- 1/4, 240, 239, 238/1- 238/2, 259, 260, 236 and passes along the Northern and Eastern bank of Wardha River and meets at point 'B'.
- B – C : Line passes through village Kunada and passes along the outer boundary of plot numbers 236, 237, 234/1- 234/2, 232/2, Nallah and meets at point 'C'.
- C – A : Line passes through village Kunada, crosses nallah, then passes in plot numbers 249, 250, 132/1- 132/2- 132/3 and passes along the outer boundary of plot number 109/1 then in plot number 109/1 and passes along the outer boundary of plot numbers 102, 273, 98, 114, 115, 71 then in plot numbers 74, 76/1- 76/2 and passes along the outer boundary of plot number 76/1- 76/2, Road, plot numbers 66/4, 54, 55 and meets at starting point 'A'.

SCHEDULE -'B'

JUNA KUNADA O/C BLOCK
MAJRI AREA
DISTRICT- CHANDRAPUR (MAHARASHTRA)

(Plan No. C-I(E)/III/JJMR/706-0403 dated the 4th April, 2003)

Mining Rights

Serial number	Name of village	Patwari circle number	Tahsil	District	Area in Hectares	Remarks
1.	Kunada	28	Bhadrawati	Chandrapur	15.25	Part

Total area : 15.25 hectares
(approximately)

or
37.68 acres
(approximately)

Plot numbers to be acquired in village Kunada :-

186 to 188, 193/1 part, 193/2, 228 to 231, 233, 235, 283, 284, Road Part.

Boundary description :-

- B – C : Line starts from point 'B' and passes through village Kunada and passes along the outer boundary of plot numbers 235, 233, 284, 283, crosses Road then passes along the outer boundary of plot numbers 187, 186 and meets at point 'C'.
- C – D : Line passes through village Kunada and passes along the outer boundary of plot numbers 186, 188, 193/2, 193/1, in plot number 193/1 and passes along the outer boundary of Road and meets at point 'D'.
- D – E : Line passes through village Kunada, crosses Road, and passes along the outer boundary of Road, plot numbers 283, 284, 228 and meets at point 'E'.
- E – B : Line passes through village Kunada and passes along the outer boundary of plot numbers 228, 231, 233, 235 and meets at starting point 'B'.

[No. 43015/8/2002-P.R./W.]
SANJAY BAHADUR, Dy. Secy.

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 2003

का. आ. 2197 .— केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गुजरात राज्य में मुन्द्रा पत्तन स्थित अपरिष्कृत तेल संस्थान से पंजाब राज्य में भटिंडा तक मुन्द्रा-भटिंडा अपरिष्कृत तेल पाइपलाइन के माध्यम से अपरिष्कृत तेल के परिवहन के लिए गुरु गोबिन्द सिंह रिफाइनरीज लिमिटेड (हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की समनुषंगी) द्वारा एक पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए;

और, केन्द्रीय सरकार को उक्त पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में जिसके भीतर उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी भारत के राजपत्र में यथाप्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, इक्कीस दिन के भीतर उसमें उपयोग के अधिकार के अर्जन या भूमि के भीतर पाइपलाइन बिछाने के संबंध में श्री डी.के. पारेख, सक्षम प्राधिकारी, मुन्द्रा-भटिंडा अपरिष्कृत तेल पाइपलाइन, गुरु गोविंद सिंह रिफाइनरीज लिमिटेड (हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, की समनुषंगी), पो.बोक्स नं. 43, यूनिट 2, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मु. पो. खारी रोहर, तालुका गाँधीधाम, गुजरात राज्य को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

तहसील:- अन्जार

जिला:- कच्छ

राज्य:- गुजरात

गाँव का नाम	सर्वे सँख्या	भाग यदि है तो	क्षेत्रफल		
			हेक्टर	आर	सेन्टी आर
1	2	3	4		
1. चन्द्रोडा	द्वार्वस 600	पैकी	00	81	29
	268		00	07	71
	266		00	07	90
	द्वार्वस 600	पैकी	00	02	08
	द्वार्वस 600	पैकी	00	14	06
	279/3	पैकी	00	05	76
	280		00	08	48
	द्वार्वस 600	पैकी	00	06	49
	-	कार्ट ट्रैक	00	00	65
	-	नाला	00	00	18
	488		00	00	03
	485/2		00	07	80
	474		00	29	80
	276		00	01	41
	-	नदी	00	00	18
	460/3		00	00	99
	-	नाला	00	03	26
	187/1		00	03	82
2. भुवड	-	नाला	00	07	98
	186/1		00	07	05
	-	नाला	00	07	32
	684		00	17	25
	692		00	07	00
	165/1		00	22	11
	164		00	02	07
	148		00	04	91
	147		00	04	84
	द्वार्वस 671	पैकी	00	09	50
	द्वार्वस 718	पैकी	00	02	10
	-	लेगाव नदी	00	05	30
	द्वार्वस 718	पैकी	00	19	60
	-	कार्ट ट्रैक	00	00	59
3. खेडोइ मोटी					

तहसील:- अन्जार

जिला:- कच्छ

राज्य:- गुजरात

गाँव का नाम	सर्वे संख्या	भाग यदि है तो	क्षेत्रफल		
			हेक्टर	आर	सेन्टी आर
1	2	3	4		
3. खेडोइ मोटी (जारी...)	द्वारस 718	पैकी	00	11	13
	468		00	03	97
	466		00	00	75
4. खंभरा	-	नाला	00	00	57
5.सीनुगा	141		00	09	83
	148/2		00	00	92
	51		00	08	81
	48		00	01	54
6.मोटा नागलपर	126/2		00	13	55
	-	सोंग नदी	00	07	65
	-	कार्ट ट्रक	00	00	33
	द्वारस 182	पैकी	00	01	30
7.नागलपुर नाना - 2	13		00	01	49
	9	पैकी	00	03	43
8. अन्जार	158/1		00	01	23
	142		00	16	51
	140/2		00	08	50
	140/1		00	07	26
	139		00	10	93
	137		00	03	65
	253	पैकी	00	14	62
	254	पैकी	00	66	59
	267	पैकी	00	27	29
	270		00	33	64
	301		00	00	93
	306	पैकी	00	02	00
	308/1		00	01	47
	374	पैकी	00	30	44
	444/2		00	01	47
	442		00	03	46
	497		00	00	12
9.मीठा पसवारीया	द्वारस 162	पैकी	00	00	49
	101		00	07	53

तहसील:- अन्जार

जिला:- कच्छ

राज्य:- गुजरात

गाँव का नाम	सर्वे सँख्या	भाग यदी है तो	क्षेत्रफल		
			हेक्टर	आर	सेन्टी आर
1	2	3	4		
9.मीठा पसवारीया (जारी...)	104/1		00	21	67
	88/2		00	03	61
	87		00	27	76
	-	नाला	00	09	20
10.खारा पसवारीया	234	पैकी	00	02	15
	197/2		00	50	68
	197/1		00	09	71
	199	पैकी	00	00	02
	198		00	05	42
	द्वारस 204	पैकी	00	00	25
	5		00	10	86
	-	नाला	00	07	41
	द्वारस 204	पैकी	00	03	72
	52		00	16	66
	51		00	07	85
	64		00	03	41
11. अजापर	296		00	11	20
	292/2		00	13	10
	224	पैकी	00	24	91
	161		00	02	19
	160	पैकी	00	00	42
12. भीमासर	625/2		00	01	60
	626		00	04	61
	-	मेटल रोड	00	04	52
	द्वारस 785	पैकी	00	03	62
	671		00	00	65
	670		00	02	22
	द्वारस 785	पैकी	00	01	65
	741		00	11	79
	731		00	13	24
	733		00	24	52
	736	पैकी	00	16	73
	17	पैकी	00	00	23
	80	पैकी	00	01	01
	89		00	00	89
	101		00	07	67

तहसील:- अन्जार

जिला:- कच्छ

राज्य:- गुजरात

गाँव का नाम	सर्वे संख्या	भाग यदि है तो	क्षेत्रफल		
			हेक्टर	आर	सेन्टी आर
1	2	3	4		
13.पसुडा	308		00	04	47
	335		00	05	79
	336	पैकी	00	06	34
	338/2		00	02	45
	342	पैकी	00	01	78
	346		00	00	32
	349		00	01	16
	368/1		00	06	40
	380	पैकी	00	04	01
		कार्ट ट्रैक			

[फा. सं. आर-31015/47/2001-ओ.आर-II]

हरीश कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS

New Delhi, the 28th July, 2003

S. O. 2197.—Whereas, it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of crude oil from crude oil terminal at Mundra Port in the State of Gujarat to Bathinda in the State of Punjab, through Mundra-Bathinda Crude Oil Pipeline, pipelines should be laid by Guru Gobind Singh Refineries Limited (a subsidiary of Hindustan Petroleum Corporation Limited);

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying the said pipelines, it is necessary to acquire the right of user in the land under which the said pipelines are proposed to be laid, and which are described in the Schedule annexed to this notification;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section(1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person, interested in the land described in the said Schedule may, within twenty-one days from the date on which the copies of this notification issued under sub-section(1) of section 3 of the said Act, as published in the Gazette of India, are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of user therein or laying of the pipeline under the land to Shri D.K. Parekh, Competent Authority, Mundra-Bathinda Crude Oil Pipeline, Guru Gobind Singh Refineries Limited, (a subsidiary of Hindustan Petroleum Corporation Limited), P.B. No. 43, Unit 2, Hindustan Petroleum Corporation Limited, At and Post Khari Rohar, Taluka Gandhidham, State Gujarat.

SCHEDULE

Taluka :- Anjar

District :- Kutch

State :- Gujarat

Name of Village	Survey No	Part if Any	ROU Area		
			Ha.	Ar.	Sq.mt.
1	2	3	4		
(1).Chandroda	Trowers 600	P	00	81	29
	268		00	07	71
	266		00	07	90
	Trowers 600	P	00	02	08
	Trowers 600	P	00	14	06
	279/3	P	00	05	76
	280		00	08	48
	Trowers 600	P	00	06	49
	-	Cart Track	00	00	65
	-	Nala	00	00	18
	488		00	00	03
	485/2		00	07	80
	474		00	29	80
	276		00	01	41
	-	River	00	00	18
	460/3		00	00	99
	-	Nala	00	03	26
	187/1		00	03	82
	-	Nala	00	07	98
	186/1		00	07	05
	-	Nala	00	07	32
(2).Bhuvad	684		00	17	25
	692		00	07	00
	165/1		00	22	11
	164		00	02	07
	148		00	04	91
	147		00	04	84
	Trowers 671	P	00	09	50
	Trowers 718	P	00	02	10
	-	Lerakh River	00	05	30
	Trowers 718	P	00	19	60
	-	Cart Track	00	00	59
(3).Khedoi Moti					

Taluka :- Anjar

District :- Kutch

State :- Gujarat

Name of Village	Survey No	Part if Any	ROU Area		
			Ha.	Ar.	Sq.mt.
1	2	3	4		
(3).Khedoi Moti (Contd...)	Trowers 718 468 466	P	00 00 00	11 03 00	13 97 75
(4).Khambhara	-	Nala	00	00	57
(5).Sinugra	141 148/2 51 48		00 00 00 00	09 00 08 01	83 92 81 54
(6).Mota Nagalpar	126/2 - -		00 00 00	13 07 00	55 65 33
	Trowers 182	P	00	01	30
(7).Nagalpur Nana-2	13		00	01	49
	9	P	00	03	43
(8). Anjar	158/1 142 140/2 140/1 139 137 253 254 267 270 301 306 308/1 374 444/2 442 497	River P P P P P	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	03 01 16 08 07 10 03 14 66 27 33 00 02 01 30 01 03 00	23 51 50 26 93 65 63 59 29 64 93 00 47 44 47 46 12
(9). Mitha Paswaria	Trowers 162 101	P	00 00	00 07	49 53

Taluka :- Anjar

District :- Kutch

State :- Gujarat

Name of Village	Survey No	Part if Any	ROU Area		
			Ha.	Ar.	Sq.mt.
1	2	3	4		
(9). Mitha Paswaria (Contd...)	104/1		00	21	67
	88/2		00	03	61
	87		00	27	76
	-	Nala	00	09	20
(10).Khara Paswaria	234	P	00	02	15
	197/2		00	50	68
	197/1		00	09	71
	199	P	00	00	02
	198		00	05	42
	Trowers 204	P	00	00	25
	5		00	10	86
	-	Nala	00	07	41
	Trowers 204	P	00	03	72
	52		00	16	66
	51		00	07	85
	64		00	03	41
(11).Ajapar	296		00	11	20
	292/2		00	13	10
	224	P	00	24	91
	161		00	02	19
	160	P	00	00	42
(12).Bhimasar	625/2		00	01	60
	626		00	04	61
	-	Metal Road	00	04	52
	Trowers 785	P	00	03	62
	671		00	00	65
	670		00	02	22
	Trowers 785	P	00	01	65
	741		00	11	79
	731		00	13	24
	733		00	24	52
	736	P	00	16	73
	17	P	00	00	23
	80	P	00	01	01
	89		00	00	89
	101		00	07	67

Taluka :- Anjar

District :- Kutch

State :- Gujarat

Name of Village	Survey No	Part if Any	ROU Area		
			Ha.	Ar.	Sq.mt.
1	2	3	4		
(13).Pasuda	308		00	04	47
	335		00	05	79
	336	P	00	06	34
	338/2		00	02	45
	342	P	00	01	78
	346		00	00	32
	349		00	01	16
	368/1		00	06	40
	380	P	00	04	01
		Cart Track			

[No. R-31015/47/2001-O.R.-II]
HARISH KUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 2003

का. आ. 2198 .— केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना संख्या का.आ. 2352, तारीख 11 जुलाई 2002 और का.आ. 2755, तारीख 23 अगस्त 2002, जो भारत के राजपत्र में क्रमशः तारीख 20 जुलाई 2002 और 31 अगस्त 2002 को प्रकाशित की गई थी, द्वारा उन अधिसूचनाओं से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में गुरु गोबिन्द सिंह रिफाइनरीज लिमिटेड (हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की समनुषंगी) द्वारा मुन्द्रा-भटिण्डा अपरिष्कृत तेल पाइपलाइन के माध्यम से गुजरात राज्य में मुन्द्रा पत्तन स्थित अपरिष्कृत तेल संस्थापन से पंजाब राज्य में भटिण्डा तक अपरिष्कृत तेल के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ; और उक्त राजपत्र अधिसूचनाओं की प्रतियां जनता की क्रमशः तारीख 17 सितम्बर 2002 और 26 अक्टूबर 2002 को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और केन्द्रीय सरकार का उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात, यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इन अधिसूचनाओं से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग का अधिकार का अर्जन किया जाता है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि पाइपलाइन बिछाने के लिए उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख को केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए सभी विल्लंगमों से मुक्त गुरु गोबिन्द सिंह रिफाइनरीज लिमिटेड (हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की समनुषंगी) में निहित होगा ।

अनुसूची

तहसील :- अंजार

जिला :- कच्छ

राज्य :- गुजरात

गाँव का नाम	सर्वे सँख्या	भाग यदि है तो	क्षेत्रफल		
			हेक्टर	आर	सेन्टी आर
1	2	3	4		
1. खेडोइ मोटी	-	नाला	00	03	59
	ट्रावर्स 718	पैकी	00	32	71
	-	नाला	00	00	53
	ट्रावर्स 718	पैकी	01	35	96
	-	लेराख नदी	00	15	35
	518		00	03	73
	ट्रावर्स 718	पैकी	00	29	13
	-	कार्ट ट्रैक	00	00	77
	ट्रावर्स 718	पैकी	00	06	87
	500		00	01	21
	-	नाला	00	04	35
	502/1		00	05	84
	504/1		00	47	29
	-	कार्ट ट्रैक	00	00	79
	468		00	06	35
	467		00	32	73
	466		00	26	87
	509		00	25	26
	510/2		00	23	03
	510/1		00	44	20
	ट्रावर्स 718	पैकी	00	15	59
	ट्रावर्स 718	पैकी	00	49	23
	295		00	32	36
	299/1		00	00	05
	ट्रावर्स 718	पैकी	00	06	00
	298		00	42	89
	321		00	30	03

तहसील :- अंजार

ज़िला :- कच्छ

राज्य :- गुजरात

गाँव का नाम	सर्वे संख्या	भाग यदि है तो	क्षेत्रफल		
			हेक्टर	आर	सेन्टी आर
1	2	3	4		
1. खेडोइ मोटी	322		00	03	28
(जारी...)	318		00	44	34
	317		00	03	69
2. खंभरा		नाला	00	08	81
	ट्रावर्स 258	पैकी	00	05	53
3. सीनुगा	156(पुराना 155)	पैकी	00	42	64
	166(पुराना 155)	पैकी	00	90	87
	ट्रावर्स 155	पैकी	00	15	00
	134/1	पैकी	00	49	52
	133/2		00	05	19
	157(पुराना 155)	पैकी	03	03	08
	143/5		00	37	25
	144		00	00	59
	145/2		00	23	28
	147/4		00	00	02
	147/3		00	12	63
	147/2		00	23	84
	147/1		00	03	46
	148/2		00	19	60
	148/1		00	20	33
	16	पैकी	00	44	02
	15		00	40	31
	-	कार्ट ट्रैक	00	07	88

तहसील :- अंजार

जिला :- कच्छ

राज्य :- गुजरात

गाँव का नाम	सर्वे सँख्या	भाग यदि है तो	क्षेत्रफल		
			हेक्टर	आर	सेन्टी आर
1	2	3	4		
3.सीनुगा (जारी...)	51		00	05	69
	50/1		00	16	86
	50/2		00	16	40
	50/3		00	06	29
	50/4		00	19	64
	48		00	12	51
	49		00	24	44
4.मोट्टा नागलपर	128		00	02	97
	126/1		00	16	24
	126/2		00	08	03
	ट्रावर्स 182	पैकी	00	13	80
	-	कार्ट ट्रैक	00	03	15
	-	सोंग नदी	00	04	50
	ट्रावर्स 182	पैकी	00	52	39
	-	कार्ट ट्रैक	00	04	06
	161/2		00	35	39
	161/1		00	00	60
	162		00	31	07
	171/1		00	15	86
	171/2		00	22	91
	159/2		00	12	42
	159/1		00	01	09
	173/1		00	29	84
	173/2		00	00	72
	157/1	पैकी	00	09	00
	155		00	29	79
	176		00	15	70

तहसील :- अंजार

जिला :- कच्छ

राज्य :- गुजरात

गाँव का नाम	सर्वे संख्या	भाग यदि है तो	क्षेत्रफल		
			हेक्टर	आर	सेन्टी आर
1	2	3	4		
4.मोटा नागलपर	153		00	26	58
(जारी...)	152		00	08	01
	ट्रावर्स 182	पैकी	00	07	58
	151		00	15	94
	ट्रावर्स 182	पैकी	00	19	28
5.चन्द्रोडा	251/1		00	03	68
	251/2		00	07	82
6.अन्जार	ट्रावर्स 984	पैकी	00	02	54
	158/2		00	40	21
	ट्रावर्स 984	पैकी	00	10	44
	142		00	39	41
	141		00	08	44
	ट्रावर्स 984	पैकी	00	49	33
	ट्रावर्स 984	पैकी	00	87	36
	253	पैकी	00	24	21
	260	पैकी	00	09	63
	266	पैकी	00	36	53
	267	पैकी	00	27	36
	270		00	32	54
	271		00	29	60
	302		00	41	60
	301		00	32	75
	300		00	20	45
	299	पैकी	00	03	47
	306	पैकी	00	17	33
	307		00	23	89
	308/1		00	30	94
	308/3		00	24	67

तहसील :- अंजार

जिला :- कच्छ

राज्य :- गुजरात

गाँव का नाम	सर्वे संख्या	भाग यदि है तो	क्षेत्रफल		
			हेक्टर	आर	सेन्टी आर
1	2	3	4		
6.अन्जार	375		00	24	92
(जारी...)	374	पैकी	00	00	79
	388/1		00	07	31
	388/2		00	03	38
	418		00	00	46
	421		00	09	37
	417		00	42	84
	422	पैकी	00	90	11
	423		00	40	91
	ट्रावर्स 984	पैकी	00	01	76
	451		00	21	62
	450	पैकी	00	79	37
	449		00	35	32
	448/2		00	15	60
	447/3		00	16	81
	447/4		00	08	38
	ट्रावर्स 984	पैकी	00	32	38
	444/2		00	05	59
	443/1		00	12	65
	443/2		00	16	11
	442		00	28	77
	-	कार्ट ट्रैक	00	02	71
	494/2		00	05	57
	494/1		00	13	92
	495		00	80	14

तहसील :- अंजार

जिला :- कच्छ

राज्य :- गुजरात

गाँव का नाम	सर्वे संख्या	भाग यदी है तो	क्षेत्रफल		
			हेक्टर	आर	सेन्टी आर
1	2	3	4		
6.अन्जार	ट्रावर्स 984	पैकी	00	16	69
(जारी...)	497		00	23	47
	498/1		00	48	01
	499		00	22	03

[फा. सं. आर-31015/47/2001-ओ.आर-II]

हरीश कुमार, अवर सचिव

New Delhi, the 28th July, 2003

S. O. 2198.— Whereas by notifications of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, number S.O.2352 dated the 11th July 2002 and S.O. 2755 dated the 23rd August 2002, issued under sub-section(1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines(Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), published in the Gazette of India dated the 20th July, 2002 and 31st August, 2002 respectively, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to those notifications for the purpose of laying pipeline for transport of crude oil from crude oil terminal at Mundra Port in the state of Gujarat to Bathinda in the State of Punjab through Mundra-Bathinda Crude Oil Pipeline by Guru Gobind Singh Refineries Limited (a subsidiary of Hindustan Petroleum Corporation Limited);

And whereas copies of the said Gazette notifications were made available to the public on 17th September 2002 and 26th October 2002 respectively.

And whereas the competent authority has under sub-section(1) of section 6 of the said Act submitted the report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire the right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section(1) of the section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipelines;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in the Guru Gobind Singh Refineries Limited (a subsidiary of Hindustan Petroleum Corporation Limited) free from all encumbrances.

SCHEDULE**Taluka :- Anjar****District :- Kutch****State :- Gujarat**

Name of Village	Survey No	Part if Any	ROU Area		
			Ha.	Ar.	Sq.mt.
1	2	3	4		
1. Khedoi Moti	-	Nala	00	03	59
	Trowers 718	P	00	32	71
	-	Nala	00	00	53
	Trowers 718	P	01	35	96
	-	Lerakh River	00	15	35
	518		00	03	73
	Trowers 718	P	00	29	13
	-	Cart track	00	00	77
	Trowers 718	P	00	06	87
	500		00	01	21
	-	Nala	00	04	35
	502/1		00	05	84
	504/1		00	47	29
	-	Cart track	00	00	79
	468		00	06	35
	467		00	32	73
	466		00	26	87
	509		00	25	26
	510/2		00	23	03
	510/1		00	44	20
	Trowers 718	P	00	15	59
	Trowers 718	P	00	49	23
	295		00	32	36
	299/1		00	00	05
	Trowers 718	P	00	06	00
	298		00	42	89
	321		00	30	03

Taluka :- Anjar

District :- Kutch

State :- Gujarat

Name of Village	Survey No	Part if Any	ROU Area		
			Ha.	Ar.	Sq.mt.
1	2	3	4		
1. Khedoi Moti	322		00	03	28
(Contd...)	318		00	44	34
	317		00	03	69
2 Khambhara	-	Nala	00	08	81
	Trowers 258	P	00	05	53
3. Sinugra	156(Old 155)	P	00	42	64
	166(Old 155)	P	00	90	87
	Trowers 155	P	00	15	00
	134/1	P	00	49	52
	133/2		00	05	19
	157(Old 155)	P	03	03	08
	143/5		00	37	25
	144		00	00	59
	145/2		00	23	28
	147/4		00	00	02
	147/3		00	12	63
	147/2		00	23	84
	147/1		00	03	46
	148/2		00	19	60
	148/1		00	20	33
	16	P	00	44	02
	15		00	40	31
	-	Cart Track	00	07	88

Taluka :- Anjar**District :- Kutch****State :- Gujarat**

Name of Village	Survey No	Part if Any	ROU Area		
			Ha.	Ar.	Sq.mt.
1	2	3	4		
3.Sinugra	51		00	05	69
(Contd...)	50/1		00	16	86
	50/2		00	16	40
	50/3		00	06	29
	50/4		00	19	64
	48		00	12	51
	49		00	24	44
4.Mota-Nagalpar	128		00	02	97
	126/1		00	16	24
	126/2		00	08	03
	Towers 182	P	00	13	80
	-	Cart Track	00	03	15
	-	Song River	00	04	50
	Towers 182	P	00	52	39
	-	Cart Track	00	04	06
	161/2		00	35	39
	161/1		00	00	60
	162		00	31	07
	171/1		00	15	86
	171/2		00	22	91
	159/2		00	12	42
	159/1		00	01	09
	173/1		00	29	84
	173/2		00	00	72
	157/1	P	00	09	00
	155		00	29	79
	176		00	15	70
	153		00	26	58
	152		00	08	01

Taluka :- Anjar

District :- Kutch

State :- Gujarat

Name of Village	Survey No	Part if Any	ROU Area		
			Ha.	Ar.	Sq.mt.
1	2	3	4		
4.Mota-Nagalpar (Contd...)	Towers 182	P	00	07	58
	151		00	15	94
	Towers 182	P	00	19	28
5.Chandroda	251/1		00	03	68
	251/2		00	07	82
6.Anjar	Towers 984	P	00	02	54
	158/2		00	40	21
	Towers 984	P	00	10	44
	142		00	39	41
	141		00	08	44
	Towers 984	P	00	49	33
	Towers 984	P	00	87	36
	253	P	00	24	21
	260	P	00	09	63
	266	P	00	36	53
	267	P	00	27	36
	270		00	32	54
	271		00	29	60
	302		00	41	60
	301		00	32	75
	300		00	20	45
	299	P	00	03	47
	306	P	00	17	33
	307		00	23	89
	308/1		00	30	94
	308/3		00	24	67
	375		00	24	92
	374	P	00	00	79
	388/1		00	07	31
	388/2		00	03	38

Taluka :- Anjar

District :- Kutch

State :- Gujarat

Name of Village	Survey No	Part if Any	ROU Area		
			Ha.	Ar.	Sq.mt.
1	2	3	4		
6.Anjar	418		00	00	46
(Contd.)	421		00	09	37
	417		00	42	84
	422	P	00	90	11
	423		00	40	91
	Towers 984	P	00	01	76
	451		00	21	62
	450	P	00	79	37
	449		00	35	32
	448/2		00	15	60
	447/3		00	16	81
	447/4		00	08	38
	Towers 984	P	00	32	38
	444/2		00	05	59
	443/1		00	12	65
	443/2		00	16	11
	442		00	28	77
	-	Cart Track	00	02	71
	494/2		00	05	57
	494/1		00	13	92
	495		00	80	14
	Towers 984	P	00	16	69
	497		00	23	47
	498/1		00	48	01
	499		00	22	03

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 2003

का. आ. 2199 .— केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1080 तारीख 28 मार्च, 2003, जो भारत के राजपत्र में तारीख 5 अप्रैल 2003 को प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में गुरु गोबिन्द सिंह रिफाइनरीज लिमिटेड (हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की समनुषंगी) द्वारा मुन्द्रा-भटिण्डा अपरिष्कृत तेल पाइपलाइन के माध्यम से गुजरात राज्य में मुन्द्रा पत्तन स्थित अपरिष्कृत तेल संस्थापन से पंजाब राज्य में भटिण्डा तक अपरिष्कृत तेल के परिवहन के लिए पाइपलाइनें बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 30 अप्रैल 2003 को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और पाइपलाइनें बिछाने के सम्बन्ध में जनता से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए थे ;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह समाधान हो जाने पर कि पाइपलाइनें बिछाई जाने के लिए उक्त भूमि अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइनें बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि पाइपलाइनें बिछाने के लिए उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख को केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाए सभी विल्लंगमों से मुक्त, गुरु गोबिन्द सिंह रिफाइनरीज लिमिटेड (हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की समनुषंगी) में निहित होगा ।

अनुसूची

तहसील : डबवाली

जिला : सिरसा

राज्य : हरियाणा

गांव का नाम	हदबस्त नं०	खसरा नं०	हिस्सा यदि कोई है	क्षेत्रफल कनाल—मरला
1	2	3	4	5
औड़ा	204	127/14	1	0 - 1
धुंकावाली	221	231	-	0 - 3
		247	1	1 - 9
		865	-	0 - 7
जगमालवाली	309	292	-	0 - 2
हस्तू	311	386	-	0 - 2
		93/8	1	1 - 0
		93/8	2	1 - 2
		93/9	2	0 - 13

[फा. सं. आर-31015/6/2002-ओ.आर-II]

हरीश कुमार, अवर सचिव

New Delhi, the 1st August, 2003

S.O. 2199.— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas number S.O.1080, dated the 28th March, 2003 published in the Gazette of India, dated the 5th April, 2003 issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of crude oil from crude oil terminal at Mundra Port in the State of Gujarat to Bathinda in the State of Punjab through Mundra-Bathinda crude oil pipeline by Guru Gobind Singh Refineries Limited (a subsidiary of Hindustan Petroleum Corporation Limited);

And whereas the copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 30th April 2003;

And whereas no objections were received from the public to the laying of the pipeline;

And whereas the competent authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act, submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying pipelines, has decided to acquire the right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipelines shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in the Guru Gobind Singh Refineries Limited (a subsidiary of Hindustan Petroleum Corporation Limited) free from all encumbrances.

SCHEDULE

Tehsil : Dabwali		District : Sirsa		State : Haryana	
Name of Village	Hadbast No.	Khasra No.	Part Hissa No. (If any)	Extent Kanal - Marla	
1	2	3	4	5	
Odhan	204	127/14	1	0 - 1	
	221	231	-	0 - 3	
Ghukanwali		247	1	1 - 9	
		865	-	0 - 7	
	309	292	-	0 - 2	
	311	386	-	0 - 2	
		93/8	1	1 - 0	
		93/8	2	1 - 2	
		93/9	2	0 - 13	
Jagmalwali					
Hassu					

[No. R-31015/6/2002-O.R.-II]
HARISH KUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 2003

का. मा. 2200 — केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की भारत के राजपत्र तारीख 20 जुलाई 2002 में प्रकाशित अधिसूचना सं. का.आ. 2357 तारीख 17 जुलाई 2002 द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में गुरु गोबिन्द सिंह रिफाइनरीज लिमिटेड (हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की समनुषंगी) द्वारा मुन्द्रा-भटिण्डा अपरिष्कृत तेल पाइपलाइन परियोजना के माध्यम से गुजरात राज्य में मुन्द्रा पत्तन स्थित अपरिष्कृत तेल संस्थापन से पंजाब राज्य में भटिण्डा तक अपरिष्कृत तेल के परिवहन के लिए पाइपलाइनें बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार के अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्रित अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 20 मार्च 2003 को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और पाइपलाइन बिछाने के सम्बन्ध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्यक रूप से विचार कर लिया गया और उन्हें अननुज्ञात कर दिया गया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और केन्द्रीय सरकार का उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइनें बिछाने के लिए उपयोग का अधिकार अर्जित किया जाता है ;

और केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि पाइपलाइनें बिछाने के संबंध में उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख को केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाए सभी विल्लंगमों से मुक्त गुरु गोबिन्द सिंह रिफाइनरीज लिमिटेड (हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की समनुषंगी) में निहित होगा ।

अनुसूची

तहसील :- रापर

जिला :- कच्छ

राज्य :- गुजरात

गाँव का नाम	सर्वे संख्या	भाग यदि है तो	क्षेत्रफल		
			हेक्टर	आर	सेन्टी आर
1	2	3	4		
1. भीमासर	944/1		00	08	50
	944/2		00	09	88
	945/1		00	02	72
	946	पैकी	00	29	27
	947	पैकी	00	10	41
	947	पैकी	00	09	75
	951/3	पैकी	00	12	82
	938/3		00	09	25
	938/1		00	05	22
	938/2		00	19	44
	937		00	31	25
	921		00	62	92
	913/2		00	03	22
	913/1		00	15	10
	912/3		00	21	00
	912/2		00	12	33
	909/1		00	06	39
	909/2		00	25	84
	910		00	05	78
	908/2		00	10	09
	908/3		00	14	73
	907		00	11	42
	906		00	11	17
	-	नाला	00	06	09
	ट्रार्वस 2220/1	पैकी	00	16	48
	718	पैकी	00	00	69
	719		00	15	14
	-	नाला	00	01	21
	720		00	19	89
	721		00	32	22

तहसील :- रापर

जिला :- कच्छ

राज्य :- गुजरात

गाँव का नाम	सर्वे सँख्या	भाग यदि है तो	क्षेत्रफल		
			हेक्टर	आर	सेन्टी आर
1	2	3	4		
1. भीमासर	722		00	22	00
(जारी...)	-	कार्ट ट्रैक	00	01	71
	795/2		00	03	75
	793		00	00	10
	728/2		00	22	28
	728/1	पैकी	00	20	18
	729	पैकी	00	19	50
	729	पैकी कार्ट ट्रैक	00	00	66
	735/4		00	12	12
	ट्रार्वस 2220/1	पैकी	00	54	47
	790/1		00	36	80
	781/1		00	07	94
	781/2		00	04	07
	782	पैकी	00	01	81
	ट्रार्वस 2220/1	पैकी	00	34	67
	780	पैकी	00	31	15
	ट्रार्वस 2220/1	पैकी	00	31	62
	809/1		00	02	08
	810/4		00	01	14
	810/2		00	14	31
	810/1		00	19	38
	ट्रार्वस 2220/1	पैकी	00	11	28
	812/1	पैकी	00	16	71
	814/1	पैकी	00	14	45
	814/2		00	15	32
	814/3		00	09	72
	819		00	33	01
	826		00	29	99
	825		00	16	00
	824/3		00	00	13
	827/1		00	16	59

तहसील :- रापर

जिला:- कच्छ

राज्य:- गुजरात

गाँव का नाम	सर्वे सँख्या	भाग यदि है तो	क्षेत्रफल		
			हेक्टर	आर	सेन्टी आर
1	2	3	4		
1. भीमासर	827/3		00	03	22
(जारी...)	827/2	पैकी	00	08	84
	828/1	पैकी	00	21	32
	828/2		00	07	20
	829	पैकी	00	08	95
	836/1	पैकी	00	00	72
	836/4		00	11	48
	836/3		00	08	28
	835/1	पैकी	00	19	04
	835/2		00	03	10
	834/1		00	11	20
	834/3	पैकी	00	00	73
	843/1		00	09	54
	843/2		00	13	63
	844		00	01	41
	845/3		00	17	60
	845/2		00	31	00
	845/1		00	01	50
	850/1		00	00	40
	851	पैकी	00	00	10
	853/4		00	20	58
	853/3		00	04	28
	853/2		00	06	44
	855/2		00	06	61
	855/1		00	05	87
	856/1		00	14	23
	857/3		00	04	72
	857/2	पैकी	00	16	28
	857/1		00	02	48

तहसील :- रापर

जिला :- कच्छ

राज्य :- गुजरात

गाँव का नाम	सर्वे संख्या	भाग यदि है तो	क्षेत्रफल		
			हेक्टर	आर	सेन्टी आर
1	2	3	4		
1. भीमासर (जारी...)	841		00	03	54
	859		00	36	28
	861/2		00	02	22
	860/1		00	19	32
	-	नाला	00	04	52
	ट्रार्वस 2220/1	पैकी	00	11	09
	-	कार्ट ट्रैक	00	02	67
	2191/1		00	07	38
	2191/2		00	17	49
	2190/2		00	01	50
	2190/1		00	25	29
	-	नदी	00	11	64
	2185/2	पैकी	00	36	89
	2185/1		00	07	49
	2183/2	पैकी	00	15	22
	2182		00	16	80
	-	कार्ट ट्रैक	00	01	06
	2180/1		00	04	87
	2179/4	पैकी	00	04	23
	2179/3		00	11	86
	2179/2		00	03	44
	2179/1		00	07	78
	2178/1	पैकी	00	14	12
	2175/2		00	09	86
	2173/1		00	11	34
	2167		00	12	17
	2169	पैकी	00	22	90
	2161/4		00	04	96
	2162/1		00	05	87
	-	कार्ट ट्रैक	00	02	92

तहसील :- रापर

जिला:- कच्छ

राज्य:- गुजरात

गाँव का नाम	सर्वे संख्या	भाग यदि है तो	क्षेत्रफल		
			हेक्टर	आर	सेन्टी आर
1	2	3	4		
1. भीमासर (जारी...)	2154/3	पैकी	00	11	17
	2152/1		00	20	62
	2152/2		00	01	36
	2146/1		00	03	96
	2146/2	पैकी	00	14	80
	2144/1		00	12	41
	2144/2		00	11	09
	-	कार्ट ट्रैक	00	01	21
	2129/1		00	08	38
	2129/2		00	02	62
	2130/1	पैकी	00	08	51
	2130/2	पैकी	00	18	69
	-	कार्ट ट्रैक	00	01	11
	2125/1	पैकी	00	11	73
	2122/3		00	16	06
	2119/2		00	00	11
	2116/2		00	04	32
	2115/1		00	20	45
	-	कार्ट ट्रैक	00	02	47
	2106/1	पैकी	00	18	24
	2110/1		00	00	84
	2107/1		00	15	29
	2211		00	10	68
	2210		00	06	16
	2056/1	पैकी	00	05	22
	2056/2	पैकी	00	01	51
	2055/4		00	06	01
	2055/6		00	08	09

तहसील :- रापर

जिला:- कच्छ

राज्य:- गुजरात

गाँव का नाम	सर्वे सँख्या	भाग यदि है तो	क्षेत्रफल		
			हेक्टर	आर	सेन्टी आर
1	2	3	4		
1. भीमासर (जारी...)	2055/8		00	05	05
	2055/7		00	04	19
	2054/6		00	04	20
	2054/4	पैकी	00	04	85
	2054/5	पैकी	00	12	82
	2054/3	पैकी	00	05	67
	2053/6		00	05	24
	2053/5		00	10	95
	2052/2		00	01	89
	2052/1		00	12	49
	2052/5		00	00	51
	2051/3	पैकी	00	00	96
	2051/2	पैकी	00	14	15
	2050/3		00	16	80
	2049/4		00	00	33
	2049/3		00	06	31
	2049/2		00	28	49
	2048/1		00	15	74
	2046/2		00	22	02
	2045		00	13	93
	2044		00	13	08
	2043/1		00	24	81
	2041/1		00	13	29
	2041/2		00	00	36
	2040/2	पैकी	00	75	13
	2039/1		00	14	60
	2038/5		00	01	83
	2038/4		00	02	88
	2038/3		00	04	65

तहसील :- रापर

जिला :- कच्छ

राज्य :- गुजरात

गाँव का नाम	सर्वे संख्या	भाग यदि है तो	क्षेत्रफल		
			हेक्टर	आर	सेन्टी आर
1	2	3	4		
1. भीमासर	2038/2		00	09	25
(जारी...)	2037/4	पैकी	00	19	44
	2037/2		00	00	08
	ट्रार्क्स 2220/1	पैकी	00	03	81

[फा. सं. आर-31015/10/2002-ओ.आर-II]

हरीश कुमार, अवर सचिव

New Delhi, the 1st August, 2003

S. O. 2200.— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas number S.O.2357 dated the 17th July 2002, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), published in the Gazette of India dated the 20th July 2002, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipelines for transportation of crude oil from crude oil terminal at Mundra Port in the State of Gujarat to Bathinda in the State of Punjab through Mundra-Bathinda crude oil pipeline by Guru Gobind Singh Refineries Limited (a subsidiary of Hindustan Petroleum Corporation Limited);

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 29th March 2003;

And whereas, the objections received from the public to the laying of the pipeline have been duly considered and disallowed by the competent authority;

And whereas the competent authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipelines, has decided to acquire the right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipelines;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipelines shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in the Guru Gobind Singh Refineries Limited (a subsidiary of Hindustan Petroleum Corporation Limited) free from all encumbrances.

SCHEDULE**Taluka :- Rapar****District :- Kutch****State :- Gujarat**

Name of Village	Survey No	Part if Any	ROU Area		
			Ha.	Ar.	Sq.mt.
1	2	3	4		
1. Bhimasar	944/1		00	08	50
	944/2		00	09	88
	945/1		00	02	72
	946	P	00	29	27
	947	P	00	10	41
	947	P	00	09	75
	951/3	P	00	12	82
	938/3		00	09	25
	938/1		00	05	22
	938/2		00	19	44
	937		00	31	25
	921		00	62	92
	913/2		00	03	22
	913/1		00	15	10
	912/3		00	21	00
	912/2		00	12	33
	909/1		00	06	39
	909/2		00	25	84
	910		00	05	78
	908/2		00	10	09
	908/3		00	14	73
	907		00	11	42
	906		00	11	17
	-	Nala	00	06	09
	Trowers 2220/1	P	00	16	48
	718	P	00	00	69
	719		00	15	14
	-	Nala	00	01	21
	720		00	19	89
	721		00	32	22

Taluka :- Rapar

District :- Kutch

State :- Gujarat

Name of Village	Survey No	Part if Any	ROU Area		
			Ha.	Ar.	Sq.mt.
1	2	3	4		
1. Bhimasar	722		00	22	00
(Contd...)	-	Cart Track	00	01	71
	795/2		00	03	75
	793		00	00	10
	728/2		00	22	28
	728/1	P	00	20	18
	729	P	00	19	50
	729	P	00	00	66
	735/4		00	12	12
	Trowers 2220/1	P	00	54	47
	790/1		00	36	80
	781/1		00	07	94
	781/2		00	04	07
	782	P	00	01	81
	Trowers 2220/1	P	00	34	67
	780	P	00	31	15
	Trowers 2220/1	P	00	31	62
	809/1		00	02	08
	810/4		00	01	14
	810/2		00	14	31
	810/1		00	19	38
	Trowers 2220/1	P	00	11	28
	812/1	P	00	16	71
	814/1	P	00	14	45
	814/2		00	15	32
	814/3		00	09	72
	819		00	33	01
	826		00	29	99
	825		00	16	00
	824/3		00	00	13
	827/1		00	16	59

Taluka :- Rapar

District :- Kutch

State :- Gujarat

Name of Village	Survey No	Part if Any	ROU Area		
			Ha.	Ar.	Sq.mt.
1	2	3	4		
1. Bhimasar	827/3		00	03	22
(Contd...)	827/2	P	00	08	84
	828/1	P	00	21	32
	828/2		00	07	20
	829	P	00	08	95
	836/1	P	00	00	72
	836/4		00	11	48
	836/3		00	08	28
	835/1	P	00	19	04
	835/2		00	03	10
	834/1		00	11	20
	834/3	P	00	00	73
	843/1		00	09	54
	843/2		00	13	63
	844		00	01	41
	845/3		00	17	60
	845/2		00	31	00
	845/1		00	01	56
	850/1		00	00	40
	851	P	00	00	10
	853/4		00	20	58
	853/3		00	04	28
	853/2		00	06	44
	855/2		00	06	61
	855/1		00	05	87
	856/1		00	14	23
	857/3		00	04	72
	857/2	P	00	16	28
	857/1		00	02	48

Taluka :- Rapar

District :- Kutch

State :- Gujarat

Name of Village	Survey No	Part if Any	ROU Area		
			Ha.	Ar.	Sq.mt.
1	2	3	4		
1. Bhimasar	841		00	03	54
(Contd...)	859		00	36	28
	861/2		00	02	22
	860/1		00	19	32
	-	Nala	00	04	52
	Trowers 2220/1	P	00	11	09
	-	Cart Track	00	02	67
	2191/1		00	07	38
	2191/2		00	17	49
	2190/2		00	01	50
	2190/1		00	25	29
	-	River	00	11	64
	2185/2	P	00	36	89
	2185/1		00	07	49
	2183/2	P	00	15	22
	2182		00	16	80
	-	Cart Track	00	01	06
	2180/1		00	04	87
	2179/4	P	00	04	23
	2179/3		00	11	86
	2179/2		00	03	44
	2179/1		00	07	78
	2178/1	P	00	14	12
	2175/2		00	09	86
	2173/1		00	11	34
	2167		00	12	17
	2169	P	00	22	90
	2161/4		00	04	96
	2162/1		00	05	87
	-	Cart Track	00	02	92

Taluka :- Rapar

District :- Kutch

State :- Gujarat

Name of Village	Survey No	Part if Any	ROU Area		
			Ha.	Ar.	Sq.mt.
1	2	3	4		
1. Bhimasar (Contd...)	2154/3	P	00	11	17
	2152/1		00	20	62
	2152/2		00	01	36
	2146/1		00	03	96
	2146/2	P	00	14	80
	2144/1		00	12	41
	2144/2		00	11	09
	-	Cart Track	00	01	21
	2129/1		00	08	38
	2129/2		00	02	62
	2130/1	P	00	08	51
	2130/2	P	00	18	69
	-	Cart Track	00	01	11
	2125/1	P	00	11	73
	2122/3		00	16	06
	2119/2		00	00	11
	2116/2		00	04	32
	2115/1		00	20	45
	-	Cart Track	00	02	47
	2106/1	P	00	18	24
	2110/1		00	00	84
	2107/1		00	15	29
	2211		00	10	68
	2210		00	06	16
	2056/1	P	00	05	22
	2056/2	P	00	01	51
	2055/4		00	06	01
	2055/6		00	08	09

Taluka :- Rapar

District :- Kutch

State :- Gujarat

Name of Village	Survey No	Part if Any	ROU Area		
			Ha.	Ar.	Sq.mt.
1	2	3	4		
1. Bhimasar	2055/8		00	05	05
(Contd...)	2055/7		00	04	19
	2054/6		00	04	20
	2054/4	P	00	04	85
	2054/5	P	00	12	82
	2054/3	P	00	05	67
	2053/6		00	05	24
	2053/5		00	10	95
	2052/2		00	01	89
	2052/1		00	12	49
	2052/5		00	00	51
	2051/3	P	00	00	96
	2051/2	P	00	14	15
	2050/3		00	16	80
	2049/4		00	00	33
	2049/3		00	06	31
	2049/2		00	28	49
	2048/1		00	15	74
	2046/2		00	22	02
	2045		00	13	93
	2044		00	13	08
	2043/1		00	24	81
	2041/1		00	13	29
	2041/2		00	00	36
	2040/2	P	00	75	13
	2039/1		00	14	60
	2038/5		00	01	83
	2038/4		00	02	88
	2038/3		00	04	65
	2038/2		00	09	25
	2037/4	P	00	19	44
	2037/2		00	00	08
	Trowers 2220/1	P	00	03	81

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2003

का. आ. 2201.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार आन्धा बैंक के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय, हैदराबाद के पंचाट (संदर्भ संख्या 263/2001) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 02-7-2003 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-12025/1/2003-आई. आर.(बी-II)]

अजय कुमार, डैस्क अधिकारी

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 2nd July, 2003

S. O. 2201.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 263/2001) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Hyderabad as shown in the annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Andhra Bank and their workman, which was received by the Central Government on 02-7-2003.

[No. L-12025/1/2003-IR(B-II)]

AJAY KUMAR, Desk Officer

ANNEXURE

**BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT
INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR
COURT AT HYDERABAD**

PRESENT :

Shri E. Ismail, B. Sc., LL.B., Presiding Officer

Dated the 9th day of June, 2003

INDUSTRIAL DISPUTE, L.C.I.D. NO. 263/2001

(Old I. D. No. 73/2000 Transferred from Labour Court-I, Hyderabad)

BETWEEN :

Sri D. Srinivasa Rao, H. No. 9-42-8, K. T. Road,
Kothapet, Behind Nehru Statue, Vijayawada-
520001. ... Petitioner

AND

1. The Assistant General Manager, (Disciplinary Matters) and Appellate Authority, Andhra Bank, Head Office, Bank Street, Koti, Hyderabad-500001.

2. The Chief Manager (Disciplinary Authority), Andhra Bank, Zonal Office, Guntur

... Respondents

APPEARANCES :

For the Petitioner : M/s. M. V. Rama Rao and K. Ravi, Advocates.

For the Respondent : M/s. S. Udayachal Rao, S. Lavanya Lakshmi, S. Vikramkadiya Babu & S. Mujib Kumar, Advocates.

AWARD

This case I. D. No. 73/2000 is transferred from Labour Court-I, Hyderabad in view of the Government of India, Ministry of Labour's Order No. H-11026/1/2001-IR(C-II) dated 18-10-2001 and renumbered in this Court as L.C.I.D. No. 263/2001. This is a case taken under Sec. 2A(2) of the I. D. Act, 1947 in view of the judgement of the Hon'ble High Court of Andhra Pradesh reported in W. P. No. 8395 of 1989 dated 3-8-1995 between Sri U. Chinnappa and M/s. Cotton Corporation of India and two others and notices were issued to the parties.

2. The brief facts of the case are : That the Petitioner was appointed as sub-staff on temporary basis in the year 1975. After working for three years he was confirmed in the year 1978.

3. While he was working as sub-staff at Mangalagiri branch of Guntur Zone a charge sheet dated 20-2-98 was issued to him by the 2nd Respondent namely Chief Manager (Disciplinary Authority) Andhra Bank, Zonal Office Guntur, alleging that he was unauthorisedly absent from duty since 19-1-98 to 31-3-98 on which date he joined duty and submitted his leave application along with a doctor certificate. As the Respondents were not satisfied with the explanation and Enquiry Officer was appointed and enquiry was conducted which was not properly conducted. Enquiry Officer held the charges proved. He was awarded with a punishment of dismissal from service by letter No. 426/20/65 dated 28-11-1998. The dismissal order was also not served as he was undergoing treatment at Guntur. When he came to know of the dismissal order he preferred an appeal on 8-4-99 to the first Respondent contending that he was absent from duty on medical ground and that he was forced to absent himself on certain days due to his ill-health. Without considering the same the major punishment was imposed on him. The appeal was also dismissed but however, the punishment of dismissal was modified to that of compulsory retirement. In fact, it is a removal from service. Even assuming that it is an act of misconduct imposing a punishment of dismissal/compulsory retirement is highly disproportionate to the misconduct alleged. It is submitted that the Petitioner is having a large family to support and his children are studying in colleges and if he is thrown out of employment for absence for reasons beyond control of the Petitioner he and his family will be put to irreparable loss. Hence, he may be directed to be reinstated.

4. In the counter it was stated that he was unauthorisedly absent on as many as six occasions and awarded various punishments of stoppage of increments for six months several times, reduction of pay by two stages. In all he was absent for a total period of 798 days. On 4-12-93 he was sanctioned extraordinary leave for 365 days out of total 13 years of service. The enquiry was fairly conducted. In fact the Appellate Authority took a lenient view and modified the punishment of dismissal into one of compulsory retirement. Para 19.7 of the Bipartite Settlement has no application in the case of the Petitioner. The Petitioner is a chronic, willful, unauthorized absentee, who by his unauthorized absence for long spells caused dislocation of the work in the branch. Hence, the petition may be dismissed.

5. Arguments were heard about the validity of domestic enquiry and this Court by an order dated 20-11-2002 held that the domestic enquiry is validly conducted.

6. Only question before me is whether this is a suitable case to invoke Sec. 11A of the I.D. Act.

7. The Learned Counsel for the Petitioner submits what all he has mentioned in the petition and further added that a lenient view may be taken otherwise the Petitioner and his family will be without any means to live.

8. The Learned Counsel for the Respondent submits that as it is already given in record that for 13 years of his service he was absent unauthorisedly for 798 days. No mercy need be shown to him. He also relied on 2003 1 CLR 989 Supreme Court, Maan Singh Vs. Union of India and others where a Constable first took medical leave for 3 days which was extended by 7 days but later he did not report and he was absent without leave. Ultimately the Supreme Court also dismissed the appeal confirming his dismissal order.

9. It may be seen that in the chargesheet his previous absence, punishment all are mentioned and as all those things are mentioned in the charge sheet they will also have to be taken into consideration. In fact all these have been brought in the enquiry about various punishments. From the counter it is clear that he has been unauthorisedly absent from duty for a total period of 790 days that is more than 2 years. I think if such chronic absenteeism is condoned, it will be a misplaced sympathy. It is not a matter of one or two occasions but number of occasions and he has been given number of chances. Hence, the order of compulsory retirement as modified by Appellate Authority is just and correct and does not warrant any interference from this Court. Hence, the Petitioner is not entitled to any relief.

Award passed accordingly. Transmit.

Dictated to Kum. K. Phani Gowri, Personal Assistant transcribed by her corrected and pronounced

by me in the Open Court on this the 9th day of June, 2003.

E. ISMAIL, Presiding Officer

APPENDIX OF EVIDENCE

Witnesses examined for the Petitioner	Witnesses examined for the Respondent
---------------------------------------	---------------------------------------

NIL

NIL

Documents marked for the Petitioner

NIL

Documents marked for the Respondent

NIL

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2003

का. आ. 2202.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय, हैदराबाद के पंचाट (संदर्भ संख्या 179/2002) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 02-7-2003 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-34011/3/2000-आई. आर.(एम.)]

अजय कुमार, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 2nd July, 2003

S.O. 2202.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 179/2002) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Hyderabad as shown in the annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Visakhapatnam Port Trust and their workman, which was received by the Central Government on 02-7-2003.

[No. L-34011/3/2000-IR(M)]

AJAY KUMAR, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT AT HYDERABAD

Present

Shri E. Ismail, Presiding Officer

Dated the 9th June, 2003

INDUSTRIAL DISPUTE, NO. 179/2002

(Old I. D. No. 25/2000 Transferred from Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Visakhapatnam)

BETWEEN :

The General Secretary,
Visakhapatnam Harbour &
Port Workers Union,
D. No. 26-26-27, Harbour
Approach Road, Visakhapatnam.Petitioner

AND

The Chairman,
Visakhapatnam Port Trust,
Visakhapatnam.Respondent

APPEARANCES :

For the Petitioner : Sri B. V. Rao, Authorised
representative

For the Respondent : M/s. A. Krishnam Raju, G.
Dinesh Kumar & G. V. N.
Babu, Advocates.

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour by its order No. L-34011/3/2000-IR(M) dated 4-7-2000 referred the following dispute under section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 for adjudication to the Industrial Tribunal cum Labour Court, Visakhapatnam between the management of Visakhapatnam Port Trust and their workmen which has been transferred to this Tribunal in view of Government of India, Ministry of Labour's Order No. H-11026/1/2001-IR(C. II) dated 18-10-2001 bearing No. ITID 25/2000. The reference is :

SCHEDULE

"Whether the seniority list published by the management of Visakhapatnam Port Trust in order No. 14456 dated 24-11-1998 keeping S/Shri R. Sree Ramulu, K. Raja Rao, S. Mohana Rao, B. Varada Raju and Y. Venkata Rao, Motor Mechanics Grade-II as seniors over S/Shri J. Aseerwadani, D. Kollayya, K. Siva Rao, Komma Venkata Rao Ch. Suryanarayana, M. Naidu and G. Ch. Y. Naidu cancelling order No. 105 dated 22-7-1996 which is under challenge by the Visakhapatnam Harbour & Port Workers Union is legal and/or justified ? If not, to what relief the concerned union is entitled ?

The reference is renumbered in this Tribunal as I. D. No. 179/2002 and notices issued to the parties.

2. The Petitioner union filed a claim statement stating that the union was registered in the year 1936 and ever since functioning as a leading bargaining agent, representing a substantial segment of workforce in the management establishment by contributing their share for the prosperity, development and growth of this Core Sector Establishment by maintaining industrial peace throughout. All the seven workmen whose seniority issue has been referred are union members and are continuing

in service since last three decades. Their details are given in the schedule.

3. The management establishment is an autonomous body corporate namely Visakhapatnam Port Trust and is established by Central Government under Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963. The Chairman and Deputy Chairman are full time Central Government servants and the Trustees of the Board are appointed by Central Government, serving part time on the Board representing various Central and State Government Departments, trade and commerce connecting with Port operations and also the labour employed in the Port. The Honorary President of the union is also represented at Trustee on the Board of Trustees. The Board of Trustees is the Governing Body and is empowered to make regulations/rules by delegated authority under Section 123 of the Act. The Chairman of the Board of Trustees is competent authority in the administration of all the employees through statutory obligation under sub-section (2) of Section 22 of the Act. That the size and importance is emphasized to high light the employee relations that the Respondent is required to maintain, under this background of public importance.

4. That all the service regulations meant for the employees have been framed by Central Government G.S.R. 324 (annexure fourteen) are Visakhapatnam Port employees (regular recruitment, seniority and promotion) Regulations, 1964. They are mandatory service rules. Contravention is illegal and is fundamental violation. Regulation 11 prescribed procedure of maintaining seniority amongst permanent employees. Regulation 4 guarantees gradation of seniority, Regulation 6 ensures procedure of substantive appointment. Regulation 7 dictates procedure of filling up of vacancies. So also Regulation 16 ensures formation and function of Departmental promotion committee. It is violation of these Regulations by Respondent management, by taking law into their own hands by the Department heads, changing seniority rating abruptly and arbitrarily, contrary to Regulations, to suit the vested interests, which in turn caused substantial damage to the career and employment conditions to the Petitioner union members, brought this dispute before this Hon'ble Tribunal praying justice.

5. That it is incumbent upon the management, statutorily imposed under Section 23 of Major Port Trust's Act, that the Respondent is required to maintain a "Schedule of Employees" and which Schedule requires sanction of Central Government. Thus, any change in the service condition of workmen requires prior approval from Central Government. That all the Petitioners (of the union) who have been put in a continuous service, ranging 30 to 20 years in Group 'A' of the Schedule, are several years senior to the workmen under Group 'B', whose dispute has been referred to this Hon'ble Tribunal. The said seniority has already been fixed confirmed and

published by Respondent in the year 1991, upon merger of grades and cadres, upon abolition of steam craft, gradually replacing it with Diesel Craft in the Floating Section of Mechanical Engineering Department. The cadre wide seniority "inter-se" in this F. C. Section is maintained under G.S.R. 324 Regulations. Contravening these statutory norms, the Respondent changed the seniority rating abruptly and arbitrarily, without obtaining prior permission from Central Government, to the detriment of the union members under Group 'A' in the Schedule. This action is illegal, mala fide besides violation of Rules and Regulations and therefore cannot be justified. The said contravention calls for interference by this Hon'ble Tribunal.

7. That their subsequent representation before management led them nowhere. Frustrated, the union took the matter into conciliation and the resultant reference by central government through Ministry of Labour Order No. L-34011/3/2000-IR(M) dated 4-7-2000 (the Schedule to the order reads as above in para 1 of this Award). That the Petitioner union respectfully submits that changing the seniority rate is illegal, mala fide and arbitrary and the said action caused substantial damage to the Petitioners service condition, and thus their seniority be restored as it stood originally. Therefore, it is prayed to declare the impugned action of the Respondent changing their seniority rating of the Petitioner workmen, represented by union through the order dated 24-11-1998 is illegal, mala fide by ab initio void and cannot be justified and consequently direct the Respondent to maintain the seniority schedule as is existing in office order No. CME/E/A/105 dated 22-7-1996, with their respective seniority for filling-up the existing promotion posts and pass such other order or orders as this Hon'ble Tribunal deems fit and proper in the interest of justice.

8. A counter was filed. That all service regulations meant for employees such as Visakhapatnam Port Trust (recruitment, seniority and promotion) Regulations, 1964 were made under the provisions of Major Port Trust Act, 1963 and these regulations came into effect w.e.f. 28-2-1964. All these changes were made according to these provisions and there is no violation in this regard. That the schedule employees is different from seniority lists. Schedule of employees contains strength of the employees in each cadre in various departments and sections. The Respondent Board is the authority for approval of schedule of employees and seniority lists, with the approval of the Respondent only, changes if any be required will be made. In the present case also, the approval of seniority list vide O.O., No. 14456 dated 24-11-98. Allegations made in para 6 of the claim statement are all denied and this Respondent submits that all the employees referred in the Petitioners' union may have put in continuous service from 22-30 years in the cadre of fitter-Gr. II and not in the cadre of MM-Gr. II.

On abolition/decommission of the Steam Crafts replacing in the FC Section, the staff in Steam Crafts became surplus and re-deployed on Diesel Crafts in consultation with the unions and on taking the approval of the Respondent. After the approval of the Respondent who is competent and accordingly the seniority was fixed as agreed in the minutes of meeting with the representatives of all the Unions, and the Petitioner is one among them. This Respondent further submits that the Union meeting was held on 14-2-91, where in CME clarified that the seniority of the incumbents in the Steam Pool has to be continued from the date of their transfer and appointment in the Diesel Pool. This was agreed by all the unions including the Petitioner's union also. So, this Respondent taken action legally valid and not violated any rules and regulations. The claim is filed with baseless allegations. Hence, the Petition should be dismissed.

9. Sri V. Ch. Masen, General Secretary of the union examined himself as WW1. He deposed that the dispute is raised by their union and it was not settled at the conciliation level. Hence, the government made the reference vide Ex. W1 dt. 18-11-1999, which is minutes of conciliation proceedings held before Assistant Labour Commissioner (C), Visakhapatnam. Ex. W2 dated 4-12-98 is the union's representation before management, Ex. W3 is dated 7-12-98 union's representation before ALC(C). Ex. W4 is the notice to all parties before the ALC(C). Ex. W5 dated 22-2-99 is the management's reply before ALC(C). Ex. W6 dated 29-6-87 management's office order. Ex. W7 management's letter to union with minutes of meeting. Ex. W8 is management's office order, Ex. W9 dated 31-12-94 relevant extracts from seniority list. Ex. W10 dated 29-5-96 management's order of approval of seniority. Ex. W11 dated 22-5-96 is management's office order of revised seniority list. Ex. W12 dated 24-11-98 is management's order changing seniority cancelling earlier order. Ex. W13 is management's order of changed seniority. Ex. W14 dated 29-2-1964 V.P.T.E. (R, S & P) Regulations, 1964. Ex. W15 is relevant extracts from the Major Port Trusts Act, 1963. Ex. W16 is the proceedings framed by the Respondent for filling up the posts of Motor Mechanical Grade-I and other resultant vacancies in the FC section. Proceedings dated 10-5-2000. The Respondent management also promoted three other workmen who are juniors to the Petitioners. Ex. W17 is the schedule attached to the claim petition showing the seniority of Group 'A' workmen over the Group 'B' workmen and the workmen shown in the Group 'B' of the Schedule are promoted ignoring the claims of Group 'A' workmen subsequent to the filing of the claim statement of workmen's union. Prayer is that the seniority of Group 'A' workmen in Ex. W17 may be maintained.

10. In the cross examination, he deposed that the workmen shown in Group 'A' Ex. W17 are the mergers

who are deployed from Steam Craft to Diesel Craft. It is true that the workmen shown in Group 'B' in Ex. W17 are the incumbents in the diesel pool. It is not true to say that as per alleged 'A' Group schedule are promoted as MM-II in diesel pool. It is true that in the meeting of the unions on 14-2-1991 the seniority of incumbent in steam pool and their appointment in the diesel pool are discussed. He does not know if the management issued any notification dated 3-4-94 fixing the seniority of existing staff. It is not true to say that mergers shown in Group 'A' in Ex. W17 are shown as juniors to Group 'B' workers contained in Ex. W17. It is true that the notification dated 3-4-1991 shown to him was issued in pursuance of the minutes held on 14-2-91 by all the unions with the management. It is true that Group 'A' workmen are shown as juniors to Group 'B' workmen as per the notification dated 3-4-91. Ex. M1 is the notification dated 3-4-1991 together with the existing seniority list of motor mechanic Grade-II. It is true that the seniority list as in 1991 is the same as even today. It is not true to say that in case of decommission workmen will be retrenched. It is true that the workmen in the steam craft were redesignated as MM Grade-II in diesel craft when the same was wound up. In the year 1996 the seniority under 105 of the order dated 22-7-96 is changed as shown in Ex. W14. Visakhapatnam Port Employees Union raised a dispute before the ALC(C), Visakhapatnam questioning the same. The ALC(C) advised to settle the matter at local level. On 24-11-98 the Respondent held a meeting that the representatives of Visakhapatnam Port Employees Union and confirmed the seniority based on the notification dated 3-4-91. It is true that they raised a dispute taking advantage of the order 105 dated 22-7-96. In the re-examination he deposed that their union is a negotiating union since 1936. The management never communicated any communication stating that it committed a mistake.

11. Sri Putta Sankar, Foreman, Chief Mechanical Engineering Department, Visakhapatnam Port Trust deposed as WW2. He deposed that right from the beginning he is working in CME Department. He was demoted as charge-man. He was awarded punishment twice. Once he was punished because he did not work according to contract, second time he participated in strike. When he was Assistant Foreman he did not maintain diesel Log Books. After his becoming foreman he maintained Log Books. Till today Log books are being maintained. The Log books are available with the Department. He cannot say who is the senior in the Department. In the cross examination he stated that the Log Books will be destroyed as per the government orders after lapse of time. Log book will not show seniority. Log books of 1991 and 1992 are not traced out and he is not aware whether they are destroyed or not.

12. Sri S. Muthyala Rao, Personnel Officer, deposed that he is working as Personnel Officer in Visakhapatnam

Port Trust in Mechanical Engineering Department. Ex. M1 is the order dated 3-4-91 which is a transfer order of the staff from steam crafts to the diesel crafts based on the decision taken in the meeting held on 14-2-91 that all the unions including claimant's union. Basing on the order dated 3-4-91 the seniority list enclosed and was prepared and intimated to all the unions as per the procedure in vogue. Ex. M2 is the certified copy of the minutes of the proceedings dated 8-11-97 held in between the Visakhapatnam Port Trust Employees Union and Manager (Operations). Ex. M3 is the certified copy of the letter dated 27-10-98 issued by Manager (Operations) addressed to Chief Mechanical Engineer restoring the original seniority as shown in Ex. M1. Ex. M4 is the certified copy of the order dated 24-11-98 showing the seniority list as per Ex. M1. Ex. M5 is the internal order dated 1-8-2000 showing the seniority as per Ex. M4 dated 24-11-98. Ex. M6 is the certified copy of the Minutes of the meeting held on 13-8-1993 with regard to the decommissioning of the Tugs Visakha and D. D. Waltair and the staff who were working the decommissioned Tugs to be absorbed in Diesel Tugs and the staff to be transferred from Steam crafts to the diesel crafts are to be shown as juniors to the staff already existing in the diesel craft. In the said meeting claimant union also participated and agreed to the same. Ex. M7 is the certified copy of the Minutes dated 14-2-91 by all the unions. Ex. M1 is in pursuance of Ex. M7. So the order dated 24-11-98 is passed basing the minutes dated 14-2-91. The claimants union did not dispute Ex. M1 order then and now they are questioning the same as well as Ex. M4 order and both the orders are one and the same. In the cross examination he deposed that he is serving in the Visakhapatnam Port Trust since last 30 years. He does not know when the steam craft and diesel craft were introduced in the Port Trust. He does not know as to why the steam craft was decommissioned in the year 1991. The material evidencing the communication of the seniority list annexed to Ex. M1 order is not now available. In the year 1996 on the representation of the workmen they altered the seniority. Again, it was rectified in the year 1998. There was no communication of the change of seniority list from the year 1996 to 1998 to all the unions. They did not communicate the change ordered in 1996 is done inadvertently by them to any union. Again the witness stated that he does not know if it is communicated to the unions. He denied the suggestion that the claimants are entitled to retain their seniority as contained in Ex. W11 order dated 22-7-96. In re-examination, he deposed that in Ex. M4 it is clearly stated that the copies are communicated to all.

13. It is argued by the Learned Counsel for the Petitioners that all the Petitioners whose matter is referred by the Government of India are in Group 'A' service from 20 to 30 years and several years seniors to the workmen

under Group 'B'. The said seniority has been fixed and confirmed and published by Respondent in the year 1991 upon merger of grades and cadres upon abolition of scheme steam craft, gradually replacing it with Diesel craft in the floating Section of Mechanical Engineering Department. The cadre wise seniority "inter-se" in this F.C. Section is maintained under the G.S.R. 324 Regulations. Contravening and Statutory norms, the Respondent changed the seniority abruptly and orderly without obtaining prior permission from Central Government to the detriment of the union members under Group 'A' in the Schedule and the change is illegal. He submits that as no notice was given it is squarely comes under the full Bench Judgement of the Hon'ble High Court reported in at page 278, 1976 Andhra Law Times Reports wherein it is held as follows, "So far as the second contention of Mr. Suryanarayana is, I am of the opinion that it was an error on the part of the authorities... Right or wrong, a certain right had been created of the Petitioner by the order dated 16-9-70 and when that has been taken away it was only proper that a show cause notice be issued to the Petitioner. Hence, only the ground that show cause notice was issued to the Petitioner before cancelling the order dated 16-9-70. Notice should be issued as to why the order dated 16-9-70 confirming the Petitioner in the permanent post of the typist with effect from 1-6-70 should not be cancelled and thereafter proceed accordingly." He therefore submits that only on that ground the reference has to be ordered in favour of the Petitioner.

14. The Learned Counsel for the Respondent submits that Ex. M1 order was prepared with the consultation of all the members of the union, then they did not dispute and now they are disputing. It is submitted by the Personnel Officer MW1 Mr. S. Muthyala Rao, that the 1991 seniority list was altered in 1996 on the representation of the workmen. Again it was rectified in the year 1998. He denied that the claimants are entitled to restore their seniority as contained in Ex. W11 order dated 22-7-96. In Ex. M4 it is mentioned that it is communicated to one and all. The Respondent management relied on *V. K. Dubey and others Vs. Union of India and others* (1997) 5 Supreme Court Cases page 81 wherein their Lordships held that staff working on diesel side of Railways absorbed on electrical side, on introduction of electrical engines—seniority on electrical side, held to be fixed from the date of deployment on that side without granting benefit of service rendered on diesel side because absorption saved the staff from retrenchment—seniority of deployed staff could not be fixed above the staff already working on electrical side." So he submits that these persons were who worked in the steam crafts on abolition of steam crafts in consultation with the unions and on taking the approval of the Respondent the seniority was fixed as grade in the minutes

of the meeting with the representatives of all the unions and the Petitioner union is one among them. The meeting was held on 14-2-1991 wherein CME clarified that the seniority of the incumbents in the steam pool has to be condemned from the date of their transfer and appointment in the diesel pool. As argued, the Petitioner union also agreed to the same and all other unions. He therefore submits that the reference may be answered in favour of the Respondent.

15. It may be seen that Ex. W1 is the failure report of the conciliation officer. Ex. W2 is dated 4-12-98 a notice given by the union stating as follows : "(1) A decision was taken by the management to utilize the services of the Fitter Gr. II of the de-commissioned Steam Crafts in a gainful manner in consultation of the recognized union, (2) It was resolved to absorb the Fitter Gr. II of the decommissioned Steam Crafts after re-designating them as M. M. Gr. II and absorbed in the Diesel Pool with the concurrence of the Chairman communicated vide, M(op)'s Lr. No. F/15343/86, dated 3-4-91, (3) The seniority of the re-designated M. M. Gr. II was fixed and issued to all the incumbents through an Order vide, CME's Order No. CME/E/A/105, dated 22-7-96, (4) That their Union has represented the concern of the incumbents when it was understood that CME is insisting action to alter the seniority for which the CME assured them that there is no alteration in the seniority of the re-designated M. M. Gr. II incumbents for which the sanction of the Chairman was obtained and communicated, (5) All of a sudden an Order was released vide CME's Order No. E/A/MM Gr. II/98/14456, dated 24-11-98 altering the seniority of the incumbents despite assurance". That the said alteration was done in response to the decision arrived at ALC(C) without making them a party for the dispute before the ALC(C) and agreed to alter the seniority which is contrary to practice and procedure. Ex. W3 is another notice that the seniority is altered without notice. Ex. W4 is the notice from ALC(C) about conciliation proceedings. Ex. M2 is dated 8-11-97 wherein it was agreed that the seniority of the existing staff should be protected over the merged steam staff. Ex. M3 is the letter to cancel the office order dated 22-7-96 and revive the original Office Order No. CME/E/A 359 dated 21-5-91. Ex. M4 is dated 24-11-96 where the change of seniority in the cadre of Motor Mechanic Gr. II in floating crafts section of Mechanical Engineering Department was communicated. That the seniority list dated 1-8-2000 is Ex. M5. Ex. M6 is the minutes of the meeting held on 13-8-93 where the union representatives also agreed to the same as follows : "the existing vacancies of diesel side are to be filled before absorbing the steam staff and the steam staff to be made juniors to the existing staff in the cadres". WW1 has stated in the cross examination that workmen shown in Group 'A' of Ex. W17 are the mergers who are deployed from steam craft

to diesel craft and workmen shown in Group 'B' in Ex. W17 are the incumbents at the diesel pool. It is true that in the meeting of the union on 14-2-91 of the union, the seniority of the incumbents in steam pool and their appointments in the diesel pool are discussed. He does not know if the management issued any notification dated 3-4-91 fixing the seniority of the existing staff. It is true that the notification dated 3-4-91 shown to him was issued in pursuance of the minutes held on 14-2-91 by all the unions with the management. It is true that Group 'A' workmen are shown as per the notifications dated 3-4-91. Ex. M1 is the notification dated 3-4-91 together with the existing seniority list of motor mechanic Gr. II. It is true that the seniority list as in 1991 is the same as even today. It is true that the workmen in the steam craft are redesignated as M. M. Gr. II in diesel craft when the steam craft was wound up. In 1996, the seniority list was changed. V.P.E. Union raised the dispute before ALC(C), Visakhapatnam questioning the same. The Respondent held a meeting of the representatives of the V. P. E. Union and confirmed the seniority list based on the notification dated 3-4-91. He deposed that the management never communicated any communication stating that it was a mistake.

16. MW1 has deposed that a decision was taken to transfer the staff from steam craft to the diesel craft basing on the decision on 14-2-91 with all the unions including the claimant's union. Seniority list was prepared and intimated to all the unions. Ex. M2 is the certified copy of the minutes of the meeting held before the ALC(C), Visakhapatnam with the V.P.E. Union. Ex. M5 is the order dated 1-8-2000 showing the seniority. Ex. M6 is the minutes of the meeting held on 13-8-93 on the subject of absorption of steam staff. The order dated 24-11-98 is passed basing on the minutes dated 16-2-91. The claimant union did not dispute the same and now they are questioning. In the year 1996 on the representation of the workmen they altered the seniority. Again it was rectified in the year 1990.

17. It may be seen that having considered all the evidences before me, it is clear that all the unions including this union was there in 1991 when all these decisions were taken and even in subsequent meetings and now they are trying to take advantage of the 1996 order which was inadvertently issued by the management. No doubt, the full Bench Judgement of the Hon'ble High Court cited by the Petitioner's Counsel goes to show that a notice should be given even if seniority is wrongly fixed. But WW1 is no other than the Port Trust Employees General Secretary of the union admits in the cross-examination that on 24-11-98 the Respondent held a meeting with the representatives of the V.P.E. Union and confirmed the seniority based on the notification dated 3-4-91. So having done so now they can not say that they have no notice. More so, the Judgement 1997 (5) Supreme

Court cases page 81, cited by the Respondent Counsel is squarely fits in the case herein actually the staff working on the steam side their jobs were saved by deployment on diesel side. Hence, I do not find any merits in the case of the Petitioners. Hence, "it is held that the seniority list published by the management of Visakhapatnam Port Trust in order No. 14456 dated 24-1-98 is legal and justified and the concerned union is not entitled for any relief."

Award passed. Transmit.

Dictated to Kum. K. Phani Gowri, Personal Assistant transcribed by her corrected and pronounced by me on this the 9th day of June, 2003.

E. ISMAIL, Presiding Officer

Appendix of Evidence

Witnesses examined for the Petitioner	Witnesses examined for the Respondent
--	--

WW1 : Sri V. Ch. Masen	MW1 : Sri M. Mutyala Rao
WW2 : Sri Putta Sankar	

Documents marked for the Petitioner

- Ex. W1 : Copy of minutes of conciliation proceedings dt. 18-11-99
- Ex. W2 : Copy Lr. No. HPW/CME(FC)/64/98/1029 dt. 4-12-98
- Ex. W3 : Copy of Lr. No. HPW/I.D./128/98/1036 dt. 7-12-98
- Ex. W4 : Copy of Lr. No. 16/43/98-ALC dt. 4-1-99
- Ex. W5 : Copy of Lr. No. F3/VHIPW/ALC/182/99 dt. 22-2-99
- Ex. W6 : Copy of O. O. No. CME/E/255 dt. 29-6-87
- Ex. W7 : Copy of Lr. No. E/U/Meeting/91/2096 dt. 18-2-91
- Ex. W8 : Copy of O. O. No. CME/E/A/359, dt. 3-4-91
- Ex. W9 : Copy of seniority list of Class III & IV as on 31-12-94
- Ex. W10 : Copy of Lr. No. F1/15343/86 dt. 29-5-96
- Ex. W11 : Copy of O. O. No. CME/E/A/105 dt. 22-7-96
- Ex. W12 : Copy of order No. E/A/MM. Gr. II/98/14456 dt. 24-11-98
- Ex. W13 : Copy of order No. CME/A/FC/SENIORITY LISTS/1999 dt. 1-8-2000
- Ex. W14 : Copy of ruling of Visakhapatnam Port Emp. (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations' 64
- Ex. W15 : Copy of Chapters I to IV of The Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963)

Ex. W16 : Copy of order No. CME/E/A/FC/MM Gr. I/2000/6103 dt. 10-10-2000

Ex. W17 : Copy of seniority list of F. C. Section Group 'A' of Mechanical Engg. Department

Documents marked for the Respondent

Ex. M1 : Copy of O. O. No. CME/E/A/359, dt. 3-4-91

Ex. M2 : Copy of minutes of the meeting held on 8-11-98

Ex. M3 : Copy of Lr. No. F1/IR/15343/472/97 dt. 4-10-98

Ex. M4 : Copy of order No. E/A/MM. Gr. II/98/I4456 dt. 24-11-98

Ex. M5 : Copy of order No. CME/A/FC/SENIORITY LISTS/1999 dt. 1-8-2000

Ex. M6 : Copy of minutes of the meeting held on 13-8-98

Ex. M7 : Copy of minutes of the meeting held on 14-2-91

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2003

का. आ. 2203.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसार गे, केन्द्रीय सरकार दूरसंचार विभाग के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय, हैदराबाद के पंचाट (संदर्भ संख्या 189/2001) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 02-7-2003 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-40025/16/2003-आई. आर.(डी. यू.)]

कुलदीप राय वर्मा, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 2nd July, 2003

S. O. 2203.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 189/2001) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Hyderabad now as shown in the annexure in the Industrial Disputes between the employers in relation to the management of Deptt. of Telecom. and their workman, which was received by the Central Government on 02-7-2003.

[No. L-40025/16/2003-IR(DU)]

KULDIP RAI VERMA, Desk Officer

ANNEXURE

**BEFOR THE CENTRAL GOVERNMENT
INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR
COURT AT HYDERABAD**

PRESENT :

Shri E. Ismail, B. Sc., LL.B., Presiding Officer

Dated the 31st day of May, 2003

INDUSTRIAL DISPUTE, L.C.I.D. No. 189/2001

(Old I. D. No. 56/2000 Transferred from Labour Court-III, Hyderabad)

.....Petitioner

BETWEEN :

Sri M. Srinivasulu S/o Sri Chandraiah, P. O. Marikal, Mahaboobnagar District.

AND

The General Manager, Telecom, Mahaboobnagar-509050,Respondent

APPEARANCES :

For the Petitioner : M/s. C. Suryanarayana and P. V. Rao, Advocates.

For the Respondent : Sri R. S. Murthy, Advocate.

AWARD

This case I. D. No. 56/2000 is transferred from Labour Court-III, Hyderabad in view of the Government of India, Ministry of Labour's order No. H-11026/1/2001-IR(C-II) dated 18-10-2001 and renumbered in this Court as L.C.I.D. No. 189/2001. This is a case taken under Sec. 2A(2) of the I. D. Act, 1947 in view of the judgement of the Hon'ble High Court of Andhra Pradesh reported in W.P. No. 8395 of 1989 dated 3-8-1995 between Sri U. Chinnappa and M/s. Cotton Corporation of India and two others.

2. The brief averments in the petition are : That the petitioner belongs to Musti Golla caste which is a BCD community. He was employed initially as direct labourer on self contract and later through contract labour agencies like Para Amount Security System (Pvt.) Ltd., and Asian Security Force to perform route patrolling to safeguard the Optical Fiber Cable (OFC) laid in the route, besides jungle cutting along the route stretching for about 22 KM and for ensuring that the stones implanted 2 KM apart at the manholes in the cable route are kept in right condition so that they may be visible from a distance. He was paid wages at the rate Rs. 1200 per month on behalf of the Department. They were also paying the Petitioner on the behalf of the said contract agencies. Such contractual employment is violative of the dictum laid down in the Judgement in Secretary, Haryana State Electricity Board Vs. Suresh & Others, 1999(2) Scale 315 [equal to 1999 SCC (L & S) page 765]. According to the said judgement on abolition of the contract system the employees become the employees of the Principal employer. Hence, retrenching him with effect from 1-1-2000 is in gross violation of the mandatory provisions of Sec. 25-F. He was employed from 6-8-98 to 31-12-99. Thereafter he was

employed through contractors referred above. Needless to say that he never saw the face of any contractor and he was retrenched from 1-1-2000 by the AE. Hence, the Petitioner may be reinstated with continuity of service and back wages protection of his seniority according to his turn on the seniority list of casual mazdoors. It may be declared that the Petitioner who has rendered 240 days of services by 2-4-99 is entitled to grant of temporary status with effect from the date under the Casual Labourers (Grant of Temporary Status and Regularization) Scheme of the Department of Telecommunications, 1989 vide DoT's No. 269-10/89 STN dt. 7-11-89 which was issued pursuant to the directions in the Judgement dated 27-10-87 in daily rated casual labour in P & T Services Vs. Union of India and others, vide AIR 1987 Supreme Court page 2347. Accordingly, the Hon'ble Court may be pleased to pass an award.

3. The brief averments in the counter are : That the petition is bad for misjoinder of unnecessary parties like Respondent and non-joinder of the effective parties who awarded the contract and who arranged the bills for payment to the contractors. The Assistant Engineer (Sub-Divisional Engineer) Coaxial Maintenance, Mahaboobnagar is working under the control of the Divisional Engineer, Coaxial Maintenance, Kurnool. The said officer is working under the control of the Director Maintenance, Southern Telecom Sub-Region, Hyderabad.

4. The Petitioner was engaged by AE concerned now redesignated as SDE, during the period 3-8-98 to 30-9-98 for route patrolling. He never worked after 30-9-98. There is no relationship of employer and employee with effect from 1-10-98.

5. Respondent organization has awarded contract works on experimental basis for protection of OFC routes and the Director, Maintenance Southern Telecom sub region, Hyderabad in his orders dated 3-9-98 has awarded the contract to M/s. Paramount Security System (Pvt.) Ltd., 610, Chenoy Trade Centre Post Box No. 1637, Secunderabad vide tender approval No. DMHD/Tenders/Vol. XXXXII/98-99/3 dated 3-9-98, accordingly the said agency executed the works. The Respondent organization has nothing to do with the engagement of agents by the said agency. The said agency has a right to employ the persons of their choice. The Petitioner has not impleaded the said agency as one of the parties in the present industrial dispute. From 1-11-99 contract was given to M/s. Asian Security Forces. The said agency is also not impleaded as one of the parties. As it was found out that, there are incidents of break down of OFC due to activities of external forces. Hence, the contract work was abolished.

6. The Petitioner never worked for 240 days. He was gainfully employed from 1-10-98 and tried to procure employment by filing the present case. He also filed further counter affidavit stating that the Petitioner appear to have

been engaged by contractors by Paramount Security System (Pvt.) Ltd. and Asian Security Forces to perform the route petrol to safeguard the optical fiber between Jedcherla-Kurnool-Mahaboobnagar-Makkal. The contractor Paramount Security System (Pvt.) Ltd., commenced from 1-10-98 and terminated on 31-10-99. And contract with Asian Security Force commenced from 1-11-99 and expired on 31-12-2000. The provisions of Sec. 25-F ID Act are not attracted for engagement of the casual labour by the said agencies. The Hon'ble High Court has settled the Law in NFC Vs. K. Penta Reddy 2002(2) ACD 384 that retrenchment of contract labour does not arise when they were engaged for a specific period and for a particular job, the provisions of Sec. 25-F are not attracted. The allegation that there was retrenchment from 1-1-2000 is baseless and the petition is misconceived frivolous, vexatious and deserves to be dismissed with costs.

7. The Petitioner examined himself as WW1 wherein he deposed something which is not mentioned in the petition that is he worked from 1992 to 1994. And he again deposed the facts stated in the petition and further deposed that he was employed from 6-8-98 he worked till 29-2-2000. Ex. W1 is the original register of his works. Ex. W2 is the Xerox copy containing the working days particulars. Ex. W3 is the cable trench along side of the water route in which casual employees and Departmental candidates are shown. Ex. W4 is the notice indicating that the important telephone cables are passing through this way and requesting to die before laying. Then he marked for some mile stones and further deposed that he rendered more than 240 days in each year during 1992 to 1994 and later from June, 1998 to 29-2-2000. He was terminated without notice or compensation. Hence, he may be granted the relief prayed for.

8. In the cross-examination he deposed that he was engaged in 1992 in the project work for laying down the cables. The work related to the portion between Kothakota and Janampet. He was sponsored by Line Inspector Sri Bal Reddy. He was paid wages at the rate of Rs. 1200 per month. He was paid roughly for 3 years. Again he was engaged in Nalgonda for about 3 months for digging to fill up man holes clean the departmental vehicles. That he was engaged on 6-8-98 by AE, Mr. Dasaratham upto February, 2000. That he was disengaged on the ground that work is completed. That he was paid wages by Dasaratham. He denied that he was employee of Paramount Security System (Pvt.) Ltd., and Asian Security Force.

9. The Respondent examined Sri A. Dasarath and MW1. He deposed that the contract was given vide Ex. M1 to M/s. Paramount Security System (Pvt.) Ltd., another contract was given to M/s. Asian Security Force from 1-9-99 to 31-12-2000. The same is Ex. M3. M/s. Paramount Security System (Pvt.) Ltd., was paid

directly and the same is marked as Ex. M2. The contract with Asian Security Force, secunderabad was terminated from 1-1-2001. The same is marked as Ex. M4. The payments are made to Asian Security Force directly vide Ex. M5. Before being engaged by the contractors, the Petitioner was engaged by the Asst. Engineer from 3-8-98 to 30-9-98. The Petitioner is admittedly an employee of the contractors. The ban letter dated 30-11-89 is Ex. M6 the said ban is retreated dated 12-2-99 vide Ex. M7. There is no retrenchment in terms of Sec. 25-F of the I.D. Act. The claim is baseless.

10. In the cross-examination he deposed that in the absence of maintenance staff being provided by territorial divisions the maintenance engaged casual labourers for a specified period on time bound basis. The reason is there no sanctioned strength in the project offices. He is not aware whether any relaxation order was issued on 22-6-88 relating to recruitment on employment of casual labour. He denied that there were no contractors. He never approached him.

11. It is agreed by the Learned Counsel for the Petitioner that assuming without admitting that his work was entrusted through licensed contractor. The Respondent employer did not file the Licence obtained under Sec. 12 of Act. The contractor has not been examined. The contract is sham and calculated to hoodwink, mislead and exploit the Petitioner. In such case, the alleged contract workers are deemed to be direct employees of the employer or principal employer. The workman stated that he was employed for route patrolling over a distance of 22 KM between Shakhapur and Bhoothpur to safeguard Optical fiber Cable. That the A.E., Mahaboobnagar directly paid him the wages. The Petitioner never saw any contractor. Further he was under paid Rs. 1200 per month ignoring Hon'ble Supreme Court's direction. Moreover, during the periods from 1992 to 1994 and again during June, 1998 to February, 2000 the workman rendered more than 240 days service in each year vide Ex. W1 and Ex. W2 and Sec. 25-F was not followed. Seniority list of casual mazdoors of Mahaboobnagar Telecom District did not include his name though he became part and parcel of it's casual mazdoors. So he submits that he may be reinstated with back wages and other benefits.

12. It is argued by the Learned Counsel for the Respondent that the Petitioner admittedly is contract labour with M/s. Paramount Security Systems Pvt. Ltd., and M/s. Asian Security Forces from 1-10-98 to 31-10-99 and from 1-11-99 to 31-12-99 vide Ex. M3 and Ex. M4. That according to the claim petition he was engaged directly during 6-8-98 to 31-10-98. That it is alleged that he was not informed that he was working under contractor. MW1 has deposed that the matter was given to the contractors. He also relied on the Hon'ble Supreme Court of India judgement in 2002-II-LLJ page

321 wherein it was held by the Hon'ble Supreme Court that engagement/appointment of the Respondent-workmen was for a specific purpose and for a particular period. Their disengagement after completion of the purpose and expiry of the period was in terms of contract of service and therefore not a 'retrenchment' within the meaning of Sec. 2(oo) of the I. D. Act."

13. It may be seen that the Petitioner has not made the contractors party. WW1 has deposed that although he was engaged by A. E. Dasarath from 6-8-98 to February, 2000 he was disengaged on the ground that the work was completed. He denied that he was an employee M/s. Paramount Security Systems Pvt. Ltd. and M/s. Asian Security Force. The Respondent examined Sri M. Srinivasulu, Mr. G. V. R. Setty, AGM (Legal) deposed that the work of laying down cable, digging carrying loads huge manual work force is required and the works are intermittent and not continuous. The works are also seasonal. That they first engaged M/s. Paramount Security System Pvt. Ltd. and M/s. Asian Security Force vide Ex. M1 and Ex. M3 are the contracts and the amount was paid directly to the said contractors. The claimant is admittedly an employee under the contractors. There is no retrenchment. No doubt, Ex. W1 is his working certificate given by officer Incharge, Telephone Exchange, Moosapet and similarly Ex. W1 is endorsed by him. But, when we go through Ex. M1 and Ex. M2 we find that it is M/s. Paramount Security Systems Pvt. Ltd., people who filed and they have received the amount for mazdoors also as per Ex. M2. Similarly Ex. M5 also, M/s. Asian Security Force have received the amounts. So it cannot be denied that there was no contractors. Even it is prohibited contract. In Steel Authority of India case, "No automatic absorption of the contract labour even if it is a prohibited contract". Now question is the only thing that is left for this Court is to find out whether the said engagement of the contractors was sham or nominal. For that there is no evidence before me except of WW1. But yet as WW1 not mentioned in the petition states that he has also worked even in 1992 to 1994 through contractors. I am of the opinion that the ends of the justice would be met if the Respondents were to engage any casual mazdoors in future the Petitioner should be given preference taking his seniority as August, 1998. In fact the very petition says that he worked only directly under the Assistant Engineer from 6-8-98 to 31-10-98. Thereafter, he was employed through contractors M/s. Paramount Security Systems Pvt. Ltd., and later through M/s. Asian Security Force. So it may be seen that the very petition says that he was employed through contractors and that he was dismissed on the ground that the contract has expired and the said contractors are not being made a party to say that the contract was sham and nominal. Hence, the only relief that can be given to him is that, in future because he has served the Department,

there is no loss to the Department also if a direction is given that the Petitioner shall be considered in future whenever any casual employment is given taking his seniority as August, 1998.

Dictated to Kum. K. Phani Gowri, Personal Assistant transcribed by her corrected award passed by me on this the 31st day of May, 2003.

E. ISMAIL, Presiding Officer

Appendix of Evidence

Witnesses examined for the Petitioner	Witnesses examined for the Respondent
--	--

WW1 : Sri M. Srinivasulu	MW1 : Sri A. Dasarath
--------------------------	-----------------------

Documents marked for the Petitioner

Ex. W1 : Original register of WW1's works
Ex. W2 : Copy of working days particulars of WW1
Ex. W3 : Cable trench photograph
Ex. W4 : Photograph showing notice of important telephone cables.
Ex. W5 : Photograph indicating stone OFC JP-6
Ex. W6 : Photograph similar to Ex. W5
Ex. W7 : Photograph indicating stone OFC JP-7
Ex. W8 : Photograph indicating stone OFC 7/5
Ex. W9 : Photograph indicating stone OFC 8/5
Ex. W10 : Photograph indicating stone OFC 8/6
Ex. W11 : Photograph indicating stone OFC 8/9
Ex. W12 : Photograph indicating stone OFC JP-9
Ex. W13 : Photograph indicating stone OFC 9/9
Ex. W14 : Photograph indicating stone OFC JP-14
Ex. W15 : Photograph indicating stone OFC 15/3
Ex. W16 : Photograph indicating stone OFC 15/6
Ex. W17 : Photograph indicating stone OFC 14/1
Ex. W18 : Photograph indicating stone OFC 16/4
Ex. W19 : Photograph indicating stone OFC JP-6
Ex. W20 : Photograph indicating stone OFC 17/4

Documents marked for the Respondent

Ex. W1 : Copy of contract with M/s. Paramount Security System Pvt. Ltd.
Ex. W2 : Copy of Payment voucher for Ex. M1 contract
Ex. W3 : Copy of contract with M/s. Asian Security Force
Ex. W4 : Copy of letter of termination of contract with M/s. Asian Security Force

Ex. W5 : Copy of payment voucher for Ex. M3 contract
Ex. W6 : Copy of ban letter No. EST-76/RLG/VI/dt. 30-11-89

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2003

का. आ. 2204.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, दूर संचार विभाग के प्रबंधन के सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, हैदराबाद के पंचाट (संदर्भ संख्या 190/2001) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 2-7-2003 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-40025/12/2003-आई.आर.(डी.यू.)]
कुलदीप राय वर्मा, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 2nd July, 2003

S.O. 2204.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 190/2001) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Hyderabad now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Deptt. of Telecom and their workman, which was received by the Central Government on 2-7-2003.

[No. L-40025/12/2003-IR(DU)]
KULDIP RAI VERMA, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT
INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT
AT HYDERABAD

PRESENT : Shri E. Ismail, B.Sc., LL.B.,
Presiding Officer

Dated the 31st day of May, 2003

INDUSTRIAL DISPUTE L.C.I.D. No. 190/2001

(Old I.D. No. 57/2000 Transferred from
Labour Court-III. Hyderabad)

BETWEEN :

Sri G. Satyanarayana,
S/o G. Balaiah,
P.O. Marikal,
Mahaboobnagar District
AND

The General manager,
Telecom,
Mahaboobnagar-509 050.

APPEARANCES :

For the Petitioner	: M/s C. Suryanarayana and P.V. Rao, Advocates
For the Respondent	: Sri R.S. Murthy, Advocate

AWARD

This case I.D. No. 57/2000 is transferred from Labour Court-III, Hyderabad in view of the Government of India, Ministry of Labour's order No. H-11026/1/2001-IR(C-II) dated 18-10-2001 and renumbered in this Court as L.C.I.D. No. 190/2001. This is a case taken under Sec. 2 A (2) of the I.D. Act, 1947 in view of the judgment of the Hon'ble High Court of Andhra Pradesh reported in W.P. No. 8395 of 1989 dated 3-8-1995 between Sri U. Chinnappa and M/s. Cotton Corporation of India and two others.

2. The brief averments in the petition are : That the petitioner belongs to Musti Golla caste which is a BCD community. He was employed initially as direct labourer on self contract and later through contract labour agencies like Para Amount Security Systems (Pvt.) Ltd., and Asian Security Force to perform route patrolling to safeguard the Optical Fiber Cable (OFC) laid in the route, besides jungle cutting along the route stretching for about 23 KM and for ensuring that the stones implanted 2 KM apart at the man holes in the cable route are kept in right conditions so that they may be visible from a distance. He was paid wages at the rate Rs. 1200 per month on behalf of the Department. They were also paying the Petitioner on the behalf of the said contract agencies. Such contractual employment is violative of the dictum laid down in the Judgement in *Secretary, Haryana State Electricity Board Vs. Suresh & Others*, 1999 (2) Scale 315 [equal to 1999 SCC (L&S) page 765]. According to the said Judgement on abolition of the contract Systems the employees become the employees of the Principal employer. Hence, retrenching him with effect from 1-1-2000 is in gross violation of the mandatory provisions of Sec. 25-F. He was employed from 5-11-98 to 31-12-99. Thereafter he was employed through contractors referred above. Needless to say that he never saw the face of any contractor and he was retrenched from 1-1-2000 by the A.E. Hence, the petitioner may be reinstated with continuity of service and back wages protection of his seniority according to his turn on the seniority of casual mazdoors. It may be declared that the Petitioner who has rendered 240 days of service by 2-4-99 is entitled to grant of temporary status with effect from the date under the Casual labourers (Grant of Temporary Status and Regularization) Scheme of the Department of Telecommunications, 1989 vide DoT's No. 269-10/89-STN dt. 7-11-89 which was issued pursuant to the directions in the Judgement dated 27-10-87 in daily rated casual labour in *P & T Services Vs. Union of India and Others*, vide AIR 1987 Supreme Court page 2347. Accordingly the Hon'ble Court may be pleased to pass an award.

3. The brief averments in the counter are : That the petition is bad for misjoinder of unnecessary parties like Respondent and non-joinder of the effective parties who

awarded the contract and who arranged the bills for payment to the contractors. The Assistant Engineer (Sub-Divisional Engineer) Coaxial Maintenance, Mahaboobnagar is working under the control of the Divisional Engineer, Coaxial Maintenance, Kurnool. The said officer is working under the control of the Director Maintenance, Southern Telecom Sub-Region, Hyderabad.

4. The Petitioner was not engaged by A.E. concerned now redesignated as SDE, for route patrolling. He never worked in the Respondent organization. There is no relationship of employer and employee in existence between the Petitioner and the Respondent.

5. Respondent organization has awarded contract works on experimental basis for protection of OFC routes and the Director, Maintenance Southern Telecom Sub-Region, Hyderabad in his orders dated 3-9-98 has awarded the contract to M/s Paramount Security Systems (Pvt.) Ltd., 610, Chenoy Trade Centre Post Box No. 1637, Secunderabad vide tender approval No. DMHD/Tenders/Vol.XXXII/98-99/3 dated 3-9-98, accordingly the said agency executed the works. The Respondent organization has nothing to do with the engagement of agents by the said agency. The said agency has a right to employ the persons of their choice. The Petitioner has not impleaded the said agency as one of the parties in the present industrial dispute. From 1-11-99 contract was given to M/s Asian Security Forces. The said agency is also not impleaded as one of the parties. As it was found out that, there are incidents of break down of OFC due to activities of external forces. Hence, the contract work was abolished.

6. The Petitioner had not worked in the Respondent organization and as such he cannot claim any protection under the provisions of the labour laws including I.D. Act, 1947. He was gainfully employed and tried to procure employment by filing the present case. He also filed further counter affidavit stating that the Petitioner appear to have been engaged by contractors by Paramount Security Systems (Pvt.) Ltd. and Asian Security Forces to perform the route patrol to safeguard the optical fiber between Jedcherla-Kurnool and Mahaboobnagar-Metal. The contractor Paramount Security Systems (Pvt.) Ltd., commenced from 1-10-98 and terminated on 31-10-99. And contract with Asian Security Force commenced from 1-11-99 and expired on 31-12-2000. The provisions of Sec. 25-F of the I.D. Act are not attracted for engagement of the casual labour by the said agencies. The Hon'ble High Court has settled the Law in *NFC Vs. K. Penta Reddy* 2002(2) ACD 384 that retrenchment of contract labour does not arise when they were engaged for a special period and for a particular job, the provisions of Sec. 25-F are not attracted. The allegation there was retrenchment from 1-1-2000 is baseless and the petition is misconceived frivolous, vexatious and deserves to be dismissed with costs.

6. The Petitioner examined himself as WW1 wherein he deposed the facts as mentioned in the petition

and further deposed that he was employed from 5-11-98 he worked till 31-12-99. Ex.W1 is the particulars of his working days from 5-11-98 to 31-12-99. The original register of Ex. W1 is Ex.W1A. Ex.W2 is his photo in Marikal Telephone Exchange from where he was required to report everyday to the A.E. He was terminated without notice or compensation. Hence, he may be granted the relief prayed for.

7. In the cross examination he deposed that he was engaged on 5-11-98 for cable patrolling between Gurumukla and Devarkadara. That he worked under A.E., Mr. Dasratham from 5-11-98 till 31-12-99. That he was disengaged on the ground that work is completed. That he was paid wages by Dasratham directly Rs. 1200 per month. He denied that he was employee of Paramount Security Systems (Pvt.) Ltd., and Asian Security Force. In the re-examination he deposed that the A.E. did not tell him that he was engaged on contract basis. The A.E. did not give him any letter or orders regarding his engagement under contractor.

8. The Respondent examined Sri A. Dasarath and MW1. He deposed that the contract was given vide Ex.M1 to M/s Paramount Security Syatem (Pvt.) Ltd., another contract was given to M/s Asian Security Force from 1-9-99 to 31-12-2000. The same is Ex.M3. M/s Paramount Security Systems (Pvt.) Ltd., was paid directly and the same is marked as Ex.M2. The contract with Asian Security Force, Secunderabad was terminated from 1-1-2001. The same is marked as Ex.M4. The payments are made to Asian Security Force directly vide Ex.M5. The claimant was never engaged by the Respondent at any time either as casual labour or contract labour. The engagement of the claimant by the contractor is not within the knowledge and no payments were made to him by the Department. The ban letter dated 30-11-89 is Ex.M6 the said ban is retreated dated 12-2-99 vide Ex.M7. There is no retrenchment in terms of Sec. 25-F of the ID Act. The claim is baseless.

9. In the cross examination he deposed that in the absence of maintenance staff being provided by territorial divisions the maintenance engaged casual labourers for a specified period on time bound basis. The reason is there no sanctioned strength in the project offices. He is not aware whether any relaxation order was issued on 22-6-88 relating to recruitment on employment of casual labour. He denied that there were no contractors. He never approached him.

10. It is argued by the Learned Counsel for the Petitioner that assuming without admitting that his work was entrusted through licensed contractor the Respondent employer did not file the Licence obtained under Sec. 12 of Act. The contractor has not been examined. The contract is sham and calculated to hoodwink, mislead and exploit the Petitioner. In such case, the alleged contract workers

are deemed to be direct employees of the employer or principal employer. The workman stated that he was employed for route patrolling over a distance of 23 KM between Devarakonda and Gudigandla to safeguard Optical Fiber Cable. That the A.E., Mahaboobnagar directly paid him the wages. The petitioner never saw any contractor. Further he was under paid Rs. 1000 per month ignoring Hon'ble Supreme Court's direction. Moreover, during the period from 5-11-98 to 31-12-99 the workman rendered more than 240 days service in each year vide Ex. W1 and Ex. W2 and Sec.25-F was not followed. Seniority list of casual mazdoors of Mahaboobnagar Telecom District did not include his name though he become part and parcel of it's casual mazdoors. So he submits that he may be reinstated with back wages and other benefits.

11. It is argued by the Learned Counsel for the Respondent that the Petitioner admittedly is contract labour with M/s Paramount Security Systems Pvt. Ltd. and M/s Asian Security Forces from 5-11-98 to 31-12-99 vide Ex.M3 and Ex.M4. That according to the claim petition he was engaged directly during 5-11-98 to 31-12-99. That it is alleged that he was not informed that he was working under contractor. MW1 has deposed that the matter was given to the contractors. He also relied on the Hon'ble Supreme Court of India in 2002-II-LLJ page 321 wherein it was held by the Hon'ble Supreme Court that engagement/appointment of the Respondent-workmen was for a specific purpose and for a particular period. Their disengagement after completion of the purpose and expiry of the period was in terms of contract of service and therefore not a 'retrenchment' within the meaning of Sec. 2(o) of the I.D. Act.

12. It may be seen that the Petitioner has not made the contractors party. WW1 has deposed that although he was engaged by A.E. Dasarath from 5-11-98 to 31-12-99 he was disengaged on the ground that the work was completed. He denied that he was an employee M/s Paramount Security Systems Pvt. Ltd. and M/s Asian Security Force. The Respondent examined Sri M. Srinivasulu, Mr. G.V.R. Setty, AGM(Legal) deposed that the work of laying down cable, digging carrying loads huge manual work force is required and the works are intermittent and not continuous. The works are also seasonal. That they first engaged M/s Paramount Security System Pvt. Ltd., and M/s Asian Security Force vide Ex.M1 and Ex.M3 are the contractors and the amount was paid directly to the said contractors. The claimant is admittedly an employee under the contractors. There is no retrenchment. No doubt, Ex.W1A is his working days particulars. But, when we go through Ex.M1 and Ex.M2 we find that it is M/s Paramount Security Systems Pvt. Ltd., people who filed and they have received the amount for mazdoors also as per Ex.M2. Similarly Ex.M5 also, M/s. Asian Security Force have received the amounts. So

it cannot be denied that there were no contractors. Even it is prohibited contract. In Steel Authority of India case, "No automatic absorption of the contract labour even if it is a prohibited contract". Now question is the only thing that is left for this Court is to find out whether the said engagement of the contractors was sham or nominal. For that there is no evidence before me except of WW1. But yet as WW1 not mentioned in the petition states that he has also worked even in 1998 to 1999 through contractors. I am of the opinion that the ends of the justice would be met if the Respondents were to engage any casual mazdoors in future the Petitioner should be given preference taking his seniority as November, 1998. In fact, the very petition says that he worked only directly under the Assistant Engineer from 5-11-98 to 31-12-99. Thereafter, he was employed through contractors M/s. Paramount Security Systems Pvt. Ltd., and later through M/s. Asian Security Force. So it may be seen that the very petition says that he was employed through contractors and that he was dismissed on the ground that the contract has expired and the said contractors are not being made a party to say that the contract was sham and nominal. Hence, the only relief that can be given to him is that, in future, because he has served the Department, there is no loss to the Department also if a direction is given that the Petitioner shall be considered in future whenever any casual employment is given taking his seniority as November, 1998.

Dictated to Kum. K. Phani Gowri, Personal Assistant transcribed by her, corrected and award passed by me on this the 31st day of May, 2003.

E. ISMAIL, Presiding Officer

Appendix of evidence

Witnesses examined for the Petitioner	Witnesses examined for the Respondent
--	--

WW1 : Sri G. Satyanarayana	MW1 : Sri A. Dasarath
----------------------------	-----------------------

Documents marked for the petitioner

Ex.W1 : Copy of working days particulars of WW1
Ex.W1A : Original register of WW1's works
Ex.W2 : Petitioner's photograph in Marikal Telephone exchange

Documents marked for the Respondent

Ex.M1 : Copy of contract with M/s. Paramount Security Systems Pvt. Ltd.
Ex.M2 : Copy of payment voucher for Ex.M1 contract
Ex.M3 : Copy of contract with M/s. Asian Security Force
Ex.M4 : Copy of letter of termination of contract with M/s. Asian Security Force
Ex.M5 : Copy of payment voucher for Ex.M3 contract

Ex.M6 : Copy of ban letter No. EST-76/RLG/VI/dt. 30-11-89

Ex.M7 : Copy of Ir. retreating Ex.M6 ban dt. 12-2-99

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2003

का. आ. 2205.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, दूर संचार विभाग के प्रबंधन के सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, हैदराबाद के पंचाट (संदर्भ संख्या 191/2001) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 2-7-2003 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-40025/13/2003-आई.आर.(डी.यू.)]

कुलदीप राय वर्मा, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 2nd July, 2003

S.O. 2205.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 191/2001) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Hyderabad now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Dept. of Telecom and their workman, which was received by the Central Government on 2-7-2003.

[No. L-40025/13/2003-IR(DU)]

KULDIP RAI VERMA, Desk Officer.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT
INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT
AT HYDERABAD

PRESENT : SHRI E. ISMAIL, B.Sc., LLB.,
Presiding Officer

Dated the 31st day of May, 2003

INDUSTRIAL DISPUTE L.C.I.D. No. 191/2001

(Old I.D. No. 59/2000 Transferred from
Labour Court-III, Hyderabad)

BETWEEN :

Sri G. Panduraju,
S/o Sri G. Ananthaiah,
P.O. Kothakota,
Mahaboobnagar District. : Petitioner

AND

The General Manager,
Telecom, BSNL,
Mahaboobnagar—509 050. : Respondent

APPEARANCE :

For the Petitioner : M/s. C. Suryanarayana and
P.V. Rao, Advocates

For the Respondent : Sri R.S. Murthy, Advocate

AWARD

This case I.D. No. 59/2000 is transferred from Labour Court-III, Hyderabad in view of the Government of India, Ministry of Labour's Order No. H-11026/1/2001-IR(C-II) dated 18-10-2001 and renumbered in this Court as L.C.I.D. No. 191/2001. This is a case taken under Sec. 2 A (2) of the I.D. Act, 1947 in view of the judgment of the Hon'ble High Court of Andhra Pradesh reported in W.P. No. 8395 of 1989 dated 3-8-1995 between Sri U. Chinnappa and M/s. Cotton Corporation of India and two others.

2. The brief averments in the petition are : That the petitioner belongs to Musti Golla caste which is a BCD community. He was employed initially as direct labourer on self contract and later through contract labour agencies like Paramount Security Systems (Pvt.) Ltd., and Asian Security Force to perform route patrolling to safeguard the Optical Fiber Cable (OFC) laid in the route, besides jungle cutting along the route stretching for about 20 Km and for ensuring that the stones implanted 2 Km apart at the manholes in the cable route are kept in right conditions so that they may be visible from a distance. He was paid wages at the rate Rs. 1200 per month on behalf of the Department. They were also paying the Petitioner on behalf of the said contract agencies. Such contractual employment is violative of the dictum laid down in the Judgement in *Secretary, Haryana State Electricity Board Vs. Suresh & Others*, 1999 (2) Scale 315 [equal to 1999 SCC (L&S) page 765]. According to the said Judgement on abolition of the contract system the employees become the employees of the Principal employer. Hence, retrenching him with effect from 1-1-2000 is in gross violation of the mandatory provisions of Sec. 25-F. He was employed from 1-11-98 to 31-12-99. Thereafter he was employed through contractors referred above. Needless to say that he never saw the face of any contractor and he was retrenched from 1-1-2000 by the A.E. Hence, the petitioner may be reinstated with continuity of service and back wages protection of his seniority according to his turn on the seniority of casual mazdoors. It may be declared that the Petitioner who has rendered 240 days of service by 1-7-99 is entitled to grant of temporary status with effect from the date under the Casual Labourers (Grant of Temporary Status and Regularization) Scheme of the Department of Telecommunications, 1989 vide DoT's No. 269-10/89-STN dt. 7-11-89 which was issued pursuant to the directions in the Judgement dated 27-10-87 in *Daily Rated Casual Labour in P & T Services Vs. Union of India and others*, vide AIR 1987 Supreme Court page 2347. Accordingly the Hon'ble Court may be pleased to pass an award.

3. The brief averments in the counter are : That the petition is bad for misjoinder of unnecessary parties like

Respondent and non-joinder of the effective parties who awarded the contract and who arranged the bills for payment to the contractors. The Assistant Engineer (Sub-Divisional Engineer) Coaxial Maintenance, Mahaboobnagar is working under the control of the Divisional Engineer, Coaxial Maintenance, Kurnool. The said officer is working under the control of the Director Maintenance, Southern Telecom Sub-Region, Hyderabad.

4. The Petitioner was not engaged by AE concerned now redesignated as SDE, for route patrolling. He never worked in the Respondent organization. There is no relationship of employer and employee between the organization and the Petitioner.

5. Respondent organization has awarded contract works on experimental basis for protection of OFC routes and the Director, Maintenance southern Telecom sub-region, Hyderabad in his orders dated 3-9-98 has awarded the contract to M/s. Paramount Security Systems (Pvt.) Ltd., 610, Chenoy Trade Centre Post Box No. 1637, Secunderabad vide tender approval No. DMHD/Tenders/Vol.XXXXII/98-99/3 dated 3-9-98, accordingly the said agency executed the works. The Respondent organization has nothing to do with the engagement of agents by the said agency. The said agency has a right to employ the persons of their choice. The Petitioner has not impleaded the said agency as one of the parties in the present industrial dispute. From 1-11-99 contract was given to M/s. Asian Security Forces. The said agency is also not impleaded as one of the parties. As it was found out that, there are incidents of break down of OFC due to activities of external forces. Hence, the contract work was abolished.

6. The Petitioner had not worked in the Respondent organization. He was gainfully employed and tried to procure employment by filing the present case. He also filed further counter affidavit stating that the Petitioner appear to have been engaged by contractors by Paramount Security Systems (Pvt.) Ltd. and Asian security Forces to perform the route patrol to safeguard the optical fiber between Jedcherla-Kurnool-Mahaboobnagar-Metal. The contractor paramount Security Systems (Pvt.) Ltd., commenced from 1-10-98 and terminated on 31-10-99. And contract with Asian Security Force commenced from 1-11-99 and expired on 31-12-2000. The provisions of Sec. 25-F of the I.D. Act are not attracted for engagement of the casual labour by the said agencies. The Hon'ble High Court has settled the Law in *NFC Vs. K. Penta Reddy* 2002(2) ACD 384 that retrenchment of contract labour does not arise when they were engaged for a specific period and for a particular job, the provisions of Sec. 25-F are not attracted. The allegation that there was retrenchment from 1-1-2000 is baseless and the petition is misconceived, frivolous, vexatious and deserves to be dismissed with costs.

6. The Petitioner examined himself as WW1 wherein he deposed that he was employed from 1-11-98

to 31-12-99 and he again deposed the facts stated in the petition and further deposed that he was employed from 1-11-98. Ex.W1 is the Xerox copy of his working days from 1-11-98 to 25-11-99. Ex W2 is the Xerox copy containing sheet containing pages 3 and 4 of original of Ex.W1. He was terminated without notice or compensation. Hence, he may be granted the relief prayed for.

7. In the cross examination he deposed that he was engaged by the Telephone Department from 1-11-98 to 26-2-2000 for route patrolling of OFC cable between Allampur and Jallapur. He was engaged directly by the AE, Sri Suresh. He was paid wages at the rate of Rs. 1200 per month. Again he was engaged for the same work between Williamkonda and Pepperu from 1-2-99 to 26-2-2000. That he was paid wages directly by AE. It is not true to suggest that he is not casual labour and not entitled for regularization after completion of 240 days and grant of temporary status as casual labour under the orders dated 7-11-89. The AE did not tell him that his employment was contractual.

8. The Respondent examined Sri T. Suresh as MW1. He deposed that the contract was given vide Ex.M1 to M/s Paramount Security Systems (Pvt.) Ltd., another contract was given to M/s Asian Security Force from 1-9-99 to 31-12-2000. The same is Ex.M3. M/s Paramount Security Systems (Pvt.) Ltd., was paid directly and the same is marked as Ex.M2. The contract with Asian Security Force, Secunderabad was terminated from 1-1-2001. The same is marked as Ex.M4. The payments are made to Asian Security Force directly vide Ex.M5. The ban letter dated 30-11-89 is Ex.M6 the said ban is reiterated dated 12-2-99 vide Ex.M7. There is no retrenchment in terms of Sec. 25-F of the ID Act. The claim is baseless.

9. In the cross examination he deposed that in the absence of maintenance staff being provided by territorial divisions the maintenance engaged casual labourers for a specified period on time bound basis. The reason is there no sanctioned strength in the project offices. He denied that there were no contractors. He never approached him.

10. It is argued by the Learned Counsel for the Petitioner that the Respondent employer did not file the Licence obtained under Sec. 12 of Act. The contractor has not been examined. The contract is sham and calculated to hoodwink, mislead and exploit the Petitioner. In such case, the alleged contract workers are deemed to be direct employees of the employer or principal employer. The workman stated that he was employed for route patrolling over a distance of 20 KM between Allampur and Jallapur to safeguard Optical Fiber Cable. That the A.E., Mahboobnagar directly paid him the wages. The petitioner never saw any contractor. Further he was underpaid Rs. 1200 per month ignoring Hon'ble Supreme Court's direction. Moreover, during the periods from 1-11-98 to 26-2-2000 the workman rendered more than 240 days

service in each year vide Ex. W1 and Ex. W2 and Sec. 25-F was not followed. Seniority list of casual mazdoors of Mahboobnagar Telecom District did not include his name though he became part and parcel of its casual mazdoors. So he submits that he may be reinstated with back wages and other benefits.

11. It is argued by the Learned Counsel for the Respondent that the Petitioner admittedly is contract labour with M/s. Paramount Security Systems Pvt. Ltd., and M/s. Asian Security Forces from 1-10-98 to 31-10-99 and from 1-11-99 to 31-12-99 vide Ex.M3 and Ex.M4. That according to the claim petition he was engaged directly during 6-8-98 to 31-10-98. That it is alleged that he was not informed that he was working under contractor. MW1 has deposed that the matter was given to the contractors. He also relied on the Hon'ble Supreme Court of India in 2002-II-LLJ page 321 wherein it was held by the Hon'ble Supreme Court that engagement/appointment of the Respondent-workmen was for a specific purpose and for a particular period. Their disengagement after completion of the purpose and expiry of the period was in terms of contract of service and therefore not a 'retrenchment' within the meaning of Sec. 2(oo) of the I.D. Act.

12. It may be seen that the Petitioner has not made the contractors party. WW1 has deposed that although he was engaged by A.E. from 1-11-98 to 26-2-2000 and he was disengaged on the ground that the work was completed. He denied that he was an employee M/s. Paramount Security Systems Pvt. Ltd. and M/s. Asian Security Force. The Respondent cross examined Sri G. Panduraju and also examined Sri Mr. G.V.R. Setty, AGM (Legal) deposed that the work of laying down cable, digging carrying loads huge manual work force is required and the works are intermittent and not continuous. The works are also seasonal. That they first engaged M/s Paramount Security System Pvt. Ltd., and M/s Asian Security Force vide Ex.M1 and Ex.M3 are the contracts and the amount was paid directly to the said contractors. The claimant is admittedly an employee under the contractors. There is no retrenchment. No doubt, Ex.W1 is his working days particulars. But, when we go through Ex.M1 and Ex.M2 we find that it is M/s. Paramount Security Systems Pvt. Ltd., people who filed and they have received the amount for mazdoors also as per Ex.M2. Similarly Ex.M5 also, M/s. Asian Security Force have received the amounts. So it cannot be denied that there were no contractors. Even it is prohibited contract. In Steel Authority of India case, "No automatic absorption of the contract labour even if it is a prohibited contract". Now question is the only thing that is left for this Court is to find out whether the said engagement of the contractors was sham or nominal. For that there is no evidence before me except of WW1. WW1 mentioned in the petition that he has worked from in 1998 to 2000 through contractors. I am of the opinion that the ends of the justice would be

met if the Respondents were to engage any casual mazdoors in future the Petitioner should be given preference taking his seniority as November, 1998. In fact, the very petition says that he worked only directly under the Assistant Engineer from 1-11-98 to 31-12-99. Thereafter, he employed through contractors M/s. Paramount Security Systems Pvt. Ltd., and later through M/s. Asian Security Force. So it may be seen that the very petition says that he was employed through contractors and that he was dismissed on the ground that the contract has expired and the said contractors are not being made a party to say that the contract was sham and nominal. Hence, the only relief that can be given to him is that, in future, because he has served the Department, there is no loss to the Department also if a direction is given that the Petitioner shall be considered in future whenever any casual employment is given taking his seniority as November, 1998.

Dictated to Kum. K. Phani Gowri, Personal Assistant transcribed by her corrected and award passed by me on this the 31st day of May, 2003.

E. ISMAIL, Presiding Officer

Appendix of evidence

Witnesses examined for the Petitioner	Witnesses examined for the Respondent
WW1 : Sri G. Panduraju	MW1 : Sri T. Suresh

Documents marked for the Petitioner

Ex.W1 : Xerox Copy of WW1's working days from 1-11-98 to 25-11-99
Ex.W2 : Xerox Copy of pages 3 & 4 of Ex.W1

Documents marked for the Respondent

Ex.M1 : Copy of contract with M/s. Paramount Security Systems Pvt. Ltd.
Ex.M2 : Copy of payment voucher for Ex.M1 contract
Ex.M3 : Copy of contract with M/s. Asian Security Force
Ex.M4 : Copy of letter of termination of contract with M/s. Asian Security Force
Ex.M5 : Copy of payment voucher for Ex.M3 contract
Ex.M6 : Copy of ban letter No. EST-76/RLG/VI/ dt. 30-11-89
Ex.M7 : Copy of reiteration letter to the ban dt. 12-2-99

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2003

का.आ. 2206.— औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार दूर संचार विभाग के प्रबंधन के सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, हैदराबाद के पंचाट (संदर्भ संख्या 244/2001) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 2-7-2003 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-40025/14/2003-आई.आर. (डी.यू.)]

कुलदीप राय वर्मा, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 2nd July, 2003

S.O. 2206.— In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 244/2001) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court, Hyderabad now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Deptt. of Telecom and their workman, which was received by the Central Government on 2-7-2003.

[No. L-40025/14/2003-IR(DU)]
KULDIP RAI VERMA, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT
INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT
AT HYDERABAD

PRESENT : Shri E. Ismail, B.Sc., LL.B.,
Presiding Officer

Dated the 9th day of June, 2003

INDUSTRIAL DISPUTE L.C.I.D. No. 244/2001

(Old I.D. No. 33/99 Transferred from Labour Court-I,
Hyderabad)

BETWEEN :

Sri J.A. Rahul,
S/o J.R. Arjun,
R/o 990, Kalasiguda, Bolaram,
Hyderabad-500 010.Petitioner

AND

The Principal General Manager,
Telecom District,
Suryalok Complex, Gunfoundry,
Hyderabad-500 001.Respondent

APPEARANCES :

For the Petitioner : M/s C. Suryanarayana &
P. Venkateswara Rao,
Advocates

For the Respondent : M/s A. Raghavaiah &
K. Bharathi Devi, Advocates

AWARD

This case I.D. No. 33/1999 is transferred from Labour Court-I, Hyderabad in view of the Government of India, Ministry of Labour's Order No. H-11026/1/2001-IR(C-II) dated 18-10-2001 and renumbered in this Court as L.C.I.D. No. 244/2001. This is a case taken under Sec. 2A (2) of the I.D. Act, 1947 in view of the judgment of the Hon'ble High Court of Andhra Pradesh reported in W.P. No. 8395 of 1989 dated 3-8-1995 between Sri U. Chinnappa and M/s. Cotton Corporation of India and two others and notices were issued to the parties.

2. The brief facts of the claim Petition are : That the Petitioner was employed as casual labourer in cross-bar installation work in Secunderabad Telephone Exchange for 789 days during the period from 1-8-85 to 16-11-87. Again from November, 1987 till 5-10-1989 for 462 days. Totally he worked for 1251 days thereafter he was not employed. That he fell sick on 16-12-89 but he continued to be sick till January, 1997 on account of rheumatic fever with arthritis. On his recovery Dr. Neelam Krishna gave him certificate that he was fit to return to work. Immediately, he approached the local authorities seeking reinstatement but, he was not taken back due to long absence. He therefore gave a representation dated 24-2-1997 which was acknowledged on 26-2-97. Hence, he may be reinstated.

3. A counter was filed stating that the Petitioner worked as a casual mazdoor in different spells of work till February, 1990, March, 1990 and April, 1990 again he remained absent. That on 24-2-97 he made his appearance for reemployment. The Petitioner stated that he was sick from 1989 but he reported for duty in February, 1990 and worked till 5th April, 1990. Again he absented himself for seven long years. The medical certificates contradict the said period. Hence, he is not entitled to any relief.

4. The Petitioner deposed as WW1 that he worked from 1-8-85 to 16-11-87 and again from 18-11-87 to 5-10-89. On 16-12-89 he fell sick and took treatment. Ex. W1 is the medical certificate issued by Medical Officer, Alwal. His representation to the Department to take him back is Ex. W2 dated 24-2-97. Ex. W3 shows his period of working from August, 1985 to November, 1987. Ex. W4 shows the number of working days from November, 1987 to October, 1989. He was not given notice or notice pay. In the cross-examination he deposed that it is not true that he failed to attend his duties now and then. It is not correct that on 23-2-90 he was warned by the Respondent for absenteeism. He denied that he worked up to 19-4-90.

5. MW1 deposed that the Petitioner worked in February, March, April, May, June and July, 1990. Ex. M1 shows that he worked upto August, 1990.

6. Arguments were advanced on the same lines.

7. It is argued by the Learned Counsel for the Petitioner and brief arguments were put forward by the Learned Counsel for the Petitioner that Sec. 25-F of the I.D. Act has not been followed. Several Judgements have been cited. Which I am afraid does not apply to the facts of this case and he submitted for reinstatement with back wages.

8. The Learned Counsel for the Respondent submitted that having worked in 1990 he has approached the Court in 1999 after a gap of 9 years and that itself is sufficient to dismiss the Petition.

9. It may be seen that as no limitation is provided people take chance and come over to the Court. Somehow, to gain something. Therefore, such persons deserve no sympathy where he says that he was sick from 16-12-89 and when Ex. M1 is produced containing 7 sheets, showing that he worked from February to August, 1990. It turns round and when he is cross-examined, says that Rheumatic Arthritis does not permit him to work. So all this is a gimmick. Now, he has come round saying that he wants some job or other. According to him from 1989 he did not work and issued the notice in 1997 and approached the Court in 1999. He deserves some sympathy as he has worked for 1251 days, if in future any casual employees are appointed, the Petitioner shall be given preference taking his seniority as 1-8-1985. However, a word of caution that this will be only for future appointment and will not affect any juniors working now.

Award passed accordingly. Transmit.

Dictated to Kum. K. Phani Gowri, Personal Assistant transcribed by her corrected and pronounced by me in the Open Court on this the 9th day of June, 2003.

E. ISMAIL, Presiding Officer

Appendix of evidence

Witnesses examined for the Petitioner	Witnesses examined for the Respondent
--	--

WW1 : Sri J.A. Rahul	MW1 : Sri V. Sudarshan
----------------------	------------------------

Documents marked for the Petitioner

Ex. W1 : Medical fitness certificate issued by Dr. Neelam Krishna dt. 16-1-97

Ex. W2 : Copy of representation of WW1 dt. 24-2-97

Ex. W3 : Copy of working days particulars of WW1 dt. 10-12-87

Ex. W4 : Copy of mazdoor days particulars of WW1 issued by SDE, Cable construction, Kavadiguda, Hyderabad

Documents marked for the Respondent

Ex. M1 : Copy of muster rolls from February to August, 1990

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2003

का.आ. 2207.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार दूर संचार विभाग के प्रबंधन के सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, हैदराबाद के पंचाट (संदर्भ संख्या 245/2001) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 2-7-2003 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-40025/15/2003-आई.आर. (डी.यू.)]

कुलदीप राय वर्मा, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 2nd July, 2003

S.O. 2207.— In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 245/2001) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court, Hyderabad now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Deptt. of Telecom and their workman, which was received by the Central Government on 2-7-2003.

[No. L-40025/15/2003-IR(DU)]
KULDIP RAI VERMA, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT
INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT
AT HYDERABAD

PRESENT : Shri E. Ismail, B.Sc., LL.B.,
Presiding Officer

Dated the 9th day of June, 2003

INDUSTRIAL DISPUTE L.C.I.D. No. 245/2001

(Old I.D. No. 37/99 Transferred from Labour Court-I,
Hyderabad)

BETWEEN :

Sri S. K. Sardar,
S/o S. K. Khader,
R/o H. No. 17-3-859/9,
Yakhutpura, Hyderabad. ...Petitioner

AND

The Principal General Manager,
Telecom District. Suryalok
Complex, Gunfoundry,
Hyderabad-500 001.Respondent

APPEARANCES :

For the Petitioner : M/s C. Suryanarayana &
P. Venkateswara Rao,
Advocates

For the Respondent : M/s A. Raghavaiah &
K. Bharathi Devi, Advocates

AWARD

This case I.D. No. 37/1999 is transferred from Labour Court-I, Hyderabad in view of the Government of India, Ministry of Labour's order No. H-11026/1/2001-IR(C-II) dated 18-10-2001 and renumbered in this Court as L.C.I.D. No. 245/2001. This is a case taken under Sec. 2A (2) of the I.D. Act, 1947 in view of the judgement of the Hon'ble High Court of Andhra Pradesh reported in W.P. No. 8395 of 1989 dated 3-8-1995 between Sri U. Chinnappa and M/s. Cotton Corporation of India and two others and notices were issued to the parties.

2. The brief facts of the claim Petition are : That the Petitioner worked as casual mazdoor in the jurisdiction

in the Assistant Engineer, Cables, Charminar. He was employed for 145 days during the months of February, March, August, and September of 1985. During May, and July, 1985 he worked for 85 days as per annexure-III though he was sick and need treatment. From 16-7-85 onwards he was at that time employed under the JTO, Cable Construction, Secunderabad under the said employer. The applicant became very sick and therefore informed his mustering Officer that he would not be able to attend and did not attend work from October, 1985 onwards due to severe illness. He was continuously under treatment from October, 1985 to August, 1987 for depression.

3. He was taken back in September, 1987 and he worked up to January, 1988 with small interruptions for 149 days. From September, 1987 to January, 1988 interruptions were due to non-employment and other reasons were not known to the Petitioner. The Petitioner has put in a total period of $145 + 80 + 149 = 374$ days. That after January, 1988 he was not employed although he approached. He was discriminated and therefore he prays for reinstatement with continuity of service.

4. A counter was filed stating that as per the work on hand casual mazdoors are engaged or disengaged and the entry of the job is contingent. As such the engagement would be so done through work order or muster rolls. They will be disengaged if there is no work. There is no retrenchment or termination. The scheme for temporary status was for those who were working continuously on muster rolls. In this case admittedly he worked for $145+80+149$ days in different spells. In the medical certificate period of treatment was from 10-7-85 to 9-8-87, whereas the Petitioner has worked for the entire 31 days in July, 1985 under muster roll No. 340/18. Hence, the petition may be dismissed.

5. The Petitioner examined himself as WW1 and deposed facts as stated in the chief examination Ex. W1 shows that he worked from February, 1985 to September, 1985 for 145 days. Ex. W2 shows that he worked in the month of May, June and July, 1985 for 80 days. Ex. W3 is the certificate shows that he was sick from 1-3-85 to 9-8-87. Ex. W4 shows that he worked from September, 1987 to January, 1988 in total 149 days. Ex. W5 shows a letter dated 7-2-89 seeking for employment. Ex. W6 is the notification for laying down cable work and calling for applications. Ex. W7 is a letter seeking for a job. That he was orally terminated in February, 1988. He was not issued any notice or notice pay. That he has been making representations. In the cross examination he deposed that there is no document to show that he informed the management before he went on long leave. He denied that he absented unauthorisedly.

6. Sri A. Pandurangam, SDO, examined himself as MW1 and deposed that any casual mazdoor works for

720 days in three years or 1200 days in five years is entitled for consideration for absorption as Group 'D' employee. By oversight another witness was examined as this is a transfer case and numbered as MW1 but actually he is MW2. MW2 Sri D. V. Krishnamachari deposed to the same facts in the chief examination. He also deposed that as Ex. W3 medical certificate shows that he was sick from 10-7-85 and although he worked for the entire July month. Hence, Ex. W3 is bogus.

7. It is argued by the Learned Counsel for the Petitioner and brief arguments were put forward by the Learned Counsel for the Petitioner that Sec. 25-F of the I.D. Act has not been followed. Several Judgements have been cited. Which I am afraid does not apply to the facts of this case and he submitted for reinstatement with back wages.

8. The Learned Counsel for the Respondent submitted that having worked in 1988 he has approached the Court in 1999 after a gap of 11 years and that itself is sufficient to dismiss the Petition.

9. It may be noted that Ex. W3 medical certificate itself is apparently bogus. However, we are not concerned with that because again he has worked from September, 87 to January, 88 and from February, 88 he has not been employed. No doubt, he has been making some representations one on 7-2-89, vide Ex. W5 and one in 1996 vide Ex. W7. So these are the two representations he has made. One immediately, one year after he was dismissed and other seven years after he was dismissed and then he took another three years to approach the Court. That itself shows would not entitle him for any relief. Moreover, he was a casual mazdoor dependent on the work he could have worked for 240 days or more at a stretch, according to himself he became sick and when he again went after number of years almost after two years he was again provided with job from September 1987 to January 1988. So whenever, there was work Department gave him the work, the casual nature of the work. The inordinate delay in approaching the Court or any forum will not entitle him to any relief except that as he has worked for 145 days in 1985 again he was taken from September 1987 to January 1988. Therefore, a direction is given that in future if any casual workers are employed by the Respondent the Petitioner shall be given preference taking his seniority as of 1985. However, a word of caution that this apply only for future engagement and will apply for engaging casual labourers and will not disturb any juniors who are already in casual employment.

Award passed accordingly. Transmit.

Dictated to Kum. K. Phani Gowri, Personal Assistant transcribed by her corrected and pronounced by me in the Open Court on this the 9th day of June, 2003.

E. ISMAIL, Presiding Officer

Appendix of evidence

Witnesses examined for the Petitioner	Witnesses examined for the Respondent
--	--

WW1 : Sri S. K. Sardar	MW1 : Sri A. Pandurangam
------------------------	--------------------------

	MW2 : Sri D. V. Krishnamachari
--	--------------------------------

Documents marked for the Petitioner

Ex. W1 : Copy of service certificate issued by A.E. Charminar, dt. 6-7-87

Ex. W2 : Copy of service certificate issued by SDO, Saifabad, dt. 30-3-95

Ex. W3 : Medical certificate for the period from 10-7-85 to 9-8-87

Ex. W4 : Copy of service certificate for a period of 149 days

Ex. W5 : Copy of representation of WW1 dt. 7-2-89

Ex. W6 : Copy of Lr. No. TA/STA/9-10/Genl/HD/II dt. 4-10-89

Ex. W7 : Copy of representation of WW1 to GMT, Hyderabad dt. Nil.

Documents marked for the Respondent

Ex. M1 : Copy of proceedings of the Asst. Director General (STN) relating to powers of C.G.M.S.

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 2003

का.आ. 2208.— औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचाट (संदर्भ संख्या 160/99) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 4-7-2003 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-42012/257/98-आई.आर. (डी.यू.)]

कुलदीप राय वर्मा, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 4th July, 2003

S.O. 2208.— In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 160/99) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court, Kanpur now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Indian Institute of Pulses Research and their workman, which was received by the Central Government on 4-7-2003.

[No. L-42012/257/98-IR(DU)]

KULDIP RAI VERMA, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SRI SURESH CHANDRA PRESIDING
OFFICER CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL
TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, SARVODAYA
NAGAR, KANPUR, U.P.

Industrial Dispute No. 160 of 1999

In the matter of dispute between—

Sri Gaffar Ali,

C/o Rajendra Prasad Shukla

115/193 A-2 Maswanpur

Kanpur - 208002

And

Director

Indian Institute of Pulses Research

G. T. Road Kanpur

AWARD

1. Central Government, Ministry of Labour, New Delhi vide notification no. L-42012/257/98/IR(DU) dated 3-5-99 has referred the following reference for adjudication to this Tribunal—

Whether the action of the Director, Indian Institute of Pulses Research, Kalyanpur, Kanpur in terminating the services of Sh. Gaffar Ali is legal and justified? If not, to what relief the workman is entitled?

2. The concerned workman has filed his statement of claim with the allegations that he was employed by the management of the Institute on 1-1-89 to perform the work of permanent nature against vacant post of permanent labour. It has been alleged that the workman was paid Rs. 2127 as wages by the management at the end of the month in accordance with the provisions of Minimum Wages as has been made applicable by the Govt. of India. It has further been alleged by the workman in his statement of claim that the management with a to protect themselves from the legal benefits payable to the workman attached his services with the licenced Contractor with effect from 1998. Workman has further alleged that he was in the services of the management much before the induction of Contractor by the management. The concerned workman alongwith his counterparts had performed the agriculture in the farm of the management, which was being supervised from time to time by the management. It has further been alleged by the workman that the management used to mark his attendance alongwith his counterparts in a attendance register. It has also been pleaded by the workman that the management is an Industry.

3. It has been further alleged by the workman that he had completed more than 240 days in each calendar year and his work and conduct remained satisfactory. It has further been alleged by the workman that the management of the Institute has terminated the services of the workman abruptly with effect from 23-5-98 and at

the time of termination of his services no notice, notice pay or retrenchment compensation was paid to him by the management, hence termination of the services is in breach of the provisions of Section 25F of the Act. It has also been alleged by the workman that after the termination of his services several fresh hands as labour were appointed by the management without affording any opportunity to him for his reemployment, hence management has also violated the provisions of Section 25H of the Act. The workman has also assailed his termination of service on the ground of Section 25G of the Act as several juniors to the workman is alleged to have been retained by the management and are working with the management. On the basis of aforesaid allegations it has been prayed by the workman that he is entitled for his reinstatement with effect from 23-5-98 with full back wages and continuity of service.

4. The management of the Institute has filed a detailed written statement wherein the claim of the workman has been denied on various grounds.

5. Workman has also filed his rejoinder statement wherein facts alleged by him in the statement of claim have been reiterated.

6. The workman was debarred from adducing his evidence on 6-6-2001 by this tribunal as none appeared in the case from the side of the workman nor workman himself appeared. The management filed their evidence on affidavit but failed to produce the witness before the Tribunal for cross examination by the workman, hence the evidence on affidavit cannot be accepted. From the order sheet of file it is evident that the workman moved an application dated 26-06-02 for permission to file certain documents and to recall the order passed by this tribunal by means of which the workman was debarred from adducing his evidence in the case. The said application of the workman came up for disposal on 21-05-03 before the tribunal but as none was present from the side of the workman nor his authorised representative appeared to press the application dated 26-6-2002, hence the application was rejected by the Tribunal, and the case was fixed for argument, on 6-6-03. Arguments in the case were advanced by the respective parties on 6-6-03.

7. As held earlier that the affidavit of the management cannot be read as evidence in the present case as the management failed to produce the person on whose behalf the affidavit has been filed for cross examination by the workman before the tribunal. The workman has already been debarred from adducing his evidence in the case. Hence it is a case in which virtually no evidence has been adduced by the either party. It was onus on the workman to have lead his evidence in support of his case but as he failed to do so the tribunal is left with no other option but to hold that the workman is not entitled for any relief for want of evidence.

8. Accordingly it is held that the concerned workman is not entitled for any relief for want of evidence on his behalf in the case. In the facts and circumstances the action of the management in terminating the services of the workman with effect from 23-5-98 cannot be held to be illegal and unjustified and the reference is answered in affirmative.

SURESH CHANDRA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 2003

का. आ. 2209.— औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार डाक विभाग के प्रबंधन के सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय, जोधपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 4-7-2003 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-40012/249/99-आई.आर. (डीयू.)]

कुलदीप राय वर्मा, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 4th July, 2003

S.O. 2209.— In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Jodhpur as shown in the annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Deptt. of Post and their workman, which was received by the Central Government on 4-7-2003.

[No. L-40012/249/99-IR(DU)]

KULDEEP RAI VERMA, Desk Officer

अनुबंध

औद्योगिक विवाद अधिकरण एवं श्रम न्यायालय,

जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती निशा गुप्ता, आर.एच.जे.एस.
औ. वि. (केन्द्रीय) सं. 07/2000

देशलाराम पुत्र श्री दानाराम गर्ग, निवासी मार्फत पूर्णलाल गर्ग मेघवाल
पाड़ा वार्ड नम्बर-24, जैसलमेरप्राथी

बनाम

1. मण्डल निरीक्षक (डाक), जोधपुर
2. उप मण्डलीय निरीक्षक (डाक) जैसलमेरअप्राथी

उपस्थिति :

- (1) प्राथी की ओर से श्री जितेन्द्र गहलोत प्रतिनिधि उप.
- (2) अप्राथी की ओर से श्री शिवकुमार व्यास प्रतिनिधि उप.

अधिनिर्णय

दिनांक 26-2-2003

श्रम मंत्रालय भारत सरकार ने अपनी अधिसूचना क्रमांक एल. 40012/249/99/आई.आर. दिनांक 29-10-1999 से निम्न विवाद वास्ते अधिनिर्णय इस न्यायालय को प्रेषित किया है :—

“Whether the action of Sr. Supdt. Postal Department, Jodhpur Division, Jodhpur in terminating the service of Shri Deshlaram S/o Sh. Danaram Garg, Ex. Extra Departmental Agent w.e.f. 1-1-99 is legal & justified ? If not to what relief the concerned workman is entitled ?”

प्राथी ने अपना माँग पत्र प्रस्तुत करते हुए अधिकथित किया कि प्राथी की नियुक्ति दिनांक 3-7-91 को अप्राथी कार्यालय में ई.डी.एम.सी. के पद पर हुई, प्राथी को समय-समय पर अलग-अलग आदेश से अप्राथीकरण के यहाँ विभिन्न शाखाओं में कार्य करने के लिए अप्राथी द्वारा निर्देशित किया गया जिस अनुरूप प्राथी ने कार्य किया, मार्च 96 से 31-12-98 तक लगातार प्राथी ने अप्राथी के यहाँ ई.डी.डी.यू. के पद पर कार्य किया, 31-12-98 को कार्य समाप्ति के बाद लिखित आदेश से प्राथी की सेवाएं समाप्त कर दी गईं, सेवा समाप्ति से पूर्व कोई कारण नहीं बताया, कोई नोटिस नहीं दिया, छंटनी मुआवजा नहीं दिया, कोई आरोप-पत्र नहीं दिया न ही कोई जाँच की गई। प्राथी का कथन है कि उसने सेवा समाप्ति से पूर्व के एक वर्ष की अवधि में 240 दिन से भी अधिक अवधि तक कार्य कर लिया था इसलिए अप्राथी द्वारा जो प्राथी की सेवा समाप्ति की गई है वह धारा 25-एफ का उल्लंघन करते हुए की गई है। यह भी कहा है कि प्राथी को सेवापृथक् करने के पश्चात उससे कनिष्ठ कुशलचन्द को सेवा में रखा, उसे स्थाई भी कर दिया तथा वह आज भी सेवा में है, अप्राथी ने फर्स्ट कम लास्ट गो के सिद्धान्त की पालना नहीं की, एक अन्य व्यक्ति कैलाशसिंह को भी प्राथी के साथ नियुक्त किया जो आज भी कार्यरत है, इस प्रकार प्राथी की सेवा समाप्ति में अप्राथी द्वारा धारा 25-जी औ.वि. अधिनियम के प्रावधानों का भी उल्लंघन किया है, सेवा समाप्ति से पूर्व खरिफ़ता सूची जारी नहीं की गई इस प्रकार नियम 77 राज. औ. वि. अधिनियम का उल्लंघन किया है। अन्त में प्रार्थना की है कि प्राथी को पुनः सेवा में लगातार मानते हुए फुल बैक वैजेज सहित सेवा में पुनर्स्थापित किये जाने का अधिनिर्णय पारित किया जावे।

अप्राथी की ओर से जवाब प्रस्तुत करते हुए कहा गया कि ओमप्रकाश भाटी एवजी ई.डी.एम.सी. गौपाचौक के 19-6-91 से 30-6-91 तक छुट्टी जाने पर अपनी जिम्मेवारी पर एवजी के रूप में प्राथी को लगाया गया जिसके 3-7-91 को छुट्टी पर आने पर देशलाराम को भारमुक्त कर दिया गया, प्राथी को अलग-अलग अंतराज में अप्राथी के यहाँ अस्थायी व्यवस्था पर लगाया गया तथा नियुक्ति-पत्र की शर्तों के अनुसार अवधि पूर्ण होने पर सेवा से पृथक् किया गया, अस्थायी सेवा शर्तों पर नियुक्ति स्वीकार करने से अवधि समाप्त होने पर उसे भारमुक्त 31-12-93 को किया गया तथा आगे उसकी सेवा उपयुक्त नहीं पाये जाने पर उसे पुनः अस्थायी नियुक्ति नहीं दी गई। डाकपाल जैसलमेर के अस्थायी नियुक्ति आदेश दिनांक 3-10-98 के अनुसार उसे 3-10-98 से 31-12-98 की अवधि के लिए अस्था.

नियुक्ति आदेश शर्तों के अनुसार सेवा से हटाया गया था। इन शर्तों को प्रार्थी ने स्वीकार किया था, औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधान अतिरिक्त विभागीय डाक एजेंटों पर लागू नहीं होता, विभागीय डाक एजेंटों की सेवा संवैधानिक रूप से बने भारतीय डाकतार अ.वि. एजेंट (सेवा व आचरण) नियम 1964 से संचालित होती है ये शर्तें प्रार्थी ने मानकर स्वीकार करके ही अस्थाई नियुक्ति को स्वीकार किया था। कुशल चन्द को अ.वि. शाखा डाकपाल डाबला डाकघर के रूप में नियुक्ति का इस प्रकरण से कोई संबंध नहीं है इसी प्रकार जैसलमेर डाकघर के ई.डी. स्टेम्प वेण्डर पद पर श्री कैलाश की नियुक्ति उनके आवेदन प्राप्ति के पश्चात् भर्ती की निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद की गई। प्रार्थी को पद विशेष पर नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया अपनाकर नियुक्ति ही नहीं दी गई तो वरिष्ठता देने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

प्रार्थी ने माँग-पत्र के समर्थन में स्वयं का शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जिस पर अप्रार्थी प्रतिनिधि द्वारा जिरह की गई तथा अप्रार्थी की ओर से सी.वी. सांखला का शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जिस पर प्रार्थी प्रतिनिधि द्वारा जिरह की गई। अप्रार्थी की ओर से तीन दस्तावेजात की फोटो प्रतियाँ पेश की गईं।

दोनों पक्षों की प्रतिनिधिगण की बहस सुनी, पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रार्थी द्वारा यह कहा गया कि उसे 3-7-91 को ई.डी.एम.सी. के पद पर नियुक्त किया गया और उसने विभिन्न शाखाओं में काम किया। 31-12-98 को उसकी सेवाएं लिखित आदेश से समाप्त कर दी गई जो कि त्रुटिपूर्ण है।

विपक्षी द्वारा यह कहा गया कि प्रार्थी को कभी भी ई.डी.एम.सी. के पद पर नियुक्ति नहीं दी थी क्योंकि इसकी नियुक्ति की एक निश्चित प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के अन्तर्गत ही नियुक्ति दी जा सकती है। प्रार्थी ने 19-6-91 को ओमप्रकाश भाटी ई.डी.एम.सी. के छुट्टी पर जाने पर एवजी में काम किया और 3-7-91 को ओमप्रकाश के आ जाने पर उसे भारमुक्त कर दिया गया। इसी प्रकार 3-10-98 से 31-12-98 में भी उसने इसी प्रकार काम किया है।

स्वयं प्रार्थी ने अपनी जिरह में यह स्वीकार किया है कि उसे नियुक्ति-पत्र नहीं दिया था, इसका यह कथन है कि वह ओमप्रकाश को नहीं जानता परन्तु प्रार्थी का यह कथन विपक्षी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से स्वतः ही गलत प्रतीत होता है क्योंकि ओमप्रकाश से प्रार्थी ने 18-6-91 को चार्ज लिया था और 3-7-91 को चार्ज वापस दिया है। ऐसी स्थिति में ओमप्रकाश को प्रार्थी नहीं जानता हो यह स्थिति नहीं है और यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी ने जानबूझकर गलत कथन किया है। विपक्षी का यह स्पष्ट कथन है कि प्रार्थी को केवल एवजी के रूप में लगाया गया।

इस प्रकार प्रार्थी ने 3-7-91 से 31-12-98 तक विपक्षी के यहाँ लगातार काम किया हो ऐसी कोई स्थिति नहीं है।

प्रार्थी की ओर से ए.आई.आर. 1998 सुप्रीमकोर्ट 656 मैनेजर टेलीकॉम बनाम श्रीनिवास राव का विनिश्चय पेश किया जिसमें कहा गया है कि जहाँ टेलीकॉम विभाग व्यापारिक गतिविधियों में कार्यरत है

तो वह उद्योग की परिभाषा में आवेगा, इस संबंध में कोई विवाद नहीं है।

प्रार्थी की ओर से एफ.एल.आर. 1984 पेज 244 साराभाई कैमीकल्स, बनाम सुभाष एन. पण्डिया का विनिश्चय पेश किया जिसमें बदली कर्मचारी की छंटनी की गई थी तब भी धारा 25-एफ को लागू माना गया, इस सिद्धांत में कोई विवाद नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा सेवामुक्ति के पूर्व एक वर्ष में 240 दिन काम किया हो ऐसी स्थिति नहीं है, ऐसी स्थिति में यह विनिश्चय प्रार्थी को कोई लाभ नहीं पहुंचाता।

प्रार्थी की ओर से एफ.एल.आर. 1991 पेज 683 माधवशंकर बनाम राजस्थान राज्य का विनिश्चय पेश किया जिसमें प्रार्थी ने 240 दिन काम किया परन्तु यहाँ पर स्थिति ऐसी नहीं है। इसी क्रम में एस.बी. सिविल रिट पिटीशन नम्बर 189/03 का विनिश्चय भी पेश हुआ जिसमें भी 240 दिन काम किया गया, यहाँ ऐसी स्थिति नहीं है। अतः यह विनिश्चय प्रार्थी को कोई लाभ नहीं पहुंचाता।

विपक्षी की ओर से पोस्टल स्टाफ के सेवा नियम पेश किये गये हैं जिससे यह स्थिति स्पष्ट होती है कि विशिष्ट पद पर नियुक्ति किस प्रकार की जायेगी। विपक्षी की ओर से ही रिट पिटीशन नम्बर 21331/2000 में बेंगलोर हाईकोर्ट का निर्णय पेश किया जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि जहाँ किसी आकस्मिक कार्य के लिए रिक्त पद को भरा गया हो और ऐसी स्थिति में यदि नियमतीकरण का आदेश दिया जाएगा तो स्थिति अत्यन्त भयावह हो जायेगी और अनावश्यक परेशानी होगी।

प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी को विपक्षी द्वारा कभी भी नियुक्त नहीं किया गया है उसके और विपक्षी के बीच कर्मकार और नियोक्ता का सम्बन्ध ही स्थापित नहीं हुआ, साथ ही प्रार्थी ने 3-7-91 से 31-12-98 तक विपक्षी के यहाँ काम किया हो या 31-12-98 से पूर्व के कलेण्डर वर्ष में 240 दिन काम किया हो ऐसी कोई स्थिति साबित नहीं है। अतः प्रार्थी कोई अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है।

अधिनिर्णय

अतः यह अधिनिर्णित किया जाता है कि अप्रार्थीगण मण्डल निरीक्षक (डाक) जोधपुर एवं उपमण्डलीय निरीक्षक (डाक) जैसलमेर द्वारा प्रार्थी देशलाराम पुत्र श्री दानाराम गर्ग को कभी भी नियुक्त नहीं किया तथा प्रार्थी व अप्रार्थी के बीच कर्मकार और नियोक्ता का सम्बन्ध ही स्थापित नहीं होता, प्रार्थी ने 31-12-98 से पूर्व के कलेण्डर वर्ष में 240 दिन अप्रार्थीगण के अधीन काम नहीं किया ऐसी स्थिति में प्रार्थी अप्रार्थीगण से कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

यह अधिनिर्णय आप दिनांक 26-2-2003 को खुले न्यायालय में हस्ताक्षर कर सुनाया गया।

निशा गुप्ता, न्यायाधीश

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 2003

का. आ. 2210. — औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार सी.पी.डब्ल्यू.डी. के प्रबंधतंत्र के सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच,

अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय, जोधपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 4-7-2003 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-42012/51/2000-आई.आर. (डीयू)]

कुलदीप राय वर्मा, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 4th July, 2003

S.O. 2210.— In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Jodhpur as shown in the annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of C.P.W.D. and their workman, which was received by the Central Government on 4-7-2003.

[No. L-42012/51/2000-IR(ĐU)]

KULDEEP RAI VERMA, Desk Officer

अनुबंध

औद्योगिक विवाद अधिकरण एवं श्रम न्यायालय,

जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती निशा गुप्ता, आर.एच.जे.एस. औ. वि. (केन्द्रीय) सं. 07/2001

शिवनारायण पुत्र श्री किशनराम जी परिहार, निवासी पोस्ट देवा, तहसील जैसलमेरप्राथी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विद्युत (बी. एफ. एल.डी.) (किलोविनि)

प्रथम गांधी कॉलोनी, 588 जैसलमेरअप्रार्थी

उपस्थिति :

- (1) प्राथी की ओर से श्री जितेन्द्र गहलोत प्रतिनिधि उप.
- (2) अप्रार्थी की ओर से श्री शिवकुमार व्यास प्रतिनिधि उप.

अधिनिर्णय

दिनांक 30-4-2003

श्रम मंत्रालय भारत सरकार ने अपनी अधिसूचना क्रमांक एल. 42012/51/2000/आई.आर. दिनांक 30-6-2000 से निम्न विवाद वास्ते अधिनिर्णय इस न्यायालय को प्रेषित किया है :—

"Whether the action of the management of B.L.F.O.-I, C.P.W.D., Jaiselmer in terminating the services of Sh. Shiv Narain S/o Sh. Kishna Ram Parihar, Ex-Motor Lorry Driver w.e.f. 1-10-99 is legal and justified? If not do what relief the workman is entitled to?"

प्राथी ने अपना माँग पत्र प्रस्तुत करते हुए कहा है कि उसे वाहन चालक के पद पर माह नवम्बर 1994 में अधिशासी अभियन्ता (विद्युत) बी.एफ. एल. डी. (प्रथम) केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग के.नि.वि.

जैसलमेर में नियुक्त किया गया, प्राथी ने लगातार 30-9-99 तक कार्य किया तथा 1-10-99 को मौखिक आदेश से प्राथी की सेवाएं अप्रार्थी द्वारा समाप्त कर दी गई। सेवा प्रथक करने से पूर्व छंटनी का मुआवजा नहीं दिया गया, एक माह का नोटिस नहीं दिया व धारा 25-एफ. औ.वि. अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया। प्राथी का कथन है कि उसकी सेवा समाप्ति के बाद अप्रार्थी ने अशोक कुमार, घनश्याम भार्गव और विनोद कुमार को सेवा में रखा तथा उन्हें सेवा में रखने से पूर्व प्राथी को सेवा में आने की ऑफर नहीं दी गई। इस प्रकार धारा 25-एच व 25-जी के प्रावधानों का भी उल्लंघन किया है। यह भी कहा है कि सेवा समाप्ति से पूर्व वरिष्ठता सूचि भी जारी नहीं की गई। अन्त में निवेदन किया है कि प्राथी का सेवा समाप्ति आदेश दिनांक 1-10-99 को अपास्त किया जाकर प्राथी को पुनः सेवा में मय लगातार सेवा व बैंक वैजज के नियुक्त किये जाने का आदेश पारित किया जाये।

अप्रार्थी की ओर से जवाब में कहा गया है कि प्राथी कभी भी इस कार्यालय में नियमित वाहन चालक के पद पर कर्मचारी नहीं रहा तथा उसे कभी भी एडहोक या दैनिक कामगार के पद पर भी नियुक्त नहीं किया गया। अप्रार्थी कार्यालय भारत-पाक सीमा पर सीमा बंद बत्ती प्रोजेक्ट को पूरा करने हेतु खोला गया था जो कि समयबद्ध कार्यक्रम है इस विभाग इस प्रोजेक्ट में वाहन चालक का कार्य आवश्यक निर्माण औपचारिकताओं को पूरा करते हुए ठेके/कार्य आदेश पर देता है, ठेकेदार ही वाहन चालकों की सेवा इस कार्यालय को उपलब्ध कराता रहता है। विभाग द्वारा भुगतान भी ठेकेदार को ही किया जाता है, वाहन चालक को उसके वेतन का भुगतान ठेकेदार द्वारा ही किया जाता है क्योंकि वह ठेकेदार का ही कर्मकार है। जब प्राथी इस विभाग का कर्मचारी ही नहीं था तो अधिशासी अभियन्ता द्वारा सेवा समाप्त करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। आवेदक और ठेकेदार के बीच में विभाग की कोई दखलान्दाजी नहीं है। प्राथी कभी भी इस कार्यालय के अधीन किसी पद पर सेवा में नहीं रहा, अप्रार्थी द्वारा किन्हीं प्रावधानों का उल्लंघन नहीं किया गया। यह भी कहा गया है कि विभिन्न ठेकादारों द्वारा प्राथी की सेवायें इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई थीं तथा उसकी सेवाओं का भुगतान भी ठेकेदार द्वारा ही किया गया न कि विभाग द्वारा। ठेकेदारों के कामगारों की वरिष्ठता सूचि कभी भी किसी विभाग द्वारा जारी नहीं की जाती है, प्राथी को इस कार्यालय द्वारा कभी भी कोई नियुक्ति-पत्र जारी नहीं किया गया। अन्त में निवेदन किया है कि प्राथी का मांग-पत्र सव्यव खारिज किया जाये।

प्राथी ने मांग-पत्र के समर्थन में स्वयं का शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जिस पर अप्रार्थी प्रतिनिधि द्वारा जिरह की गई तथा अप्रार्थी की ओर से आर.एन.मंगल का शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर प्राथी प्रतिनिधि द्वारा जिरह की गई। प्राथी व अप्रार्थी की ओर से विभिन्न दस्तावेजात की फोटो स्टेट प्रतियां पेश की गईं।

दोनों पक्षों के प्रतिनिधिगण की बहस सुनी, पत्रावली का अवलोकन किया।

प्राथी द्वारा यह कहा गया कि उसने विपक्षी के यहां नवम्बर 1 से लगातार काम किया। 1.10.99 को उसकी सेवाएं मौखिक आदेश से समाप्त कर दी गई जो कि त्रुटिपूर्ण है।

विपक्षी द्वारा यह कहा गया कि प्रार्थी व उनके बीच नियोक्ता व कर्मकार का सम्बन्ध नहीं है, ठेकेदार के माध्यम से वाहन चालक विभाग को उपलब्ध कराये जाते थे।

स्वयं प्रार्थी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में प्रदर्श-1 पर ए से बी अपने दस्तावेजों को स्वीकार किया है जो कि ठेका दिये जाने का कार्यादेश है।

विपक्षी की ओर से आर.एन. मंगल पेश हुए हैं जिनका यह स्पष्ट कथन है कि प्रार्थी कभी भी विभाग की नौकरी में नहीं रहा।

प्रार्थी का यह कथन है कि प्रदर्श-2 व 3 प्रमाण-पत्र से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी विपक्षी के यहां कार्यरत था, यह प्रमाण-पत्र केवल इस बात के हैं कि प्रार्थी ने विभाग में चालक का काम किया है। परन्तु यह काम किस केपेसिटी में किया है, यह स्थिति प्रदर्श-2 व 3 प्रमाण-पत्र से स्पष्ट नहीं होती। जो दस्तावेजात पेश हुए हैं उनसे यह स्थिति स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा वाहन चलाने का ठेका दिया गया है जो कि तीन माह के लिए दिया गया और बाद में भिन्न-भिन्न आदेशों से बढ़ाया गया है। इस सम्बन्ध में एजेन्सी का विवरण भी पेश हुआ है जिसमें कब-कब किसे ठेका दिया गया और ठेकेदार की ओर से कितने वाहन चालक उपलब्ध कराये गये, इसका विवरण पेश हुआ है।

प्रार्थी का यह कथन है कि लॉग-बुक पर उसके हस्ताक्षर हैं परन्तु लॉग-बुक पर हस्ताक्षर होने मात्र से प्रार्थी की स्थिति में कोई अन्तर नहीं पड़ता। विपक्षी ने इस बात से इन्कार नहीं किया है कि प्रार्थी ने उनके यहां वाहन चालक का काम किया और जब प्रार्थी वाहन चालक था तो लॉग-बुक पर उसके हस्ताक्षर होंगे ही। परन्तु जो दस्तावेजात प्रस्तुत हुए हैं उससे यह स्थिति स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा ठेकेदार के माध्यम से काम किया गया और ऐसी स्थिति में प्रार्थी व विपक्षी के बीच नियोक्ता व कर्मकार का कोई सम्बन्ध नहीं था।

विपक्षी की ओर से सेन्ट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्युनल कटक का विवाद सं. 102/98 का आदेश पेश किया गया है जिसमें भी ठेकेदार के माध्यम से काम कराया गया था इसी क्रम में सेन्ट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्युनल के विवाद सं. 1127/91 और 1544/99 के आदेश भी पेश किये गये हैं।

इस प्रकार यह स्थिति स्पष्ट है कि प्रार्थी और विपक्षी के बीच नियोक्ता व कर्मकार का कोई सम्बन्ध नहीं था। ऐसी स्थिति में विपक्षी द्वारा प्रार्थी की सेवाएं समाप्त की गई हों, यह स्थिति साबित नहीं है और प्रार्थी कोई अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है।

अधिनिर्णय

अतः यह अधिनिर्णीत किया जाता है कि प्रार्थी शिवनारायण पुत्र श्री किशनराम परिहार व अप्रार्थी अधिशासी अभियन्ता, विद्युत [बी.एफ. एल. डी. (I)] सी.पी.डब्ल्यू.डी., जैसलमेर के बीच नियोक्ता व कर्मकार का कोई सम्बन्ध नहीं था। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी श्रमिक की सेवाएं समाप्त की गई हों वह स्थिति साबित नहीं होती है। अतः प्रार्थी अप्रार्थी से कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

यह अधिनिर्णय आज दिनांक 30-4-2003 को खुले न्यायालय में हस्ताक्षर कर सुनाया गया।

निशा गुप्ता, न्यायाधीश

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 2003

का. आ. 2211.— औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार शिक्षता प्रशिक्षण बोर्ड के प्रबंधन के सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय, जोधपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 4-7-2003 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-42012/170/99-आई.आर. (डीयू)]

कुलदीप राय वर्मा, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 4th July, 2003

S.O. 2211.— In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Jodhpur as shown in the annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Board of Apprenticeship Training and their workman, which was received by the Central Government on 4-7-2003.

[No. L-42012/170/99-IR(DU)]

KULDEEP RAI VERMA, Desk Officer

अनुबंध

औद्योगिक विवाद अधिकरण एवं श्रम न्यायालय,

जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती निशा गुप्ता, आर.एच.जे.एस.

ओ. वि. (केन्द्रीय) सं. 38/2001

श्री शैतानसिंह भाट्ट, पुत्र श्री रावतसिंह भाटी जाति राजपूत निवासी बागर बैरी, किला रोड, जोधपुरप्रार्थी

बनाम

1. अध्यक्ष शिक्षता प्रशिक्षण बोर्ड (उत्तरी क्षेत्र) एवं प्रबन्ध निदेशक, इण्डिया ग्लासकोल्ड लि०, सी-124, ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस प्रथम, नई दिल्ली।
2. निदेशक शिक्षता प्रशिक्षण बोर्ड (उत्तरी क्षेत्र) 117 एल/440 काकादेव, कानपुर।
3. सहायक निदेशक, विस्तार केन्द्र, शिक्षता प्रशिक्षण बोर्ड, छात्रावास नं. 3, कमरा नं. 4 व 5 राजकीय पालिटेकनिक कॉलेज कैम्पस, जोधपुर।अप्रार्थीगण

उपस्थिति :

1. प्रार्थी की ओर से श्री डी.के. परिहार प्रतिनिधि
2. अप्रार्थी इकतरफा।

अधिनिर्णय

दिनांक 21-2-2003

श्रम मंत्रालय नई दिल्ली ने अपनी अधिसूचना क्रमांक एल. 42012/170/99 आई.आर. (डी. यु.) दिनांक 27-1-2000 से निम्न विवाद वास्ते अधिनिर्णय इस न्यायालय को प्रेषित किया है :—

"Whether action of the management of Board of Apprenticeship Training, Extension Centre, Jodhpur in terminating the services of Sh. Shaitan Singh Bhati S/o Sh. Rawat Singh, Ex. Peon-cum-chowkidar w.e.f. 1-11-98 without notice and retrenchment compensation is legal and justified? If not, to what relief the concerned workman is entitled?"

प्रार्थी ने अपना मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए अभिकथित किया है कि प्रार्थी का पंजीयन उपक्षेत्रीय नियोजन कार्यालय, जोधपुर में पंजीयन सं. 3778/97 एन.सी.ओ. 02-10 दिनांक 7-8-97 पर पंजीकृत था। अप्रार्थी सं. 1 ने प्रार्थी को निर्देश दिया कि वह अपनी नौकरी से संबंधित संपूर्ण कागजातों के साथ अप्रार्थी सं. 3 जोधपुर कार्यालय में दिनांक 17-3-98 को प्रातः 10 बजे साक्षात्कार के लिए उपस्थित हो, प्रार्थी को यह भी सूचना मिली कि उसका नाम राज. सरकार के नियोजन कार्यालय, जोधपुर से उनके कार्यालय में उक्त पद के लिये प्रस्तावित किया गया है, अप्रार्थी सं. 2 के पत्र दिनांक 23-3-98 के द्वारा इच्छा जाहिर करते हुए उक्त पद हेतु एक निर्धारित प्रपत्र दिनांक 10-4-98 तक भरवा कर मय समस्त दस्तावेजात प्रस्तुत करने के प्रार्थी को निर्देश प्राप्त हुए जिसकी पालना में प्रार्थी ने निर्धारित दिनांक को चाही गई सूचना प्रपत्र में भरकर मय दस्तावेजात पेश की तत्पश्चात् अप्रार्थीगण के बोर्ड द्वारा प्रार्थी का पीओन-कम-चौकीदार के पद के लिये साक्षात्कार लिया गया व चयनित होने के पश्चात् प्रार्थी ने दिनांक 1 जनवरी 1998 को पीओन-कम-चौकीदार के पद पर अपना कार्यभार ग्रहण किया तब से अर्थात् 1-1-1998 से अप्रैल 1998 तक प्रार्थी लगातार पीओन-कम-चौकीदार के पद पर 50 रुपये प्रतिदिन वेतन पर काम करता आ रहा है। तत्पश्चात् प्रबन्धक-पक्ष द्वारा उपक्षेत्रीय नियोजन कार्यालय, जोधपुर से पीओन-कम-चौकीदार के पद हेतु योग्य अभ्यर्थियों के नाम प्रस्तावित कराये गये जिसमें प्रार्थी का नाम भी सम्मिलित था नियोजन विभाग द्वारा प्रस्तावित सभी पांच नाम वाले अभ्यर्थियों के बोर्ड द्वारा विधिवत् साक्षात्कार लिये गये, प्रार्थी को बोर्ड द्वारा साक्षात्कार में चयनित किया गया जिसकी पालना में प्रार्थी ने 23-4-98 को पीओन-कम-चौकीदार के पद पर एकमुश्त वेतन 1500 रुपये पर अपना कार्यभार संभाल लिया तब से प्रार्थी लगातार पूर्ण निष्ठा से कार्य कर रहा है। प्रार्थी की सेवाएं अचानक दिनांक 1-11-1998 से अप्रार्थी सं. 2 ने समाप्त कर दी, प्रार्थी ने 1-1-1998 से 1-11-1998 तक कुल 304 दिन तक लगातार कार्य किया, उक्त अवधि में प्रार्थी का कार्य संतोषजनक था उसके विरुद्ध किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं थी न ही उसके विरुद्ध विभागीय जांच की कोई कार्यवाही की गई, प्रार्थी को बिना किसी स्पष्टीकरण का मौका दिये बिना किसी जाँच कार्यवाही में दोषी ठहराये, बिना किसी लिखित आदेश, बिना एक माह का नोटिस दिये, बिना एक माह का नोटिस की एवज में वेतन दिये एवं बिना मुआवजा दिये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध अप्रार्थी ने मात्र मौखिक आदेश से बिना किसी कानून की पालना किये दिनांक 1-11-98 से सेवा से पृथक् कर दिया जो विधि विरुद्ध एवं धारा 25-एफ ओ.वि. अधिनियम के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन होने के कारण निरस्तनीय है। यह भी कहा है कि अप्रार्थी की सेवा समाप्ति से पूर्व वरिष्ठता सूची तैयार नहीं की गई। इस प्रकार धारा 25-जी.ओ.वि. अधिनियम का

उल्लंघन होने के कारण सेवा पृथक्ता का आदेश निरस्तनीय है। यह भी कहा है कि उसे सेवापृथक् करने के पश्चात् अन्य श्रमिकों को पीओन-कम-चौकीदार के पद पर सेवा में नियुक्त रखा और उन्हें नियुक्ति देने से पूर्व प्रार्थी को कोई सूचना नहीं दी गई इस प्रकार धारा 25-एच. ओ. वि. अधिनियम का अप्रार्थी द्वारा स्पष्ट उल्लंघन किया गया है जिसके कारण भी सेवापृथक्ता का आदेश निरस्तनीय है। यह भी कहा है कि प्रार्थी से कनिष्ठ श्रमिक आज भी अप्रार्थी के यहाँ कार्यरत हैं जिन्हें स्थाई एवं नियमित कर्मचारी घोषित किया जा चुका है। प्रार्थी का कथन है कि उसे अप्रार्थी द्वारा नियमित कर्मचारी की भांति समस्त प्रक्रियाएं पूर्ण कर नियुक्त किया गया है। अप्रार्थी का कार्य परमानेंट नेचर का है जो प्रार्थी की अवैधानिक सेवामुक्ति के बाद भी इसी प्रकार के अस्थाई एवं तथाकथित संविदा के आधार पर आज भी नियुक्तियाँ प्रदान करने की प्रक्रिया जारी रखी हुई है प्रार्थी का कथन है कि वह सेवामुक्ति से लेकर आज तक बेरोजगार है और वह आज भी अप्रार्थी के यहाँ पीओन-कम-चौकीदार के पद पर कार्य करने को तैयार है। अन्त में निवेदन किया है कि प्रार्थी के गैर कानूनी मौखिक सेवा पृथक्ता के आदेश दिनांक 1-11-98 को निरस्त किया जावे, प्रार्थी को समस्त लाभों सहित पुनः नौकरी पर रखा जाने तथा सेवा से हटाने की तिथि से लेकर सेवा में पुनर्स्थापित करने तक की अवधि का समस्त वेतन व लाभ अप्रार्थी से दिलाये जावे।

अप्रार्थीगण पर नोटिस की तामील 28-6-2002 की पेशी के हो जाने के उपरान्त अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ जिसके पश्चात् 13-8-2002, 18-9-2002 व 12-11-2002 को भी अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ जिस पर दिनांक 12-11-2002 को अप्रार्थीगण के विरुद्ध इकतरफा कार्यवाही का आदेश पारित किया गया।

प्रार्थी ने अपने मांग-पत्र के समर्थन में स्वयं का शपथ-पत्र प्रस्तुत किया व विभिन्न दस्तावेजात की फोटो प्रतियां प्रस्तुत की गईं।

प्रार्थी प्रतिनिधि की बहस सुनी, पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रार्थी द्वारा अपने मांग-पत्र के समर्थन में प्रस्तुत किय गये शपथ-पत्र में यह कथन किया है कि उसकी नियुक्ति अप्रार्थी संस्थान में पीओन-कम-चौकीदार के पद पर 1-1-1998 को की गई, प्रार्थी ने अप्रैल 1998 तक लगातार कार्य किया जो 50 रुपये प्रतिदिन वेतन पर किया तत्पश्चात् प्रबन्धक-पक्ष द्वारा उपक्षेत्रीय नियोजन कार्यालय जोधपुर से पीओन-कम-चौकीदार के पद पर हेतु योग्य अभ्यर्थियों के नाम मांगे गये जिसमें प्रार्थी का नाम भी सम्मिलित था, बोर्ड द्वारा विधिवत् साक्षात्कार लिये जाने के पश्चात् प्रार्थी को चयनित किया जिसकी पालना में प्रार्थी ने 23-4-98 को पीओन-कम-चौकीदार के पद पर एकमुश्त वेतन 1,500 रुपये पर अपना कार्यभार संभाला, प्रार्थी की सेवाएं अचानक दिनांक 1-11-98 से समाप्त कर दी गई, प्रार्थी ने 1-1-98 से 1-11-98 तक कुल 304 दिन कार्य किया लेकिन उसे सेवामुक्त करने से पूर्व एक माह का नोटिस, नोटिस वेतन व छंटनी मुआवजा नहीं दिया, उसे कोई आरोपपत्र नहीं दिया न ही कोई जाँच कार्यवाही की गई, अप्रार्थी द्वारा की गई सेवा मुक्ति की कार्यवाही धारा 25-एफ.ओ.वि. अधिनियम के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। यह

भी कहा है कि सेवा समाप्ति से पूर्व वरिष्ठता सूची तैयार नहीं की गई, उसे सेवामुक्त करने के पश्चात् अन्य श्रमिकों को पीओन-कम-चौकीदार के पद पर सेवा में नियुक्त रखा परन्तु उसे कोई सूचना नहीं दी गई इस प्रकार धारा 25-जी व 25-एच.ओ.वि. अधिनियम के प्रावधानों का भी उल्लंघन किया गया है।

प्रार्थी की ओर से पत्रावली पर जो दस्तावेजी साक्ष्य पेश की गई है उसमें पहचान कार्ड, शिक्षता प्रशिक्षण बोर्ड का चपरासी-कम-चौकीदार के पद की भर्ती हेतु पत्र दिनांक 6-3-98 नियोजन कार्यालय का पत्र दिनांक 21-2-1998 पीओन-कम-चौकीदार के साक्षात्कार यावत, प्रार्थी का आवेदन-पत्र, प्रार्थी का नौकरी पर लगने बाबत आवेदन-पत्र दिनांक 2-4-98, विपक्षी का प्रार्थी को प्रेषित पत्र 16-4-98, कार्यभार ग्रहण करने का प्रार्थना पत्र दिनांक 23-4-98 प्रार्थी को जारी नियुक्ति पत्र 18 सितम्बर 1998 आदि दस्तावेजों से प्रार्थी का अप्रार्थी के अधीन 1-1-98 से 1-11-98 तक 1,500 रुपये एकमुश्त वेतन पर कार्यरत रहना प्रमाणित होता है। प्रार्थी के उक्त माँग-पत्र व शपथ-पत्र का कोई खण्डन विपक्षी की ओर से नहीं किया गया है। अतः प्रार्थी के माँग-पत्र, शपथ-पत्र तथा दस्तावेजी साक्ष्य से प्रार्थी का अप्रार्थी के अधीन सेवामुक्ति दिनांक 1-11-98 से पूर्व के एक कलेण्डर वर्ष में लगातार 240 दिन से अधिक कार्य करना व सेवामुक्ति से पूर्व अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी को एक माह का नोटिस, नोटिस वेतन व छंटनी मुआवजा नहीं दिया जाना प्रमाणित है ऐसी स्थिति में धारा 25-एफ ओ.वि. अधिनियम के आदेशात्मक प्रावधानों की पालना नहीं होने से प्रार्थी द्वारा प्रार्थी की सेवामुक्ति निःसन्देह अनुचित एवं अवैध है।

जहां तक पूर्वभूति का संबंध है, प्रार्थी को 1-11-98 को सेवामुक्त किया गया जब कि यह रेफरेन्स दिनांक 27-1-2000 को इस न्यायालय को प्रेषित किया गया, यह स्थिति भी सही है कि प्रार्थी ने 1-11-98 से 27-1-2000 तक की अवधि में अप्रार्थी के यहां कार्य नहीं किया है। अतः समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थी को रेफरेन्स की तिथि 27-1-2000 से आदेश की पालना तक 30 प्रतिशत राशि पूर्वभूति के रूप में दिलाई जाती है।

अधिनिर्णय

अतः यह अधिनिर्णित किया जाता है कि सहायक निदेशक विस्तार केन्द्र शिक्षता प्रशिक्षण बोर्ड, छात्रावास नं. 3, कमरा नं. 4 व 5 राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज कैम्पस, जोधपुर द्वारा प्रार्थी शैतानसिंह भाटी पुत्र रावतसिंह भाटी को पीओन-कम-चौकीदार के पद से 1-11-98 से सेवामुक्त करना अनुचित एवं अवैध है। अतः आदेशित किया जाता है कि अप्रार्थी नियोजक प्रार्थी को तुरन्त सेवा में पुनर्स्थापित करे, प्रार्थी की सेवाएं निरन्तर मानी जावेंगी, प्रार्थी रेफरेन्स की तिथि 27-1-2000 से आदेश की पालना तक 30 प्रतिशत राशि पूर्वभूति के रूप में अप्रार्थी नियोजक से प्राप्त करेगा।

यह अधिनिर्णय आज दिनांक 21-2-2003 को खुले न्यायालय में हस्ताक्षर कर सुनाया गया।

निशा गुप्ता, न्यायाधीश

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 2003

का. आ. 2212.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार टिड्डी प्रतिरक्षा विभाग के प्रबंधन के संबंध में नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय, जोधपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 04-7-2003 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-42012/103/2000-आई. आर.(डी. यू.)]

कुलदीप राय, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 4th July, 2003

S. O. 2212.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Jodhpur as shown in the annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Locust Warning Organisation and their workman, which was received by the Central Government on 04-7-2003.

[No. L-42012/103/2000-IR(DU)]

KULDIP RAI VERMA, Dcsk Officer

अनुबन्ध

औद्योगिक विवाद अधिकरण एवं श्रम न्यायालय, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :

श्रीमती निशा गुप्ता, आर. एच. जे. एस. ओ. वि. (केन्द्रीय) सं. : 29/2001 अब्दुल हफीज पुत्र श्री अब्दुल अजीज जाति मुसलमान नि. मोहल्ला लाईबान किले की घाटी मजिस्ट्र के पास, जोधपुर।
... प्रार्थी

बनाम

उप निदेशक टिड्डी प्रतिरक्षा विभाग अफसर मैस के पास एयरफोर्स रोड, रातानाडा, जोधपुर।
... अप्रार्थी

उपस्थिति :

- (1) प्रार्थी प्रतिनिधि श्री दिलीप चौहान उप.
- (2) अप्रार्थी प्रतिनिधि श्री एस. के. व्यास उप.

अधिनिर्णय

दिनांक 28-4-2003

श्रम मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ने अपनी अधिसूचना क्रमांक एल. 42012/103/2000/आई. आर. दिनांक 24-4-2001 से निम्न विवाद वास्ते अधिनिर्णय इस न्यायालय को प्रेषित किया है :—

Whether the action of the management of Locust Warning Organisation, Jodhpur in terminating the services of Sh. Abdul Hafiz S/o Sh. Abdul Aziz, Ex-Daily Paid

Mazdoor w.e.f. 6-11-83 is legal and justified ? If not, to what relief the concerned workman is entitled ?

प्राथी ने अपना माँग-पत्र प्रस्तुत करते हुए कहा है कि प्राथी की नियुक्ति दिनांक 1-3-1978 को अप्राथी के यहाँ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर की गई, नियुक्ति के समय लिखित आदेश दिया गया था कि प्राथी को प्रतिदिन 5/- रुपये व प्रतिमाह 150/- रुपये वेतन दिया जायेगा जो दिया गया, प्राथी ने नियुक्ति तिथि से लगाकर 6-11-1983 तक लगातार बिना किसी रोक-टोक के कार्य किया तथा 6-11-1983 को अप्राथी ने मौखिक आदेश से प्राथी की सेवाएं समाप्त कर दी, संवत्समाप्त से पूर्व कोई कारण नहीं बताया न ही कोई नोटिस या छंटनी का मुआवजा दिया, प्राथी ने सेवा समाप्ति से पूर्व के एक वर्ष में 240 दिन से अधिक कार्य किया। यह भी कहा है कि सेवापृथक्ता से पूर्व अप्राथी ने कोई वरिष्ठता सूची जारी नहीं की तथा अप्राथी ने प्राथी की सेवा समाप्ति में धारा 25-एफ का उल्लंघन किया। यह भी कहा है कि प्राथी की सेवा समाप्ति के पश्चात् अप्राथी ने दलपतसिंह भानाराम चौधरी, शंकरलाल, भंवरलाल, रामदास को नियुक्ति दी तथा इन्हें नियुक्ति देने से पूर्व प्राथी को सेवा में लिये जाने बाबत किसी प्रकार की कोई ऑफर नहीं दी गई। प्राथी का कथन है कि उसने वर्ष 1994 में सेन्ट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में प्रकरण पेश किया जो दिनांक 11-1-99 को इस शर्त के साथ तय किया गया कि प्राथी अपना केस औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत कार्यवाही करना चाहता है अतः इस न्यायालय में शिकायत पेश करने में देरी हुई। अन्त में निवेदन किया है कि प्राथी की सेवाएं दिनांक 6-11-83 यानि सेवा समाप्ति से लगाकर पुनः नियुक्ति देने तक लगातार सेवा मानी जावेगी, प्राथी को अप्राथी से यक़ायी वेतन मय ब्याज सहित दिलाया जावे।

अप्राथी की ओर से जवाब प्रस्तुत करते हुए प्रारम्भिक आपत्तियों में कहा गया है कि प्राथी का प्रार्थना-पत्र पोषणी नहीं है क्योंकि अप्राथी विभाग इण्डस्ट्रीज की परिभाषा में नहीं आता है। जवाब में प्राथी के माँग-पत्र में वर्णित तथ्यों से इन्कार किया है तथा कहा है कि प्राथी औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की परिभाषा में नहीं आता है, प्राथी ने आवश्यक पक्षकार नहीं बनाये हैं तथा देरी का कोई समुचित कारण नहीं दिया है, प्राथी ने अपना केस कोर्ट में खारिज होता देखकर उसे वापस लेने की योजना बनाई। अतिरिक्त आपत्तियों में कहा है कि प्राथी का विवादित काल लगभग 20 वर्ष पुराना है और पहला वाद भी तेरह वर्ष बाद 1994 में दायर हुआ था जो कि जोधपुर में स्थापित केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण ने प्राथी के वाद को खारिज कर दिया था इसलिये भी प्राथी का प्रार्थना-पत्र निराशाजनक रूप से बेलटेड डिले है, मात्र इस आधार पर ही प्राथी का प्रार्थना-पत्र पोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य हैं। अन्त में निवेदन किया है कि प्राथी कोई अनुतोप प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है, प्राथी का माँग-पत्र मय खर्च खारिज किया जावे।

प्राथी ने माँग-पत्र के समर्थन में स्वयं का शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जिस पर अप्राथी द्वारा जिरह की गई तथा अप्राथी की ओर से के. पी. सिंह का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जिस पर प्राथी प्रतिनिधि द्वारा

जिरह की गई। प्राथी की ओर से विभिन्न दस्तावेजात की फोटो प्रतियाँ पेश की गई।

दोनों पक्षों के प्रतिनिधिगण की बहस सुनी, पत्रावली का अवलोकन किया।

प्राथी द्वारा यह कहा गया कि उसने 1-3-78 से विपक्षी के यहाँ काम किया और 6-11-83 तक लगातार काम किया। विपक्षी द्वारा इससे इन्कार किया गया है और यह कथन किया है कि पूर्व में केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा प्रकरण खारिज कर दिया गया और देरी का कोई कारण नहीं बताया गया है।

प्राथी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में भी यह कथन किया है कि उसने विपक्षी के यहाँ लगातार काम किया, इस संबंध में प्रदर्श-1 से 5 दस्तावेजात पेश हुए हैं। विपक्षी के साक्षी के. पी. सिंह परिवहन अभियन्ता का यह कथन रहा है कि जब जरूरत होती थी काम लिया जाता था जो रिकार्ड में दर्ज है परन्तु ऐसा कोई रिकार्ड पेश नहीं हुआ है। इस साक्षी ने यह स्पष्ट स्वीकार किया है कि प्राथी को हटाया गया।

इस प्रकार प्राथी का यह कथन है कि उसने मार्च 78 से 6-11-83 तक विपक्षी के यहाँ लगातार काम किया, इसका कोई खण्डन विपक्षी की ओर से पेश नहीं किया गया है। जवाब में भी इससे संबंधित पैरा को इन्कार किया गया है। परन्तु इन्कारी का कोई आधार नहीं बताया गया है। जब जरूरत होती थी लगान का कोई रिकार्ड विपक्षी की ओर से पेश नहीं हुआ है। विपक्षी द्वारा प्राथी को हटाया गया परन्तु इससे पूर्व औद्योगिक विवाद अधिनियम के आदेशात्मक प्रावधानों की पालना नहीं की गई।

विपक्षी की यह आपत्ति है कि पूर्व में केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा प्रकरण खारिज कर दिया गया था। परन्तु यह तर्क त्रुटीपूर्ण है, 11-1-99 का केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण का आदेश पेश हुआ है जिसमें प्राथी का प्रार्थना-पत्र वापस लेने की अनुमति दी गई है। इस प्रकार प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण नहीं हुआ था।

विपक्षी की ओर से यह आपत्ति भी की गई है कि उनका विभाग इण्डस्ट्री की परिभाषा में नहीं आता व अपने समर्थन में आर. एल. डब्ल्यू. 2000(1) राजस्थान पेज 562 डायरेक्टर सेन्ट्रल फार्म सूरतगढ़ बनाम राजस्थान राज्य का विनिश्चय पेश किया जिसमें स्पष्ट किया गया है कि जहाँ कार्य इस प्रकृति का हो वह राज्य की वैध व सार्वभौम शक्ति के अन्तर्गत किया गया कार्य हो तो ऐसा कार्य उद्योग की परिभाषा में नहीं आता परन्तु यहाँ जो कार्य किया जा रहा है वह इस प्रकृति का कार्य नहीं है ऐसी स्थिति में विपक्षी विभाग उद्योग की परिभाषा में नहीं आता हो यह तर्क माने जाने योग्य नहीं है।

विपक्षी द्वारा यह आपत्ति भी की गई है कि प्रकरण अत्यन्त देरी से उठाया गया है। यह सही है कि प्रकरण देरी से उठाया गया है परन्तु केवल इस आधार पर अनुतोप से इन्कार नहीं किया जा सकता व इस संबंध में एफ. एल. आर. 2003(96) पेज 389, महाराष्ट्र राज्य बनाम संयद लाल गनी संयद का विनिश्चय पेश किया जिसमें कहा गया है कि केवल देरी के आधार पर रेफरेन्स को निरस्त नहीं किया जा सकता। इस

प्रकार यह स्थिति स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा विपक्षी के यहाँ 1-3-78 से 6-11-1983 तक काम किया गया और प्रार्थी को अवैध रूप से सेवामुक्त कर दिया गया जो कि उचित नहीं है।

प्रार्थी की सेवामुक्ति 6-11-1983 को की गई जब कि यह रेफरेन्स भारत सरकार द्वारा इस न्यायालय का 24-4-2001 को प्रेषित किया गया, यह स्थिति भी सही है कि प्रार्थी ने 6-11-83 से 24-4-2001 की अवधि में अप्रार्थी के अधीन कोई कार्य नहीं किया है तथा प्रकरण स्वयं प्रार्थी ने अत्यन्त देरी से उठाया है, इन सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी को रेफरेन्स की तिथि 24-4-2001 से आदेश की पालना तक 25 प्रतिशत राशि पूर्व भूति के रूप में दिलाई जाती है।

अधिनिर्णय

अतः यह अधिनिर्णित किया जाता है कि प्रार्थी श्रमिक अब्दुल हफीज पुत्र श्री अब्दुल अजीज को अप्रार्थी नियोजक कीट विज्ञान टिड्डी चेतावनी संगठन, जोधपुर द्वारा 6-11-1983 से सेवामुक्त करना अनुचित एवं अवैध है। अतः आदेशित किया जाता है कि अप्रार्थी नियोजक प्रार्थी को तुरन्त सेवा में पुनर्स्थापित करे, प्रार्थी की सेवाएं निरन्तर मानी जावेगी, प्रार्थी रेफरेन्स की तिथि 24-4-2001 से आदेश की पालना तक 25 प्रतिशत राशि पूर्व भूति के रूप में अप्रार्थी नियोजक से प्राप्त करेगा।

यह अधिनिर्णय आज दिनांक 28-4-2003 को खुले न्यायालय में हस्ताक्षर कर सुनाया गया।

निशा गुप्ता, न्यायाधीश

नई दिल्ली, 8 जुलाई, 2003

का. आ. 2213.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार भा. को. लि. के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-I, धनबाद के पंचाट (संदर्भ संख्या 64/96) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 07-7-2003 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-20012/187/95-आई. आर. (सी-1)]

एस. एस. गुप्ता, अवर सचिव

New Delhi, the 8th July, 2003

S. O. 2213.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 64/96) of the Central Government Industrial Tribunal-I, Dhanbad, now as shown in the annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of BCCL and their workman, which was received by the Central Government on 07-7-2003.

[No. L-20012/187/95-IR(C-I)]

S. S. GUPTA, Under Secy.

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. I, DHANBAD

In the matter of a reference U/s. 10(1)(d)(2A) of I. D. Act

Reference No. 64 of 1996

PARTIES :

Employers in relation to the management of Lodna Colliery of M/s. B. C. C. Ltd.

AND

Their Workmen

PRESENT :

Shri S. H. Kazmi, Presiding Officer

APPEARANCES :

For the Employers : Shri D. K. Verma, Advocate.

For the Workmen : Shri K. Chakravarty, Advocate.

State : Jharkhand

Industry : Coal

Dated, the 20th June, 2003

AWARD

By Order No. L-20012/187/95-IR (Coal-I) dated, the 3rd September, 1996 the Central Government in the Ministry of Labour has, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, referred the following dispute for adjudication to this Tribunal :

“Whether the demand by the Union that the dependent of Shri Raj Karan Singh is eligible for employment as per para 9.4.3 of NCWA-IV is justified ? If so, to what relief is the workman entitled ?

2. In this case to-day was the date fixed for adducing evidence on behalf of the workman. But like earlier again, no witness is present for being examined on behalf of the workman.

Sri K. Chakravarty appearing on behalf of the workman submits that he has no instruction either from the concerned workman or from the union and they appear to be no more interested in pursuing the present case and so this Tribunal is at liberty to pass any necessary and appropriate order in such circumstances.

It appears from the record that this case is pending for evidence to be adduced by the workman since 21-11-2001 despite several adjournments being granted for the said purpose.

Thus, taking into account the developments which have been made so far in this case as also in view of the aforesaid submissions being made by the workman's representative it is evident that the workman/union is no more interested in pursuing the present dispute or case and when the person aggrieved himself is no more interested, it would be sheer wastage of valuable time of this Tribunal to allow this case to remain pending any further.

This reference, as such, stands finally disposed of.

S. H. KAZMI, Presiding Officer

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 2003

का. आ. 2214.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार स्टेट बैंक आफ इंडिया के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, लखनऊ के पंचाट (संदर्भ संख्या आई डी 107/2002) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 10-7-2003 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-12012/478/2000-आई. आर.(बी-1)]

अजय कुमार, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 11th July, 2003

S. O. 2214.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. I. D. 107/2002) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court, Lucknow now as shown in the annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of State Bank of India and their workman, which was received by the Central Government on 10-7-2003.

[No. L-12012/478/2000-IR(B-I)]

AJAY KUMAR, Desk Officer

ANNEXURE

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, LUCKNOW PRESENT :

Shrikant Shukla, Presiding Officer

I. D. No. 107/2002

L-12012/478/2000/IR(B-I) dated 28-5-2002

BETWEEN :

Raj Kumar, S/o Munna Lal, R/o Mohalla
Krishnapur Behind Police Lines, Badaun, U.P.

AND

The Dy. General Manager, State Bank of India,
Zonal Office, 148, Civil Lines, Bareilly (U.P.)

AWARD

Bharat Sarkar Shram Mantralaya, Ministry of Labour, New Delhi vide their Order No. L-12012/478/2000/IR(B-I) dated 28-5-2002 has referred following reference for adjudication to this Tribunal :

“Whether the action of the Management of State Bank of India in not giving appointment to Raj Kumar, while he has already declared successful in the written test and interview, is justified ? If not, what relief he is entitled ?

Government's order was received and registered in this court on 14-6-2002. It is noteworthy that the notices were issued to the worker Raj Kumar as well as Dy. General Manager, State Bank of India and the worker was directed that he shall file statement of claim complete with relevant list of reliance and witness with the Tribunal within 15 days after the receipt of the order of reference and also forwarded the copy of each to the opposite party involved in dispute under Rule 10(B) of the I. D. Act. But the worker did not file any statement of claim. On 14-6-2002 the Tribunal ordered for issuance of fresh notice fixing 1-8-2002 for hearing and Raj Kumar was also directed that on the said date i.e. 1-8-2002 he or his A/R appear in the court and file the statement of claim together with all relevant evidence and the details of witnesses.

On 1-8-2002 Sri R. S. Tewari appeared for the workman and requested for adjournment, which was allowed, and 27-8-2002 was fixed for filing of statement of claim. On the date so fixed, worker remained absent but Sri R. S. Tewari appeared and orally requested time for filing statement of claim and therefore 1-10-2002 was fixed for filing of statement of claim.

On 1-10-2002 the worker did not turned up and his representative Sri R. S. Tewari orally requested time for filing statement of claim. Sri Tewari allowed and 5-11-2002 was fixed for filing statement of claim.

On 5-11-2002 Authorised representative of parties appeared and matter was referred for preliminary hearing of Lok Adalat on 12-11-2002, but on 12-11-2002 the opposite party representative did not turned up. The next date fixed was 10-12-2002 and parties could not reconcile the matter by compromise therefore 10-2-2003 was fixed for filing statement of claim, but on the date so fixed are thereafter on 29-4-2003 & 3-6-2003, the worker did not turned up nor filed statement of claim. Therefore on 3-6-2003 case was ordered to proceed ex-party against Raj Kumar and 27-6-2003 for filing statement of management's written statement. On 27-6-2003 the opposite party filed its submission.

The issue referred is whether the management of State Bank of India in not giving appointment to Raj Kumar while he has already declared successful in written

test and interview, is justified? If not, what relief the workman is entitled to?

The allegations of the management is that the concerned workman was engaged on daily wage basis at the rate of Rs. 20/- per day in the exigency of work for the period 15-11-1989 to 15-2-1990 and during the said period he worked for 76 days for which wages had already been paid to him which he accepted without any protest. He was not engaged substantively or against any permanent post and did not work for 240 or more days in a calendar year, even otherwise no right for the appointment on the basis of above working period accrued to the concerned workman. It is further stated that Bank considered the request of All India State Bank of India Staff Federation and gave a fair chance of absorption to the various persons who were engaged in Bank on temporary basis or daily wage basis as per settlements. As per these settlements the persons who had been engaged on temporary basis or daily basis were called for interview and those who were eligible and who qualified the interview were placed into wait list panel of the various categories to the nature and the amount of service put in. They were to be absorbed in permanent service depending upon the vacancies, which were to arise with the Bank. The panel was valid upto December 1996. The validity of the wait list was extended upto 31-3-1997 and as per agreement, the panel were to stand lapsed after the validity period of the wait list panels and thereafter remaining candidates wait listed on the panel will have no claim whatsoever for being considered for permanent appointment in the Bank. Even the candidates in the scale wages panel could not be completely absorbed and as such there was no occasion to absorb any person from the panel of daily wagers to which the concerned worker belonged and finally the panel of the workman stood lapsed on 31-3-1997.

It is also alleged that the workman has not filed his statement of claim and as such the Bank keeps its right reserved to file written statement against any claim statement, which may be filed by the concerned workman.

It is pertinent to mention here that the worker had put up only 76 working days of working on daily wage basis from 15-11-1989 to 15-2-1990 and more than 12 years have been passed.

According to settlement arrived at between the State Bank of India on the one hand and All India State Bank of India Staff Federation there was a settlement with regard to give fair chance of absorption to various persons who were engaged in Bank on temporary or daily wage basis. As per settlement all persons were called for interview and those who were eligible and who qualified the interview were placed in the panel of the wait list. Such panel lapsed on 31-3-1997.

In the circumstances as stated above the management of State Bank of India in not giving

appointment to Raj Kumar while he was already declared successful in written test and interview is justified. The issue is accordingly adjudicated in favour of the management.

LUCKNOW

4-7-2003

SHRIKANT SHUKLA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 2003

का. आ. 2215.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार बम्बई मरकेन्टाइल को. बैंक लि. के प्रबंधन के संबंध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण सं.-1, मुम्बई के पंचाट (संदर्भ संख्या सी जी आई टी 40/98) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 10-7-2003 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-12012/193/98-आई. आर.(बी-1)]

अजय कुमार, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 11th July, 2003

S. O. 2215.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. CGIT-40/98) of the Central Government Industrial Tribunal No. 1, Mumbai now as shown in the annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Bombay Mercantile Co-op Bank Ltd., and their workman, which was received by the Central Government on 10-7-2003.

[No. L-12012/193/98-IR(B. I)]

AJAY KUMAR, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1, MUMBAI

PRESENT :

Shri Justice S. C. Pandey, Presiding Officer

Reference No. CGIT-40/I998

PARTIES :

Employers in relation to the management of
Bombay Mercantile Co-op. Bank Ltd.

AND

Their Workmen.

APPEARANCES :

For the Management : Mr. R. N. Shah, Advocate

For the Workman : Mr. Umesh Nabar,
Advocate, Maharashtra

Mumbai, dated, the 23rd June, 2003

AWARD

1. This is a reference made by the Central Government to this tribunal for resolving the industrial dispute between Bombay Mercantile Co-operative Bank Ltd. (the Bank for short) and its employee Shri Mohammed Sheikh Saleem (the workman for short) in exercise of its power under clause (d) of sub-section 1 and sub-section 2A of Section 10 of the Industrial Disputes Act (the Act for short). The terms of reference culled out from the schedule to the order of reference are as follows :

"Whether the action of the management of Bombay Mercantile Co-operative Bank Ltd., in imposing punishment of stoppage of one annual increment and denying promotion to Shri Mohammed Saleem Shaikh is legal and justified ? If not, to what relief the workman is entitled ?"

2. The workman was represented by the President, Bombay Mercantile Co-operative Staff Union. The Union filed its statement of claim on behalf of the workman. It was stated in the Statement of claim that workman joined the Bank as Clerk from 1st November, 1972. He was working as an Asstt. Accountant in the year 1992. His name was approved for promotion to the Officers Cadre. It was stated further that the workman received a requisition slip for new cheque book for Savings Bank Account No. 839 held by Shri Shikari which was transmitted to him for verification by the token clerk to whom it was submitted by one Dilip Subdeo Patil. The workman stated that he had some doubt about the signature on requisition book, he referred to Mr. Kapasi who was the Officer of the Bank. On the advise of Mr. Kapasi, the requisition slip was handed over to the ledger-keeper for verification if the requisition slip was issued from the previous cheque book of the account holder. The verification was completed and requisition slip was found to be that of the account holder. Accordingly, the cheque book bearing serial No. 26091 to 260700 was issued in favour of Shri Shikari and was handed to Mr. Patil. Thereafter, the workman found that a cheque of Rs. 20,000 did not appear to bear the signature of Mr. Shikari, Mr. Kapasi wanted the workman to get it verified as was done in the case of requisition slip. However, the workman in his written opinion said that the cheque of Rs. 20,000 was not signed by Mr. Shikari. It is, thereafter, at the instance of Mr. Kapasi, verification was done. Thereafter, payment was made to Dilip Subdeo Patil. Another cheque of 7th September 1992, presented by the aforesaid gentleman was not passed by the workman Mr. Kapasi however, got it verified on his own responsibility. He allowed it to pass but the cheque of Rs. 25,000 remained unpaid due to lack of funds. Subsequently, a cheque of Rs. 2,000 presented by one servant was passed but the cheque of Rs. 8,000 by Shri D. S. Patil was again referred to Mr. Kapasi. At the

instance of the workman, Mr. Kapasi obtained a fresh specimen signature of Mr. Shikari. He then passed the cheque. About the same time Mr. Sawant pointed out Rs. 25,000 were never withdrawn by Mr. Shikari by issuing a cheque. Mr. Patil, thereafter, went away from the Bank. Upon investigation, it was found that by fraud of the withdrawal of cheque of Rs. 20,000 was committed. The Branch Manager reported the matter to the Managing Director. Pursuant to report Mr. Kapasi and the workman were suspended. However, no action was taken against ledger-keeper Mr. Vispee and Asstt. Accountant Shaikh Ali. The workman gave his explanation defining the role of each employee. The workman received the charge-sheet dated 3rd October 1992, on 08th October 1992. The workman was charged with improper verification of signature of Mr. Shikari on requisition of the slip with specimen signature. It was also alleged that workman did failed to notice the discrepancies in the requisition slip which was submitted by Mr. Dilip Subdeo. The workman was charged for negligence in performance of duties involving the Bank in serious loss, doing acts prejudicial to the interests of the Bank, and for the breach of the rules of the business of the Bank for running the department. The workman submitted reply to charge sheet but the Bank decided to hold the enquiry against the workman. The workman assailed the entire enquiry proceedings on the following grounds.

3. It was alleged that initiation of disciplinary proceedings against the workman by Miss. C. D. D'Souza was bad because she was not properly notified as a Disciplinary Authority of the workman. The second contention of the workman was that during the course of the enquiry proceedings vital and material witnesses were not examined by the Bank. It was further stated that certain material documents were withheld. The workman stated that by letter dated 07th December 1992, the copies of certain documents were demanded by him. These documents were not given to him with an assurance that they shall be produced during the course of enquiry. In the enquiry those documents were not supplied to the workman and his prayer was rejected on the ground that he could not compel the opposite party to produce the documents which it does not rely upon. The workman assailed the findings recorded against him as perverse. The workman stated that he was punished by the disciplinary authority by order dated 06th Jan, 1995 with stoppage of one increment. The workman asserted that the punishment of stoppage of one increment was wrongly confirmed by the Appellate Authority. He further contended that in any case the Bank could not withhold his promotion merely because he was punished. It was claimed that workman was entitled to be considered for promotion after the conclusion of enquiry. The workman claimed that he had submitted an application in prescribed form.

4. The workman claimed that he had raised an industrial dispute before Asstt. Labour Commissioner, Central, which was contested by the Bank. The reference was made on submission of failure of conciliation report by the Asstt. Labour Commissioner.

5. The banks case may be shortly stated. In the written statement, it claimed that the workman had no *locus standi* to file the written statement when his cause was espoused by the Union. It was alleged that this tribunal had no jurisdiction to direct promotion of the workman. It was not disputed by the Bank that the workman was given a charge sheet dated 03-10-1992 for issuing a new cheque book to D. S. Patel on 05th September 1992 without carefully verifying the signature of Mr. Shikari, the holder of account and the requisition slip which did not appear to have been part of the cheque book earlier given to Mr. Shikari. The charges were as alleged by the workman. He was defended by his advocate B. K. Hegde. The Presenting Officer also an advocate K. H. Granvankore. In the enquiry the Branch Manager, Mr. J. N. Amballa, and the account holder Shri Shikari were examined by the Bank. They were cross-examined by the defence counsel. The documents which were exhibited were supplied to the workman. The workman was given full opportunity to defend himself. The enquiry report is based on evidence on record. The workman was sent a copy of the enquiry report on it along with the notice of the proposed punishment on 06-1-1995. The workman made two representations dated 27-1-1995 and 4-2-1995. Thereafter, considering all the factors in this case, the Disciplinary Authority passed the order of punishment of stoppage of one increment dated 06th April 1995, which was confirmed in appeal by order dated 6th May 1996.

The Bank in its para-wise reply admitted the issues regarding the framing of charge sheet, the submission of the explanation by the workman, the holding of an enquiry but denied the core issues raised by the workman regarding the issuance of charge sheet by Miss C.D.D'Souza. It was said that she was competent to issue the charge sheet in capacity of Dy. General Manager (Establishment and Personnel). It was denied that the enquiry officer violated the principles of natural justice. It was stated that workman was supplied with all the documents and it has been so recorded in the enquiry proceedings. It was said that findings of the facts are not perverse. It was stated that workman cannot take the plea that since the concerned persons involved in the fraud were not examined and the documents relating them were not filed before the enquiry officers. Fair opportunity was given to the workman to defend his case. The Disciplinary Authority and the Appellate Authority had dealt with these points adequately. It was submitted that the promotion of the workman was kept in abeyance pending the enquiry as per memorandum of settlement dated 09-1-1991 since

the workman was not exonerated. He was not considered for promotion on the basis of the list prepared in year 1992 because he was punished in the enquiry. He did not take the next chance for promotion by participating in the promotion process started in December 1997. The Bank claimed that he could not rightfully claim promotion earlier because he was not exonerated.

7. The workman filed his rejoinder to the written statement. He contested the claim that he could not file the statement of claim. He further denied the averment made in the written statement. It is not necessary to repeat the version of the workman in the rejoinder.

8. The workman filed the affidavit of M. Salim in lieu of examination in chief on the point of fairness and propriety of the enquiry. The Bank countered by filing the affidavit of the representative of Bank in the enquiry Shri K. H. Gavankal Advocate. The workman was cross examined on 07-2-2002 and the witness for the Bank was cross examined on 18-2-2003. Both the counsel filed the written arguments.

9. It appears from the written argument filed on behalf of the Bank that it is not pursuing its objection to filing of Statement of claim or to the power and jurisdiction of this tribunal.

10. Similarly, the learned counsel for the workman has not raised the point that Mrs. C.D.D'Souza had no authority to issue to the charge sheet.

11. This brings us to the core issue involved in this case. Whether the workman was given a fair opportunity to defend himself? This tribunal must consider if the workman was given the documents necessary for his defence. It appears that on 19th March 1993 (page 40 of record of this tribunal) there was a demand of 4 documents. It appears that the aforesaid 4 documents were produced along with one more and they were marked as Ex. 17 to Ex. 21. The copies of these documents were supplied to the defence representative. These documents are related to event of issuance of cheque book by the workman. There were other documents. They too supplied to workman. However, the grievance of the workman that (see page 32) the workman was supplied document Nos. 1 to 4 mentioned at page 32. The document No. 4 of exhibit No. 7 and Nos. 6 to 10 were not supplied. The Ex. 7 which has filed by workman shows that he had demanded a copy of enquiry report of Mr. Kapasi. The other document Nos. 6 to 10 were circulars which were not supplied to the workman on the ground that did not exist. Let us now examine if any prejudice was caused to the workman in respect of a report of Mr. Kapasi. It was for the workman to prove that how his case was prejudiced by non supply of the aforesaid document. The workman says that the charges were framed on the basis of document No. 4. The workman appears to have stated that similar charge sheet was issued on the basis of enquiry

report against Kapasi. He admitted that there was no enquiry held against Mr. Kapasi. The version of the Bank is that the document No. 4 related to Mr. Kapasi and therefore, it was not produced. It appears from the description of document No. 4 in Ex-7 in the enquiry that workman was not himself sure of document. It is described as report/statement/decision in respect of Kapasi. Therefore, it is very difficult come to the conclusion that the workman was seriously prejudiced. His statement before this tribunal in cross-examination does not show that he was seriously prejudiced. Moreover, he did make attempt before this tribunal to require the Bank to produce that document. Under these circumstances, it is not possible to hold that the workman was seriously prejudiced. His defence was that he had pointed out that the signature of Mr. Shikari on the requisition slip did not tally with the specimen signature to Mr. Kapasi. However, Mr. Kapasi asked him to pass the requisition slip. If that be so, he should have taken care to get an order in writing from Mr. Kapasi.

12. It appears that otherwise the workman was given full opportunity and it is not his case that during the course of participation he was in any way obstructed.

13. However, the further case of the workman appears to be that Bank has chosen to examine two witnesses Mr. J. N. Amballa and Mr. K. S. Shikari. Other natural witnesses were omitted by the Bank. It may be remembered that on merits of the charges, it was necessary for the Bank to prove that workman was negligent in allowing the requisition slip to be handed over to Mr. Patil. The workman did not dispute that signature on the requisition slip was not tallying with the specimen. The workman should not have allowed the requisition slip to be issued to a third person. The defence of the workman that he referred the matter to Mr. Kapasi was not accepted by the enquiry officer on the basis of the evidence on record. The bank could not probably examine other persons, who may have been guilty as its witnesses. Their interests and their duties to give fair evidence conflicted. The material witness means only that witness who would prove the case of the Bank. The fact that other staff of member of the Bank too were guilty shall not absolve the workman of his guilt.

14. This tribunal has perused the enquiry report. The findings recorded there are based on the appreciation of evidence on record. The evidence recorded therein has not been misread or any illegal evidence has been considered for finding the workman guilty. Under these circumstances, this tribunal finds that the findings are not perverse.

15. This tribunal has also examined the findings of the enquiry officers from the point of view its powers vested in it under Section 11-A of the Act. After going through the evidence on record and the report of the

enquiry officer in quite details, this tribunal is not able to persuade itself that this is one of the these cases where this tribunal could interfere with the findings of the fact. It would be fair to say that the Enquiry Officer has not found the workman guilty of charge not verifying the requisition slip on the charge that on close examination it did not appear taken from the requisition slip supplied by the Fort Branch of the Bank.

The next question that has been determined is if the workman was given proper punishment. This tribunal is vested with the power to examine this question in exercise of its power under Section 11-A of the Act. It is also clear from the order dated 06-1-1995 (at page 139 of the documents of Bank) that the workman was awarded stoppage of one annual increment. This punishment was confirmed in appeal.

16. It is also clear that the workman could be given one punishment only in terms of order dated 06-1-1995. The other aspect of the matter is that whether the workman was denied promotion because he was found guilty. It is not disputed that the workman was due for promotion to the post of Officers but prior to passing of the order of promotion, the workman was charge sheeted. In paragraph 15 of the written statement it is admitted that the name of the workman was included in the list prepared on the basis merit on 24-1-1992. Before promotion, the workman was suspended on 11-9-1992. The Bank stated in paragraph 23 that as per settlement dated 09-1-1991 a person against whom the enquiry is pending is allowed to take part in promotion process but the promotion is withheld till the enquiry is completed. It has been stated that since the workman was not exonerated, his promotion on the basis of list of 1992 was not considered.

The workman in his rejoinder to paragraph 23 of the written statement stated that the contention that the workman was not eligible for promotion on account of punishment awarded to him was not acceptable. The order of punishment did not affect his promotion as he was already in the merit list.

19. The copy of the memorandum of settlement dated 09-1-1991 has been filed by the bank. It is marked as M-29. It is apparent from the opening paragraph of chapter IV that its provisions *inter alia* apply to promotion from the post of Clerical/Asstt. Accountant to the Officer cadre. It has been provided under the heading II REFUSAL TO ACCEPT THE PROMOTION as follows :

"II REFUSAL TO ACCEPT PROMOTION

If any employee refuses to accept promotion without adducing sufficiently convincing reason, he shall be debarred for promotion for a period of 3 years.

Employee in respect of whom disciplinary action has been taken for gross misconduct in the past would

not normally be permitted to participate in the promotion process for a period of 3 years from the time of infliction of the punishment.

In case, however, where minor penalties have been inflicted, a Committee of Executives would review and take a decision in regard to the eligibility for promotion having regard to the gravity of the misconduct and subsequent service record.

Employee in respect of whom disciplinary action is in process, will however, be permitted to take part in the promotion process, subject to the condition that the promotions will be withheld until the completion of the disciplinary action. In the event of the employee being exonerated, if due, will be given effect from the date on which it would have been otherwise effected but for the disciplinary action."

It will be readily seen that the workman was participated in the promotion process prior to the initiation of enquiry. The workman was already enlisted for promotion. Therefore, the clauses on which Bank relied upon did not strictly apply. The fact nevertheless remains that the workman was not exonerated. He was punished with stoppage of one annual increment. In the opinion of this tribunal that matter of punishment of the workman ended with the passing of order dated 06-1-1995 and the order in appeal dated 06-5-1995. The fact that workman was found eligible for promotion transpired before the order of punishment. As per settlement 09-1-1991 (Exhibit M 29) Chapter III the promotion policy under the heading Marks for Ranking the following items are relevant for award from Maximum number of marks amounting to 100.

(i) Length of service	...	30 marks
(ii) Test	...	45 marks
(iii) Interview	...	15 marks
(iv) Past Service Record	...	10 marks

All that can be said that due to result of enquiry the past service record involving only 10 marks could be affected. It is true that the punishment for a misconduct in last three years could be considered by the concerned by the authority. However, such punishment automatically does not oust of a workman from consideration for promotion. In view of this matter it is difficult to understand that how the workman disentitled himself from consideration for promotion. He could still be considered on the basis of all the marks obtained by him under of four heads except the head of past service. His position in list could be reviewed as compared to other candidates by awarding less marks. However, he could not be rejected out right. The Bank cannot be permitted to deny consideration for promotion on the ground a person is not exonerated in the enquiry and punished for a gross misconduct. The clause of settlement which says

that the memo/show cause notice issued for more than three occasions and/or punishment awarded by the Disciplinary Authority for last three years shall be considered shows that punishment for misconduct beyond three years can not be taken into account. This clause was made for fixing the period so far as it relates to punishment. It follows that the past service record could be considered in granting or refusing the promotion. However, the commission of a misconduct within three years by itself would not amount wiping out the other record of a workman and entitle the Bank to refuse consideration of promotion. Even to these persons who are disentitled from participating in the promotional process for three years. The rule is not absolute. It is not a normal rule. There can be exceptions in a given case. That means even in such a case mind has to be applied.

17. Although, the Bank had not pressed the objection taken by the Bank that this tribunal had no jurisdiction to direct it to grant promotion to the workman with effect from 1st April 1993 and grant consequential benefit. It is necessary to consider shortly whether this tribunal had any power to grant relief to the workman. It cannot be disputed that non-consideration of a workman for the post of promotion is covered by industrial dispute within meaning of Section 2k of the Act. It is a dispute concerned with the employment or non-employment or terms of employment or with the conditions of labour. If that be so, it may be noted that Bank itself had stated that settlement dated 15-1-1992 between the Bank and employees governed the service conditions of employees so far as their promotion was concerned. This tribunal has jurisdiction and power prescribed by the Second and the Third Schedule of the Act as per Section 7-A of the Act and any other act assigned to it under the Act. It cannot be disputed the question of punishment of a workman for a misconduct would be either covered by the standing orders or by the rules of Discipline mentioned in clause 1 of Second Schedule and clause 8 of third schedule of the Act. It is also not in dispute that the Memorandum of Settlement dated 15 Jan, 1992 filed by the Bank in booklet form (Marked as M 10) at page 16 of documents filed by the Bank controls the conditions of service of the workman. It includes misconduct and procedure for punishment as a term of Settlement. Therefore, it is obvious that this Tribunal is empowered to investigate if the workman was punished after following fair procedure. Once the tribunal was authorized to examine the above question as per second and third schedules of the Act, the Central Govt. had further power to refer the question of non-promotion of the workman because it was inevitably and inextricably mixed up with the question of punishment. Such power emanates from 10(1)(d) of the Act which authorizes the appropriate Govt. to refer the dispute or any matter connected with or relevant to the dispute, whether it relates to any matter specified in

second or third schedule for adjudication. It is not necessary to refer to any other provision. The clause 1(d) of section 10 assigns the power to this tribunal to adjudicate upon the matter connected with or relevant to the dispute referred to this tribunal. Section 7A itself say the tribunal can perform any other function assigned to it apart from adjudication of the matters referred to in second or third schedule. Even if this interpretation of section 7A may not be acceptable, the clause 1(d) of the dispute regarding promotion as matter connected with or relevant to the dispute referred to this tribunal for the misconduct committed by the workman.

18. The next question is what relief can be granted to the workman. This tribunal is of the opinion that the domestic enquiry against the workman cannot be faulted and the punishment of stoppage of one annual increment was proper. However, the Bank was not entitled to ignore the rights of the workman to be considered for promotion in the light of new facts emerging on the result of domestic enquiry. It is no doubt true that this tribunal cannot by any means promote the workman. Therefore, it would be proper to direct the Bank to reconsider the case of the workman for promotion to post of Officer with an additional factor that he has been punished. The factor of punishment shall be taken into consideration as if it is the past service record of the workman prior to promotion in accordance with the Memorandum Settlement dt. 09-1-91 filed by Bank at page 203 as per list of document and marked exhibit Ex-M-30 by this tribunal. If the authority or the committee authorized to promote the workman finds that workman is still eligible promotion. It shall compare the record of the workman with those who would in below rank and were promoted. If he is found fit compared those persons then he shall be promoted and given his seniority according to fitness. The Bank is directed to pass a reasoned order showing application of mind while comparing record of workman with those persons who were below him in the list of promotion prepared by the Bank in the year 1992.

19. Accordingly, this reference is answered by saying that there is no defect in the enquiry held against the workman but he could not be punished with non-consideration for promotion. Such a case would amount to punishing the workman with punishment of with holding promotion besides stoppage of one year annual increment. The workman can be punished only in accordance with the order of punishment. In view of this matter the Bank is directed to consider the case of promotion of the workman as stated in the previous paragraph. The reference is answered accordingly by granting the relief to workman partly.

S. C. PANDEY, Presiding Officer

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 2003

का. आ. 2216.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार ईस्टर्न रेलवे, धनबाद के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण सं. 1, धनबाद के पंचाट (संदर्भ संख्या 130/1997) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 10-7-2003 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-41012/45/96-आई. आर. (बी-1)]

अजय कुमार, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 11th July, 2003

S. O. 2216.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Reference No. 130 of 1997) of the Central Government Industrial Tribunal No. 1 Dhanbad now as shown in the annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Eastern Railway, Dhanbad and their workman, which was received by the Central Government on 10-07-03.

[No. L-41012/45/96-I.R.(B-I)]

AJAY KUMAR, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1, DHANBAD.

In the matter of a reference U/S. 10(1)(d) of I.D. Act, 1947.

Reference No. 130 of 1997.

Parties : Employers in relation to the management of Eastern Railway, Dhanbad.

AND

Their Workman.

PRESENT :

Shri S.H. Kazmi, Presiding Officer.

APPEARANCES :

For the Employers : None.

For the Workman : None.

State : Jharkhand.

Industry : Railway.

Dated, the 27th June, 2003

AWARD

By Order No. L-41012/45/96-I.R. (B-I) dated 23-6-1997 the Central Government in the Ministry of Labour has, in exercise of the powers conferred by clause

(d) of sub-section (1) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, referred the following dispute for adjudication to this Tribunal :

“Whether the action of the Divisional Railway Manager, Eastern Railway, Dhanbad Division, P.O. & Dist. Dhanbad in reverting Sh. Kanti Lal Saw, Peon as Waterman is justified? If not to what relief is the concerned workman entitled?”

2. In this reference case of the year 1997 none has appeared so far on behalf of the parties by filing letter of authority and at no stage during pendency of this case any step whatsoever was taken. From time to time only notices were being sent repeatedly and adjournments were granted on several occasions to enable the parties particularly the workman/union to appear and file written statement. However, to-day when the case was called out Sri R.A. Chamaria, President of the sponsoring union, namely, Rashtriya Mazdoor Sangh, appeared and by filing one petition submitted that exactly for the same subject matter and with the same term of reference concerning the workman concerned named Kanti Lal Saw, one another reference being numbered as Reference No. 21 of 1998 is pending for final disposal before Central Govt. Industrial Tribunal No. 2, Dhanbad and in that case, according to him, presently the evidence is going on. According to Shri Chamaria, in such circumstances keeping the present reference pending is absolutely needless and some necessary order in regard to the disposal of the reference be passed. None is appearing on behalf of other side to dispute the aforesaid contention or submission. There does not appear to be any reason to disbelieve the aforesaid fact or development brought to the notice of this Tribunal particularly when the concerned office bearer of the sponsoring union is furnishing the number of that reference case also which is pending before another Tribunal. From the aforesaid fact it is evident that wrongly or by mistake for the same subject matter two cases were referred to two different Central Govt. Industrial Tribunals by the concerned Ministry for adjudication. Anyway, since now the aforesaid fact has been brought to the notice of this Tribunal the present reference is simply required to be dropped or finally disposed of in terms of the aforesaid observation.

This reference, as such, stands dropped and is hereby disposed of.

S.H. KAZMI, Presiding Officer

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 2003

का. आ. 2217.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार इंडिया गवर्नमेन्ट मिनट के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण सं. 2, मुम्बई के पंचाट (संदर्भ संख्या सी जी आई टी-

2/105 ऑफ 2000) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 9-7-2003 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-16012/1/2000-आई. आर. (डी.यू.)]
कुलदीप राय वर्मा, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 9th July, 2003

S. O. 2217.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. CGIT-2/105 of 2000) of the Central Government Industrial Tribunal/Labour Court No. 2 Mumbai now as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of India Government Mint, and their workman, which was received by the Central Government on 9-7-2003.

[No. L-16012/1/2000-IR(DU)]
KULDIP RAI VERMA, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2, MUMBAI

PRESENT :

Shri S.N. Saundankar, Presiding Officer.

Reference No. CGIT-2/105 of 2000

EMPLOYERS IN RELATION TO THE
MANAGEMENT OF INDIA GOVERNMENT
MINT

The General Manager,
India Government Mint,
Ministry of Finance,
Mumbai 400 023.

V/s.

THEIR WORKMEN

Shri Gopinath S. Nadekar,
CGS Colony, Sector 6,
Bldg. No. 202, Room No. 2443,
Antop Hill, Sion-Koliwada,
Mumbai 400 037.

APPEARANCES :

For the Employer : Mr. V. Narayanan, Advocate.

For the Workmen : Mr. A.M. Koyande, Advocate.

Mumbai, Dated 26th May, 2003.

AWARD PART-II

By the Interim Award dated 17th September, 2002 this Tribunal held that the domestic inquiry conducted against the workman Nadekar was against the Principles of Natural Justice and the findings of the Inquiry Officer

are perverse. Consequently management was directed to lead evidence to justify its action.

2. On perusal of the record it is seen workman by the application (Exhibit-24) pointed out that since management India Government Mint did not aver in their Written Statement that in case inquiry held vitiated it be given an opportunity to lead evidence to justify its action and that till the decision the management did not choose to adduce any evidence, relying on the decision in Karnataka State Road Transport Corporation case and the land mark Judgement in Shankar Chakravarty case, since, inquiry held vitiated, workman be reinstated in service with full back wages. Consequently this Tribunal vide order dated 27/1/03 (Exhibit-25) modified the Interim Award to the extent to allow the management to lead evidence to justify its action and Corrigendum to that effect was issued vide (Exhibit-32).

3. In so far as issues 3 & 4 (Exhibit-14) which remained for adjudication of this Tribunal, after the Corrigendum (Exhibit-32) management Mint vide (Exhibit-27) requested to allow them to lead evidence to justify its action in the light of the charges and also filed written submission (Exhibit-31) and the workman Ex. 28 on the issues and after hearing the Learned Counsel, perusing the record as a whole, I record my findings as follows :

Issues	Findings
3. Whether the action of the Management of India Government Mint, Mumbai by compulsorily retiring Shri Gopinath Santu Nadekar from the services of India Government Mint is justified and proper ?	No
4. What relief the workman is entitled to ?	As per order below.

REASONS

4. The learned Counsel Mr. Narayanan for the management inviting attention to the written submissions (Exhibit-31) urged that the Mint is a very sensitive Department and that the alleged misconduct on the part of the workman in respect of theft cannot go unpunished and from this point of view, he submits action of compulsorily retiring the workman from service is fully justified. On the other hand, the Learned Counsel Mr. Koyande for the workman relying on the KSRTC's case urged that management admittedly did not recite in their Written Statement nor thereafter till the disposal of the matter chosen to lead evidence to justify its action in case inquiry held vitiated which shows, the management is not willing to avail opportunity to lead evidence and that no obligatory duty in law to give any such opportunity *suo motu* by the Tribunal, notwithstanding the fact that

none was ever asked for or not even departed from, the management in any event now, cannot be allowed to lead evidence as Their Lordships in the said decision while making the observation to the above effect in their anxiety, that there is no undue delay in industrial adjudication. He submits that in view of the observation of Their Lordships of Apex Court in Shankar Chakravarty case and also in K.S.R.T.C. case referred to above, management cannot be allowed to lead evidence resultantly workman is entitled to reinstatement with full back wages.

5. I have gone through the decision referred to above and the ratio in the said ruling is applicable to the facts of the present case. Therefore relying on the said decision in view of the order dated 27-1-03 (Exhibit-25) and corrigendum (Exhibit-32) there is no alternative except to direct the management to reinstate the workman in service with full back wages. Consequently issue Nos. 3 & 4 are answered accordingly and hence the order :

ORDER

Since domestic inquiry held vitiated and there is no request to allow the management to lead evidence in case inquiry held vitiated till the disposal of the matter, management is directed to reinstate the workman Nadekar in service with full back wages.

S.N. SAUNDANKAR, Presiding Officer

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 2003

का. आ. 2218.—दिनांक 12 अप्रैल, 2003 को भारत के राजपत्र के भाग II, खण्ड-3, उप खण्ड (ii) में का. आ. संख्या 1173 द्वारा प्रकाशित श्रम मंत्रालय की अधिसूचना में, निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

क्रम संख्या

56. "कारपोरेट ऑफिस ऑफ मैसर्स हिन्दुस्तान लैटैक्स लिमिटेड, त्रिवेन्द्रम (पूजापुरा), त्रिवेन्द्रम (काँगला में इसकी निरोध फैक्ट्री तथा काँगला इकाई सहित)" के स्थान पर "कारपोरेट ऑफिस ऑफ मैसर्स हिन्दुस्तान लैटैक्स लिमिटेड, त्रिवेन्द्रम (पूजापुरा) और त्रिवेन्द्रम (काँगला में इसकी निरोध फैक्ट्री तथा पेरोकाडा इकाई और काँगला इकाई के ठेका श्रमिकों सहित)" पढ़ें।

38. "सेन्ट्रल स्टोर्स एंड सप्लाय डिबीजन ऑफ नेशनल सीइस कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली" के स्थान पर "सेन्ट्रल स्टोर्स एंड सप्लाय डिबीजन आफ नेशनल सीइस कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली तथा इसकी भटिन्डा, जालंधर, सिकन्द्राबाद, कुरनूल, गुन्नूर तथा नंदयाल इकाइयाँ" पढ़ें।

78. "मैसर्स भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बंगलौर" के स्थान पर "मैसर्स भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, बंगलौर/के जी एफ/मैसूर" पढ़ें।

11. "मैसर्स हिन्दुस्तान जिक लिमिटेड, उदयपुर, राजस्थान" के स्थान पर "मैसर्स हिन्दुस्तान जिक लिमिटेड, उदयपुर तथा चित्तोड़गढ़, राजस्थान" पढ़ें।

[संख्या एस-38014/49/2002-एस एस-1]

के. सी. जैन, निदेशक

CORRIGENDUM

New Delhi, the 17th July, 2003

S.O. 2218.—In the Notification of the Ministry of Labour published in the Gazette of India Part-II, Section 3, Sub-Section (ii) dated 12th April, 2003 vide SO No. 1173, the following entries shall be substituted namely :—

S.No.

56. For 'Corporate Office of M/s. Hindustan Latex Ltd., Trivandrum (Poojapura), Trivandrum (including its Nirodh Factory at Kanagala and Kanagala unit' Read 'Corporate Office of M/s. Hindustan Latex Ltd., Trivandrum (Poojapura) and Trivandrum (including its Nirodh Factory at Kanagala and Perokada unit and contract employees of Kanagala unit.'

38. For 'Central Stores and Supply Division of National Seeds Corporation Ltd., New Delhi, Read 'Central Stores & Supply Division of National Seeds Corporation Ltd., New Delhi and its units at Bhatinda, Jalandhar, Secunderabad, Kurnool, Guntur and Nandyal'.

78. For 'M/s. Bharat Earth Movers Ltd., Bangalore', Read 'M/s. Bharat Earth Movers Ltd., Bangalore/KGF/ Mysore'.

11. For 'M/s. Hindustan Zinc Ltd., Udaipur, Rajasthan', Read 'M/s. Hindustan Zinc Ltd., Udaipur & Chittorgarh, Rajasthan'.

[No. S-38014/49/2002-S.S.I]

K.C. JAIN, Director

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 2003

का. आ. 2219.—केन्द्रीय सरकार संतुष्ट हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उप-खण्ड (vi)

के उपबंधों के अनुसरण में भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 512 दिनांक 14-1-2003 द्वारा ताम्बा खनन उद्योग जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 13 में शामिल है, को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए दिनांक 25-1-2003 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था;

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है;

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उप-खण्ड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए दिनांक 25-7-2003 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. संख्या एस-11017/11/97-आई. आर. (पी. एल.)]

जे. पी. पति, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 22nd July, 2003

S.O. 2219.—Whereas the Central Government having been satisfied that the public interest so required that in pursuance of the provisions of sub-clause (vi) of the clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), declared by the Notification of the Government of India in the Ministry of Labour S.O. No. 512 dated 14-1-2003 the services in the Copper Mining Industry which is covered by item 13 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) to be a public utility service for the purpose of the said Act, for a period of six months from the 25th January, 2003.

And whereas, the Central Government is of opinion that public interest requires the extension of the said period by a further period of six months.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of Section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947, the Central Government hereby declares the said industry to be a public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months from the 25th July, 2003.

[F. No. S-11017/11/97-IR(PL)]

J.P. PATI, Jt. Secy.